



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2026 की प्रतिवेदन संख्या 17
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2026 की प्रतिवेदन संख्या 17
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I: परिचय		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
बजट एवं व्यय नियंत्रण	1.4	3
केंद्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.5	5
बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	1.6	10
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	1.7	11
2023-24 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए/माफ़ किए गए अप्राप्य देयताएं एवं हानियां	1.8	13
पिछले निरीक्षण रिपोर्टों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	1.9	13
मसौदा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रियाएं	1.10	14
लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.11	15
अध्याय II: परमाणु ऊर्जा विभाग		
परमाणु ऊर्जा विभाग में भूमि और संपदा प्रबंधन पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1	17
टाटा मेमोरियल केंद्र की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	2.2	58
स्थापना स्थलों के पूर्ण न होने और लिफ्ट के पुर्जों के लंबे समय तक भंडारण के कारण खराब होने से ₹1.45 करोड़ का परिहार्य व्यय	2.3	127
अध्याय III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
लेजर वेल्डिंग मशीन के गैर/उप-इष्टतम (सब-ऑप्टिमल) उपयोग के कारण ₹1.52 करोड़ का निष्फल व्यय	3.1	131

अध्याय IV: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1	135
अध्याय V: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय	5.1	168
अध्याय VI: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सिस्टम के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	6.1	172
₹5.07 करोड़ का निष्फल व्यय	6.2	223
अनुलग्नक		229

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2023-24 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, साथ ही वे भी जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्ज नहीं किए जा सके। आवश्यकतानुसार, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की यह रिपोर्ट भारत सरकार के आठ¹ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ उनके अधीन स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। इस रिपोर्ट में चार पैरा, दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) और अप्रभावी/टालने योग्य व्यय, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और शासन, अक्षम परियोजना और अनुबंध प्रबंधन और आई.टी. सिस्टम और स्वचालन से संबंधित मामलों से संबंधित दो सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग में भूमि और संपदा प्रबंधन की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के पास भूमि और संपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए कोई व्यापक नीति या नोडल अनुभाग नहीं है। नवंबर 2011 में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, डी.ए.ई. ने 14 से अधिक वर्षों के बाद भी एक सामान्य भूमि हस्तांतरण नीति तैयार नहीं की थी और ऐसी नीति के अभाव के परिणामस्वरूप इकाइयों में असमान प्रथाओं का पालन किया गया था। एक व्यापक नीतिगत ढांचे या एक नामित नोडल प्राधिकरण की अनुपस्थिति के कारण इसके सभी इकाइयों में निर्णय लेने में कमी और कमजोर निगरानी हुई। केन्द्रीयकृत तंत्र के बिना, भूमि आवंटन, पट्टा प्रबंधन और परिसंपत्ति निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को असंगत रूप से संभाला गया था। इस कमी का एक प्रमुख परिणाम भूमि हस्तांतरण और पट्टा प्रशासन के लिए एक संरचित प्रणाली की कमी थी। कई मामलों

¹ 1. परमाणु ऊर्जा विभाग, 2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, 3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, 4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 5. अंतरिक्ष विभाग, 6. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 7. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और 8. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

में, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना भूमि को स्थानांतरित या बरकरार रखा गया, जिससे स्थापित शासन मानदंडों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, पट्टे के समझौतों के नवीनीकरण में देरी के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व का नुकसान हुआ, क्योंकि संपत्तियों पर संशोधित शर्तों या संशोधित पट्टे के किराए की वसूली के बिना कब्जा जारी रहा। विभाग ने अनुचित वित्तीय रियायतें भी दीं, जिसमें अनुमेय सीमा से अधिक सरकारी आवासों को बनाए रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किराए से मुक्त आवास का प्रावधान और निजी संस्थाओं को रियायती लाइसेंस शुल्क शामिल है, जिसके लिए सदस्य (वित्त) से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

डी.ए.ई. ने 1954 में अपनी स्थापना के 71 वर्षों से अधिक समय बाद भी अपने सभी घटक इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू समान विभागीय पूल आवासीय आवास नियम तैयार नहीं किए थे। मानकीकृत दिशानिर्देशों के बिना, आवंटन, प्रतिधारण और शुल्क वसूली प्रथाएं व्यापक रूप से भिन्न थीं। क्षति दरों, विशेष लाइसेंस शुल्क, अंतिम स्थान पर पुनः हस्तांतरण पर आवंटन के नियमितीकरण और संघों से लाइसेंस शुल्क की वसूली से संबंधित प्रमुख प्रावधान, जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के विभिन्न आदेशों में शामिल हैं, को समान रूप से नहीं अपनाया गया था। इन प्रणालीगत कमियों के परिणामस्वरूप, विभाग को महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ा। वैध समझौतों को निष्पादित करने और भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने में देरी के कारण बकाया राशि की कम वसूली और अनावश्यक व्यय हुआ। आवासीय क्वार्टर बनाने और इमारतों के रखरखाव/देखभाल के लिए समय पर कार्रवाई न करने में बहुत ज़्यादा देरी के कारण एच.आर.ए. के भुगतान और अन्य संबंधित खर्चों पर अनावश्यक खर्च हुआ।

(पैरा 2.1)

प्रमुख अनुशंसाएं

- डी.ए.ई. कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एक व्यापक भूमि हस्तांतरण और पट्टे की नीति तैयार और अधिसूचित कर सकता है।
- डी.ए.ई. अपनी सभी घटक इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर लागू समान विभागीय पूल आवासीय आवास नियम तैयार और कार्यान्वित कर सकता है।
- डी.ए.ई. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार कर सकता है ताकि वह या तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एच.आर.ए. घटक की वसूली कर सके या वह संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त क्वार्टरों की निर्माण लागत के लिए दावा करने के लिए योगदान की राशि का आकलन कर सके।
- डी.ए.ई. सदस्य (वित्त) की मंजूरी से बैंकों/डाकघरों को स्थान प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क के निर्धारण की दिशा में व्यापक समीक्षा कर सकता है।
- डी.ए.ई. समय पर नवीनीकरण की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है, जिसमें संशोधित पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क/जमीनी किराया शामिल है।

टाटा मेमोरियल सेंटर की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

टी.एम.सी. के पास अनुमोदित आई.टी. नीति नहीं थी, जिसके कारण आई.टी. संचालन और सुरक्षा के लिए संरचित मार्गदर्शन की कमी हुई. क्रमागत कमियों में बिजनेस निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना का अभाव था, साथ ही पासवर्ड प्रबंधन और तार्किक पहुंच नियंत्रण में महत्वपूर्ण अंतराल थे। इसके अलावा, टी.एम.सी. विक्रेताओं के साथ औपचारिक सेवा स्तर समझौते को निष्पादित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनसुलझे तकनीकी मुद्दों और सिस्टम खराबी के बावजूद निरंतर भुगतान हुआ। अस्पताल सूचना प्रणाली (एच.आई.एस.)

के कार्यान्वयन में अत्यंत देरी देखी गई, कई माँड्यूल केंद्रों में गैर-कार्यात्मक रहे। नतीजतन, इन कमजोरियों ने केंद्र में संभावित डेटा हानि के खतरे को उत्पन्न किया और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता को प्रभावित किया।

(पैरा 2.2)

प्रमुख अनुशंसाएं

- टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए आई.टी. रणनीतिक योजना तैयार की जा सकती है ताकि प्रौद्योगिकी योजना और कार्यान्वयन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
- बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर विकास और साइबर सुरक्षा की रणनीतिक योजना के संबंध में संगठन को सौंपे गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए आई.टी. संचालन समिति का गठन किया जा सकता है।
- टाटा मेमोरियल सेंटर में सुव्यवस्थित योजना और इन-हाउस विकास, सॉफ्टवेयर के परीक्षण और तैनाती के लिए एक औपचारिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नीति को अपनाया और उसका पालन किया जा सकता है, साथ ही डेटा सुरक्षा के लिए परीक्षण वातावरण और लाइव सर्वर का उचित पृथक्करण भी किया जा सकता है।
- संगठन के उद्देश्य के अनुरूप आई.टी. सुरक्षा नीति तैयार की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नीति उद्देश्य-उन्मुख, अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध और निरंतर सुधार पर केंद्रित है।
- फ़िशिंग, क्रेडेंशियल्स लीक या अनधिकृत एक्सेस हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को शामिल करते हुए एक मजबूत पासवर्ड प्रबंधन नीति लागू की जा सकती है। नवीनतम सुरक्षा पैच आई.टी. सिस्टम पर स्थापित किए जा सकते हैं और साइबर हमलों को रोकने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन

प्रतिक्रिया दल/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आई.टी. सुरक्षा प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी की जा सकती है।

- सिस्टम में डेटा के मैनुअल इनपुट के बजाय सिस्टम स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन को जांच लागू करने की आवश्यकता है।

स्थापना स्थलों के पूरा न होने और लंबे समय तक भंडारण के कारण लिफ्ट घटकों के क्षरण के कारण ₹1.45 करोड़ का अपरिहार्य व्यय

स्थापना स्थल के सात वर्षों से अधिक समय तक पूरा न होने के कारण, निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय ने स्थापना से पहले लिफ्ट घटकों के प्रतिस्थापन और मरम्मत पर ₹1.45 करोड़ का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय किया।

(पैरा 2.3)

लेजर वेल्डिंग मशीन के गैर/उप-इष्टतम उपयोग के कारण ₹1.52 करोड़ का निष्फल व्यय

यद्यपि इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स ने लेजर वेल्डर की खरीद के लिए ₹1.08 करोड़ का व्यय किया, तथापि उसने यह सुनिश्चित करने में उचित सावधानी नहीं बरती कि उपकरण स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गई है। इस कारण लेजर वेल्डिंग मशीन लंबे समय तक अप्रयुक्त रही, जिससे वह मुख्य उद्देश्य विफल हो गया जिसके लिए इसे खरीदा गया था।

(पैरा 3.1)

‘प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि’ योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि (एल.एच.आर.एफ.) को बजटीय संसाधनों के पूरक के रूप में और उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाली प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग में

क्रमागत कमियों को देखा। एल.एच.आर.एफ. से व्यय न्यूनतम था, क्योंकि अधिकांश समय, नमूना प्रयोगशालाओं (सी.एस.आई.आर. मुख्यालय सहित) ने पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पन्न निधि के अनिवार्य एक तिहाई का भी उपयोग नहीं किया था। नतीजतन, एल.एच.आर.एफ. में संचित शेष राशि बढ़ती रही और 31 मार्च 2025 को ₹3,490.68 करोड़ पर पहुंच गई।

सी.एस.आई.आर. ने हाल ही में 2024-25 से एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग के लिए वार्षिक बजटीय योजना और दीर्घकालिक योजना को अपनाया है। सी.एस.आई.आर. इनोवेशन फंड के तहत ₹627.71 करोड़ की धनराशि, जो प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केंद्रों और प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना, स्टार्ट-अप और स्पिन-ऑफ आदि के लिए थी, अप्रयुक्त रही। एल.एच.आर.एफ. प्राप्तियों का लगभग 48 प्रतिशत ब्याज से आया। यह अपर्याप्त उपयोग के कारण एल.एच.आर.एफ. के संचय को इंगित करता है और यह कि निधियों में वृद्धि काफी हद तक अनुसंधान और विकास प्राप्तियों के बजाय संचित निधियों पर अर्जित ब्याज के लिए जिम्मेदार थी। एल.एच.आर.एफ. को विविध प्राप्तियों के अनधिकृत क्रेडिट, बंद बाहरी नकद प्रवाह परियोजनाओं के खातों का निपटान नहीं होना और बाहरी नकद प्रवाह परियोजनाओं के तहत प्रायोजक/वित्तपोषण एजेंसी से लगाए गए काल्पनिक प्रत्यक्ष खर्चों के उदाहरण भी देखे गए। इसके अलावा, सी.एस.आई.आर. अनिवार्य समिति, पोर्टल और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एल.एच.आर.एफ. के उपयोग पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण का अभाव हुआ।

(पैरा 4.1)

प्रमुख अनुशंसाएं

- **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने बजटीय संसाधनों की पूर्ती के लिए पिछले वर्ष में उत्पन्न प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का कम से कम 1/3 भाग सुनिश्चित करते हुए संचित निधियों का उपयोग करने का प्रयास कर सकती है।**

- सी.एस.आई.आर. और उसकी प्रयोगशालाएं वार्षिक बजटीय योजना में एल.एच.आर.एफ. के प्रस्तावित उपयोग को शामिल कर सकती हैं।
- सी.एस.आई.आर. और उसकी प्रयोगशालाओं को एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग के लिए अपनी योजना और बजट तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- सी.एस.आई.आर. यह सुनिश्चित कर सकता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.) के लाइसेंस से उत्पन्न होने वाले रॉयल्टी और प्रीमियम जैसे वैकल्पिक स्रोतों से धन उत्पन्न करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।
- सी.एस.आई.आर. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-अनुसंधान और विकास प्राप्तियों को एल.एच.आर.एफ. में जमा नहीं किया जाए और उनका उचित उपयोग किया जाए ताकि बजटीय समर्थन पर निर्भरता कम की जा सके।
- सी.एस.आई.आर. यह सुनिश्चित कर सकता है कि बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के खातों का निपटान उनकी स्वीकृत अवधि की समाप्ति पर तुरंत किया जाए और बंद परियोजनाओं की गैर-वापसी योग्य शेष राशि बिना किसी देरी के एल.एच.आर.एफ. में स्थानांतरित कर दी जाए।
- सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रत्यक्ष लागत से संबंधित प्राप्तियों के लेखांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है।
- सी.एस.आई.आर. मुख्यालय एक समर्पित पोर्टल सहित एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार कर सकता है।

फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया, जिसे अनुमोदित योजना में

शामिल नहीं किया गया था, इसके अलावा प्रतिपूरक वनीकरण निधि से प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(पैरा 5.1)

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

एस.ई.सी.आई. ने स्वचालन, पारदर्शिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की परिकल्पना की थी; हालाँकि, महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं और प्रमुख मॉड्यूल गैर-कार्यान्वित होने के कारण इसने तंत्र का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। वित्तीय स्वचालन के लिए प्रणाली का लाभ उठाने में एक मौलिक विफलता देखी गई, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से संबंधित 96 प्रतिशत लेनदेन अभी भी मैनुअल रूप से संसाधित किए गये थे। मैनुअल प्रक्रियाओं पर निरंतर निर्भरता ने ई.आर.पी. समाधान के प्राथमिक उद्देश्य को कमजोर कर दिया है, जिससे परिचालन अक्षमता और जोखिम बढ़ गया है। अपर्याप्त पहुंच नियंत्रण और सिस्टम इंटीग्रेटर को अनधिकृत उच्च-विशेषाधिकार भूमिकाओं के असाइनमेंट के कारण सुरक्षा जोखिम बढ़ गए थे। इसके अलावा, औपचारिक परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण की कमी ने स्वीकरण को सीमित कर दिया, जिससे संगठन विक्रेता निर्भरता के प्रति संवेदनशील हो गया। एस.ई.सी.आई. शासन तंत्र के लिए आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने में विफल रहा, जिसके लिए शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता थी। नतीजतन, महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं के गैर-कार्यान्वयन ने सिस्टम को मूल रूप से योजना के अनुसार उपयोग करने से रोक दिया है।

(पैरा 6.1)

प्रमुख अनुशंसाएं

- एस.ई.सी.आई. को यह सुनिश्चित करके अपने आई.टी. शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए कि संचालन समिति ई.आर.पी. कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करे।

- एस.ई.सी.आई. को मापने योग्य लक्ष्यों के साथ परिवर्तन प्रबंधन प्रदेयों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परिवर्तन प्रबंधन रणनीति और योजना तैयार करके भविष्य की परियोजनाओं के लिए अपने शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए, उन्हें ई.आर.पी. विकास/परीक्षण चरणों से जोड़ना चाहिए और समय-सीमा के सापेक्ष प्रगति को ट्रैक करने के लिए तंत्र प्रदान करना चाहिए।
- एस.ई.सी.आई. को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित सभी प्रमुख कार्यक्षमताओं, जिसमें शेड्यूलिंग, विचलन निपटान तंत्र और डनिंग गणना शामिल हैं, को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में लागू किया गया है।
- एस.ई.सी.आई. को अलर्ट तंत्र के साथ मेमोरी सीमा को परिभाषित करना चाहिए, नियमित सिस्टम स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए, स्पष्ट विक्रेता जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए और बाहरी विक्रेताओं पर निर्भरता को कम करने के लिए उचित डेटाबेस आकार और स्टाफ प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च मेमोरी उपयोग के मूल कारण का समाधान करना चाहिए।
- एस.ई.सी.आई. को वर्कफ़्लो-आधारित एस.ए.पी. एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना चाहिए।
- एस.ई.सी.आई. को भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण लागू करते समय अनावश्यक तालिका प्रदर्शन और संशोधन प्राधिकरणों को रद्द कर देना चाहिए। डिबगिंग विशेषाधिकारों को अनुमोदित डेवलपर्स तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और अनधिकृत पहुंच को हटा दिया जाना चाहिए।
- एस.ई.सी.आई. को मेकर-चेकर नियंत्रणों, लेखापरीक्षा ट्रेल्स और स्वचालित वर्कफ़्लो के साथ ई.एम.डी., बैंक गारंटी और प्रदर्शन प्रतिभूतियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक एस.ए.पी.-आधारित मॉड्यूल के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।

- एस.ई.सी.आई. को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया और सभी प्रासंगिक खरीद नीति खंडों को बिजनेस ब्लूप्रिंट में शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में मैप किए गए हैं।

₹5.07 करोड़ का निष्फल व्यय

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल परियोजना (लघु जलविद्युत परियोजनाएं) की खराब योजना के कारण ₹5.07 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैरा 6.2)

अध्याय I

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

संघ और राज्यों, सरकारी कंपनियों और निगमों, निकायों और प्राधिकरणों के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश, संविधान और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण हैं, जिन्हें संघ और राज्यों के खातों की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिनियम की धारा 13 (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ की सरकारों, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों और अन्य लेन-देन का लेखापरीक्षण करे। भारत के संविधान और सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों की लेखापरीक्षा को भी कवर करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता स्तर, लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियां और निर्देश तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन में योगदान मिलेगा और बेहतर शासन होगा।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा को समझाने के अलावा, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।

अध्याय II से आगे उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष/अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

यह रिपोर्ट भारत सरकार के निम्नलिखित आठ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और सी.पी.एस.ई. सहित उनकी इकाइयों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है:

1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)
3. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - क. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)
 - ख. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) और
 - ग. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
5. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
6. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा से आशय व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित लेन-देन की जांच करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के संविधान और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं और साथ ही उनके उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी

वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावशीलता का निर्धारण करना है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली निरीक्षण रिपोर्ट इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाइयों से अनुरोध है कि वे निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो निपटाया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण रिपोर्टों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए मसौदा पैरा के रूप में अलग से जारी की जाती हैं और लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए संसाधित की जाती हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

2023-24 के दौरान, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सहित 356 इकाइयों में से 157 इकाइयों का अनुपालन लेखापरीक्षा उपलब्ध संसाधनों और इकाइयों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

1.4 बजट एवं व्यय नियंत्रण

वर्ष 2023-24 और पिछले वर्ष 2022-23 के लिए वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 1** में दी गई है।

तालिका 1: वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	2022-23	2023-24
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	34487.31	35885.96
2.	अंतरिक्ष विभाग	10158.48	10726.78
3.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5853.37	6152.32
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4559.99	4113.11
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2121.42	1537.81
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2837.75	3522.11

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	2022-23	2023-24
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	11121.14	12594.81
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1586.08	2409.45
	कुल	72725.54	76942.35

(स्रोत: विस्तृत अनुदान की मांग)

भारत सरकार के आठ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹76,942.35 करोड़ था, जबकि वर्ष 2022-23 में यह ₹72,725.54 करोड़ था, अर्थात् ₹4,216.81 करोड़ (5.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹76,942.35 करोड़ के कुल व्यय में से 46.64 प्रतिशत व्यय केवल परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए व्यय की तुलना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में व्यय में क्रमशः 9.80 प्रतिशत और 27.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

विनियोजन खातों का सारांश नीचे **तालिका 2** में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग से दिया गया है।

तालिका 2: वर्ष 2023-24 के दौरान वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुदान और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (पूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य	अव्ययित घटक का प्रतिशत
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	37506.05	35885.96	(-)1620.09	4.32
2.	अंतरिक्ष विभाग	13130.26	10726.78	(-)2403.48	18.30
3.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6202.53	6152.32	(-)50.21	0.81
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7932.28	4113.11	(-)3819.17	48.15
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2683.88	1537.81	(-)1146.07	42.70

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (पूरक अनुदान सहित)	व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य	अव्ययित घटक का प्रतिशत
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3940.35	3522.11	(-)418.24	10.61
7.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	17734.97	12594.81	(-)5140.16	28.98
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3324.43	2409.45	(-)914.98	27.52
कुल		92454.75	76942.35	(-)15512.40	16.78

(स्रोत: विस्तृत अनुदान की मांग)

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹92,454.75 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों ने कुल ₹15,512.40 करोड़ की बचत की थी, जो कुल अनुदान/विनियोजन का 16.78 प्रतिशत है।

₹15,512.40 करोड़ के कुल अप्रयुक्त बजट में से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (48.15 प्रतिशत) का अप्रयुक्त बजट सबसे अधिक था, इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी विभाग (42.70 प्रतिशत), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (28.98 प्रतिशत) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (27.52 प्रतिशत) का स्थान रहा।

1.5 केंद्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के तहत 85 केंद्रीय स्वायत्त निकाय हैं। इनमें से, 11 केंद्रीय स्वायत्त निकायों² का लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा³ 19(2) और 20(1) के तहत किया गया है और शेष

² जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली भी शामिल है, जिसे कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं होती है। उन्हें बजटीय सहायता दी जाती है जो अंततः राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष से पूरी की जाती है/घटाई जाती है।

³ धारा 19(2)-संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित निगमों (कंपनियों के रूप में नहीं) के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। धारा 20(1)-जहां किसी निकाय या प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षण संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपा गया है, वहां वह, यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, जैसा भी मामला हो, ऐसे निकाय या प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षण ऐसी शर्तों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो सकती हैं और ऐसे लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, उस निकाय या

74 केंद्रीय स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा धारा⁴ 14 या 15 के तहत किया गया है। 2023-24 के दौरान 74 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (धारा 14 या 15 के तहत) को जारी कुल अनुदान ₹7,119.90 करोड़ था (अनुलग्नक 1)। 2022-23 और 2023-24 के दौरान 10 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (धारा 19(2) और 20(1) के तहत) को जारी कुल अनुदान क्रमशः ₹8,617.67 करोड़ और ₹7,676.79 करोड़ था, जैसा कि नीचे तालिका 3 में विस्तृत है।

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान धारा 19 (2) और 20 (1) के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	केन्द्रीय स्वायत्त संस्था का नाम	मंत्रालय/विभाग	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी अनुदान की राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी अनुदान की राशि
1.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	5829.42	6141.43
2.	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	डी.एस.टी.	335.00	342.50
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	100.00	4.70
4.	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली (अब अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन)	डी.एस.टी.	2176.00	1004.50
5.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	डी.बी.टी.	52.45	60.00
6.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	52.85	24.96
7.	वन्यजीव संस्थान, देहरादून जिसमें सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री शामिल है	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	30.60	54.82
8.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	10.83	10.05
9.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.	17.92	16.48

प्राधिकरण की पुस्तकों और खातों तक पहुंच का अधिकार होगा, बशर्ते कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श किए बिना ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

⁴ धारा 14-संघ या राज्य राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण।
धारा 15-अन्य प्राधिकरणों या निकायों को दिए गए अनुदान या ऋण के मामले में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्य।

क्रम संख्या	केन्द्रीय स्वायत्त संस्था का नाम	मंत्रालय/विभाग	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी अनुदान की राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी अनुदान की राशि
		एवं सी.सी.		
10.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	12.60	17.35
कुल			8617.67	7676.79

1.5.1 वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुई कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे **तालिका 4** में दी गई हैं:

तालिका 4: केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	स्वायत्त संस्था का नाम	टिप्पणी
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
1.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी और रिफंड से संबंधित ₹266.90 करोड़ की राशि को भुगतान के रूप में शामिल किया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने वार्षिक खातों में इस राशि का हिसाब नहीं रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ वर्तमान परिसंपत्तियों में भी ₹266.90 करोड़ का अतिकथन हुआ।
2.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वर्ष 2019-23 की अवधि के दौरान अनुदान सहायता के तहत खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न परियोजनाओं से ₹1.16 करोड़ का ऋण लिया था। जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इन राशियों को 2023-24 में परियोजनाओं को वापस कर दिया, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1.16 करोड़ के व्यय के रूप में भी दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय का अतिकथन और पूर्व अवधि के व्यय को ₹1.16 करोड़ कम आंका गया।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
3.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	स्थायी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास के कारण व्यय को आय और व्यय खाते में आस्थगित आय के रूप में बुकिंग करके सेट ऑफ किया गया था, जो खातों के समान प्रारूप के खिलाफ था।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बैंकों द्वारा दिए गए ₹0.21 करोड़ और ₹0.78 करोड़ के असमाहित क्रेडिट को अनुसूची

क्रम संख्या	स्वायत्त संस्था का नाम	टिप्पणी
	अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	11 (अन्य विविध प्राप्तियां) में आय के रूप में दर्ज किया गया था। चूंकि इन क्रेडिट की प्रकृति ज्ञात नहीं थी, इसलिए इसे देयता के बजाय आय के रूप में दर्ज करने के परिणामस्वरूप आय का अतिकथन और वर्तमान देयता में ₹0.98 करोड़ (₹0.21 करोड़ + 0.77 करोड़) की कमी हुई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
5.	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	₹6.50 करोड़ की राशि, जो बकाया व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, को 2023-24 के दौरान भुगतान के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया था, हालांकि कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 'बचत खातों पर बैंक बैलेंस' को ₹22.99 करोड़ के बजाय ₹16.49 करोड़ के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों दोनों का कम आंकलन हुआ।
6.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	टी.डी.बी. अधिनियम 1995 की धारा 9 के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि (एफ़.टी.डी.ए.) नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित स्रोत और अनुप्रयोग होंगे। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी से संबंधित अनुमतियाँ प्राप्त करके उपरोक्त निधि का विधिवत गठन नहीं किया गया था और न ही निधि के संचालन के लिए कोई नियम बनाया गया था। इसके अलावा, निधि को कॉर्पस/पूंजी निधि के तहत समाहित करते हुए खातों में अलग आरक्षित निधि के रूप में नहीं दर्शाया गया था और यहां तक कि मूल्यहास आदि से संबंधित काल्पनिक व्यय भी इस निधि में लगाए जा रहे थे, जिससे आवेदन के लिए बोर्ड के पास उपलब्ध वास्तविक राशि का पता लगाने में स्पष्टता की कमी हो रही थी।

1.5.2 लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने और संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी

सदन के पटल पर रखे गए पत्रों की समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) 1975-76 और सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 237 में उल्लेख किया है कि प्रत्येक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को लेखा वर्ष समाप्त होने के तीन महीने के भीतर अपने खातों को पूरा करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए तथा लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित वार्षिक रिपोर्ट को लेखा वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के भीतर संसद के समक्ष रखना चाहिए।

11 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में से तीन केंद्रीय स्वायत्त निकायों ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने

खातों को प्रस्तुत किया, जिसमें 6 दिनों से लेकर 32 दिनों तक की देरी हुई। इसका विवरण नीचे **तालिका 5** में दिया गया है।

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा हेतु खातों को प्रस्तुत करने में देरी

क्रम संख्या	केंद्रीय स्वायत्त संस्था का नाम	मंत्रालय/विभाग	लेखाओं को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की दिनांक	बिलंब दिनों में
1.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	15.7.2024	15 दिन
2.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.	2.8.2024	32 दिन
3.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद	डी.बी.टी.	6.7.2024	6 दिन

इसके अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का विवरण **तालिका 6** में दिया गया है।

तालिका 6: केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति में देरी

क्रम संख्या	स्वायत्त संस्था का नाम	संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि		विलंब	
		लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा
1.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	21.7.2025	31.7.2025	6 महीने और 21 दिन	7 महीने
2.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), नई दिल्ली, (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	4.8.2025	7.8.2025	7 महीने और 4 दिन	7 महीने और 7 दिन
3.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	10.3.2025	20.3.2025	2 महीने और 10 दिन	2 महीने और 20 दिन
4.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	21.7.2025	20.3.2025	6 महीने और 21 दिन	2 महीने और 20 दिन
5.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	11.8.2025	7.8.2025	7 महीने और 11 दिन	7 महीने और 7 दिन

क्रम संख्या	स्वायत्त संस्था का नाम	संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि		विलंब	
		लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा
				दिन	
6.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली (डी.एस.टी.)	12.3.2025	20.3.2025	2 महीने और 12 दिन	2 महीने और 20 दिन
7.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (डी.एस.आई.आर.)	अभी तक (31.10.2025 तक) संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।			

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदान प्राप्तकर्ताओं, अर्थात् सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों आदि से उपयोग के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे और जहां अनुदान सशर्त थे, निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया था। आठ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जारी किए गए अनुदानों के लिए ₹16,761.41 करोड़ की कुल राशि के लिए 41,002 उपयोगिता प्रमाण पत्र (31 मार्च 2024 तक) इन सात मंत्रालयों/विभागों से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	बकाया यू.सी. की संख्या	कुल बकाया यू.सी. का हिस्सा (प्रतिशत)	बकाया यू.सी. से संबंधित राशि (करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि का हिस्सा (प्रतिशत)
1.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)	20500	50.00	9674	57.72
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)	651	1.59	74.93	0.45
3.	अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)	310	0.76	12.13	0.07
4.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)	695	1.70	75.29	0.45
5.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.)	4733	11.54	1223.46	7.30

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	बकाया यू.सी. की संख्या	कुल बकाया यू.सी. का हिस्सा (प्रतिशत)	बकाया यू.सी. से संबंधित राशि (करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि का हिस्सा (प्रतिशत)
6.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)	810	1.98	882.95	5.27
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)	13303	32.43	4818.65	28.74
कुल		41002	100	16761.41	100

तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया यू.सी. की सबसे अधिक संख्या डी.बी.टी. (50.00 प्रतिशत) से संबंधित है, इसके बाद डी.एस.टी. (32.43 प्रतिशत) और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. (11.54 प्रतिशत) हैं। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मंत्रालय/विभाग-वार और अवधि-वार स्थिति **अनुलग्नक 2** में दी गई है।

1.7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के तहत उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर कंपनी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसे पूरक करने का अधिकार प्रदान करती है।

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 26 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। इसने वर्ष 2023-24 के लिए इनमें से 25 उद्यमों से वित्तीय विवरण प्राप्त किए हैं और एक सी.पी.एस.ई., अर्थात् अंडमान द्वीप वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर को एम.सी.ए. 21 डेटाबेस के अनुसार बंद कर दिया गया है, हालांकि संबंधित मंत्रालय से पुष्टि अभी भी लंबित है।

25 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक सी.पी.एस.ई. (हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड)

को लेखापरीक्षा टिप्पणियां और प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे, जबकि आठ सी.पी.एस.ई. के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इसके अलावा, शेष 16 सी.पी.एस.ई. में से 15 सी.पी.एस.ई. को शून्य टिप्पणियां जारी की गईं, जिनमें से 13 सी.पी.एस.ई. को प्रबंधन पत्र जारी किए गए और एक सी.पी.एस.ई. (भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के लिए 12 जनवरी 2026 को खाते प्राप्त हुए और लेखापरीक्षा प्रमाणन प्रक्रियाधीन है। इसका विवरण **अनुलग्नक 3** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में, वित्तीय विवरणों की मंजूरी में कमियां थीं, क्योंकि बोर्ड ने केवल लेखांकन नीतियों और नोट्स के साथ बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते को मंजूरी दी है, जबकि इंड ए. एस. में परिभाषित वित्तीय विवरणों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(40)) के अनुसार इसमें नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण की स्वीकृति भी शामिल है। इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था और 25 प्रतिशत से अधिक के अनुपात में परिवर्तन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हालांकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत आवश्यक था।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पांच टिप्पणियां जारी की गईं, जिनमें ऑडिटिंग 700 पर मानक का अनुपालन न होना, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के तहत रिपोर्टिंग में कमी शामिल थी। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन को 'असंतोषजनक' करार दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि फर्म को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई लेखापरीक्षा आवंटित नहीं की जाएगी।

1.8 2023-24 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए/माफ़ किए गए अप्राप्य देयताएं एवं हानियां

2023-24 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए/माफ़ किए गए अप्राप्य देय राशियों एवं हानियों का विवरण, **अनुलग्नक 4** वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और अंतरिक्ष विभाग में 'अन्य कारणों' की श्रेणी के तहत 13 मामलों में कुल ₹0.11 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी।

1.9 पिछले निरीक्षण रिपोर्टों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों और अगले उच्च अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों का जवाब देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट में सूचित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर समय-समय पर बैठकों में महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग) के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है।

31 मार्च 2024 तक, पिछले वर्षों से संबंधित 7,858 अनुच्छेद वाली 1,291 निरीक्षण रिपोर्ट निपटान के लिए लंबित थीं और इनमें से, **तालिका 8** में दिए गए विवरण के अनुसार 445 अनुच्छेद वाली 42 निरीक्षण रिपोर्टों के संबंध में पहली प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी:

तालिका 8: निपटान के लिए लंबित अनुच्छेद वाली निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण

वर्ष	31 मार्च 2024 तक निपटान के लिए लंबित आई.आर./अनुच्छेद की संख्या		आई.आर./अनुच्छेद जहां 31 मार्च 2024 तक पहले जवाब भी प्राप्त नहीं हुए हैं	
	आई.आर.	अनुच्छेद	आई.आर.	अनुच्छेद
2018-19 तक	781	3293	14	79
2019-20	71	533	2	32
2020-21	85	554	2	16
2021-22	121	990	4	36
2022-23	127	1261	9	129
2023-24	106	1227	11	153

वर्ष	31 मार्च 2024 तक निपटान के लिए लंबित आई.आर./अनुच्छेद की संख्या		आई.आर./अनुच्छेद जहां 31 मार्च 2024 तक पहले जवाब भी प्राप्त नहीं हुए हैं	
	आई.आर.	अनुच्छेद	आई.आर.	अनुच्छेद
कुल	1291	7858	42	445

इसके अलावा, बकाया निरीक्षण रिपोर्ट और अनुच्छेद का विभाग-वार विवरण *अनुलग्नक 5* में दिया गया है।

1.10 मसौदा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रियाएं

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा अनुच्छेद के मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के निर्देश जारी किए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के पैरा 142 के तहत लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकारी प्रतिक्रिया से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित किया गया है।

मसौदा अनुच्छेद संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित करने के लिए भेजा जाता है, और उनसे चार सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद अगस्त 2025 और अक्टूबर 2025 के बीच व्यक्तिगत रूप संबंधित सचिवों को उन्हें संबोधित पत्रों के माध्यम से भेजे गए थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा सब्सिडी वाली कैंटीन सुविधा के बदले अपने कर्मचारियों को किए गए ₹2.06 करोड़ के अनियमित भुगतान पर प्रकाश डालने वाले ऐसे ही एक मसौदा अनुच्छेद के जवाब में, सी.पी.सी.बी. ने कैंटीन सब्सिडी को बंद करने की सिफारिश की है।

इस रिपोर्ट में चार अनुच्छेद, दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो आई.टी. लेखापरीक्षा

शामिल हैं। मंत्रालयों/विभागों ने सभी अनुच्छेद/एस.एस.सी.ए./आई.टी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, जिसे रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

क. सिविल इकाइयों के लिए

अपनी नौवीं रिपोर्ट (ग्यारहवीं लोकसभा) में, जो 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत की गई थी, लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि वर्ष 31 मार्च 1996 के बाद समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई की गई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) उन्हें संसद में रिपोर्ट पेश करने की तारीख से चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी.ए.जी. की रिपोर्ट में शामिल अनुच्छेद पर 31 जनवरी 2026 तक लंबित ए.टी.एन. की समीक्षा (*अनुलग्नक 6*) से पता चला कि दो मंत्रालयों/विभागों (डी.बी.टी. और एम.ओ.ई.एस.) से लंबित दो ए.टी.एन. संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से 5 महीने और 20 दिनों से लेकर 64 महीने और 9 दिनों तक की देरी के बाद भी पहली बार प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा, संशोधित ए.टी.एन. जिन्हें लेखापरीक्षा टिप्पणियों/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर मंत्रालय द्वारा अपलोड किया जाना है, चार मंत्रालयों/विभागों (एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., डी.एस.आई.आर., डी.बी.टी. और डी.ए.ई.) से छह मामलों में लंबित थे, जिनमें 31 जनवरी 2026 (*अनुलग्नक 7*) तक 2 महीने और 20 दिन से लेकर 26 महीने और 15 दिन तक की देरी थी।

ख. वाणिज्यिक इकाइयों के लिए

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया (जुलाई 1985) कि वे विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए नोट्स (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच) प्रस्तुत करें जो सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा

रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में शामिल हैं, जैसा कि संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति द्वारा विस्तृत जांच के लिए चयनित नहीं किए गए अनुच्छेद/मूल्यांकन के संबंध में भी ऐसे नोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को संसद में प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करना चाहिए। समिति को प्रस्तुत करने से पहले नोट की लेखापरीक्षा द्वारा जांच करवाई जा सकती है।

इन मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सी.पी.एस.यू. से संबंधित सी.ए.जी. रिपोर्टों में शामिल अनुच्छेद पर 31 जनवरी 2026 तक बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा (**अनुलग्नक 6**) से पता चला कि परमाणु ऊर्जा विभाग से दो ए.टी.एन. पहली बार प्राप्त नहीं हुए थे, जिसमें 23 महीने 23 दिन से लेकर 58 महीने 8 दिन तक की देरी हुई थी।

अध्याय II

परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 परमाणु ऊर्जा विभाग में भूमि और संपदा प्रबंधन पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

‘भूमि प्रबंधन’ शब्द के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का रखरखाव, भूमि उपयोग का नियंत्रण, अतिक्रमणों का पता लगाना, रोकथाम और उन्हें हटाना, भूमि सीमाओं का रखरखाव, अन्य संगठनों और पक्षों को लाइसेंस या पट्टे पर देकर वाणिज्यिक और अन्य उपयोगों के लिए भूमि का उपयोग करना शामिल है, जिसमें वनीकरण आदि भी शामिल है। वहीं, संपदा प्रबंधन शब्द के अंतर्गत भौतिक अवसंरचना, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर और साज-सामान की सुरक्षा, उपयोग, संवर्धन और रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं।

मुंबई और कल्पाक्कम/अनुपुरम में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के इकाइयों की भूमि और संपदा प्रबंधन, डी.ए.ई. की दो सेवा इकाइयों अर्थात् (i) निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डी.सी.एस.ई.एम. निदेशालय), मुंबई, एवं (ii) सामान्य सेवा संगठन (जी.एस.ओ.), कल्पाक्कम के अंतर्गत है। मुंबई और कल्पाक्कम/अनुपुरम के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित डी.ए.ई. इकाइयों की भूमि और संपदा की देखभाल, संबंधित इकाइयों द्वारा स्वयं की जाती है।

2.1.1.1 लेखापरीक्षा का दायरा

‘डी.ए.ई. में भूमि एवं संपदा प्रबंधन’ पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.)

आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य डी.ए.ई. और इसकी घटक इकाइयों द्वारा भूमि एवं संपदा परिसंपत्तियों के प्रबंधन और अनुपालन में अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच करना था। लेखापरीक्षा में डी.ए.ई. की 30 इकाइयों में से 11 इकाइयों⁵ के 2019-20 से 2023-24 की अवधि के अभिलेखों के साथ-साथ डी.ए.ई. मुख्यालय के अभिलेखों की भी जांच की गई। इसके अतिरिक्त, डी.ए.ई. की अन्य इकाइयों, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), विशाखापत्तनम और परमाणु पुनर्चक्रण बोर्ड (एन.आर.बी.), तारापुर की अनुपालन लेखापरीक्षाओं से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

2.1.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित का आकलन करना था:

1. क्या डी.ए.ई. के पास प्रभावी भूमि और संपदा प्रबंधन नीति मौजूद है?
2. क्या परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के स्वामित्व वाली भूमि भारत सरकार/परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई थी और भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं?
3. क्या कर्मचारियों को आवंटित और बैंकों, डाकघरों, दुकानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी पक्षों को पट्टे पर दी गई भूमि और भवन के संबंध में मौजूदा नियमों के अनुसार लाइसेंस शुल्क वसूला जा रहा था? और क्या इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही थी?
4. क्या भवनों के रखरखाव और देखभाल के लिए कोई व्यवस्था मौजूद थी?

⁵ (i) निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय (डी.सी.एस.ई.एम.), मुंबई; (ii) सामान्य सेवा संगठन (जी.एस.ओ.), कल्पाक्कम; (iii) नाभिकीय ईंधन सस्मिथ (एन.एफ.सी.), हैदराबाद; (iv) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आर.आर.सी.ए.टी.), इंदौर (v) भारी पानी बोर्ड (एच.डब्ल्यू.बी.), मुंबई (जिसमें बड़ौदा, थल और मुनगुरु में स्थित तीन संयंत्र शामिल हैं); (vi) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टी.आई.एफ.आर.), मुंबई (जिसमें राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र (एन.सी.बी.एस.), बेंगलूर; (राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र (एन.सी.आर.ए.), पुणे; टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद शामिल हैं); (vii) भौतिकी संस्थान (आई.ओ.पी.), भुवनेश्वर; (viii) राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.एस.ई.आर.), भुवनेश्वर; (ix) सहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीअर फिज़िक्स कोलकाता; (x) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान (एच.आर.आई.), प्रयागराज; (xi) टाटा स्मारक केंद्र (टी.एम.सी.), मुंबई (जिसमें इसका उप-केंद्र कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र (ए.सी.टी.आर.ई.सी.), नवी मुंबई शामिल है)।

2.1.1.3 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए थे:

1. पंजीकरण अधिनियम, 1908 और उसके संशोधन,
2. भूमि एवं संपदा प्रबंधन से संबंधित वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन/दिशानिर्देश,
3. सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधान,
4. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन,
5. भारत सरकार/डी.ए.ई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेश/दिशानिर्देश,
6. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882,
7. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग रखरखाव नियमावली, 2019

आगामी अनुच्छेदों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है:

2.1.2 भूमि एवं संपदा प्रबंधन नीति

2.1.2.1 नीति/नियम/दिशानिर्देशों का निर्माण न होना

क. भूमि हस्तांतरण एवं पट्टा नीति

वित्त मंत्रालय ने मार्च 2011 में सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि जब तक एक व्यापक नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक सरकार या सरकार के नियंत्रण वाले वैधानिक प्राधिकरणों से संबंधित भूमि की बिक्री या दीर्घकालिक पट्टे के प्रत्येक मामले में विशिष्ट रूप से कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके बाद, नवंबर 2011 में कैबिनेट सचिवालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) सहित सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया कि भूमि हस्तांतरण पर नीतिगत प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएं ताकि अलग-अलग मामलों में स्वीकृति देने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसंबर 2025 तक, डी.ए.ई. में भूमि हस्तांतरण या पट्टे को

नियंत्रित करने वाली कोई समान नीति मौजूद नहीं थी। भूमि हस्तांतरण और पट्टे का कार्य व्यक्तिगत इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जा रहा था। निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डी.सी.एस.ई.एम.) ने डी.ए.ई. के स्वामित्व वाली भूमि को सार्वजनिक/निजी प्राधिकरणों, पी.एस.यू. और राज्य-केंद्रीय सरकारों के स्वायत्त निकायों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक पट्टे पर देने के लिए एक नीति बनाने का प्रस्ताव जनवरी 2025 में भेजा था। दिसंबर 2025 तक यह प्रस्ताव डी.ए.ई. के पास लंबित था।

इस प्रकार, नवंबर 2011 में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, डी.ए.ई. ने 14 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक समान भूमि हस्तांतरण नीति तैयार नहीं की थी। ऐसी नीति के अभाव के कारण विभिन्न इकाइयों में असमान प्रक्रियाएं अपनाई गईं और परिणामस्वरूप भूमि प्रबंधन में कमियां पाई गईं, जिसे आगामी लेखापरीक्षा पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में संयंत्रों की प्रारंभिक स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान, एक समान दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा सका, साथ ही अन्य मंत्रालयों की नीतियों की जांच करने के प्रयास किए गए, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं पाई गई।

इस जवाब में कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के बावजूद लंबे समय तक नीति तैयार न होने के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि अन्य मंत्रालयों, जैसे कि जहाजरानी मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने क्रमशः 2014 और 2022 में भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश तैयार कर लिए थे। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करने में डी.ए.ई. द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्पष्टता और व्यवहार में एकरूपता के

लिए, भूमि प्रबंधन पर एक समान नीति विकसित करना और भी आवश्यक था।

अनुशंसा 1:

डी.ए.ई. कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एक व्यापक भूमि हस्तांतरण और पट्टे की नीति तैयार और अधिसूचित कर सकता है।

ख. आवासीय व्यवस्था नियम

केंद्रीय सरकार सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (सी.जी.पी.आर.ए.) नियम पहली बार मई 1963 में अधिसूचित किए गए थे और अप्रैल 1982 से मार्च 2017 के बीच 35 बार संशोधित किए गए थे। व्यवसाय आवंटन नियमों के अनुसार, डी.ए.ई. को संपत्तियों से संबंधित मामलों में शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करने से छूट दी गई थी। इसलिए, संपत्ति संबंधी मामलों के लिए डी.ए.ई.-विशिष्ट एक समान ढांचा आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. की 11 नमूना इकाइयों में से, डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई और सामान्य सेवा संगठन (जी.एस.ओ.), कल्पाक्कम ने क्रमशः 1982 और 1980 में आवासीय व्यवस्था नियम बनाए थे। अन्य डी.ए.ई. इकाइयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में विभागीय पूल आवासीय व्यवस्था के आवंटन के लिए इन्हीं नियमों का पालन किया। परिणामस्वरूप, डी.ए.ई. के अंदर आवासीय व्यवस्था का आवंटन दो अलग-अलग नियमों द्वारा नियंत्रित होता था।

कई नियमों के अस्तित्व और लंबे परिचालन अनुभव के बावजूद, डी.ए.ई. ने 1954 में अपनी स्थापना के 71 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, अपने सभी घटक इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होने वाले एक समान विभागीय पूल आवासीय व्यवस्था नियम नहीं बनाए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि क्षतिपूर्ति दरों, विशेष लाइसेंस शुल्क, अंतिम तैनाती

स्थान पर पुनः स्थानांतरण पर आवंटन का नियमितीकरण और एसोसिएशनों जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के विभिन्न आदेशों में उल्लेखित है, से लाइसेंस शुल्क की वसूली से संबंधित प्रमुख प्रावधान, दोनों नियमों में से किसी में भी शामिल नहीं किए गए थे। ये त्रुटियाँ, सी.जी.जी.पी.आर.ए. नियमों में बाद में हुए संशोधनों के अनुरूप, नियमों को अद्यतन न करने के कारण उत्पन्न हुईं।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उसे व्यवसाय आवंटन नियम, 1961 के तहत संपत्तियों से संबंधित मामलों में शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श करने से छूट प्राप्त है। डी.ए.ई. ने आगे कहा कि डी.सी.एस.ई.एम., जी.एस.ओ. और एच.डब्ल्यू.बी. के संशोधित आवंटन नियम, 2025 में प्राप्त हुए थे और डी.ए.ई. आवंटन नियमों के रूपरेखा की जांच के लिए एक समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने सी.जी.जी.पी.आर.ए. नियमों से डी.ए.ई. की छूट को स्वीकार किया, लेकिन यह भी पाया कि डी.ए.ई. ने पिछले कुछ वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय (संपत्ति निदेशालय) द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली, अनधिकृत कब्जे के लिए क्षतिपूर्ति दर और आवासीय क्वार्टरों के वर्गीकरण से संबंधित विभिन्न आदेशों को समय-समय पर अपनाया था। डी.ए.ई.-विशिष्ट एक समान ढांचे के अभाव में, गैर-संशोधित नियमों पर निरंतर निर्भरता के परिणामस्वरूप संपत्ति संबंधी मामलों को लागू करने में कमियाँ और विवेकाधिकार की गुंजाइश बनी रही, जैसा कि इस रिपोर्ट के बाद के अनुभागों में बताया गया है।

अनुशंसा 2:

डी.ए.ई. अपनी सभी घटक इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर लागू समान विभागीय पूल आवासीय आवास नियम तैयार और कार्यान्वित कर सकता है।

2.1.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को भूमि हस्तांतरण/आवंटन में असमानता

व्यवसाय संचालन नियम, 1961 में यह प्रावधान है कि वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना कोई भी विभाग ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें भूमि का अनुदान, राजस्व का आवंटन, रियायत, कोई भी सुगमता या ऐसी रियायत से संबंधित कोई विशेषाधिकार शामिल हो। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 279(4) के अनुसार, जिसे सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 310(4) के तहत दोहराया गया है, पी.एस.यू. से भूमि का आवंटन और भवनों की लागत की वसूली बाजार दर पर किया जाना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. और उसकी इकाइयों ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.), इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.), इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) को अलग-अलग समय पर और अलग-अलग शर्तों के तहत भूमि आवंटित की, जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

क. डी.ए.ई. ने ई.सी.आई.एल. को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए और एन.पी.सी.आई.एल. को अनुशक्तिनगर में कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए क्रमशः वर्ष 2002 और 2006 में मुंबई में निःशुल्क भूमि आवंटित की। जबकि, डी.ए.ई. ने जनवरी 2020 में आई.आर.ई.एल. को चेंबूर (मुंबई में भी) में कार्यालय निर्माण के लिए ₹8.15 करोड़ के लीज प्रीमियम पर भूमि आवंटित की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि डी.ए.ई. ने ई.सी.आई.एल. और आई.आर.ई.एल. के मामलों में क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और वित्त मंत्रालय से भूमि आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था, लेकिन एन.पी.सी.आई.एल. को निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए ऐसा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था और जी.एफ.आर. के तहत उसे बाजार दरों पर भूमि की लागत का भुगतान करना

था।

एन.पी.सी.आई.एल. को हस्तांतरित भूमि के मामले में, डी.ए.ई./एन.पी.सी.आई.एल. ने (दिसंबर 2025) कहा कि परमाणु ऊर्जा बोर्ड (एन.पी.बी.) के एन.पी.सी.आई.एल. में पुनर्गठन के बाद, भूमि आवंटन डी.ए.ई. के अंदर चल रही प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्थाओं का हिस्सा था और इसके लिए वित्त मंत्रालय या भारत के राष्ट्रपति से अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

डी.ए.ई. के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एन.पी.सी.आई.एल. को भूमि का आवंटन 2006 में उसके 1987 में निगमन के बहुत बाद किया गया था और कार्यालय परिसर हेतु भूमि आवंटन के समय वह एक लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। इसलिए, मुफ्त में आवंटित भूमि को नियमित करने के लिए या तो वित्त मंत्रालय/भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी या भूमि की लागत एन.पी.सी.आई.एल. से बाजार दरों पर वसूल की जानी चाहिए थी।

ख. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र⁶, कल्पाक्कम ने 2004 में आई.जी.सी.ए.आर., कल्पाक्कम और भाविनी के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से भाविनी⁷ को डी.ए.ई. की भूमि निःशुल्क और स्वतंत्र स्वामित्व के आधार पर आवंटित की थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.जी.सी.ए.आर., कल्पाक्कम ने वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए थे और वह बाजार दर पर भूमि की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उसने (जून 2025 में) भाविनी को डी.ए.ई. के संबंधित अधिकारियों के साथ भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया था।

⁶ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पाक्कम, डी.ए.ई. की एक अनुसंधान एवं विकास इकाई है।

⁷ अक्टूबर 2003 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया।

अनुशंसा 3:

डी.ए.ई., एन.पी.सी.आई.एल. और भाविनी को आवंटित भूमि के नियमितीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है और अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के संबंध में एकरूपता सुनिश्चित कर सकता है।

2.1.2.3 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निजी पक्षों को भूमि/स्थान का आवंटन

जी.एफ.आर. के नियम 28 (ii) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए सामान्य प्रत्यायोजन या उनकी स्वीकृति के अलावा, कोई भी अधीनस्थ प्राधिकारी वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें किसी भी प्रकार से राजस्व का त्याग शामिल हो।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. की इकाइयों ने सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निजी पक्षों को भूमि/स्थान आवंटित किया था। मामलों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

क. लेखापरीक्षा में पाया गया कि (फरवरी 2024) आई.जी.सी.ए.आर. परिसर के भीतर सात निजी चाय-पैन्ट्री, कैंटीन और छोटी दुकानें आई.जी.सी.ए.आर. द्वारा उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे और बिजली के उपकरणों⁸ का उपयोग करके निःशुल्क संचालित हो रही थीं। इन सुविधाओं के लिए स्थान आवंटित करने हेतु कोई पट्टा समझौता नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि इन आवंटनों के लिए न तो डी.ए.ई. से कोई अनुमोदन लिया गया था और न ही उपयोग करने वालों से लाइसेंस शुल्क या संबंधित शुल्क (जैसे बिजली, पानी) वसूल किए गए थे।

⁸ विद्युत, गैस, प्रेरण और माइक्रोवेव।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2025 (लेखापरीक्षा के बाद) में आई.जी.सी.ए.आर. ने इन प्रतिष्ठानों के संचालन को नियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार किया और इसके लिए डी.ए.ई. से अनुमोदन मांगा। इसके जवाब में, डी.ए.ई. ने (अक्टूबर 2025) में आई.जी.सी.ए.आर. को निर्देश दिया कि चाय की दुकानों और कैंटीनों का संचालन विभागीय रूप से या सरकार द्वारा अनुमोदित बोली प्रक्रिया जैसे जी.ई.एम./सी.पी.पी.पी. के माध्यम से ठेका देकर किया जाए।

इस प्रकार, आई.जी.सी.ए.आर. में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन निजी चाय की दुकानों, कैंटीनों और छोटी दुकानों का संचालन जारी रहा (दिसंबर 2025)।

- ख. डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई ने (1985-88) अणुशक्ति नगर निवास उपभोक्ता सहकारी समितिको ₹1 प्रति दुकान प्रति माह के नाममात्र लाइसेंस शुल्क पर सात दुकानें आवंटित की थीं। डी.ए.ई. से प्राप्त निर्देश (नवंबर 2015) के अनुसार, डी.सी.एस.ई.एम. ने समितियों/एसोसिएशनों के लाइसेंस शुल्क की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन (मार्च 2016) किया और लाइसेंस शुल्क को ₹1 से बढ़ाकर ₹25,760 प्रति माह करने की सिफारिश की, जिसे डी.ए.ई. ने अप्रैल 2017 में अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.सी.एस.ई.एम. ने संशोधित दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया। इसके बाद, जुलाई 2025 (लेखापरीक्षा के बाद) में डी.ए.ई. ने डी.सी.एस.ई.एम. को अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक ₹1 की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल करने का निर्देश दिया और जनवरी 2026 से दुकानों को बंद करने और उन्हें लाभप्रद तरीके से उपयोग करने के अन्य तरीकों की खोज के लिए अपने कब्जे में लेने की सिफारिश की। यह निर्णय भी डी.ए.ई. द्वारा सदस्य (वित्त) की सहमति के बिना लिया गया था।

- ग. लेखापरीक्षा में पाया गया कि आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर (जुलाई 2001 से) और जी.एस.ओ., कल्पाक्कम (1979 से) ने वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की स्वीकृति प्राप्त किए बिना, सेंटर फॉर

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को-ऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी और एटॉमिक एनर्जी एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट स्टोर्स को क्रमशः ₹1 प्रति माह के लाइसेंस शुल्क पर दुकानें/भवन/परिसर आदि आवंटित किए।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) बताया कि आर.आर.सी.ए.टी. के शुरुआती वर्षों में संबंधित दुकानें सोसायटी को मात्र ₹1 की मामूली दर पर आवंटित की गई थीं।

लेखापरीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी नीति के अभाव में, रियायतें देने का निर्णय डी.ए.ई. के विवेक पर छोड़ दिया गया, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि डी.ए.ई. ने सदस्य वित्त की स्वीकृति के बिना निजी पक्षों को भूमि/स्थान आवंटित करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का पालन किया है। डी.ए.ई. ने लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का भी कोई प्रयास नहीं किया था और निजी पक्षों को रियायती दरों पर अपनी भूमि/स्थान आवंटित करना जारी रखा।

अनुशंसा 4:

विधिवत अनुमोदित नीति के अभाव में, डी.ए.ई. को किसी भी निजी पक्ष को भूमि/स्थान आवंटित करने से पहले सदस्य (वित्त) की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

2.1.2.4 समान दिशा-निर्देशों/नियमों के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी पक्षों को आवासीय व्यवस्था आवंटित करने के कारण राजस्व हानि

मानक प्रक्रिया के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को सरकारी आवासीय व्यवस्था का आवंटन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों/नियमों पर आधारित होना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश/नियम नहीं बनाए और न ही उनका पालन किया है।

दिसंबर 2025 तक भूमि और संपदा प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली डी.ए.ई.-विशिष्ट नीतियों और नियमों के अभाव में, लेखापरीक्षा ने अनुपालन का आकलन करने और आगे के अनुच्छेदों

में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकालने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के नीतिगत ढांचे और दिशा-निर्देशों को मानक के रूप में अपनाया है और पाया है कि डी.ए.ई. को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी पक्षों को अपने आवासीय आवासों के आवंटन पर राजस्व हानि हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क. रियायती दरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के कारण राजस्व हानि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी समान दिशा-निर्देश या नियमों के अभाव में, डी.ए.ई. ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्वार्टरों के आवंटन के लिए रूप-नहीं बनाए। कुछ मामलों में डी.ए.ई. ने संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के साथ क्वार्टर आवंटन हेतु समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किए, जबकि अन्य मामलों में ये आवंटन बिना किसी औपचारिक नियम एवं शर्तों के किए गए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जिन मामलों में डी.ए.ई. ने समझौता ज्ञापन किए थे, उनमें भी शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि डी.ए.ई. ने एन.पी.सी.आई.एल., ई.सी.आई.एल. और एम.ए.पी.एस. को बिना किसी सुसंगत नियम एवं शर्तों के आवासीय आवास⁹ आवंटित किए।

i. एन.पी.सी.आई.एल. के मामले में, मुंबई में डी.ए.ई. के अंतर्गत आवासीय पूल आवास साझा करने के लिए डी.सी.एस.ई.एम. और एन.पी.सी.आई.एल. के बीच एक समझौता ज्ञापन (दिसंबर 1997) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा वित्तपोषित संसाधनों से विभिन्न प्रकार के 432 फ्लैट/क्वार्टर¹⁰

⁹ तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एन.पी.सी.आई.एल., ई.सी.आई.एल. और एम.ए.पी.एस.) लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

¹⁰ टाइप Vई-100 इकाई, टाइप IIIसी-100 इकाई, टाइप IIबी-100 इकाई और एकशिफ्टी प्लस अपार्टमेंट-132 इकाई।

बनाए जाने थे, जिसके लिए एन.पी.सी.आई.एल ने ₹39.86 करोड़ का योगदान दिया था। समझौता ज़ापन में यह भी निर्धारित किया गया था कि फ्लैटों के आगे निर्माण के लिए एन.पी.सी.आई.एल. का भविष्य का योगदान लगभग एन.पी.सी.आई.एल. के कर्मचारियों की सापेक्ष संख्या के अनुपात में होगा।

- ii. ई.सी.आई.एल. के मामले में, अतिरिक्त आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के नियमों और शर्तों के संबंध में ई.सी.आई.एल. और एन.एफ.सी. के बीच कोई औपचारिक समझौता/समझौता ज़ापन नहीं किया गया था। हालाँकि, ई.सी.आई.एल. ने अपने कर्मचारियों के लिए 60 टाइप II क्वार्टरों के निर्माण लागत के लिए एन.एफ.सी. को ₹0.82 करोड़ का योगदान (1992) दिया था।
- iii. तीसरे मामले में, जी.एस.ओ., कल्पाक्कम ने 1987 में एन.पी.सी.आई.एल. के अंतर्गत शामिल होने के बाद से एम.ए.पी.एस. में कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए या निर्माण लागत में कोई योगदान प्राप्त किए बिना आवासीय क्वार्टर आवंटित किए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि डी.ए.ई. ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जितने क्वार्टरों के लिए योगदान किए गए थे उससे अधिक एन.पी.सी.आई.एल. और ई.सी.आई.एल. को सरकारी आवासीय व्यवस्था आवंटित किए। इसके अतिरिक्त, एम.ए.पी.एस. के मामले में, निर्माण लागत में किसी भी प्रकार का योगदान प्राप्त किए बिना, क्वार्टर निःशुल्क आवंटित किए गए थे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है:

तालिका 9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटित क्वार्टरों की संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए लागत का योगदान/वसूली प्राप्त हुई है	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए लागत का कोई योगदान/वसूली प्राप्त नहीं हुई है
एन.पी.सी.आई.एल.	432	445 से 747

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए लागत का योगदान/वसूली प्राप्त हुई है	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए लागत का कोई योगदान/वसूली प्राप्त नहीं हुई है
ई.सी.आई.एल.	60	104 से 458
एम.ए.पी.एस.	-	587 से 676

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.जी.जी.पी.आर.ए. नियमों के नियम 88 में यह प्रावधान है कि भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मकान किराया भत्ता और लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि, उन सभी आवासों के लिए, जो उधार लेने वाले मंत्रालय या विभागों की अभिरक्षा में रहते हैं, संपदा निदेशालय को भुगतान करने का वचन देगा। परिणामस्वरूप, और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी नीति/दिशानिर्देश के अभाव में, डी.ए.ई., जो कि ऋण देने वाला विभाग है, को उधार लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए एच.आर.ए. घटक की वसूली करनी चाहिए, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इन क्वार्टरों को उपलब्ध कराकर अपने कर्मचारियों को एच.आर.ए. के भुगतान पर बचा रहे हैं।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ए.ई. ने उन अतिरिक्त/आवासीय व्यवस्थाओं जिसके लिए कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ था, के आवंटन के लिए संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एच.आर.ए. घटक की वसूली नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹80.19 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ, जैसा कि **तालिका 10** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 10: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एच.आर.ए. की वसूली न होने के कारण राजस्व हानि

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए अंशदान प्राप्त नहीं हुआ	राजस्व हानि ¹¹ (₹ करोड़ में)
एन.पी.सी.आई.एल.	445 से 747	55.86
ई.सी.आई.एल.	104 से 458	13.42

¹¹ वास्तविक राशि कहीं अधिक होती, यह गणना अप्रैल 2019 से मार्च 2024 की अवधि के लिए सरकारी आवास के पात्र वर्ग के संबंधित वेतन मैट्रिक्स में न्यूनतम वेतन को ध्यान में रखते हुए की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	आवंटित इकाइयों की संख्या जिनके लिए अंशदान प्राप्त नहीं हुआ	राजस्व हानि ¹¹ (₹ करोड़ में)
एम.ए.पी.एस.	587 से 676	10.91

एन.पी.सी.आई.एल. और ई.सी.आई.एल. को अतिरिक्त क्वार्टर के आवंटन के संबंध में, डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) कहा कि ऐसा कोई नियम/प्रक्रिया नहीं है जिसमें यह निर्धारित हो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रेषित एच.आर.ए. सरकारी खातों में जमा की जानी चाहिए थी। एम.ए.पी.एस. के मामले में, डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उसे आवास आवंटन संबंधी नियम बनाने का अधिकार है। आवास को डी.ए.ई. के कर्मचारियों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं, के लिए सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जी.पी.आर.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सामान्य पूल से आवास का आवंटन लाइसेंस शुल्क की एक समान दर पर आधारित था। उपरोक्त के आलोक में, एच.आर.ए. घटक की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

विभाग के उत्तर पर इस तथ्य के साथ विचार करने की आवश्यकता है कि आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए डी.ए.ई. द्वारा अपनाए जा रहे दो सेट के नियमों में पी.एस.यू. से एच.आर.ए. की वसूली के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, सी.जी.जी.पी.आर.ए. के नियम 88, जिसमें संबंधित मंत्रालय या उधार लेने वाले मंत्रालय या विभागों के निपटान में रखे गए आवासों के लिए भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग को एच.आर.ए. के बराबर राशि के भुगतान का प्रावधान है, लागू किया जाना था। हालांकि, इस मामले में, यह देखा गया कि डी.ए.ई. ने इन आवासों के निर्माण पर खर्च की गई सरकारी धनराशि की वसूली नहीं की और न ही संबंधित पी.एस.यू. से सरकारी आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के एवज में एच.आर.ए. घटक की वसूली की। इस प्रकार, डी.ए.ई. सरकार के वित्तीय हित की रक्षा नहीं कर सका।

इसी तरह के एक मामले में, जिसमें आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर ने ई.सी.आई.एल. कर्मचारी

को आवासीय क्वार्टर आवंटित किया था, डी.ए.ई. ने दिसंबर 2025 में ई.सी.आई.एल. से एच.आर.ए. घटक की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की थी।

अनुशंसा 5:

डी.ए.ई. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार कर सकता है ताकि वह या तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एच.आर.ए. घटक की वसूली कर सके या वह संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त क्वार्टरों की निर्माण लागत के लिए दावा करने के लिए योगदान की राशि का आकलन कर सके।

ख. सरकारी आवासीय क्वार्टरों को निजी पक्षों को रियायती दरों पर आवंटित करने से राजस्व की हानि

कार्य संचालन नियम, 1961 में यह प्रावधान है कि कोई भी विभाग वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें भूमि का अनुदान, राजस्व का आवंटन, रियायत, कोई सुविधा या ऐसी रियायत से संबंधित कोई विशेषाधिकार शामिल हो।

इसके अतिरिक्त, लोक लेखा समिति (तीसरी लोकसभा) ने अपनी 34वीं रिपोर्ट के अनुच्छेद 43 में यह अनुशंसा की थी कि निजी पक्षों को सरकारी आवास देने की प्रथा को बंद कर दिया जाए। हालाँकि, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि विशेष परिस्थितियों में, अस्थायी उपाय के रूप में, पूर्ण बाजार दर पर आवास दिया जा सकता है। उक्त अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

रिकॉर्डों की जांच से पता चला कि सरकारी आवास विभाग (डी.ए.ई.) ने सरकारी आवासीय क्वार्टरों को बाजार दर/क्षति दर के बजाय रियायती दरों पर निजी पक्षों को आवंटित किया, जिससे विभाग को राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में रियायती दरों

पर सरकारी आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

तालिका 11: सरकारी आवासीय क्वार्टरों को निजी पक्षों को रियायती दरों पर आवंटित करने के कारण

राजस्व की हानि

एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु द्वारा क्षति/बाजार दर पर लाइसेंस शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹5.33 करोड़ का राजस्व नुकसान

एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु ने 2019-20 से अक्टूबर 2025 तक एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु कॉलोनी में 11 ठेकेदारों को आवासीय क्वार्टर आवंटित किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाइसेंस शुल्क की वसूली पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसित बाजार दर के अनुरूप नहीं थी। एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु ने बाजार दरयानी सामान्य लाइसेंस शुल्क से 40 गुना से वसूली करने के बजाय सामान्य लाइसेंस शुल्क से नौ गुना दर से वसूली। इसके परिणामस्वरूप ₹5.33 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) बताया कि लाइसेंस शुल्क विशेष दर पर वसूला गया था। इसमें यह भी कहा गया कि विशेष लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन किया जाएगा।

जी.एस.ओ., कल्पाक्कम द्वारा निजी पक्षों को रियायती दर पर आवासीय क्वार्टर आवंटित करने के कारण ₹2.55 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

जी.एस.ओ., कल्पाक्कम ने वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की मंजूरी के बिना मार्च 2024 तक 77 आवासीय क्वार्टर,¹² निजी व्यक्तियों को¹³ आवंटित किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षतिपूर्ति¹⁴ दर (सामान्य लाइसेंस शुल्क का 40 गुना) वसूलने के बजाय, जी.एस.ओ. ने 75¹⁵ आवासीय¹⁶ क्वार्टरों के लिए रियायती लाइसेंस शुल्क वसूला।

जी.एस.ओ., कल्पाक्कम ने अपने जवाब (अक्टूबर 2024) में कहा कि डी.ए.ई. से बाद में मंजूरी प्राप्त कर ली जाएगी। डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) कहा कि ये सभी एजेंसियां परियोजनाओं के चालू होने के बाद से कल्पाक्कम में बुनियादी जरूरतों जैसे कि किराना और राशन, खाना पकाने का ईंधन, सब्जियां और सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं - ये सेवाएं एक स्वस्थ समुदाय को बढ़ावा देने और मानव संसाधन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

अतः सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) या निजी संस्थाओं को आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए किसी भी ढांचे (फ्रेमवर्क) या दिशा-निर्देशों के तैयार न होने के कारण, या तो लाइसेंसशुल्क तथा एच.आर.ए. घटक की वसूली या क्वार्टरों की निर्माण लागत में योगदान की वसूली के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतरता का अभाव है। डी.ए.ई. को

¹² टाइप I क्वार्टर-70, टाइप II क्वार्टर-2 और टाइप III क्वार्टर-5।

¹³ परमाणु ऊर्जा सहकारी भंडार, एन.ई.एस.सी.ओ., होम्योपैथी, महतवा, किंडरगार्टन स्कूल आदि।

¹⁴ संपदा निदेशालय का दिनांक 7 सितंबर 2016 का कार्यालय ज्ञापन।

¹⁵ टाइप I क्वार्टर-68, टाइप II क्वार्टर-2 और टाइप III क्वार्टर-5।

¹⁶ जी.एस.ओ., कल्पाक्कम द्वारा आवंटित 77 आवासीय क्वार्टरों में से केवल दो आवासीय क्वार्टरों के लिए बाजार दर (यानी सामान्य लाइसेंस शुल्क का 40 गुना) ली गई थी।

अपने परिसर से संचालित होने वाले सार्वजनिक उपक्रमों और निजी एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, वे एक समान नीतिगत ढांचा होने के महत्व को और अधिक बढ़ा देती हैं, ताकि सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं के साथ लेनदेन करते समय डी.ए.ई. की विभिन्न इकाइयों के पास पूर्ण स्पष्टता हो।

अनुशंसा 6:

डी.ए.ई., निजी पक्षों को आवासीय क्वार्टरों के आवंटन हेतु पी.ए.सी. की सिफारिश का पालन कर सकता है और निर्धारित बाजार दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूल कर सकता है।

2.1.2.5. सरकारी आवासीय व्यवस्था के लिए वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की स्वीकृति के बिना प्रतिधारण अवधि बढ़ाने के कारण लाइसेंस शुल्क की हानि

जी.एफ.आर., 2005 और 2017 के नियम 28 (ii) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा या उनकी स्वीकृति से किए गए सामान्य प्रत्यायोजन के अलावा, कोई भी अधीनस्थ प्राधिकरण वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिससे किसी भी प्रकार से राजस्व का त्याग हो।

संपदा निदेशालय ने दिसंबर 2012 और सितंबर 2016 में जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से सरकारी आवासीय व्यवस्था पर अनाधिकृत कब्जे के लिए क्षति की दरों को संशोधित किया, जो क्रमशः जनवरी 2013 और जुलाई 2016 से प्रभावी हुआ। डी.ए.ई. ने इन आदेशों को फरवरी 2013 और अक्टूबर 2016 में कार्यान्वयन के लिए अपनी सभी घटक इकाइयों को पृष्ठांकित किया। इन निर्देशों के अनुसार, मौजूदा स्थान से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण (तबादला) होने के बाद, सरकारी आवास को आठ महीने तक रोके रखने (प्रतिधारण) के पश्चात क्षति शुल्क लागू होते हैं। पहले महीने के लिए, क्षति शुल्क की वसूली लाइसेंस शुल्क के 40 गुना की दर से किया जाना था, दूसरे महीने-क्षति शुल्क प्लस क्षति शुल्क की दर का 10

प्रतिशत; तीसरे महीने-क्षति शुल्क प्लस क्षति शुल्क की दर का 20 प्रतिशत; और चौथे महीने-क्षति शुल्क प्लस डैमेज चार्ज की दर का 40 प्रतिशत वसूल किया जाना था। इसके अलावा, अनधिकृत कब्जेके प्रत्येक अगले महीने के लिए प्रतिशत दर तब तक बढ़ाई जानी थी जब तक कि आवंटिती द्वारा आवास खाली न कर दिया जाए, जो कि अनधिकृत कब्जे के पहले महीने के क्षति शुल्क की दरों के अधिकतम पांच गुना तक सीमित थी। अणुशक्ति नगर, मुंबई के लिए क्षति शुल्क की दरें 50 गुना वसूल की जानी थीं, क्योंकि मुंबई और दिल्ली शहरों के लिए यही दर निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, डी.ए.ई. ने वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की सहमति प्राप्त किए बिना, सरकारी आवासीय आवास को दोगुने लाइसेंस शुल्क पर रोके रखने की अधिकतम अनुमेय सीमा को आठ महीने (जो संपदा निदेशालय द्वारा निर्धारित थी) से बढ़ाकर क्रमशः दो वर्ष (दिसंबर 2018 में) और चार वर्ष (मई 2023 में) कर दिया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2019-20 से 2024-25 तक, 93 अधिकारियों¹⁷ ने अपने पूर्ववर्ती पदस्थापन¹⁸ स्थान पर आवासीय व्यवस्था को आठ महीने की अनुमत अवधि से अधिक समय तक अपने पास रखा। जबकि विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के 40/50 गुना के बजाय केवल दोगुना लाइसेंस शुल्क ही वसूला गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹6.01 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) बताया कि राजस्व का कोई त्याग नहीं हुआ है, क्योंकि डी.ए.ई. ने

¹⁷ परमाणु ऊर्जा विभाग की मुंबई इकाइयों, यानी निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय के 79 अधिकारी, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर के सात, सामान्य सेवा संगठन कल्पाक्कम के तीन, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद के दो और भारी जल संयंत्र बड़ौदा के दो अधिकारी इसमें शामिल थे।

¹⁸ इन कर्मचारियों ने मुंबई/हैदराबाद/कल्पाक्कम/इंदौर/बड़ौदा में सरकारी आवासीय क्वार्टर बरकरार रखे थे, जबकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति/स्थानांतरण कोलकाता/तारापुर/काकरापार/हैदराबाद/मैसूर/थल/इंदौर/कुडनकुलम/मनुगुरु/विजाग/कोटा/नईदिल्ली/कल्पाक्कम/जादुगुडा/जयपुर/तालचेर/तूतीकोरिन में स्थित विभिन्न परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में हो गया था।

अपनी अंतर-विभागीय स्थानांतरण नीति के तहत सामान्य लाइसेंस शुल्क के दोगुने और सामान्य लाइसेंस शुल्क के 16 गुना¹⁹ पर छह महीने से अधिक समय तक आवासों को अपने पास रखने की अनुमति दी थी, यह देखते हुए कि विभागीय कर्मचारियों का स्थानांतरण बाहरी स्टेशनों पर होने के कारण वे इन आवासों को अपने पास रख रहे थे। डी.ए.ई. ने आगे कहा कि यद्यपि डी.ए.ई. को अपनी आवास नीतियों का पालन करने का अधिकार है, फिर भी उसने यथासंभव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.) की आवास नीतियों, जैसे लाइसेंस शुल्क दरें, आवास को अपने पास रखने आदि का पालन किया है। हालाँकि, दी गई छूट कभी भी रियायती दर पर नहीं थी और या तो लाइसेंस शुल्क की दोगुनी दर या अनुमत अवधि²⁰ से अधिक होने पर बाजार दर वसूल की गई थी। डी.ए.ई. ने यह भी बताया कि एम.ओ.एच.यू.ए. ने (अगस्त 2024) आवासों को अपने पास रखने की अवधि को तीन साल तक बढ़ा दिया था।

डी.ए.ई. के जवाब को उपर्युक्त जी.एफ.आर. प्रावधान के आलोक में देखा जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना कोई भी प्राधिकरण ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता जिससे किसी भी तरह से राजस्व का त्याग हो। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2018 तक, डी.ए.ई. ने संपदा निदेशालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति दरों को लागू किया था। वित्त सदस्य (डी.ए.ई.) की स्वीकृति के बिना एक नई नीति (दिसंबर 2018) का निर्माण, जिससे सरकारी खजाने को भारी राजस्व हानि हुई, अनियमित था। साथ ही, डी.ए.ई. द्वारा संदर्भित गृह मंत्रालय का कार्यालय जापन (अगस्त 2024) केवल तभी लागू होता था जब तैनाती का स्थान गैर-पारिवारिक स्टेशन (अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप) में हो। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा सूचीबद्ध मामले गैर-पारिवारिक स्टेशन के अंतर्गत नहीं आते थे।

¹⁹ जब कोई कर्मचारी पुराने स्टेशन पर विभागीय क्वार्टर रखता है और साथ ही नए स्टेशन पर भी विभागीय क्वार्टर में रहता है। कर्मचारी का या तो पुराने स्टेशन पर या नए स्टेशन पर अपना निजी आवास भी है।

²⁰ आवास रखने की अवधि चार वर्ष रही।

अनुशंसा 7:

डी.ए.ई. वित्तीय निहितार्थों वाली नई नीति/दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए सदस्य (वित्त) की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है या सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए संपदा निदेशालय द्वारा जारी मौजूदा नियम का पालन कर सकता है।

2.1.3 पट्टा/लाइसेंस समझौतों का नवीनीकरण न होना/निष्पादन न होना, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि/कम वसूली होती है

पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार, अचल संपत्ति के पट्टे जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हों, या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हों, या जिनका वार्षिक किराया निर्धारित हो, उनका पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

क. लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि डी.ए.ई.²¹ की तीन इकाइयों ने सरकारी भूमि को तेल कंपनियों, पेट्रोल पंप, बैंक और राज्य परिवहन निगम आदि को पट्टे पर दिया था, लेकिन पट्टा/लाइसेंस समझौतों की समाप्ति के बाद उनका नवीनीकरण न होने के कारण राजस्व की कम वसूली हुई और हानि उठानी पड़ी। इन मामलों का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

लाइसेंस समझौते के नवीनीकरण में अत्यधिक देरी के कुछ मामले सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2 (2018) के पैरा संख्या 3.2 और सी.ए.जी. रिपोर्ट संख्या 2 (2021) के पैरा संख्या 3.2 में दर्ज किए गए थे। डी.ए.ई. ने अपने कृत कार्यवाही नोट में भविष्य में अनुपालन के लिए इन मामलों को नोट किया था। हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बाद भी (दिसंबर 2025 तक), इन लाइसेंस समझौतों को संशोधित पट्टा किराए के साथ नवीनीकरण नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2007 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान ₹47.27 करोड़ के लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराए की कम वसूली हुई,

²¹ डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई, जी.एस.ओ., कल्याणकम और आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर।

जिसका विवरण तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12: किराया शुल्क की कम वसूली

क्रम संख्या	संगठन का नाम	लाइसेंस समझौता नवीनीकरण के लिए देय	अवधि के लिए वसूल की जाने वाली संशोधित पट्टा	प्राप्त होने वाली पट्टा किराया राशि (₹ में)	ए.टी.एन. के अनुसार डी.ए.ई. की प्रतिक्रिया
1.	बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और आर.आई.आई.एल. ²²	अगस्त 2007	अगस्त 2007 से जुलाई 2025	40,99,27,128	कार्रवाई नोट में डी.ए.ई. ने (अगस्त 2022) कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया था। हालाँकि, दिसंबर 2025 तक कोई सुधार नहीं देखा गया।
2.	तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम	अक्टूबर 2012	1.10.2012 से 30.6.2024	3,58,11,925	कार्रवाई नोट में डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025) कहा कि एस.बी.आई.9 और
3.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	अगस्त 2013	1.08.2013 से 30.6.2024	2,69,34,979	टी.एन.एस.टी.सी. पूर्वव्यापी संशोधन से सहमत नहीं थे।

इस प्रकार, संशोधित पट्टा किराया के साथ पट्टा समझौतों के नवीनीकरण में अत्यधिक देरी (12 से 18 वर्ष) के कारण ₹47.27 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इस तरह की प्रथाएं जारी रहीं, जैसा कि उन मामलों में परिलक्षित होता है जिनमें 2018 के बाद लाइसेंस/पट्टा समझौते का नवीनीकरण होना था, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप डी.ए.ई. को राजस्व की हानि हुई, जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

- i. डी.ए.ई. ने 1973 में प्रभादेवी, मुंबई में 836.13 वर्ग मीटर भूमि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) को 30 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए पट्टे

²² भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

पर दी थी, जिसे (₹2,28,332 प्रति माह पर) आगे 6 जुलाई 2018 तक बढ़ाया गया था। डी.सी.एस.ई.एम. ने अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए संशोधित पट्टा किराया (₹9,82,801 प्रति माह²³) पर पट्टा समझौते के नवीनीकरण के लिए (अप्रैल 2018 में) डी.ए.ई. से संपर्क किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2019 से फरवरी 2024 की अवधि के दौरान, डी.ए.ई. और डी.सी.एस.ई.एम. के बीच कई पत्राचार हुए, हालाँकि, मई 2024 तक सदस्य (वित्त) की विभिन्न आपत्तियों और प्रस्ताव में स्पष्टता की कमी के कारण वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.ए.ई. के सचिव ने सदस्य (वित्त) का अनुमोदन लिए बिना ही, मई 2024 में भूमि को 'वाणिज्यिक भूमि' मानकर तय किए गए फॉर्मूला²⁴ के आधार पर संशोधित दरों पर लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए, 7 जुलाई 2018 से 6 जुलाई 2023 तक के पट्टा समझौते के नवीनीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से अनंतिम मंजूरी दे दी। फिर भी, इसे दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। आई.ओ.सी.एल. ने (अक्टूबर 2025 में) स्पष्ट किया कि पट्टा समझौते के बिना संशोधित दर का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, ₹12.98 करोड़ (जुलाई 2018 से अक्टूबर 2025) के पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क की कम वसूली मुख्य रूप से डी.ए.ई. द्वारा पट्टा किराया समझौते में संशोधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में अत्यधिक समय (यानी सात साल से अधिक) लेने के कारण हुई।

इसी तरह के एक मामले में, डी.ए.ई. ने देवनार में आई.ओ.सी.एल. को पट्टे पर दी गई 1908.885 वर्ग मीटर भूमि के पट्टा समझौते की अवधि को 18 अगस्त 2008 से 17

²³ (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) × भूमि का रेट रेडी रेकनर के अनुसार × प्राइम लेंडिंग रेट × 1/12) यानी 836.13 × 1,55,000 × 9.10 × 1/12 = ₹9,82,801।

²⁴ भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में × भूमि का रेट रेडी रेकनर के अनुसार × प्राइम लेंडिंग रेट × 1/12।

अगस्त 2023 तक ₹0.02 करोड़ प्रति माह²⁵ की लागत पर बढ़ाया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.सी.एस.ई.एम. ने (जनवरी 2023 में) पट्टे को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की आई.ओ.सी.एल. की इच्छा के बारे में डी.ए.ई. को सूचित किया था। जवाब की प्रतीक्षा करते हुए, डी.सी.एस.ई.एम. ने पट्टा के नवीनीकरण के लिए समझौते का मसौदा डी.ए.ई. को भेजा (मई 2024), जिसमें संशोधित पट्टा किराया की दर ₹0.11 करोड़ प्रति माह निर्धारित की गई थी। डी.ए.ई. ने जुलाई 2024 में सूचित किया कि 18 अगस्त 2023 से 17 अगस्त 2028 की अवधि के लिए फॉर्मूले²⁶ के आधार पर पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहिए। हालाँकि, दिसंबर 2025 तक पट्टा समझौते का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विभाग को ₹1.75 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त दोनों मामलों के संबंध में, डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि देवनार और प्रभादेवी में आई.ओ.सी.एल. को पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टा समझौते के नवीनीकरण का प्रस्ताव डी.ए.ई. को प्राप्त हुआ था। सदस्य, वित्त (डी.ए.ई.) द्वारा मांगी गई स्पष्टीकरण के लंबित होने के कारण दोनों प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

अतः डी.ए.ई. की ओर से प्रतिक्रिया में देरी के कारण, पट्टा विलेख को पिछली तारीखों से संशोधित दरों पर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रकार, डी.ए.ई. ने आई.ओ.सी.एल. को बिना किसी वैध समझौते के कई वर्षों तक पुराने पट्टा किराया दरों पर दोनों स्थानों पर सरकारी भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी।

- ii. 1999 में, डी.ए.ई. ने आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर में एस.बी.आई. को 1400 वर्ग मीटर भूमि ₹8,270 प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए किराये पर देने की मंजूरी दी थी,

²⁵ मूल पट्टा समझौता 1 दिसंबर 1970 को किया गया था।

²⁶ भूमि का क्षेत्रफल × रेडी रिकनर दर × एम.सी.एल.आर./12।

जिसमें यह शर्त थी कि हर 10 साल में उस समय की भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर किराए की समीक्षा की जाएगी। दिसंबर 2000 में आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर और एस.बी.आई. के बीच 10 वर्षों के लिए एक पट्टा समझौता किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि पट्टा के नवीनीकरण के समय आपसी सहमति से किराया बढ़ाया जाएगा। आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर ने (अगस्त 2011 में), 2010-11 की बाजार दरों के आधार पर एस.बी.आई. को ₹0.06 करोड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टा के नवीनीकरण का प्रस्ताव दिया। एस.बी.आई. ने असहमति जताई और (फरवरी 2012 में) पट्टा किराया को हर पांच साल में 25 प्रतिशत तक बढ़ाने, यानी ₹10,340 प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2013 में) आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर को निर्देश दिया कि पट्टा किराया की गणना के लिए राज्य के 'रेडी रेकनर' का पालन किया जाए। अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान डी.ए.ई. और एस.बी.आई. के बीच बार-बार पत्राचार के बावजूद, नवीनीकृत पट्टा किराया निर्धारित करने का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

इस प्रकार, पट्टा किराया के नवीनीकरण में देरी के कारण, एस.बी.आई. ₹8,270 प्रति वर्ष का भुगतान करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2025 तक ₹1.84 करोड़ की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, आर.आर.सी.ए.टी. ने एस.बी.आई. को 15 से अधिक वर्षों तक बिना किसी वैध समझौते के सरकारी भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि आर.आर.सी.ए.टी. पट्टा समझौते के नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

ख. लेखापरीक्षा ने डी.ए.ई./उसकी घटक इकाइयों और पट्टेदारों जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (ए.पी.एस.आर.टी.सी.), आई.ओ.सी.एल. के बीच पट्टा

समझौतों के निष्पादन न होने का अवलोकन भी किया, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हुई, जिसका विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

- i. एन.एफ.सी. ने डी.ए.ई. के अनुमोदन (मई 1984) के साथ, हैदराबाद में बस डिपो और बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 5.937 एकड़ भूमि ए.पी.एस.आर.टी.सी. को 99 वर्षों की अवधि के लिए ₹1,366 प्रति वर्ष की दर से पट्टा किराया²⁷ पर दी थी, जिसमें यह शर्त थी कि पट्टा विलेख का औपचारिक निष्पादन बाद में किया जाएगा। हालाँकि 1991 में डी.ए.ई. द्वारा एक मसौदा पट्टा विलेख की जाँच की गई थी, लेकिन पट्टा समझौता साकार नहीं हो सका।

बाद में दिसंबर 2010 में, डी.ए.ई. ने एन.एफ.सी. को निर्देश दिया कि भूमि के लागत कारक में वृद्धि होने के कारण एक फॉर्मूले²⁸ के आधार पर पट्टा किराया की गणना की जाए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2018 तक संशोधित पट्टा किराया के निर्धारण के साथ पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए एन.एफ.सी. की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। सात साल से अधिक की देरी के बाद, अप्रैल 2018 में एन.एफ.सी. ने डी.ए.ई. को पट्टा विलेख का मसौदा भेजा। डी.ए.ई. ने (मार्च 2020 में) तीन²⁹ प्रस्तावित फॉर्मूलों में से सबसे कम वाले के अनुसार पट्टा किराया में संशोधन का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टी.जी.एस.आर.टी.सी.)³⁰ ने (मार्च 2023 में) अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाने पर असहमति जताई और ₹1,366 प्रति वर्ष के मौजूदा वार्षिक पट्टा किराया को ही जारी रखने का अनुरोध किया। दिसंबर 2025 तक डी.ए.ई. द्वारा पट्टा विलेख निष्पादन या पट्टा किराया के संशोधन की

²⁷ भूमि की मूल लागत पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से।

²⁸ भूमि की दर x भूमि का क्षेत्रफल x 12 प्रतिशत (प्रधान उधार दर)।

²⁹ सूत्र 1: अधिग्रहित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) x प्रति वर्ग मीटर भूमि की लागत (रेडी रेकनर के अनुसार) x प्रधान उधार दर = ₹17,35,32,585 प्रति वर्ष।

सूत्र 2: दर/वर्ग फुट x क्षेत्रफल (वर्ग फुट) x 14 प्रतिशत = ₹18,06,28,713 प्रति वर्ष।

सूत्र 3: पट्टा किराया = पूंजी लागत x 12 प्रतिशत (प्रधान उधार दर) = (भूमि की दर x क्षेत्रफल) x 12 प्रतिशत = ₹15,48,24,611 प्रति वर्ष।

³⁰ पूर्ववर्ती ए.पी.एस.आर.टी.सी.।

दिशा में कोई और प्रगति नहीं की गई।

डी.ए.ई. ने अपने जवाब (दिसंबर 2025) में कहा कि पट्टा विलेख के निष्पादन के संबंध में टी.जी.एस.आर.टी.सी. की खराब प्रतिक्रिया के कारण उसे 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जा रहा था। हालाँकि, इसमें आगे कहा गया कि चूंकि 1984 के आवंटन पत्र में लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए टी.जी.एस.आर.टी.सी. द्वारा संशोधित दर पर पट्टा किराया स्वीकार नहीं किया गया।

लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के संबंध में डी.ए.ई. के तर्क को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि यदि दोनों पक्षों के बीच एक औपचारिक पट्टा समझौता किया गया होता, तो ऐसी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा सकता था। पट्टा विलेख के निष्पादन न होने के कारण, संशोधित दरों पर पट्टा किराए की वसूली लागू नहीं की जा सकी, जिससे वर्ष 2020-21 से अक्टूबर 2025 तक ₹86.39 करोड़³¹ के राजस्व की हानि हुई। साथ ही, टी.जी.एस.आर.टी.सी. बिना किसी वैध पट्टा समझौते के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सरकारी भूमि का उपयोग करना जारी रखा है।

- ii. अक्टूबर 1987 में, आई.ओ.सी.एल. ने डी.ए.ई. का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, कल्पाक्कम टाउनशिप में मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल के उपभोक्ता पंपों के लिए जी.एस.ओ., कल्पाक्कम की भूमि आवंटित करने हेतु 'एटॉमिक एनर्जी एम्प्लॉइज कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड'³² (ए.ई.ई.सी.सी.) के साथ शुरुआती 10 वर्षों के लिए एक समझौता किया। बाद में, जी.एस.ओ., कल्पाक्कम ने (जुलाई 2000 में) उपभोक्ता पंप को डीलर पंप में बदलने के लिए आई.ओ.सी.एल. को 1,826 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर देने का एक प्रस्ताव³³ डी.ए.ई. को प्रस्तुत किया। इसे सदस्य (वित्त)

³¹ (₹15,48,24,611x5.58)-(₹1,366x5.58)=₹86,39,13,707.10।

³² पूर्व मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति।

³³ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त (अप्रैल 2000)।

(डी.ए.ई.) द्वारा 30 वर्षों के लिए ₹7,667 प्रति वर्ष की बाजार दर पर अनुमोदित (जुलाई 2003) किया गया था, जिसमें हर पांच साल में किराए को संशोधित करने का प्रावधान था। पट्टा प्रस्ताव को मंजूरी देते समय, सदस्य (वित्त) ने डी.ए.ई. को वर्ष 1987 की अवधि के बाद से ए.ई.ई.सी.सी. से उचित पट्टा किराया वसूलने का निर्देश भी दिया था।

लेखापरीक्षा ने हालाँकि यह पाया कि 2003 में डी.ए.ई. के अनुमोदन के बावजूद, नवंबर 2024 तक न तो जी.एस.ओ., कल्पाक्कम और आई.ओ.सी.एल./ए.ई.ई.सी.सी. के बीच कोई पट्टा समझौता निष्पादित किया गया, और न ही जुलाई 2003 से निर्धारित दरों पर आई.ओ.सी.एल. से पट्टा शुल्क की कोई वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ए.ई.ई.सी.सी. से पट्टा किराए के संबंध में न तो कोई शुल्क निर्धारित किया गया और न ही वसूला गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, जी.एस.ओ., कल्पाक्कम ने अक्टूबर 2024 में आई.ओ.सी.एल. को जुलाई 2003 से अगस्त 2024 तक के लंबित पट्टा शुल्क के लिए ₹0.57 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया। हालाँकि, इसकी वसूली अभी बाकी थी। इसके अलावा, सदस्य, वित्त (डी.ए.ई.) के निर्देशानुसार उचित पट्टा किराया के बदले वर्ष 2017-18 से 2023-24 की अवधि के लिए ₹1 प्रति माह की दर से लाइसेंस शुल्क की वसूली हेतु ए.ई.ई.सी.सी. को भी एक डिमांड नोटिस (सितंबर 2024 में) जारी किया गया था।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि पेट्रोल रिटेल आउटलेट का संचालन ए.ई.ई.सी.सी. द्वारा आई.ओ.सी.एल. के डीलर के रूप में किया जा रहा था। इसमें आगे कहा गया कि आई.ओ.सी.एल. को कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी गई थी। इसलिए, आई.ओ.सी.एल. से पट्टा किराया की वसूली और उसके साथ पट्टा समझौते के नवीनीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

डी.ए.ई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सदस्य (वित्त) का अनुमोदन आई.ओ.सी.एल. से ₹7,667 प्रति वर्ष की दर से पट्टा किराया निर्धारित करने के लिए था। तदनुसार, पट्टा किराया की वसूली के लिए आई.ओ.सी.एल. को एक डिमांड नोटिस भी जारी किया गया था। यदि ए.ई.ई.सी.सी. ने वास्तव में आई.ओ.सी.एल. पेट्रोल पंप को डीलर के रूप में संचालित किया था, जैसा कि डी.ए.ई. के उत्तर में कहा गया है, तो उस भूमि का उपयोग ए.ई.ई.सी.सी. द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसलिए, या तो 2003 में सदस्य (वित्त) द्वारा निर्धारित पट्टा किराया की वसूली ए.ई.ई.सी.सी. से की जानी चाहिए थी, या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए डी.ए.ई. की भूमि के उपयोग हेतु मामूली पट्टा किराया (₹1 प्रति माह) वसूलने के लिए सदस्य (वित्त) की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में पट्टा विलेख/समझौतों के निष्पादन में देरी/निष्पादन न होने के प्रेक्षणों के संदर्भ में, डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) बताया कि सरकारी खजाने को होने वाले अनजाने नुकसान से बचने के लिए पट्टा समझौतों/विलेखों की समय पर समीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं (अगस्त 2025)।

इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में, डी.ए.ई. और इसकी घटक इकाइयों द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण, पट्टा समझौते या तो नहीं किए गए या उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे वे पट्टेदारों के लिए अस्वीकार्य हो गए। इसके अलावा, चूंकि डी.ए.ई. ने इन समझौतों की समाप्ति से पहले इनके संशोधन के लिए कार्रवाई नहीं की, इसलिए डी.ए.ई. के लिए पट्टा किराया के संशोधन को लागू करना कठिन होता।

अनुशंसा 8:

डी.ए.ई संबंधित पट्टा/लाइसेंस समझौतों की समाप्ति से पहले समय पर नवीनीकरण की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है, जिसमें संशोधित पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क/जमीनी किराया शामिल है।

2.1.4 लाइसेंस शुल्क की समय-समय पर समीक्षा

कर्मचारियों को आवंटित आवासीय क्वार्टरों या बैंकों/डाकघरों/दुकानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी पार्टियों को पट्टे पर दी गई भूमि/भवन के संबंध में लाइसेंस शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए इसकी समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है।

2.1.4.1 लाइसेंस शुल्क की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानी

गृह मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) ने (दिसंबर 2017 में) संपदा निदेशालय के कार्यालय जापन का पृष्ठांकित किया, जिसमें 1 जुलाई 2017 से 'रेंट-फ्री अकोमोडेशन अलाउंस' (किराया मुक्त आवास भत्ता) को समाप्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.आई.एस.एफ. ने डी.ए.ई. की घटक इकाइयों³⁴ द्वारा दिए गए स्टाफ क्वार्टरों के लिए मई 2019 तक लाइसेंस शुल्क जमा किया था। हालाँकि, जून 2019 से निरीक्षक के पद तक के अपने कर्मचारियों से न तो लाइसेंस शुल्क एकत्र किया गया और न ही डी.ए.ई.

³⁴ निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (मुंबई), सामान्य सेवा संगठन, (कल्पाक्कम और अनुपुरम), परमाणु ईंधन परिसर (हैदराबाद), भारी पानी संयंत्र (मनुगुरु)।

के पास जमा किया गया। यह संपदा निदेशालय के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें ऐसी किसी छूट का प्रावधान नहीं था।

डी.ए.ई. ने सी.आई.एस.एफ. से लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹2.87 करोड़ (जून 2019 से अक्टूबर 2025 तक) के राजस्व की हानि हुई।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि घटक इकाइयों/सहायता प्राप्त संस्थानों/पी.एस.यू. के सभी प्रशासनिक प्रमुखों को सभी सी.आई.एस.एफ. कर्मियों से लागू लाइसेंस शुल्क वसूलने का निर्देश (फरवरी 2025) दिया गया था। इसके अलावा, डी.ए.ई. ने निर्देश के साथ एक कार्यालय ज्ञापन (जनवरी 2026) भी जारी किया था, जिसमें सी.आई.एस.एफ. कर्मियों से लागू लाइसेंस शुल्क वसूलने और कोई भी छूट केवल तभी देने जब वह वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो।

2.1.4.2 बैंकों/डाकघरों से लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए कोई समान नीति नहीं

कार्य संचालन नियम 1961 का नियम 4(2)(b) यह स्पष्ट करता है कि जब तक कोई मामला वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किसी सामान्य या विशेष आदेश के तहत खर्च की शक्ति के भीतर पूरी तरह से कवर न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व का समनुदेशन, रियायत, या ऐसी रियायत के संबंध में कोई सुविधा या विशेषाधिकार शामिल हो। इसी बात को वित्त मंत्रालय द्वारा 25 जून 2010 के कार्यालय ज्ञापन और सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.), 2017 के नियम 28 (ii) के माध्यम से सख्त अनुपालन के लिए दोहराया गया है।

डी.ए.ई. की बारह इकाइयों ने अपने परिसर में डाकघरों और बैंकों के संचालन के लिए स्थान आवंटित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ए.ई. ने सदस्य (वित्त) की मंजूरी के बिना बैंकों/डाकघरों से लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए अपनी दरें निर्धारित की थीं। रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डाकघरों के मामले में डी.ए.ई. ने ₹1 प्रति माह का मामूली लाइसेंस शुल्क

लिया और बैंकों से लिया गया लाइसेंस शुल्क संपदा निदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों से बहुत कम था। इसके परिणामस्वरूप बैंकों/डाकघरों से रियायती दरों पर लाइसेंस शुल्क लिया गया, जिसके लिए सदस्य (वित्त) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उसने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार किया है और हाल ही में मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी (एम.डी.सी.सी.) बैंक की शाखा खोलने के लिए संपदा निदेशालय की दरों पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, डी.सी.एस.ई.एम. से संपदा निदेशालय के आदेशों के अनुरूप बैंकों और डाकघरों के संबंध में लाइसेंस शुल्क की समीक्षा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैंकों के लाइसेंस शुल्क का मामला डी.ए.ई. में प्रक्रियाधीन है और डाकघरों के लाइसेंस शुल्क के संबंध में डी.सी.एस.ई.एम. से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डी.सी.एस.ई.एम. से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया जाएगा कि डाकघर के लिए लाइसेंस शुल्क संपदा निदेशालय के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाना है या नहीं।

अनुशंसा 9:

डी.ए.ई. सदस्य (वित्त) की मंजूरी से बैंकों/डाकघरों को स्थान प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क के निर्धारण की दिशा में व्यापक समीक्षा कर सकता है।

2.1.5 संपत्ति रजिस्टर और केंद्रीकृत डेटा बैंक/एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव न करना

क. वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में भूमि, भवन और ढांचागत संपत्तियों सहित संपत्ति रजिस्टर बनाने, अद्यतन करने और बनाए रखने के लिए तथा ई-संपत्ति रजिस्टर पोर्टल शुरू करने के लिए दिशानिर्देश (सितंबर 2017) जारी किए थे। दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि मंत्रालयों/विभागों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) नियम, 2004 में निर्धारित प्रारूप में संपत्ति रजिस्टर बनाए रखना

आवश्यक है। उन्हें भूमि, भवन और ढांचागत संपत्तियों पर किए गए व्यय का मिलान 'वित्त खातों' में दिखाए गए आंकड़ों से करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.), 2017 का नियम 213(1) कार्यालय प्रमुख द्वारा अचल संपत्तियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ए.ई. और उसकी घटक इकाइयों ने भूमि, भवन और ढांचागत संपत्तियों के लिए संपत्ति रजिस्टर नहीं बनाए थे। ऐसे रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा एक ही स्थान पर संपत्ति की स्थिति, उसकी दशा और उपयोग की स्थिति की जानकारी का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, ऐसे रजिस्टर की अनुपस्थिति में, आवश्यकतानुसार भूमि, भवन और ढांचागत संपत्तियों पर किए गए व्यय का डी.ए.ई. के वित्त खातों के आंकड़ों के साथ मिलान नहीं किया गया।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि संपत्ति डेटा को संकलित करने, सत्यापित करने और मानकीकृत करने के लिए एक व्यापक अभ्यास किया जा रहा है।

अनुशंसा 10:

डी.ए.ई. और उसकी इकाइयां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार भूमि, भवन और ढांचागत संपत्तियों के संबंध में संपत्ति रजिस्टर बनाए रख सकती हैं।

ख. डी.ए.ई. (दिसंबर 2014 में) अपनी सभी घटक इकाइयों (सहायता प्राप्त संस्थानों सहित) के भूमि रिकॉर्ड पर केंद्रीकृत डेटा बैंक बनाने और एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली का कार्य डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई को सौंपा था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि केंद्रीकृत डेटा बैंक स्थापित किया गया था और डी.सी.एस.ई.एम. द्वारा सरकारी भूमि सूचना प्रणाली के उद्देश्य से सभी इकाइयों से जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में इस बैंक को भंग कर दिया गया था।

डी.ए.ई., लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से सहमत हुआ। फलस्वरूप, वर्तमान में विभागीय स्तर पर कोई एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली मौजूद नहीं है, जो आंतरिक उपयोग के लिए भी, डी.ए.ई. इकाइयों के कब्जे वाली भूमि क्षेत्र का सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश कर सके।

2.1.6 भूमि हस्तांतरण और अतिक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

डी.ए.ई. के कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व, अधिग्रहण के तुरंत बाद डी.ए.ई. के नाम पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और अतिक्रमण का पता लगाने, रोकथाम और उसे हटाने, भूमि की सीमाओं और भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव आदि के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। इन मुद्दों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.1.6.1 कब्जे के बावजूद डी.ए.ई./भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण न होना

डी.ए.ई. की दस इकाइयों³⁵ ने पिछले कई वर्षों में अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना, संयंत्र लगाने, आवासीय आवास के निर्माण आदि उद्देश्यों के लिए भूमि का कब्जा/अधिग्रहण/खरीद की थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को देखा जहाँ काफी समय बीत जाने के बाद भी इन जमीनों का स्वामित्व डी.ए.ई./भारत के राष्ट्रपति के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 13: गैर-हस्तांतरित भूमि की सूची

इकाई का नाम	भूमि अधिग्रहण की अवधि	कब्जे वाली भूमि (एकड़ में)	भारत के राष्ट्रपति/डी.ए.ई. के नाम पर हस्तांतरित न की गई भूमि (एकड़ में)
बी.ए.आर.सी., विशाखापत्तनम	2005 से 2021	4235	4235
डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई	1956 से फरवरी 2024	1433.13	72.02
एन.एफ.सी., बेंगलुरु	1967 से 1990	1182.82	421.55
आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर	1983 और 1988	1731.89	1731.89

³⁵ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम, राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम, परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद, भारी जल संयंत्र, थाल, भारी जल संयंत्र, हजीरा, भारी जल संयंत्र, कोटा, भारी जल संयंत्र, तूतीकोरिन, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज।

इकाई का नाम	भूमि अधिग्रहण की अवधि	कब्जे वाली भूमि (एकड़ में)	भारत के राष्ट्रपति/डी.ए.ई. के नाम पर हस्तांतरित न की गई भूमि (एकड़ में)
जी.एस.ओ., कल्पाक्कम	1979 से 1991	749.71	462.70
एच.डब्ल्यू.पी., हजीरा	1990	123.4	123.4
एच.डब्ल्यू.पी., कोटा	1969	149.60	80.00
एच.डब्ल्यू.पी., थल	1984	35.10	35.10
एच.डब्ल्यू.पी., तूतीकोरिन	1973 से 2012	94.83	48.06
एच.आर.आई., प्रयागराज	1990	55.96	55.96
कुल		9791.44	7265.68

इस प्रकार, इन 10 मामलों में कब्जे वाली 9,791.44 एकड़ भूमि में से 7,265.68 एकड़ भूमि का स्वामित्व डी.ए.ई. के नाम पर नहीं था। एक महत्वपूर्ण मामले की चर्चा नीचे की गई है:

तालिका 14: डी.ए.ई./भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना

भारी पानी संयंत्र (एच.डब्ल्यू.पी.), थल

एच.डब्ल्यू.पी., थल की स्थापना (1984) डी.ए.ई. और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ.) के बीच एक समझौते के आधार पर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि आरसीएफ परिसर के भीतर एच.डब्ल्यू.पी. की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि और आवास के लिए टाउनशिप भूमि का स्वामित्व डी.ए.ई. के नाम पर स्थानांतरित किया जाना था। तदनुसार, डी.ए.ई. ने 35,096 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए 1984 में आर.सी.एफ., थल को ₹0.07³⁶ करोड़ का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दिसंबर 2025 तक, भूमि का स्वामित्व डी.ए.ई./भारत के राष्ट्रपति के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया था। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 285(1) के अनुसार, संघ (केंद्र सरकार) की संपत्ति को राज्य द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्राप्त है। हालाँकि, यह देखा गया कि एच.डब्ल्यू.पी. ने संबंधित भूमि पर संपत्ति कर के रूप में स्थानीय निकाय प्राधिकरण को ₹4.08 करोड़³⁷ (2018-2024) का भुगतान किया था।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि भूमि को या तो डी.ए.ई. को स्थानांतरित करने या इसे पट्टे पर देने के लिए आर.सी.एफ. के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

इस प्रकार, भूमि के स्वामित्व को स्थानांतरित करने की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किए बिना ही, डी.ए.ई. ने थल में एच.डब्ल्यू.पी. और आवास कॉलोनियां स्थापित कर दी थीं।

³⁶ कारखाने के परिसर में 24.156 एकड़ भूमि के लिए ₹4,63,795 और कुरुल कॉलोनी में 10.94 एकड़ भूमि के लिए ₹2,10,048 का भुगतान किया गया।

³⁷ वास्तविक संपत्ति कर भुगतान इससे कहीं अधिक होगा। लेखापरीक्षा में पिछले छह वर्षों (2018-2024) के दौरान किए गए भुगतान को ही आधार माना गया है।

अनुशंसा 11:

डी.ए.ई. अपने नाम पर कब्जे वाली/आवंटित सभी भूमि के स्वामित्व को यथाशीघ्र स्थानांतरित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने हेतु एक 'कार्य बल' गठित कर सकता है।

2.1.6.2 आर.आर.सी.ए.टी. के कब्जे वाली 500 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण

आर.आर.सी.ए.टी., इंदौर ने वर्ष 1983-1988 के बीच मध्य प्रदेश राज्य सरकार से नवदापंथ गांव में 37 एकड़ और श्रीराम तलावली गांव में 4.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि लगभग 500 मीटर भूमि पर झोपड़ियों, ईंट की दीवारों वाले घरों और अन्य अवैध निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

डी.ए.ई. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए आर.आर.सी.ए.टी. जिला अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है।

2.1.7 भवनों के रखरखाव और रख-रखाव की प्रणाली का अस्तित्व

भवन निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्य किसी संरचना या भवन की सुविधाओं को बनाए रखने, बहाल करने या सुधारने के लिए किए जाते हैं, जिसमें संरचना और भवन की उपयोगिता और मूल्य को बनाए रखने के लिए हाउसकीपिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और रखरखाव सेवाएं, बागवानी और लैंडस्केपिंग शामिल हैं। लेखापरीक्षा ने भवनों के रखरखाव में कमियां पाईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

2.1.7.1 कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण में अत्यधिक देरी और सुरक्षा एवं आकस्मिक व्ययों पर ₹2.51 करोड़ का व्यय

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जहां कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण में देरी हुई, जबकि डी.ए.ई. की इकाइयां इन संपत्तियों पर आवर्ती व्यय करती रहीं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क. टाटा मेमोरियल सेंटर (टी.एम.सी.) ने 1968 में 1379 वर्ग मीटर की संपत्ति खरीदी और

चेंबूर में आवासीय क्वार्टर बनाए। मार्च 2009 में, टी.एम.सी. की शासी परिषद ने पुराने क्वार्टरों के स्थान पर नए क्वार्टर बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे 40 वर्ष से अधिक पुराने और संरचनात्मक रूप से कमजोर थे। मई 2010 में, डी.ए.ई. ने जून 2013 तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश के साथ नए क्वार्टरों के लिए ₹13 करोड़ स्वीकृत किए। उक्त परियोजना को डी.सी.एस.ई.एम., मुंबई द्वारा निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टी.एम.सी. ने विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण के लिए मई 2009 से अप्रैल 2014 तक छह बार अपनी आवश्यकताओं में संशोधन किया। हालाँकि, डी.सी.एस.ई.एम. ने (अप्रैल 2014 में) सूचित किया कि टी.एम.सी. की संशोधित आवश्यकता के लिए डी.ए.ई. के अनुमोदन की आवश्यकता है। इसके अलावा, डी.सी.एस.ई.एम. ने यह भी उल्लेख किया कि डी.ए.ई. ने परियोजना को बंद करने का सुझाव दिया था। हालाँकि, टी.एम.सी. की शासी परिषद ने परियोजना को जारी रखने की सलाह दी थी। इस संबंध में एक नया प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा आयोग को केवल अक्टूबर 2025 में भेजा गया था। हालाँकि, इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार, नए क्वार्टरों के निर्माण में 12 वर्षों से अधिक की देरी के कारण सुरक्षा और बिजली एवं पानी के आकस्मिक खर्चों पर ₹0.59 करोड़ का आवर्ती व्यय हुआ।

ख. इसी तरह, टी.एम.सी., मुंबई के मुलुंड में 300 स्टाफ क्वार्टर³⁸ थे, जिन्हें (मार्च 2016 में) जर्जर घोषित किया गया था और वे जुलाई 2017 से खाली पड़े थे। हालाँकि, टी.एम.सी. ने संबंधित अधिकारियों को बिजली/पानी काटने के संबंध में जानकारी नहीं दी और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹0.31 करोड़³⁹ का अनावश्यक खर्च हुआ।

ग. एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वडोदरा नगर निगम से 7.54

³⁸ टाइप IA-160 स्टाफ क्वार्टर और टाइप IIB-140 स्टाफ क्वार्टर।

³⁹ बिजली शुल्क और वैधानिक शुल्क के लिए क्रमशः ₹0.27 करोड़ और ₹0.04 करोड़।

एकड़ भूमि (1985) इस शर्त पर खरीदी थी कि भूमि का उपयोग केवल स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के उद्देश्य से किया जा सकता है। तदनुसार, एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा ने वर्ष 1988 में 90 आवासीय क्वार्टर बनाए। 2017 में भवनों की संरचनात्मक अखंडता के मूल्यांकन के अनुसार, सुदृढीकरण स्टील में गंभीर जंग के कारण क्वार्टर असुरक्षित माने गए। तदनुसार, मई 2020 में क्वार्टरों के खाली होने के बाद, एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा ने (जनवरी 2021 में) स्टाफ क्वार्टरों को छोड़ने और उनका निपटान करने का निर्णय लिया। चूंकि भूमि स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, विभाग ने (मार्च 2022) एच.डब्ल्यू.पी. को राज्य सरकार के साथ 'भूमि उपयोग शर्तों' की छूट तलाशने का निर्देश दिया। हालाँकि, अक्टूबर 2025 तक भूमि उपयोग पर डी.ए.ई./एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा की ओर से उक्त क्वार्टरों को ढहाने से बनी जगह का उपयोग करने के निर्णय में देरी के कारण सेवा, पानी, बिजली और सुरक्षा शुल्क पर ₹0.72 करोड़ (2021 से अक्टूबर 2025) का अनावश्यक खर्च हुआ।

- घ. एन.एफ.सी., हैदराबाद (1990 में) वरिष्ठ अधिकारियों के आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ₹0.33 करोड़ में हैदराबाद में छह फ्लैट खरीदे थे। हालाँकि, सभी छह फ्लैट 2011 से खाली पड़े रहे। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन फ्लैटों के निपटान/पट्टा पर देने के संबंध में एन.एफ.सी. और डी.ए.ई. के बीच कई पत्राचार (दिसंबर 2012 से मई 2019) के बावजूद, अक्टूबर 2025 तक डी.ए.ई. द्वारा कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके कारण रखरखाव और बिजली शुल्क (2011 से सितंबर 2025)⁴⁰ पर ₹0.89 करोड़ का आवर्ती खर्च हुआ, साथ ही छह फ्लैटों की खरीद के लिए ₹0.33 करोड़ की धनराशि भी अवरुद्ध रही।

इस प्रकार, डी.ए.ई. और उसकी इकाइयों के शिथिल दृष्टिकोण के कारण, उनके कब्जे वाली

⁴⁰ अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 की अवधि को छोड़कर, जिसके लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

संपत्तियां अनुपयोगी रहीं। इस बीच, एक ओर सुरक्षा, आकस्मिक व्यय, बिजली, पानी इत्यादि के शुल्क आदि पर ₹2.51 करोड़ का आवर्ती व्यय किया गया, तो दूसरी ओर 2011 से ₹0.33 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण, कर्मचारियों को एच.आर.ए. के भुगतान के कारण सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है।

डी.ए.ई. ने दिसंबर 2025 में प्रस्तुत अपने जवाब में इस प्रेक्षण पर चुप्पी साधे रखी।

अनुशंसा 12:

डी.ए.ई. सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अपने भूमि/संपदा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के विकल्प तलाश सकता है।

2.1.7.2 संपत्ति कर के रूप में ₹4.12 करोड़ का परिहार्य व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 (1) यह निर्धारित करता है कि 'संघ (केंद्र सरकार) की संपत्ति को किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट दी जाएगी।' इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2009 में निर्देश दिया था कि भारत संघ और उसके विभाग नगर निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए केवल सेवा शुल्क⁴¹ का भुगतान करेंगे, न कि संपत्ति कर का।

यह देखा गया कि डी.ए.ई. की चार इकाइयों और एक सहायता प्राप्त संस्थान के दो उप-केंद्र ने नवंबर 1983 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान ₹4.12 करोड़ की राशि का संपत्ति कर के रूप में भुगतान किया, जैसा कि **तालिका 15** में उल्लेखित है।

⁴¹ निजी मालिकों पर लगाए गए संपत्ति कर की दर क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत है।

तालिका 15: परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों और उप-केंद्रों द्वारा भुगतान किए गए संपत्ति कर का विवरण

क्रम संख्या	इकाई का नाम	संपत्ति का स्थान	कर का प्रकार	अवधि	परिहार्य व्यय भुगतान किया गया (₹ लाख में)	संबंधित इकाइयों का उत्तर
1.	डी.सी.एस.ई.ए म., मुंबई	अंधेरी, मुंबई	संपत्ति कर	नवंबर 1983 से अक्टूबर 2025	6.05	मामला बॉम्बे नगर निगम के पास लंबित था।
2.	जी.एस.ओ., कल्पाक्कम	कल्पाक्कम और अन्नपुरम टाउनशिप	मकान कर	2019-24	66.17	मामले का समाधान विभाग और स्थानीय निकाय के परामर्श से किया जाएगा।
3.	एन.एफ.सी., हैदराबाद	कारखाना भवन और आवासीय क्वार्टर	पुस्तकालय कर	2022-26	62.59	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
4.	एन.आर.बी., तारापुर	सरकारी आवासीय क्वार्टर, तारापुर	संपत्ति कर	2002-2015	260.00	2015-16 के बाद संपत्ति कर का भुगतान बंद हो गया।
5.	वाराणसी और गुवाहाटी स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के उप-केंद्र	वाराणसी और गुवाहाटी के संपूर्ण अस्पताल परिसर	संपत्ति कर/सामान्य कर/अन्य कर	2023-2025	17.42	टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपने उप-केंद्रों को छूट के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।
कुल					412.23	

इस प्रकार, सरकार के धन के हितों की रक्षा के लिए डी.ए.ई. इकाइयों/सहायता प्राप्त संस्थानों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था, जिसके कारण सरकारी खजाने की हानि हुई।

डी.ए.ई. ने दिसंबर 2025 में प्रस्तुत अपने उत्तर में इस अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं की।

अनुशंसा 13:

डी.ए.ई. इकाइयों/सहायता प्राप्त संस्थानों को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों या शुल्कों का कोई भी भुगतान,

जिनसे डी.ए.ई. को छूट प्राप्त है, केवल उचित सत्यापन और लागू होने की पुष्टि के बाद ही किया जाए।

2.1.8 निष्कर्ष

भूमि और संपदा प्रबंधन के मुद्दों से निपटने के लिए डी.ए.ई. में न तो कोई व्यापक नीति थी और न ही कोई नोडल अनुभाग। इसके परिणामस्वरूप भूमि/स्थान के हस्तांतरण और पट्टा/लाइसेंस समझौतों के समय पर नवीनीकरण के लिए किसी व्यवस्थित तंत्र का अभाव रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी संस्थाओं को आवासीय क्वार्टरों के आवंटन के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए थे, और समान 'विभागीय पूल आवासीय आवास नियम' भी निर्धारित नहीं किए गए थे। इन प्रणालीगत कमियों का क्रमिक प्रभाव पड़ा, जिससे डी.ए.ई. को संभावित और आवर्ती राजस्व हानि का सामना करना पड़ा।

डी.ए.ई. ने सरकारी आवासीय आवास की प्रतिधारण अवधि बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को किराया-मुक्त आवास प्रदान करने, और निजी पार्टियों, बैंकों एवं डाकघरों को रियायती लाइसेंस शुल्क पर क्वार्टर आवंटित करने जैसी विभिन्न रियायतें, सदस्य (वित्त), डी.ए.ई. की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रदान कीं। इसके अलावा, डी.ए.ई. और उसकी इकाइयाँ निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी पट्टेदारों के साथ पट्टा/लाइसेंस समझौतों का नवीनीकरण या निष्पादन करने में विफल रहीं, जिससे पट्टा किराया की कम वसूली हुई।

अधिग्रहण के बाद पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद, डी.ए.ई. और उसकी इकाइयों ने डी.ए.ई. के नाम पर भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया, जो कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई और अपर्याप्त स्वामित्व नियंत्रण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, भवनों के निर्माण, रखरखाव और रख-रखाव के लिए समय पर कार्रवाई करने में अत्यधिक देरी के कारण बिजली, सुरक्षा और संबंधित शुल्कों पर अनावश्यक व्यय हुआ।

2.2 टाटा मेमोरियल केंद्र की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

टाटा मेमोरियल केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अनुदान प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करता है और इसे कैंसर के क्षेत्र में सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कैंसर केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत है।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो वर्तमान में मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र का एक उप-केंद्र है, की स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा 1941 में एक ऐसे केंद्र के रूप में की गई थी जिसका स्थायी महत्व हो और जो भारतीय जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। 1952 में, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना मूलभूत अनुसंधान के लिए एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई, जिसे बाद में कैंसर अनुसंधान संस्थान कहा गया। 1957 में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्थायी रूप से टाटा मेमोरियल अस्पताल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1962 में टाटा मेमोरियल केंद्र (टाटा मेमोरियल अस्पताल और कैंसर अनुसंधान संस्थान) का प्रशासनिक नियंत्रण परमाणु ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1966 में टाटा मेमोरियल अस्पताल और कैंसर अनुसंधान संस्थान टाटा मेमोरियल केंद्र के दो अंगों के रूप में विलय हो गए।

वर्ष 2002 में, कैंसर अनुसंधान संस्थान के स्थानांतरण के साथ, खारघर, नवी मुंबई में कैंसर उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र की स्थापना खारघर स्थित नए परिसर में की गई। इसके बाद, 2005 में नैदानिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिससे कैंसर उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र परियोजना पूरी हुई। इसके बाद, टाटा मेमोरियल अस्पताल और कैंसर उपचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र के अलावा,

टाटा मेमोरियल केंद्र ने पूरे भारत में आठ⁴² उप-केंद्र स्थापित किए।

उद्देश्य

टाटा मेमोरियल केंद्र का मिशन सेवा, शिक्षा और अनुसंधान में अच्छे कार्य के अपने उद्देश्य के द्वारा सभी को व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करना है।

दूरदर्शिता

देश के सबसे बड़े कैंसर केंद्र के रूप में, टाटा मेमोरियल केंद्र का उद्देश्य है कि वह कैंसर देखभाल हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्यनीति के मार्गदर्शन हेतु नेतृत्व प्रदान करें:

- कैंसर विज्ञान के साक्ष्य-आधारित अभ्यास के माध्यम से उत्कृष्ट सेवाओं को बढ़ावा देना।
- छात्र, प्रशिक्षुओं, पेशेवरों, कार्मिकों और आम जनता को कैंसर के बारे में शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता।
- ऐसे अनुसंधान पर जोर देना जो किफायती, नवीन और देश की जरूरतों के अनुरूप हो।

2.2.2 बजट एवं व्यय

तालिका 16: टाटा मेमोरियल सेंटर का बजट एवं व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट आवंटन/आर.ई.	व्यय	राजस्व सृजन
2019-20	81495	120161	39111
2020-21	88863	119699	25851
2021-22	100627	143174	43911
2022-23	114311	177381	62165
2023-24	130778	206252	76336

⁴² 1. सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, महाराष्ट्र, 2. होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, 3. होमी भाभा, कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्तापुर, पंजाब, 4. होमी भाभा कैंसर अस्पताल, संगरूर, पंजाब, 5. महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 6. होमी भाभा कैंसर अस्पताल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 7. डॉ बी बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम, 8. होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार।

2.2.3 श्रमशक्ति

मार्च, 2024 तक, 2,839 स्वीकृत कार्मिकों के स्थान पर 2,429 कार्मिक तैनात थे। स्वीकृत पद और तैनात कार्मिकों में से चिकित्सा, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य (वरिष्ठ-I/II/III/एस.पी. वरिष्ठ नर्सिंग एवं सहायक) शामिल हैं ।

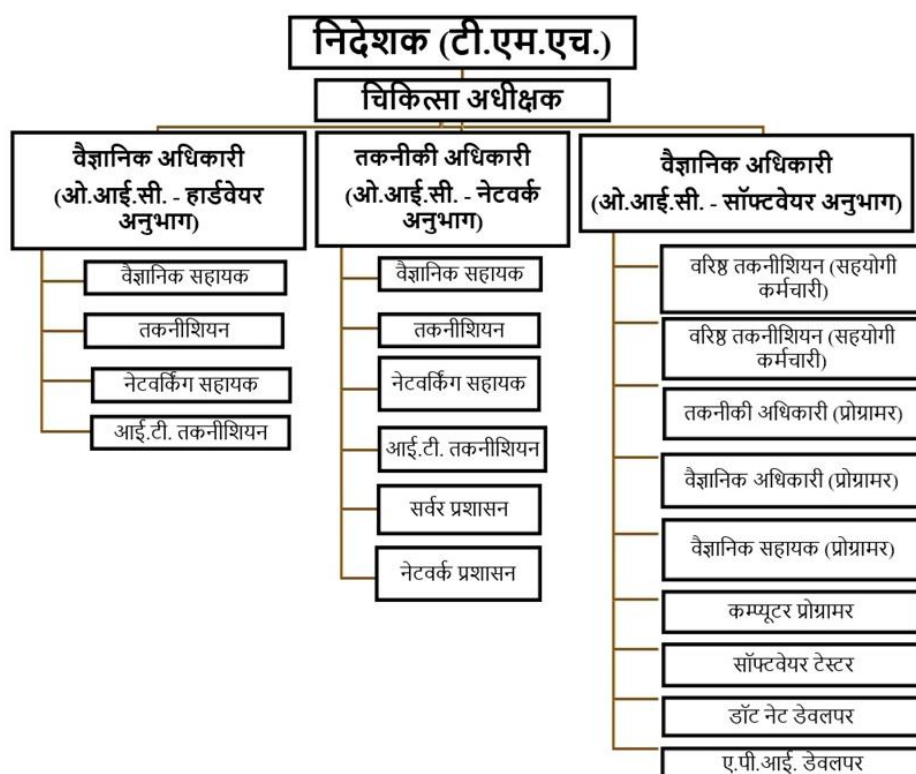
2.2.4 संगठनात्मक संरचना

केंद्र का नियंत्रण एवं दिशा-निर्देश गवर्निंग परिषद के अंतर्गत है और सभी नीतिगत मामलों पर चर्चा होती है और उन्हें शासी परिषद स्वीकृति प्रदान करती है। कॉलेजियम और अलग-अलग समितियों में प्रतिदिन के मामलों पर चर्चा होती है और उन पर निर्णय किया जाता है।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई की आई.टी. विभाग के पदानुक्रमिक संरचना का विवरण निम्न प्रकार से है:

निदेशक, टाटा मेमोरियल केंद्र	निदेशक, टाटा मेमोरियल अस्पताल
	निदेशक, शैक्षणिक
	निदेशक, कैंसर इपिडिमियोलॉजी केंद्र
	निदेशक, कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा हेतु उन्नत केंद्र
	निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, वाईजैंग
	निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, वाराणसी
	निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, संगरूर एवं मुल्लांपुर
	निदेशक, डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान गुवाहाटी
	निदेशक, होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर

चित्र 1: संगठनात्मक संरचना



चित्र 2: टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के आई.टी. विभाग की पदानुक्रमित संरचना

मुंबई के टाटा मेमोरियल केंद्र के अन्य अस्पतालों के आई.टी. विभागों का संचालन उन आई.टी. कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जो चिकित्सा अधीक्षक को रिपोर्ट करते हैं, जो आगे संबंधित अस्पतालों के निदेशकों को रिपोर्ट करते हैं।

2.2.5 टाटा मेमोरियल केंद्र के आई.टी. एप्लीकेशन

हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के अनुरूप, टाटा मेमोरियल केंद्र ने महत्वपूर्ण रोगी अभिलेखों के प्रबंधन और अस्पताल संचालन के सभी प्रशासनिक और कार्यात्मक पहलुओं को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सा अभिलेखों के संकलन के लिए कई आई.टी. एप्लीकेशन विकसित किए हैं। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बाह्यश्रोत से विकसित किया गया था और संशोधन टाटा मेमोरियल केंद्र के आई.टी. विभाग द्वारा आंतरिक रूप से किए गए थे। टाटा मेमोरियल केंद्र ने 2001 से आई.टी. सिस्टम का उपयोग शुरू किया था।

सर्वप्रथम टाटा मेमोरियल केंद्र के अंतर्गत आने वाले टाटा मेमोरियल अस्पताल ने सी.ओ.बी.ओ.एल. प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके अस्पताल सूचना प्रणाली विकसित की थी। इसके उपरांत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर डीबेस-3 प्लस और फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया। वर्तमान में, सभी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विजुअल बेसिक और नेट में विकसित किए जाते हैं।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने 35 एप्लीकेशन⁴³ को लागू किया है, जिनके अंतर्गत 146 उप- एप्लीकेशन कार्यरत हैं, जो केंद्रों की समग्र गतिविधियों के प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रदान करते हैं।

मुंबई के टाटा मेमोरियल केंद्र के सभी उप-केंद्रों में कार्यात्मक एप्लिकेशन और उप- एप्लिकेशन टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई द्वारा विकसित किए गए थे और उन्हें कार्यान्वयन के लिए अन्य केंद्रों को सौंप दिया गया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के सोर्स कोड में केंद्रीय रिपॉजिटरी में किए गए बदलाव सभी केंद्रों को सूचित किए जाते हैं और उपलब्ध होते हैं।

2.2.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आई.टी. लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आकलन करना था कि यदि:

1. आई.टी. प्रणालियाँ स्वीकृत कार्यात्मकताओं के अनुरूप लागू की गई हैं।
2. आई.टी. प्रणालियों के संचालन तथा सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त सामान्य नियंत्रण लागू किए गए, ताकि अखंडता, विश्वसनीयता, गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
3. व्यावसायिक नियमों का सही प्रकार से मानचित्रण किया गया है तथा प्रणाली में अनुप्रयोग

⁴³ 1. वित्तीय 2. संपत्ति प्रबंधन, 3. अकादमिक, 4. चैटबॉट, 5. एच.एम.आई.एस., 6. सम्मेलन, 7. डी.एल.एल., 8. दस्तावेज़ प्रबंधन, 9. दान, 10. कर्मचारी कार्ड प्रणाली, 11. कर्मचारीपोर्टल-, 12. फ़ाइल ट्रैकिंग प्रणाली, 13. गेटपास, 14. अतिथि गृह आवेदन, 15. एच.बी.सी.एच.आर.सी. मुल्तापुर वेबसाइट, 16. एच.बी.वी. वैक्सीन, 17. एच.एल.7, 18. घटना रिपोर्ट, 19. के.ई.वी.ए.टी., 20. सामग्री प्रबंधन, 21. एम.आई.एस., 22. एम.पी.क्यू.ए.पी., 23. ओ.पी.डी. आवेदन, 24. रोगी योजना प्रबंधन, 25. भुगतान गेटवे, 26. पेंशन आवेदन, 27. डाक के लिए आवेदन, 28. परियोजना पर कर्मचारी के लिए आवेदन, 29. एस.एम.एस., 30. कार्य प्रक्रिया, 31. टेलीसलाह, 32. ऊतक बैंक प्रणाली, 33. टोकन प्रणाली, 34. ट्यूमर ऊतक रिपॉजिटरी, 35. टाटा मेमोरियल अस्पताल में स्थान बुक करने के लिए आवेदन।

नियंत्रण लागू किए गए हैं।

2.2.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र और इसके अस्पतालों में कार्यरत आई.टी. एप्लिकेशन की आई.टी. लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के (कर्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। आई.टी. लेखापरीक्षा का संचालन लेखापरीक्षा और खातों पर नियम (संशोधन 2020) के अध्याय 3 के नियम 16 से 18 के तहत किया गया। लेखापरीक्षा ने नीचे उल्लेखित एप्लिकेशन की कुल प्रदर्शन और मूल्य वृद्धि की समीक्षा की।

मुंबई के टाटा मेमोरियल केंद्र का आई.टी. लेखापरीक्षा 2019-24 की अवधि को कवर करते हुए किया गया, जिसमें उन एप्लिकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया जो रोगी सेवाओं, वित्तीय मामलों और सामग्री प्रबंधन से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा के लिए चयनित एप्लिकेशन का विवरण नीचे दिया गया है:

- अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली
- ओ.पी.डी. एप्लीकेशन
- मरीज योजना प्रबंधन
- भुगतान गेटवे
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
- सामग्री प्रबंधन

निम्नलिखित पाँच अस्पतालों का चयन डेटा आकार, सर्वर के स्थान, निकटता के आधार पर किया गया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई
- एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, खारगर, नवी मुंबई

- महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर, पंजाब
- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।

2.2.8 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में ये शामिल थे:

- 12 सितंबर 2024 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, दायरे और लेखापरीक्षा पद्धति को टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के निदेशक को समझाया गया और लेखापरीक्षा के संचालन के लिए सहयोग की अपील की गई।
- प्रबंधन को पत्राचार/प्रश्नावली जारी की गई और उत्तर का विश्लेषण किया गया। अन्य दस्तावेजों के साथ स्रोत दस्तावेजों और सिस्टम रिपोर्ट की जांच की गई।
- स्रोत दस्तावेजों और प्रणाली रिपोर्टों सहित अन्य दस्तावेजों की समीक्षा।
- कंप्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीक का उपयोग करके प्रणाली से मानक और अनुकूलित रिपोर्टों का डेटा विश्लेषण।
- रोगी जानकारी से संबंधित डेटा के विश्लेषण के मामले में, तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि के लिए संबंधित अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित की गईं और उन बैठकों के मिनट तैयार किए गए।

चूंकि इन प्रणालियों में केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है, प्रत्येक पांच चयनित अस्पतालों से गैर-रोगी से संबंधित डेटा एकत्र किया गया और उसी का डेटा विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के प्रतिनिधियों और महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा, के कार्यालय के बीच 29 जुलाई 2025 को वीडियो

कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें यह चर्चा की गई कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को जून 2025 में आयोजित संयुक्त बैठक के आधार पर मसौदा रिपोर्ट में तैयार और शामिल किया गया है, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों के गोपनीय और संवेदनशील मरीज डेटा के तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र ने लेखापरीक्षा निरीक्षणों पर चर्चा की और परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त संबंधित उत्तरों को शामिल किया गया है। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र के प्रशासन ने रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की और भारत सरकार द्वारा निर्धारित आई.टी. दिशानिर्देशों और आई.टी. एप्लिकेशन के कार्यान्वयन में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में इन्हें सुधारने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.9 लेखापरीक्षा मानदंड

आई.टी. लेखापरीक्षा हेतु मानदंड मुख्य रूप से निम्न प्रकार से थे:

- सॉफ्टवेयर के विकास के समय टाटा मेमोरियल केंद्र द्वारा निर्धारित उद्देश्य।
- व्यावसायिक नियम, मैनुअल, अधिकारों का प्रतिनिधित्व और टाटा मेमोरियल केंद्र/भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ।
- आई.टी. नियंत्रण, विकास, कार्यान्वयन और सुरक्षा मानक में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास।
- सूचना प्रणाली शासन, विकास और रखरखाव के सामान्य सिद्धांत।

2.2.10 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, आई.टी. लेखापरीक्षा का संचालन करने में टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई और इसके अस्पतालों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता की सराहना करती है।

2.2.11 लेखापरीक्षा की सीमाएँ

टाटा मेमोरियल केंद्र ने मरीजों से जुड़ा डेटा लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया, और इसका कारण भारतीय मेडिकल काउंसिल विनियम, 2002 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण

अधिनियम, 2023 के तहत निजता और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बताया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा रोगी-संबंधित रिकॉर्ड पर डेटा विश्लेषण या सत्यापन नहीं कर सका। तदनुसार, इन पहलुओं पर आश्वासन प्रदान नहीं किया जा सका और लेखापरीक्षा कवरेज केवल उस जानकारी और पहुँच तक सीमित रहा जो संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

2.2.12 आई.टी. गवर्नेंस

आई.टी. गवर्नेंस एक समग्र रूपरेखा है जिसमें संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत संरचनाएं और प्रक्रियाएं और अन्य तंत्र शामिल होते हैं जो संगठन में आई.टी. संचालन का मार्गदर्शन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वर्तमान व्यापार की जरूरतों को पूरा करता है और भविष्य की जरूरतों और विकास की योजनाओं को शामिल करता है।

2.2.12.1 आई.टी. रणनीति और योजना का निर्माण न करना

आई.टी. रणनीति योजना एक पूरा नक्शा है जो यह बताता है कि संगठन के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए क्या लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियाँ हैं। आई.टी. रणनीतिक योजना यह पहचानने में मदद करती है कि संसाधनों का आवंटन अवसंरचना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या साइबरसुरक्षा किस मुख्य क्षेत्रों में होना चाहिए।

मई 2024 तक टाटा मेमोरियल केंद्र द्वारा किसी दस्तावेजीकृत आई.टी. रणनीतिक योजना या आई.टी. एप्लिकेशन प्रणाली के उन्नयन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई थी। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था और समय के साथ यह तकनीकी उन्नयन के साथ कदम मिलाने और अप्रचलन को दूर करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित हुआ। आवेदन सॉफ्टवेयर को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों और कभी-कभी चर्चाओं (मई 2024) के आधार पर संशोधन के तहत रखा गया, लेकिन टाटा मेमोरियल केंद्र ने ई-मेल की प्रतियाँ और चर्चा के मिनट प्रदान नहीं किए। टाटा मेमोरियल केंद्र के लिए आई.टी. रणनीतिक योजना मई 2024 से तैयार की जा रही

थी।

दस्तावेजीकृत आई.टी. रणनीतिक योजना की अनुपस्थिति में, टाटा मेमोरियल केंद्र के उप-केंद्र आई.टी. सुरक्षा योजना तैयार नहीं कर सकते थे और आई.टी. एप्लिकेशन में पर्याप्त नियंत्रण शामिल नहीं कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप रोगी रूपांतरण और बिलिंग प्रक्रियाओं में असंगति, दिवंगत रोगियों से संबंधित विसंगतियाँ आदि उत्पन्न हुईं। टाटा मेमोरियल केंद्र ने जून 2025 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और औपचारिक आई.टी. रणनीतिक योजना की आवश्यकता के साथ सहमति व्यक्त की।

विभाग ने (दिसंबर 2025) इस अवलोकन को स्वीकार किया और औपचारिक आई.टी. रणनीतिक योजना की आवश्यकता के साथ सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 14:

टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए आई.टी. रणनीतिक योजना तैयार की जा सकती है ताकि प्रौद्योगिकी योजना और कार्यान्वयन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

2.2.12.2 आई.टी. संचालन समितियों का गठन न होना

यह केंद्र शासी परिषद के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है। सभी नीतिगत मामलों पर शासी परिषद चर्चा करती है और उन्हें मंजूरी देती है। टाटा मेमोरियल केंद्र के सभी कर्मचारियों पर संबंधित नियमों (जो परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों पर लागू होते हैं) को किस हद तक लागू किया जाए, इस पर अंतिम फैसला टाटा मेमोरियल केंद्र की शासी परिषद⁴⁴ ही लेती है।

⁴⁴ टाटा मेमोरियल केंद्र की शासी परिषद में एक चेयरमैन होते हैं जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी होते हैं। इसके अलावा, इसमें पांच सदस्य होते हैं: दो सदस्य पदेन होते हैं, दो सदस्य सह-चयनित होते हैं, सात स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं जो टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के निदेशक (प्रशासन) होते हैं।

आई.टी. व्यवसायिक उद्यमों में बार-बार एक आई.टी. विशेषज्ञ समिति शामिल होती है, जिसमें शीर्ष और वरिष्ठ उद्यमों के सदस्य होते हैं। यह समिति आई.टी. जांच की समीक्षा करने के लिए, उन्हें मंजूरी देने और उनके लिए निधि तय करने के लिए सहायक के रूप में काम करती है।

चुने गए पाँच अस्पतालों में से तीन अस्पतालों - (1) टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई, (2) होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम और (3) होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्तापुर ने पुष्टि की कि आई.टी. एप्लीकेशन के विकास और कार्यान्वयन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी। 'कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र' ने समितियाँ तो गठित की थीं, लेकिन वे विशेष रूप से आई.टी. विकास और कार्यान्वयन के लिए नहीं थीं।

महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर केंद्र, वाराणसी ने मई 2022 में आई.टी. रणनीतिक और संचालन समिति बनाई, जो केंद्र के आई.टी. विभाग की एक आंतरिक समिति थी।

आई.टी. संचालन समिति न होने के कारण विभिन्न आई.टी. एप्लिकेशन में सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र प्रक्रिया की निगरानी का अभाव, डिजिटल अनुमोदन की अनुपस्थिति के कारण कार्यप्रवाह में अंतराल, स्टॉक में बची हुई समाप्त हो चुकी दवाएँ और खरीद संबंधी घटनाओं की तिथियों में असंगति हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि टाटा मेमोरियल केंद्र एक संस्थागत स्तर की आई.टी. शासन समिति का गठन करेगा।

अनुशंसा 15:

बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर विकास और साइबर सुरक्षा की रणनीतिक योजना के संबंध में संगठन को सौंपे गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए आई.टी.

संचालन समिति का गठन किया जा सकता है।

2.2.12.3 सुव्यवस्थित एस.डी.एल.सी. प्रक्रिया, परीक्षण वातावरण और औपचारिक गुणवत्ता आश्वासन/उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण ढांचे की कमी

सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र एक संरचित प्रक्रिया है जो सॉफ्टवेयर को प्रारंभिक अवधारणा से लेकर विकास, परिनियोजन और निरंतर रखरखाव तक निर्देशित करती है। आई.एस.ओ. 27002 नियंत्रण 8.31 डेटा लीक या अनधिकृत पहुंच जैसे सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए विकास, परीक्षण और उत्पादन वातावरण को अलग करने के महत्व पर बल देता है।

एम.ई.आई.टी.वाई. के क्लाउड-रेडी एप्लिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर विकास और पुनर्चना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जीवनचक्र पर कई मानक उपलब्ध हैं जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विकास और निरंतर सुधार की गुंजाइश सुनिश्चित करते हैं। प्रस्तावित समाधान, अन्य बातों के अलावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मानकों और अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुकूल होने चाहिए। पैरा 2.3 में कहा गया है कि किसी भी उत्पाद की एक प्रमुख आवश्यकता अन्य प्रौद्योगिकी सूटों के साथ इंटरफ़ेस करने, एकीकृत करने और उससे भी महत्वपूर्ण, अंतरसंचालनीय होने की क्षमता है। एप्लिकेशन को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि वह लचीली, मॉड्यूलर और विस्तार योग्य सेवाओं का समर्थन करे। एम.ई.आई.टी.वाई. के सुरक्षित एप्लिकेशन डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और संचालन संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 4.8 में कहा गया है कि एप्लिकेशन को सुरक्षा परीक्षण संचालित विकास (एस.डी.एल.सी.) दृष्टिकोण का उपयोग करके विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के दौरान सुरक्षा परीक्षण शामिल होता है।

क. सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र प्रक्रिया का अभाव: टाटा मेमोरियल केंद्र और इसके अस्पतालों ने किसी भी सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र का पालन नहीं किया। कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र ने बताया कि अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताएं ई-मेल

द्वारा भेजते हैं, जिन्हें आई.टी. विभाग आगे की चर्चा और उनकी आवश्यकताओं को समझने के बाद अंतिम रूप देता है। इसके बाद, एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिखाया जाता है, और सिस्टम को सीमित रूप से परीक्षण के लिए अंतिम उपयोगकर्ता को जारी किया जाता है। उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, एप्लिकेशन को उत्पादन स्तर पर जारी किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरचित सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र (एस.डी.एल.सी.) के अभाव में (क) एक्सेस प्रबंधन में खामियाँ, (ख) रोगी श्रेणी में परिवर्तन से संबंधित डेटा में विसंगतियाँ, (ग) नए बिल पोर्टल में प्रदर्शित रोगियों के बिलिंग विवरण में त्रुटियाँ और (घ) मेमो मूल्यों और संबंधित बिल राशियों में असंगति पाई गई। यह भी पाया गया कि परीक्षण वातावरण में किसी रोगी के नाम से जनरेट किया गया प्रिस्क्रिप्शन स्वचालित रूप से लाइव सर्वर पर रोगी के खाते में स्थानांतरित हो गया, जिससे पता चलता है कि एप्लिकेशन विकसित करते समय अपर्याप्त एस.डी.एल.सी. प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो एम.ई.आई.टी.वाई. और आई.एस.ओ. दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

ख. परीक्षण वातावरण का अभाव और औपचारिक गुणवत्ता आश्वासन/उपयोगकर्ता स्वीकृति

परीक्षण ढाँचे का अभाव: लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन अस्पतालों (होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम, महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर केंद्र, वाराणसी और होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर) में समर्पित परीक्षण सर्वर नहीं थे। एप्लिकेशन परीक्षण कभी-कभी सीधे लाइव सर्वरों पर किया जाता है (उदाहरण के लिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर में), जिससे उत्पादन प्रणालियाँ जोखिमों के अधीन हो जाती हैं। होमी भाभा कैंसर अस्पताल विशाखापत्तनम स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक विकास और परीक्षण टाटा मेमोरियल अस्पताल में किए जाते हैं और एक स्थानीय परीक्षण सर्वर के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (अक्टूबर 2024)। वाराणसी स्थित महामना पंडित मदनमोहन मालवीय

कैंसर केंद्र ने सूचित किया कि आपदा रिकवरी सेटअप पूरा होने के बाद ही उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण वातावरण पर विचार किया जाएगा। परीक्षण सर्वर की अनुपलब्धता के कारण, मुल्लापुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से स्थानांतरित किए गए एप्लिकेशन के परीक्षण में समस्याओं का सामना करना पड़ा और परीक्षण रोगी मामलों पर परीक्षण केवल लाइव सर्वर पर ही किया गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में औपचारिक गुणवत्ता आश्वासन और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण ढांचे की अनुपस्थिति देखी गई। टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने स्वीकार किया कि उसकी सॉफ्टवेयर विकास और परीक्षण प्रक्रियाएं अनौपचारिक थीं, जिनमें कोई दस्तावेजी परीक्षण योजना या परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम ने भी पुष्टि की कि उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट नहीं रखी जाती हैं। संरचित सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र का पालन करने के बजाय, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को अनौपचारिक रूप से (ई-मेल/बैठकों के माध्यम से) संप्रेषित किया गया, प्रोटोटाइप विकसित किए गए और उत्पादन तैनाती से पहले सीमित परीक्षण किए गए।

गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण के अभाव में, सुरक्षा संबंधी समस्याएं जैसे कि टूटे हुए एक्सेस कंट्रोल और सत्यापन नियंत्रण में विसंगतियां उत्पन्न हुईं।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि एस.डी.एल.सी. नीति को अपनाना आवश्यक है और बजटीय बाधाओं और विकास की समय-सीमा में भिन्नता के कारण, सभी स्थानों पर समर्पित परीक्षण सर्वर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। हालांकि, विभाग ने समर्पित परीक्षण/उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण वातावरण स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा कि यह प्रक्रिया में है।

अनुशंसा 16:

टाटा मेमोरियल सेंटर में सुव्यवस्थित योजना और इन-हाउस विकास, सॉफ्टवेयर के परीक्षण और तैनाती के लिए एक औपचारिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नीति को अपनाया और उसका पालन किया जा सकता है, साथ ही डेटा सुरक्षा के लिए परीक्षण वातावरण और लाइव सर्वर का उचित पृथक्करण भी किया जा सकता है।

अनुशंसा 17:

जोखिमों को कम करने के लिए, एक मानक सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के तहत एक औपचारिक गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण ढांचा लागू किया जा सकता है।

2.2.12.4 आउटसोर्स कर्मचारियों की अप्रतिबंधित पहुंच

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र में लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिकाओं से संबंधित जिम्मेदारियों और विशेषाधिकारों को आधिकारिक रूप से किसी नामित कर्मचारी को सौंपा नहीं गया था। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर विकास, सॉफ्टवेयर परीक्षण और सर्वर एवं नेटवर्क प्रशासन जैसी गतिविधियाँ आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा बिना किसी लिखित विशेषाधिकार नीति के की जा रही थीं। विभाग (दिसंबर 2025) ने कहा कि टाटा मेमोरियल अस्पताल को गैर-खुलासा समझौतों पर हस्ताक्षर करने और बाह्यश्रोत किए गए कर्मचारियों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक नीति लागू करनी होगी।

2.2.12.5 डेटा प्रतिधारण नीति का निर्माण न करना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संरक्षण योग्य ई-रिकॉर्ड उत्पादन संबंधी दिशानिर्देश के पैरा 6.3 के अनुसार, संबंधित विभागों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए लागू प्रतिधारण, निपटान और पहुंच नीति/नियमों को परिभाषित और अधिसूचित करना होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

- संरक्षण के लिए जिन प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सहेज कर रखना चाहिए,
- ई-रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए,
- ई-रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देशों में उन कानूनी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना आवश्यक है, सुरक्षित रखने की अवधि समाप्त होने के बाद ई-रिकॉर्ड्स के निपटान की प्रक्रिया, वर्तमान ई-सिस्टम में रहने वाले ई-रिकॉर्ड्स की सूची और उनकी अवधि।

डेटा प्रतिधारण नीति के निर्माण के संदर्भ में, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (फरवरी 2025 में) स्वीकार किया कि कोई लिखित नीति मौजूद नहीं थी।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अनुरूप एक व्यापक डेटा प्रतिधारण और अभिलेखीय नीति पर काम किया जाएगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार एक नीति तैयार करेगा।

अनुशंसा 18:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक डेटा संरक्षण और अभिलेखीय नीति को यथाशीघ्र तैयार किया जा सकता है।

2.2.12.6 आई.टी. एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अभाव

सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश सॉफ्टवेयर की कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

टाटा मेमोरियल केंद्र के आई.टी. एप्लीकेशन के लेखापरीक्षा के दौरान, संगठन ने 95

एप्लिकेशन/उप-एप्लिकेशन की एक सूची प्रस्तुत की, जिनके सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, टाटा मेमोरियल केंद्र ने 16 एप्लिकेशन/उप-एप्लिकेशन की एक सूची भी प्रस्तुत की, जिनमें एप्लिकेशन के गो-लाइव होने और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश प्रस्तुत करने की तिथियों के बीच एक से 12 वर्ष का अंतर था। इस प्रकार, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास के काफी समय बाद सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेजों की तैयारी से सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में गिरावट, बग की संख्या में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विस्तार का जोखिम बढ़ गया।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र ने विकसित किए जा रहे नए एप्लिकेशन के साथ-साथ मौजूदा एप्लिकेशन के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अनुशंसा 19:

किसी भी सॉफ्टवेयर को परिनियोजन से पहले सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश, तकनीकी विनिर्देश और उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार करना अनिवार्य हो सकता है।

2.2.13 सामान्य नियंत्रण और सुरक्षा

सूचना सुरक्षा नियंत्रण बहुमूल्य सूचना संपत्तियों की सुरक्षा, अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। इन नियंत्रणों को कुछ व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि पहुंच नियंत्रण, एन्क्रिप्शन, फ़ायरवॉल और मैलवेयर सुरक्षा।

2.2.13.1 आई.टी. सुरक्षा नीति का निर्माण न करना

आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 27001:2022(ई) का खंड 5.2 सूचना सुरक्षा नीति स्थापित करने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। यह अनिवार्य करता है कि शीर्ष प्रबंधन एक दस्तावेजित

नीति विकसित करे जो संगठन के उद्देश्य के अनुरूप हो, लक्ष्य-उन्मुख हो, अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध हो और निरंतर सुधार पर केंद्रित हो।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने अपने सिस्टम की प्रारंभिक तैनाती के दौरान कोई औपचारिक आई.टी. सुरक्षा नीति विकसित नहीं की, जिसके कारण संगठन साइबर खतरों के प्रति असुरक्षित हो गया। समय के साथ, शासन और नियंत्रण तंत्र में यह कमी तब स्पष्ट हो गई जब संगठन को तीन अलग-अलग साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने मार्च 2025 तक कोई सूचना सुरक्षा नीति तैयार नहीं की है। इससे संगठन को नीति तैयार करने में देरी और अधिक सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ा। एप्लिकेशन की सुरक्षा जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं।

टूटा हुआ पहुँच नियंत्रण: यह एक सुरक्षा खामी है जो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को उन डेटा तक पहुँचने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति देती है जिन तक उन्हें पहुँच नहीं होनी चाहिए।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए केवल परीक्षण वातावरण तक ही पहुँच प्रदान की, क्योंकि लाइव सर्वर केवल पढ़ने की अनुमति (रीड-ओनली एक्सेस) का समर्थन नहीं करता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे संगठन के इंटरनेट एप्लिकेशन तक केवल परीक्षण सर्वर यू.आर.एल. के माध्यम से ही पहुँचें, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाइव सर्वर तक कोई सीधी पहुँच प्रदान न की जाए।

हालांकि, मॉनिटर टेस्ट सर्वर तक पहुँचने के लिए दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एक विशिष्ट एप्लिकेशन में लॉग इन कर सकते थे। एप्लिकेशन के यू.आर.एल. में एक साधारण बदलाव से उसी एप्लिकेशन के लाइव सर्वर तक पहुँच प्राप्त हो गई। इससे पता चलता है कि सिस्टम में उचित एक्सेस कंट्रोल तंत्र का अभाव था, जो विभिन्न वातावरणों के बीच अपर्याप्त अलगाव को उजागर करता है।

इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन में एक और गंभीर खामी मौजूद थी; यू.आर.एल. में मेमो नंबर को बदलकर रोगी के मेमो और बिलिंग रिकॉर्ड तक आसानी से पहुँचा जा सकता था।

निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने मई/जून 2025 में कहा कि वह आवेदनों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और पूरे संगठन में सुरक्षा शासन को संस्थागत रूप देने के लिए एक औपचारिक आई.टी. सुरक्षा नीति के महत्व को स्वीकार किया।

अनुशंसा 20:

संगठन के उद्देश्य के अनुरूप आई.टी. सुरक्षा नीति तैयार की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नीति उद्देश्य-उन्मुख, अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध और निरंतर सुधार पर केंद्रित है।

क. अशक्त यूजर पंजीकरण एवं पंजीकरण रद्द करने के नियंत्रण

उपयोगकर्ता पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पहुंच अधिकार उचित रूप से प्रदान किए जाएं और जब उनकी आवश्यकता न हो या किसी व्यक्ति की भूमिका बदल जाए तो उन्हें रद्द कर दिया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टाटा मेमोरियल केंद्र ने उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई लिखित नीति नहीं बनाई थी। टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई और होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च केंद्र, मुल्लनपुर, उपयोगकर्ता पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए विभागीय ई-मेल पर निर्भर थे, लेकिन औपचारिक नीति के अभाव से प्रशासनिक खामियां पैदा हुईं और कर्मचारियों के रिकॉर्ड की सटीकता पर चिंताएं उत्पन्न हुईं।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 36 कर्मचारियों के रिकॉर्ड एक जैसे थे, जिनमें नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सभी समान थीं और सभी में अप्रैल 2016 में सेवानिवृत्ति दर्शाई गई थी। इसके अलावा, रिकॉर्ड अपूर्ण थे, क्योंकि इन कर्मचारियों के पूरे नाम कर्मचारी मास्टर डेटाबेस में मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद, 2024 में इन निष्क्रिय खातों के तहत कुछ लेनदेन किए गए।

इससे यह संकेत मिलता है कि निष्क्रिय उपयोगकर्ता खातों का अनुचित उपयोग लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, जिससे डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने बताया कि समान व्यक्तिगत विवरण वाले कर्मचारी कोड निष्क्रिय कर दिए गए हैं और उक्त लेन-देन के लिए उपयोग की गई आई.डी. वास्तव में रोग प्रबंधन समूह कोड हैं, न कि कर्मचारी कोड। इस जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि रोग प्रबंधन समूह मास्टर में छह अंकों के संख्यात्मक कोड नहीं होते हैं, जो इंटरनेट पोर्टल तक पहुँचने के लिए आवश्यक हैं।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि टाटा मेमोरियल केंद्र द्वारा आवेदन में सत्यापन को संशोधित करने की संभावना तलाशी जाएगी ताकि नियमित रोग प्रबंधन समूह कोड प्रारूप का उपयोग किया जा सके।

ख. अनियमित यूजर आई.डी. प्रैक्टिसेस

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई और उसके अस्पतालों में, इंटरनेट पोर्टल तक पहुँचने के लिए मानक छह-अंकीय संख्यात्मक उपयोगकर्ता आई.डी. आवंटित की गई थीं। हालाँकि, रोगी संबंधी कार्य, प्रवेश/निकास संबंधी कार्य, बी.पी. योजना कार्य, बिलिंग कार्य, चिकित्सा कार्यालय संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को उचित

अनुमोदन या लेखापरीक्षा ट्रेल के बिना छह-अंकीय संख्यात्मक उपयोगकर्ता आई.डी. प्रारूप से हटकर वर्णानुक्रमिक/अल्फा-संख्यात्मक आई.डी. आवंटित की गई थीं।

विचलन के बारे में पूछताछ करने पर, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (मार्च 2025) बताया कि अल्फा-न्यूमेरिक उपयोगकर्ता आई.डी. का उपयोग मेडिकल सोशल वर्क विभाग द्वारा तीसरे पक्ष के कर्मचारियों द्वारा रोगी योजना प्रबंधन के संचालन के लिए शुरू किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में इसके समर्थन में कोई दस्तावेज़ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, अनियमित उपयोगकर्ता आई.डी. में इस बारे में विशिष्ट विवरण नहीं थे कि किसने इसे अधिकृत या बनाया था, जिससे जवाबदेही के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं और उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करना या दुरुपयोग के मामले में ज़िम्मेदारी सौंपना मुश्किल हो गया।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन प्रक्रिया में है। इसने आगे बताया कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ता आई.डी. की समीक्षा चल रही है।

विभाग ने (दिसंबर 2025) कहा कि बाह्यश्रोत कर्मचारियों को पहले स्थायी कर्मचारियों से अलग करने के लिए अल्फा-न्यूमेरिक कंप्यूटर कोड नंबर आवंटित किए जा रहे थे। इसमें आगे कहा गया है कि सभी टाटा मेमोरियल केंद्र इकाइयों में अल्फा-न्यूमेरिक आई.डी. को धीरे-धीरे समाप्त करने की योजना है।

2.2.13.2 अशक्त कमजोर पासवर्ड नियंत्रण और अपर्याप्त प्रमाणीकरण तंत्र

अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए मजबूत पासवर्ड नीतियाँ और बहु-कारक प्रमाणीकरण आवश्यक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जटिल पासवर्ड (कम से कम 8 अक्षर, केस, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण, अनुमानित पैटर्न से बचना) अनिवार्य करता है।

क. पासवर्ड नियंत्रणों का अभाव: लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण मिले जहाँ उपयोगकर्ताओं ने अपनी

उपयोगकर्ता आई.डी. को पासवर्ड के रूप में सेट किया था। फ्रंटएंड एप्लिकेशन ने पहले साइन-इन पर डिफॉल्ट पासवर्ड के रूप में कंप्यूटर कोड (सी.सी. नंबर) के उपयोग का सुझाव देने वाले संकेत भी प्रदर्शित किए। हालाँकि उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड बदलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन अनिवार्य पहली बार रीसेट को लागू करने का कोई तंत्र नहीं था। इसके अलावा, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और गैर-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली एप्लिकेशन के लिए पासवर्ड परिवर्तन इतिहास बनाए नहीं रखा गया था, जिसमें नए पासवर्ड पुराने पासवर्ड को ओवरराइट कर देते थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पासवर्ड निर्माण मानक कमजोर थे, जिनमें विशेष वर्णों के साथ आवश्यक न्यूनतम आठ-अक्षर वाले अल्फान्यूमेरिक प्रारूप का अभाव था। कैंसर में उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र ने यह भी बताया कि स्मार्ट कार्ड पिन पंजीकरण वर्ष और रोगी केस संख्या के आधार पर एक अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं, जिससे वे अनधिकृत पहुँच के लिए उजागर होते हैं।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (मई 2025 में) जोखिमों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि कर्मचारियों को उपयोग में आसानी के लिए लचीलापन दिया गया था और एक आई.एस.एम.एस.-अनुरूप मजबूत पासवर्ड नीति को लागू किया जा रहा था।

एक अन्य चिंता पासवर्ड की समय सीमा समाप्त होने की नीति का अभाव था, जो समझौता किए गए क्रेडेंशियल्स को अनिश्चित काल तक सक्रिय रहने की अनुमति देता है, जिससे लगातार उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वेब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स (वेब ई.एम.आर.) में मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया गया था, जबकि अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और अन्य एप्लिकेशन में इस नियंत्रण का अभाव था।

ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए, टाटा मेमोरियल केंद्र को सुरक्षा को मजबूत करने के

लिए सभी प्रणालियों में जटिल पासवर्ड, आवधिक समाप्ति, इतिहास ट्रैकिंग और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करना होगा।

ख. इयूटी के घंटों के बाद सिस्टम का एक्सेस: उपयोगकर्ताओं के उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि कुछ यादृच्छिक तिथियों पर उपयोगकर्ताओं के आने-जाने का समय उसी दिन रोगियों के श्रेणी रूपांतरण से संबंधित लेनदेन समय से मेल नहीं खाता था। जांच किए गए मामलों का विवरण *तालिका 17* में दिया गया है।

तालिका 17: टेस्ट चेक केस का विवरण

यूजर आई.डी.	तिथि	उपस्थिति पंजिका के अनुसार दिनों की स्थिति		ट्रांज़ैक्शन की तिथि	ट्रांज़ैक्शन का समय (घंटों में)
		समय पर (घंटों में)	समय पर (घंटों में)		
651587	20.3.2024	06:56	15:22	21.3.2024	02:06
	21.3.2024	06:56	15:17		
	27.2.2023	20:57	07:07	28.2.2023	22:16
	28.2.2023	साप्ताहिक अवकाश के दिन अनुपस्थित			
	1.3.2023	06:08	15:38		
690525	17.5.2024	सप्ताहांत के दौरान अनुपस्थित		18.5.2024	00:00
	18.5.2024	12:40	21:02		

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों ने प्रशिक्षु होने के कारण, नए भर्ती हुए कर्मचारियों के साथ यूजर आई.डी. साझा की थी, जिनके पास सभी अधिकार नहीं थे। इस प्रकार, मरीजों के लिए यूजर आई.डी. उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा साझा की गई थी।

उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल साझा करने से जवाबदेही कम हो जाती है, त्रुटियों, दुरुपयोग और नियमों का पालन न करने का जोखिम बढ़ जाता है, जबकि कमजोर आई.टी. सुरक्षा उपाय ऐसी गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहते हैं। बार-बार साइबर हमलों और 2021 के भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण की सिफारिश के बावजूद, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने एक मजबूत पासवर्ड नीति लागू नहीं की है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप पासवर्ड नीति अपनाई जाएगी, जिससे एम.ई.आई.टी.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार पासवर्ड की जटिलता, अनिवार्य आवधिक परिवर्तन और पासवर्ड इतिहास ट्रैकिंग को लागू किया जा सके। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र अपने उपयोगकर्ताओं को लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने के खतरों के बारे में भी जागरूक करेगा।

2.2.13.3 आवधिक सुरक्षा लेखापरीक्षा का संचालन न करना

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सी.ई.आर.टी.-आई.एन.) द्वारा प्रकाशित वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि वेबसाइट को उत्पादन वातावरण में होस्ट करने से पहले कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा सूचीबद्ध विक्रेता से सुरक्षा लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा क्लियरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रत्येक छह महीने में या स्रोत कोड में किसी भी परिवर्तन के होने पर किया जाना चाहिए।

आज के निरंतर साइबर खतरों के माहौल में, भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वी.ए.पी.टी.) महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संवेदनशील डेटा का प्रबंधन करने वाली सरकारी एजेंसियों के लिए, क्योंकि यह सक्रिय रूप से जोखिमों का पता लगाता है और उल्लंघनों को रोकता है।

विभाग ने पाया कि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने मार्च 2019 में केवल एक साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा और अप्रैल 2021 में एक भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण किया था। तब से, इसके अस्पतालों या एप्लिकेशन के लिए कोई नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा या आवधिक भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण या सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं किया गया है। निरंतर निगरानी की इस कमी से सिस्टम की गलत कॉन्फिगरेशन या कमजोरियों का पता न चलने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे महत्वपूर्ण अस्पताल प्रणालियाँ साइबर हमलों के लिए असुरक्षित हो जाती हैं, जैसा कि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के अंतर्गत तीन इकाइयों द्वारा पहले ही अनुभव किया

जा चुका है।

विभाग (दिसंबर 2025) इस अवलोकन से सहमत हुआ और कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने सी.ई.आर.टी.-आई.एन. पैनल में शामिल भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण लेखापरीक्षा एजेंसी को नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2.2.13.4 व्यावसायिक निरंतरता और आपदा से उबरने की क्षमता

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 17.10.2000 की अधिसूचना के नियम 19(2) में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुच्छेद 26(1) में कहा गया है कि आपदा निवारण योजनाएं विकसित की जानी चाहिए, उनका उचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सूचना प्रणाली की विफलता या सुविधा के नष्ट होने की स्थिति में आवश्यक स्तर की सेवा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार, अनुच्छेद 24(2) में कहा गया है कि व्यावसायिक निरंतरता योजना विकसित की जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उपकरणों की आपातकालीन व्यवस्था और सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रक्रियाएं शामिल हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लंबे समय से स्थापित आई.टी. सिस्टम के बावजूद, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई और इसके अस्पतालों में अक्टूबर 2024 तक कोई औपचारिक बिजनेस कंटीन्यूटी प्लान/डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी नहीं थी। अक्टूबर 2024 में एक प्लान तैयार किया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। नमूना लिए गए पांच अस्पतालों में से केवल टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई और कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर, नवी मुंबई में ही डिजास्टर रिकवरी सेटअप थे, फिर भी दोनों एक-दूसरे के सर्वरों पर निर्भर थे, जो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। यह व्यवस्था जियो-रिडंडेंसी मानकों को पूरा नहीं कर सकती थी, जिससे दोनों साइटें क्षेत्रीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाती थीं।

इसके अलावा, दोनों अस्पतालों में आपदा राहत अभ्यास आयोजित नहीं किए गए। आपदा राहत

अभ्यास, जिनमें बैकअप बहाली अभ्यास भी शामिल हैं, तैयारियों का परीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि वास्तविक आपात स्थितियों के दौरान राहत प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से कार्य करें।

विभाग ने (दिसंबर 2025) मौजूदा आपदा रिकवरी सेटअप में भौगोलिक अतिरेक की कमी को नोट किया और टाटा मेमोरियल केंद्र की सभी इकाइयों में आपदा रिकवरी अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है।

2.2.13.5 मास्टर डेटा प्रबंधन

मास्टर डेटा प्रबंधन का उद्देश्य आवश्यक डेटा संस्थाओं, जैसे ग्राहकों, उत्पादों, कार्मिकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के लिए एक एकल, सटीक और विश्वसनीय स्रोत स्थापित करना है। इसकी सटीकता, निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर डेटा प्रबंधन रणनीति लागू की जाती है।

क. रोगी अभिलेखों में कर्मचारी डेटा का दुरुपयोग

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर के रोगी मास्टर टेबल में कर्मचारियों के रिकॉर्ड गलत तरीके से दर्ज किए गए थे। एक जांच में पाया गया कि रोगी श्रेणी 'एस' और रोगी प्रकार 'एस.एस.' नए कर्मचारियों की पूर्व-रोजगार चिकित्सा जांच के लिए निर्धारित थे। हालांकि, होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लापुर ने मार्च 2025 तक इस श्रेणी को आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया था, जबकि रिकॉर्ड जुलाई 2021 से इसके उपयोग को दर्शाते हैं। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली में श्रेणी 'एस' के लिए कोई औपचारिक मास्टर प्रविष्टि मौजूद नहीं थी।

इस अभ्यास के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई और अस्पताल के आंकड़ों की रिपोर्टिंग गलत हुई। उचित वर्गीकरण के अभाव से डेटा की सत्यता प्रभावित होती है और विश्लेषण विकृत हो जाता है, जिससे डेटा में हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य

प्रणाली के अभिलेखों की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) मास्टर रिकॉर्ड के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक मास्टर डेटा प्रबंधन प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।

ख. गैर-मानक रोगी श्रेणियाँ

लेखापरीक्षा में मुल्तापुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में मरीजों के वर्गीकरण में अनियमितताएं पाई गईं। मरीज के मास्टर रिकॉर्ड में 'टी' श्रेणी के तहत 881 प्रविष्टियां दर्ज थीं, जिन्हें अस्पताल ने 'सी प्लस' श्रेणी के मरीज बताया था और जिन्हें अधिक छूट मिल रही थी।

हालांकि, मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र ने स्पष्ट किया कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.) श्रेणी के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है। एक ही उद्देश्य के लिए 'बी.पी.' और 'टी'⁴⁵ दोनों श्रेणियों का एक साथ मौजूद होना मानकीकरण की कमी और कमजोर मास्टर डेटा प्रबंधन को दर्शाता है।

अन्य विसंगतियों में स्वीकृत श्रेणियों के अतिरिक्त अमान्य रोगी प्रकार 'I' और '-' का अस्तित्व शामिल था।

विभाग ने इस मुद्दे को स्वीकार किया (दिसंबर 2025) और कहा कि डेटा को साफ करने की आवश्यकता है और अनुमोदन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

2.2.13.6 साइबर हमले और संवेदनशील डेटा की भेद्यता

सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण-सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-आवश्यकताएं (अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 27001, तीसरा संस्करण, 2022-10) के पैरा 1 में

⁴⁵ सी-सामान्य श्रेणी, बी.पी.-गरीबी रेखा से नीचे, टी और आई-गैर-विशिष्ट श्रेणी।

अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया गया है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सूचना की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को संरक्षित करती है।

अप्रैल 2022 में, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई.सी.टी.) ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य निर्धारित किए, जिनमें शामिल हैं: क) साइबर घटनाओं से संबंधित जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, ख) साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया कि कोई भी सेवा प्रदाता, मध्यस्थ, डेटा केंद्र, निगमित निकाय और सरकारी संगठन साइबर घटनाओं की सूचना मिलने या सूचना प्राप्त होने के छह घंटे के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को इसकी अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट की गई घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर, सुरक्षा प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि संगठनों की घटनाओं का तुरंत पता लगाने और उन्हें कम करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

टाटा मेमोरियल केंद्र और इसके उप-केंद्र लाखों मरीजों से संबंधित बड़ी संख्या में संवेदनशील चिकित्सा रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें उनके केस आई.डी., नाम, पते, निदान और संपूर्ण उपचार विवरण शामिल हैं।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने सितंबर 2022 में यह जानकारी प्रसारित की थी कि रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है और लक्षित सिस्टम पर विभिन्न फाइलों को एन्क्रिप्ट करके या सिस्टम की स्क्रीन को लॉक करके, जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वैध उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम को अनुपयोगी बना देता है। इसके अलावा, टीम ने सभी सिस्टम पर नवीनतम पैच तैनात करके सिस्टम को सुरक्षित बनाने की सिफारिश की थी।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने अक्टूबर 2022 में पासवर्ड प्रबंधन और सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुशंसाओं को प्रकाशित किया। पासवर्ड प्रबंधन मजबूत पासवर्ड नीतियों

और बहु-कारक प्रमाणीकरण का संयोजन है, जिसका उद्देश्य फिशिंग, क्रेडेंशियल लीक या अनधिकृत पहुंच हमलों से होने वाले नुकसान को कम करना है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपनी पासवर्ड नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि ऐसे पासवर्ड चुने जाएं जो अनुमान लगाने में कठिन हों लेकिन याद रखने में आसान हों।

जांच से पता चला कि टाटा मेमोरियल केंद्र के उप-केंद्रों, अर्थात् होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम, कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर, नवी मुंबई और होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र, मुल्लांपुर, ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की अवधि के दौरान तीन साइबर हमलों का सामना किया, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क. सिस्टम पर नवीनतम पैच लागू न होने के कारण संवेदनशील डेटा की सुरक्षा न होना

15 अक्टूबर 2022 को, विशाखापत्तनम स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र की आई.टी. टीम ने पाया कि आई.टी. सिस्टम रैंसमवेयर मैलवेयर की चपेट में आ गए थे और सर्वर का सारा डेटा नष्ट हो गया था तथा कुछ क्लाइंट मशीनें बुरी तरह प्रभावित हुई थीं।

केंद्र की सिमेंटेक टीम की एंडपॉइंट प्रोटेक्शन सपोर्ट टीम ने 16 अक्टूबर 2022 को निरीक्षण किया और सुझाव दिया कि सभी डेटा मिटाकर पूरे सर्वर को फिर से बनाया जाए, क्योंकि इसमें रैंसमवेयर हटाने का कोई टूल या सुरक्षा उत्पाद नहीं था जो रैंसमवेयर द्वारा एन्क्रिप्ट की गई फाइलों को डिक्रिप्ट कर सके। केंद्र की आई.टी. टीम ने बैकअप बेस सर्वर को फॉर्मेट किया, उसमें नवीनतम सुरक्षा पैच इंस्टॉल किए और उन्हें प्रोडक्शन के लिए अपडेट किया।

केंद्र ने घटना की सूचना विशाखापत्तनम स्थित साइबर अपराध विभाग को दी और घटना

के दो दिन बाद 18 अक्टूबर 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई। केंद्र ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई.सी.टी.) को घटना की जानकारी मिलने के पांच दिन बाद 20 अक्टूबर 2022 को सूचित किया, जबकि घटना की सूचना छह घंटे के भीतर दी जानी थी। हालांकि, साइबर हमले के माध्यम से एन्क्रिप्ट किए गए डेटा की मात्रा और उसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्र भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के निर्देशों का पालन नहीं कर सका, जैसे कि सिस्टम पर नवीनतम पैच की तैनाती, घटना की समय पर रिपोर्टिंग और यद्यपि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने रैंसमवेयर मैलवेयर हमले के बारे में काफी पहले (सितंबर 2022) चेतावनी दी थी, फिर भी केंद्र अपने संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने और आई.टी. सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने में सक्षम नहीं था।

ख. लीक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अनधिकृत एडमिन लॉगइन करना

नवी मुंबई स्थित कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर की वेबसाइट लिनक्स प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई है और इसमें डुपल (वी.8) कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है।

जांच से पता चला कि लीक हुए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अनधिकृत वेबसाइट एडमिन लॉगिन के कारण एक साइबर सुरक्षा घटना घटी और 10 नवंबर 2023 को वेबसाइट विकृत पाई गई। सिस्टम लॉग से पता चला कि 10 नवंबर 2023 को 04:03:03 बजे इंडोनेशिया के आई.पी. एड्रेस (36.68.221.214) से हमलावर द्वारा सफलतापूर्वक एडमिन लॉगिन किया गया था।

यह वेबसाइट अहमदाबाद स्थित कंपनी सिल्वरटच टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित और अनुरक्षित की गई थी। इसका दैनिक संचालन डुपल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रदान

किए गए एडमिन इंटरफेस के माध्यम से किया जाता था, जो इंटरनेट पर उपलब्ध था और इसमें केवल उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के आधार पर सिंगल-फैक्टर ऑथेंटिकेशन था। एडमिन खाते का पासवर्ड सरल और आसानी से अनुमान लगाने योग्य था। कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर के प्रशासक कार्यालय के निजी कंप्यूटर के साथ-साथ घर के लैपटॉप और निजी मोबाइल फोन से भी वेबसाइट अपडेट के लिए इंटरफेस का उपयोग करते थे।

पहचाने गए सिस्टम को नेटवर्क से अलग कर दिया गया। कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर की वेबसाइट पर हुई छेड़छाड़ की सूचना उसी दिन शाम 19:07 बजे भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को दी गई। सिफारिश पर, वेबसाइट के एडमिन इंटरफेस को इंटरनेट से ब्लॉक कर दिया गया। एडमिन पासवर्ड को बदलकर उसे और अधिक जटिल बना दिया गया।

सच्चाई यह है कि केंद्र ने घटना की जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को साइबर घटना की सूचना नहीं दी। एडमिन खाते के लिए निर्धारित पासवर्ड और केवल एकल-कारक प्रमाणीकरण वाला इंटरफेस निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

ग. साइबर हैकर द्वारा प्राप्त संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करने में असमर्थता

2 दिसंबर 2024 को, पंजाब के न्यू चंडीगढ़ स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को एक घटना (इंटरलॉक रैंसमवेयर) का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और उनकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप संदेश दिखाई दे रहा था: *"डेटा सुरक्षा संकट। आपके संगठन का सबसे महत्वपूर्ण डेटा खतरे में है, नेटवर्क में घुसपैठ हो गई है, फाइलें एन्क्रिप्ट हो गई हैं और अत्यंत संवेदनशील जानकारी प्राप्त हो गई है। आपके व्यवसाय के लिए विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक*

हैं।”

आई.टी. विभाग ने उसी दिन स्थानीय अधिकारियों और कंप्यूटर एवं सूचना सुरक्षा सलाहकार समूह (सी.आई.एस.ए.जी.) की टीम को इस मामले की जानकारी दी। 12 दिसंबर 2024 तक, लगभग 95 प्रतिशत आई.टी. सेवाएं बहाल कर दी गई थीं और अस्पताल के आई.टी. बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से चालू करने के लिए शेष पांच प्रतिशत सेवाओं को बहाल किया जाना बाकी था।

पूछे जाने पर केंद्र ने कहा कि मूल कारण विश्लेषण नहीं किया गया था और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निवारक उपाय अभी तक नहीं किए गए।

सितंबर 2022 में रैंसमवेयर मैलवेयर हमले के बारे में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा अग्रिम चेतावनी दिए जाने के बावजूद, साइबर हमले के पीछे का वास्तविक कारण पता नहीं चल सका।

केंद्र द्वारा मूल कारण विश्लेषण शुरू न किए जाने के कारण इसकी पहचान की गई। उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हुए, टाटा मेमोरियल केंद्र ने जून 2025 में कहा कि आंतरिक प्रतिक्रिया समय और मूल कारण विश्लेषण प्रोटोकॉल में सुधार की आवश्यकता है और यह भी कहा कि मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सहित उचित सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं।

विभाग ने (दिसंबर 2025) इन टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि टीमों को सर्ट-इन द्वारा सूचित किए जाने पर नवीनतम पैच अपडेट करने के लिए जागरूक किया गया है। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि प्रत्येक टाटा मेमोरियल केंद्र इकाई में आई.टी. सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी.आई.एस.ओ.) और उप-सी.आई.एस.ओ. को नियुक्त किया गया है।

अनुशंसा 21:

फिशिंग, क्रेडेंशियल्स लीक या अनधिकृत एक्सेस हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को शामिल करते हुए एक मजबूत पासवर्ड प्रबंधन नीति लागू की जा सकती है। नवीनतम सुरक्षा पैच आई.टी. सिस्टम पर स्थापित किए जा सकते हैं और साइबर हमलों को रोकने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आई.टी. सुरक्षा प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी की जा सकती है।

2.2.13.7 आगजनी की घटना

डेटा केंद्र आई.टी. संचालन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जहां छोटी-मोटी घटनाएं भी गंभीर व्यवधान पैदा कर सकती हैं। आग लगना विशेष रूप से विनाशकारी जोखिम पैदा करता है, जिससे सेवा बाधित हो सकती है, डेटा का नुकसान हो सकता है और भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रभावी अग्नि सुरक्षा उपाय व्यावसायिक निरंतरता के लिए आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि जून 2024 में वाराणसी के होमी भाभा कैंसर अस्पताल के आई.टी. सर्वर रूम में आग लग गई थी। घटना का कारण ए.सी. यूनिट का फटना था। हालांकि नियंत्रण कक्ष में अग्नि अलार्म प्रणाली सक्रिय हो गई थी, लेकिन इससे आग का शीघ्र पता नहीं चल सका। आग से ₹1.91 करोड़ के आई.टी. उपकरणों को नुकसान पहुंचा, लेकिन डेटा हानि के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।

जांच में कई तकनीकी खामियां पाई गईं, जैसे कि (1) ए.सी. संचालन के लिए कोई मानकीकृत प्रक्रिया नहीं, (2) तापमान पहचान इकाइयों का अभाव, (3) गलत अलर्ट से बचने के लिए फायर अलार्म निष्क्रिय, (4) घटनाओं के क्रम को कैप्चर करने के लिए सर्वर रूम में सी.सी.टी.वी. नहीं।

जांच में अन्य बातों के अलावा, बैकअप सेवाओं के साथ आपदा रिकवरी सेटअप स्थापित करने और इन प्रणालियों के आंतरिक और बाहरी लेखापरीक्षण करने की सिफारिश की गई।

इस घटना ने डेटा केंद्र और आपदा तैयारियों में मौजूद गंभीर कमियों को उजागर किया है। प्रारंभिक पहचान प्रणालियों की कमी और आपदा रिकवरी अवसंरचना के अभाव ने महत्वपूर्ण आई.टी. संपत्तियों को अत्यधिक असुरक्षित बना दिया है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि आग लगने की घटना के बाद, एचबीसीएच वाराणसी ने भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न पहल कीं और सभी प्रभावित उपकरणों को एक व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत कवर किया गया, जिसके कारण उपकरणों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बरामद किया गया।

हालांकि, मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र और इसके अन्य केंद्रों में आग लगने की स्थिति में शीघ्र पता लगाने के साथ-साथ आग की घटनाओं के कारण हुए डेटा नुकसान के संबंध में कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं दी गई।

2.2.13.8 डेटा संरक्षण और क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा की कमी

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड के मूल (प्लेनटेक्स्ट) संस्करण, साथ ही रोगियों के आधार कार्ड नंबर, संबंधित डेटा टेबल में उनके एन्क्रिप्टेड संस्करणों के साथ संग्रहीत थे। इसका अर्थ यह था कि एन्क्रिप्शन लागू होने के बावजूद, सिस्टम ने डेटाबेस में इन संवेदनशील डेटा तत्वों के अनएन्क्रिप्टेड (पठनीय) संस्करणों को भी सुरक्षित रखा था।

प्लेनटेक्स्ट पासवर्ड और आधार नंबर को उनके एन्क्रिप्टेड समकक्षों के साथ एक ही स्थान पर संग्रहीत करने से एन्क्रिप्शन का उद्देश्य विफल हो जाता है, क्योंकि यह संवेदनशील डेटा के अनधिकृत प्रकटीकरण को नहीं रोकता है।

उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केवल पासवर्ड और आधार नंबर के एन्क्रिप्टेड संस्करणों

को ही संग्रहीत किया जाना चाहिए, जबकि प्लेनटेक्स्ट डेटा को उचित सुरक्षा व्यवस्था वाले एक अलग सर्वर पर संग्रहीत किया जाना चाहिए।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

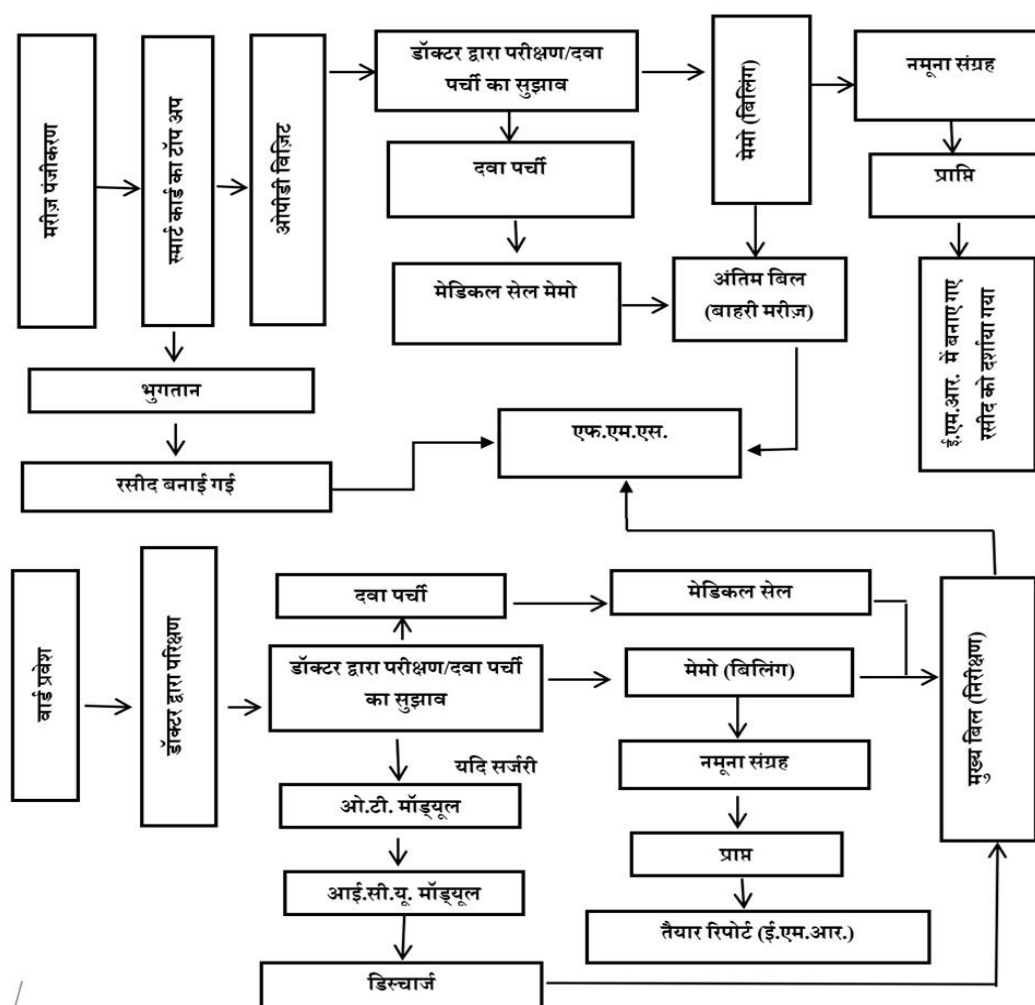
2.2.14 व्यावसायिक नियमों का मानचित्रण और एप्लिकेशन नियंत्रणों का कार्यान्वयन

आंतरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि संगठन के संसाधनों के उपयोग सहित सभी संचालन प्रभावी और कुशल हों, आंतरिक और बाह्य उपयोग के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग विश्वसनीय हो और लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया जाए। प्रत्येक आई.टी. एप्लिकेशन के लिए विशिष्ट एप्लिकेशन नियंत्रण, एप्लिकेशन के चलने के दौरान लेनदेन और डेटा की पूर्णता, सटीकता, वैधता, गोपनीयता और उपलब्धता को नियंत्रित करते हैं।

2.2.14.1 अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

टाटा मेमोरियल अस्पताल में आने वाले मरीजों का सबसे पहले पंजीकरण कराया जाता है, जिसमें उन्हें सभी आवश्यक विवरण जमा करने होते हैं ताकि उन्हें एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या - 'केस नंबर' - प्राप्त हो सके। इसके बाद मरीजों को क्लिनिक जाने की सलाह दी जाती है, जहाँ उनके पंजीकरण विवरण देखे जाते हैं और उनका चिकित्सा इतिहास दर्ज किया जाता है। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र में मरीज के पंजीकरण से लेकर बाह्य रोगी के अंतिम बिल तैयार होने तक की पूरी प्रक्रिया को नीचे दिए गए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यप्रवाह में दर्शाया गया है। इस कार्यप्रवाह में मरीजों के प्रवेश से संबंधित विवरण भी शामिल हैं।

चित्र 3 में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट दिखाया गया है।



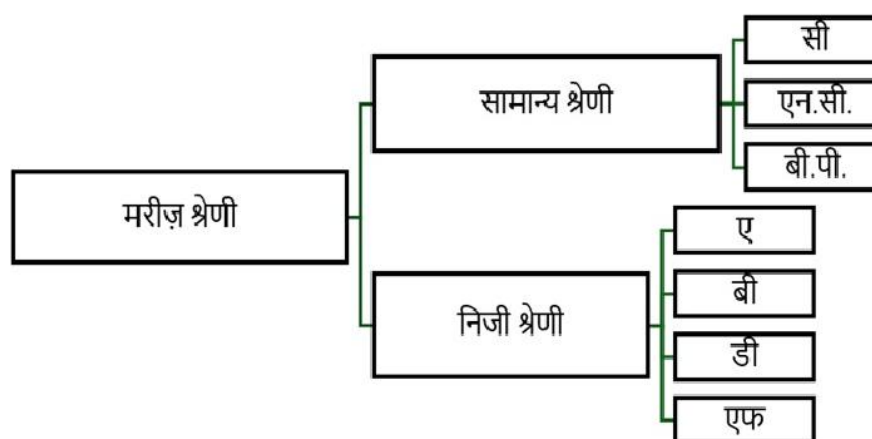
चित्र 3: अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यप्रवाह

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लेखापरीक्षा से रोगी पंजीकरण और रोगी प्रवेश के तहत समूहीकृत निम्नलिखित अवलोकन सामने आए।

क. रोगी पंजीकरण

मरीजों से अनुरोध किया जाता है कि वे पंजीकरण के लिए अस्पताल आते समय अपना और अपने जीवनसाथी या माता-पिता का आधार कार्ड साथ लाएं। रोगी पंजीकरण रोगी प्रवेश बिलिंग और पंजीकरण एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है। रोगी प्रवेश बिलिंग और पंजीकरण एक वेब-आधारित रोगी पंजीकरण, प्रवेश और डिस्चार्ज मॉड्यूल है। मरीजों को

किसी भी बिस्तर पर भर्ती किया जाता है ताकि उन्हें भर्ती मरीजों के रूप में दिखाया जा सके। रोगी का पंजीकरण किया जाता है और चित्र⁴⁶ 4 में दी गई श्रेणी के अनुसार रोगी को एक श्रेणी सौंपी जाती है।



चित्र 4: मरीज़ श्रेणी

चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के बाद, कर्मचारी अंतिम बिल तैयार करते हैं और मरीजों को सिस्टम में डिस्चार्ज के रूप में दर्ज किया जाता है। डी.आई.एस. एक रोगी निदान सूचना प्रणाली है जिसमें रोगी के केस प्रणाली है जिसमें मरीज के केस नंबर के आधार पर अनुरोध पत्र और मेमो तैयार किए जाते हैं। अनुरोध पत्र और मेमो तैयार होने के बाद, नमूनों को संबंधित प्रयोगशालाओं में प्रसंस्करण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा जा सकता है। बाह्य रोगी विभाग या भर्ती वार्ड से परामर्श के बाद, डॉक्टर मरीजों को बिक्री काउंटर (फार्मसी) से दवा लेने के लिए एक पर्ची जारी कर सकते हैं। फार्मसी बाह्य रोगी विभाग और वार्ड से जारी पर्ची के आधार पर दवाएं जारी करती है। डिस्चार्ज मॉड्यूल डॉक्टरों को डिस्चार्ज सारांश तैयार करने में मदद करता है।

⁴⁶ सी, एन.सी. - सामान्य श्रेणी के मरीज, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.) योजना श्रेणी के मरीज। सी और बी.पी. श्रेणी के मरीजों से शुल्क अनुसूची में दिए गए सी श्रेणी के शुल्कों के अनुसार और एन.सी. श्रेणी के मरीजों से शुल्क अनुसूची में दिए गए एन.सी. श्रेणी के शुल्कों के अनुसार लिया जाता है। सभी को सामान्य श्रेणी के वार्ड में भर्ती किया जाता है।

ए (निजी), बी (अर्ध-निजी), डी (डीलक्स) और एफ (विदेशी) निजी श्रेणी के मरीज हैं। ए, बी, डी और एफ श्रेणी के मरीजों के लिए सेवाओं का भुगतान शुल्क अनुसूची में दिए गए ए, बी, डी और एफ श्रेणी के शुल्कों के अनुसार किया जाता है। सभी को निजी श्रेणी के वार्ड में भर्ती किया जाता है।

i. पंजीकृत रोगियों के लिए अनिवार्य विशिष्ट पहचानकर्ता का अभाव

सटीक चिकित्सा रिकॉर्ड सुनिश्चित करने और दोहराव, गलत पहचान और उपचार संबंधी त्रुटियों को रोकने के लिए विशिष्ट रोगी पहचानकर्ता महत्वपूर्ण हैं।

जांच से पता चला कि रोगी पंजीकरण के मामले में, सिस्टम में कोई अनिवार्य डेटा फ़ील्ड परिभाषित नहीं किया गया था, जो एक ही रोगी के लिए दोहरे पंजीकरण संख्या बनने से रोकने के लिए विशिष्टता स्थापित करने हेतु प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सिस्टम में आधार फ़ील्ड के संबंध में दर्ज किए गए डेटा की सत्यता को सत्यापित करने की कोई कार्यक्षमता नहीं थी।

मई 2025 में, मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-माइलस्टोन 1 के कार्यान्वयन के साथ आधार सत्यापन सक्षम किया जाएगा। इसके अलावा, जून 2025 में, टाटा मेमोरियल केंद्र ने यह भी बताया कि टाटा मेमोरियल अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-माइलस्टोन 1 का एकीकरण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही सभी इकाइयों में सभी रोगियों के लिए विशिष्ट रोगी पहचानकर्ता के रूप में विस्तारित किया जाएगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

ii. एक ही रोगी के लिए कई पंजीकरण संख्याएँ उत्पन्न होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र में, सिस्टम एक विशिष्ट संख्या जनरेट करता है जिसे पंजीकरण संख्या कहा जाता है और यह कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। सिस्टम में प्रत्येक रोगी को ट्रैक करने के लिए यह संख्या आवंटित की जाती है।

मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल और मुल्तापुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में क्रमशः 13 और 9 मरीजों के आंकड़ों की जांच से पता चला कि एक विशेष मरीज

के नाम पर एक विशेष दिन में कई पंजीकरण संख्याएं मौजूद थीं।

हालांकि, समस्या यह है कि मरीजों के एक ही पंजीकरण की प्रतिलिपि और कई पंजीकरण संख्याएँ सिस्टम डेटाबेस पर एक ही मरीज से संबंधित कई बिखरे हुए रिकॉर्ड के जमा होने जैसे जोखिम पैदा करती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी प्राप्त करने में बाधा आती है और निदान या उपचार में त्रुटियाँ हो सकती हैं।

इस संबंध में, टाटा मेमोरियल केंद्र ने स्पष्ट किया (मई/जून 2025) कि पंजीकरण के प्रकार (अर्थात, निवारक, रेफरल, टेलीकंसल्टेशन, आदि) के आधार पर रोगियों को कई बार पंजीकृत किया जा सकता है। एक ही प्रकार के पंजीकरण के मामले में, मोबाइल नंबर के लिए डुप्लिकेट पैरामीटर होने पर अलर्ट करने के लिए सिस्टम में एक जाँच होती है। उत्तर इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करता है कि सिस्टम में एक अद्वितीय पहचानकर्ता की जाँच के अभाव में, यह पहचानना संभव नहीं होगा कि रोगी पहले से पंजीकृत है या नहीं। इसके अलावा, यह किसी विशेष दिन एक ही रोगी के कई पंजीकरणों का पता नहीं लगाएगा या उन्हें रोकेगा नहीं।

विभाग ने (दिसंबर 2025) लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ माइलस्टोन 1 एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान डुप्लिकेट आधार नंबर की जाँच की गई है।

अनुशंसा 22:

सिस्टम में एक अंतर्निहित जांच शामिल की जा सकती है जो पंजीकरण के समय जमा किए जाने वाले रोगी पहचान दस्तावेज का पूर्ण सत्यापन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकरण नया है और उसी रोगी के लिए दोहराया नहीं गया है।

iii. विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में आधार एवं पैन के समुचित एवं व्यापक सत्यापन का अभाव

आधार और पैन को विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में मान्य करने के लिए व्यापक सत्यापन का अभाव सटीक चिकित्सा रिकॉर्ड सुनिश्चित करने और दोहराव, गलत पहचान और उपचार संबंधी त्रुटियों को रोकने के लिए विशिष्ट रोगी पहचानकर्ता महत्वपूर्ण हैं।

जांच से पता चला कि रोगी पंजीकरण के मामले में, आधार कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं था। सत्यापन केवल वेब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पोर्टल में वाक्य संरचना की जांच (वेरहोएफ़⁴⁷ एल्गोरिदम का उपयोग करके) तक ही सीमित था, डेटा की सटीकता की पुष्टि नहीं की गई थी।

इसके अलावा, सिस्टम ने कई मरीजों के लिए एक ही आधार/पैन नंबर को दोहराने की अनुमति दी और आधार फ़ील्ड में अमान्य या यादृच्छिक मान (जैसे, ".", "00000000000", "NIL") स्वीकार किए गए। ऐसे मामले भी सामने आए जहां विदेशी नागरिकों के आधार नंबर दर्ज किए गए, जिससे डेटा की वैधता पर सवाल उठे।

जून 2025 में टाटा मेमोरियल केंद्र ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-माइलस्टोन 1 का एकीकरण टाटा मेमोरियल अस्पताल में पूरा हो गया है और आधार सत्यापन जल्द ही सक्षम किया जाएगा और सभी इकाइयों में सभी रोगियों के लिए विशिष्ट रोगी पहचानकर्ता के रूप में विस्तारित किया जाएगा।

iv. इनपुट नियंत्रण की कमी के कारण गलत डेटा दर्ज होना

- रोगी के नाम वाले फ़ील्ड में इनपुट सत्यापन संबंधी समस्याएँ: कैंसर के उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र में, रोगी प्रवेश बिलिंग और पंजीकरण

⁴⁷ आधार नंबर में 12 डिजिट होते हैं, जिनमें से 11 डिजिट खास तौर पर बनाए जाते हैं और आखिरी डिजिट चेकसम होता है। वर्होफ़ एल्गोरिदम एक चेकसम एल्गोरिदम है जो इनपुट नंबर के आधार पर चेकसम डिजिट कैलकुलेट करता है और उसकी तुलना पहले से तय वैल्यू से करता है। यह चेकसम कैलकुलेट करता है और आधार नंबर के आखिरी डिजिट से मैच करता है।

प्रणाली रोगी के नाम वाले फ़ील्ड में अंक दर्ज करने की अनुमति देती है।

- **मरीज की जानकारी में अप्रतिबंधित संशोधन:** टाटा मेमोरियल केंद्र में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सिस्टम केस आई.डी. के अंतर्गत आने वाली सभी मरीज की जानकारी में संशोधन की अनुमति देता है, जिसमें नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर शामिल हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया के लिए कोई अनुमोदन दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा, रोगी की जानकारी में किए गए परिवर्तनों के इतिहास को ट्रैक करने या दर्ज करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने अपने जवाब में (जून 2025 में) कहा कि सिस्टम ने इसकी अनुमति दी थी, क्योंकि मरीज की जानकारी में विभिन्न क्षेत्रों में संशोधन की वास्तविक आवश्यकता थी। सिस्टम में किसी भी संशोधन के लिए क्षेत्रों का लॉग रखा जाता था (जैसे, देश, राज्य, स्थायी मोबाइल नंबर, आदि)। हालांकि, बेहतर ट्रेसबिलिटी के लिए, वे सभी क्षेत्रों के लिए लॉग रखने का प्रावधान शामिल करेंगे।

डेटा सत्यापन और सिस्टम की कार्यक्षमता में ये कमियां डेटा की अखंडता, रोगी की गोपनीयता और गंभीर स्थितियों में कुशल संचार के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि आवश्यक प्रक्रियागत परिवर्तन किए जाएंगे और सत्यापन के साथ-साथ लॉग रखरखाव को भी सिस्टम में शामिल किया जाएगा।

अनुशंसा 23:

रोगी के मास्टर डेटा में संशोधन को अधिकृत करने के लिए एक उचित अनुमोदन चैनल स्थापित किया जा सकता है और किए गए ऐसे परिवर्तनों का एक लॉग बनाए

रखा जा सकता है।

v. विदेशी रोगी के पते की जानकारी भरते समय अनियंत्रित जाँच

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के रोगी प्रवेश बिलिंग और पंजीकरण से संबंधित इंटरफेस की जांच से पता चला कि विदेशी रोगियों के संबंध में रोगी विवरण, जैसे कि पत्राचार पता, परिजनों का विवरण, उस राज्य/जिले के नाम पर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी जो उस देश का हिस्सा नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि उपर्युक्त त्रुटि तब हो सकती है जब ड्रॉपडाउन मेनू से चुने गए किसी विशेष देश के राज्य/जिले के नामों में कोई चेक इनपुट मौजूद न हो और उन्हें मैन्युअल रूप से दर्ज किया गया हो।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन पर ध्यान दिया और कहा कि आवेदन में आवश्यक सत्यापन शामिल किए जाएंगे।

अनुशंसा 24:

राज्य/जिले के नामों के संबंध में मास्टर डेटा तालिका को विशेष रूप से एक देश से जोड़ा जा सकता है और सिस्टम में एक निगरानी जांच शामिल की जा सकती है।

vi. मरीज़ प्रबंधन समूहों के चयन के लिए सत्यापन नियंत्रणों का अभाव

पंजीकरण पृष्ठ में रोग प्रबंधन समूहों के सही चयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सत्यापन नियंत्रणों का अभाव है। लेखापरीक्षा ने रोग प्रबंधन समूहों के इनपुट नियंत्रण के सिस्टम सत्यापन की जाँच के लिए चार परीक्षण रोगी पंजीकरण बनाए, जिनमें से दो टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में और दो कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर में थे। हालांकि, यह देखा गया कि वयस्क रोग प्रबंधन समूह नाबालिग रोगियों को और बाल रोग प्रबंधन समूह वयस्क रोगियों को आवंटित किए जा सकते हैं।

इस खामी से पता चलता है कि आयु मानदंड के आधार पर रोगियों को उचित रोग प्रबंधन समूह आवंटित करने के लिए सिस्टम में सत्यापन इनपुट नियंत्रण का अभाव है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन पर ध्यान दिया और कहा कि आवेदन में आवश्यक सत्यापन शामिल किए जाएंगे।

अनुशंसा 25:

रोग प्रबंधन समूहों का आवंटन रोगी की आयु के साथ उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है और उक्त नियंत्रण को प्रणाली में शामिल किया जा सकता है।

vii. अपलोड किए बिना यादृच्छिक मरीज़ की तस्वीरें प्रदर्शित

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान, लेखापरीक्षा टीम ने टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई और कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर, नवी मुंबई के टेस्ट सर्वर पर कुल 17 टेस्ट मरीज़ों के केस बनाए, लेकिन निर्धारित फ़ील्ड में कोई फ़ोटो अपलोड नहीं की। हालांकि, इन केसों को सफलतापूर्वक बनाने और रजिस्टर करने के बाद, सिस्टम ने खाली फ़ोटो फ़ील्ड के बजाय बेतरतीब फ़ोटो प्रदर्शित कीं। यह विसंगति सिस्टम के डेटा हैंडलिंग और डिस्प्ले तंत्र में एक महत्वपूर्ण खामी को उजागर करती है।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने इस विसंगति को स्वीकार किया और कहा (जून 2025) कि यह घटना परीक्षण वातावरण के निर्माण से संबंधित कुछ समस्या के कारण हुई, जिसके कारण लाइव सर्वर पर एक ही पंजीकरण संख्या की तस्वीरें परीक्षण सर्वर पर केस नंबरों के सामने प्रदर्शित हुईं।

इस जवाब में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि सिस्टम में नए मरीज़ों के पंजीकरण के दौरान कुछ यादृच्छिक तस्वीरें अपलोड की गई थीं, जिससे गलत जानकारी मिली। सिस्टम में आवश्यक नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए ताकि पहले से अपलोड की

गई कोई भी यादृच्छिक तस्वीर नए मरीजों के पंजीकरण से मेल न खाए।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन पर ध्यान दिया और कहा एप्लीकेशन में आवश्यक सत्यापन शामिल किए जाएंगे।

viii. रोगी रूपांतरण और बिलिंग प्रक्रियाओं में विसंगतियां

मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में रोगी रूपांतरण और बिलिंग प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि रोगियों को नकद भुगतान करने वाले रोगियों से कंपनी द्वारा रेफर किए गए रोगियों की श्रेणी में बिना किसी विशिष्ट कंपनी को अनिवार्य रूप से सौंपे ही परिवर्तित कर दिया गया था, जिससे उपचार लागत अस्थायी रूप से किसी भी जिम्मेदार भुगतानकर्ता से संबंधित नहीं रह गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि रोगियों को पहले नकद भुगतान करने वाले रोगियों की श्रेणी में वापस लाया गया और फिर कंपनी द्वारा रेफर किए गए रोगियों की श्रेणी में पुनः डाल दिया गया, जिससे बिल और रसीदों की स्थिति अनिश्चित बनी रही। एक मामले में, एक रोगी को कंपनी द्वारा रेफर किए गए रोगियों की श्रेणी में तो परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन उसे कभी किसी कंपनी से नहीं जोड़ा गया, फिर भी रसीदों पर कंपनी का टैग लगा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप विसंगतियां और राजस्व आवंटन पर सवाल उठे।

जिस अवधि में मरीज किसी कंपनी से संबद्ध नहीं था, उस दौरान प्रदान की गई सेवाओं और दवाओं की रसीदों को बाद में अंततः नियुक्त की गई कंपनी से जोड़ दिया गया। हालांकि, उस दौरान मरीज को प्राप्त राशि के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई थी।

एक अन्य मामले में, एक मरीज को नकद भुगतान करने वाले मरीज से कंपनी द्वारा रेफर किए गए मरीज के रूप में परिवर्तित किया गया, लेकिन उसे कभी किसी विशिष्ट कंपनी को सौंपा नहीं गया। इसके बावजूद, कुछ मरीजों की रसीदें एक कंपनी से जुड़ी हुई थीं, जिससे बिलिंग रिकॉर्ड में विसंगतियां उत्पन्न हुईं।

इस प्रकार, मरीजों को नकद भुगतान करने वाले मरीजों से कंपनी द्वारा रेफर किए गए मरीजों की श्रेणी में बदलने की क्षमता, बिना किसी विशिष्ट कंपनी को अनिवार्य रूप से सौंपे जाने के कारण के कारण उपचार लागत अस्थायी रूप से किसी भी उत्तरदायी भुगतानकर्ता से अलग हो गई है। वर्तमान प्रक्रिया डिज़ाइन लागू करने योग्य प्रणालीगत नियंत्रणों के बिना रोगी की स्थिति को बदलने की अनुमति देता है, जिससे भुगतानकर्ता वर्गीकरण में हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है और एक गंभीर शासन संबंधी जोखिम उत्पन्न होता है, क्योंकि यह भुगतान दायित्वों को जानबूझकर या अनजाने में टालने या उनसे बचने का रास्ता खोलता है।

जून 2025 में, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने पुष्टि की कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को छोड़कर, किसी मरीज को कंपनी-रेफर किए गए मरीज की श्रेणी में परिवर्तित करते समय सिस्टम के तहत एक कंपनी को असाइन करना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया कि मरीज को कंपनी-रेफर किए गए मरीज से नकद भुगतान करने वाले मरीज में परिवर्तित करने से पहले बिल तैयार किए जाते हैं और कंपनी के नाम से मेमो टैग किए जाते हैं। हालांकि, लॉग, प्राधिकरण रिकॉर्ड और अनुमोदन संबंधी रिकॉर्ड के अभाव में, सही कंपनी असाइनमेंट या सटीक रसीद आवंटन को सत्यापित करना संभव नहीं है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के रोगियों को कंपनी का नाम आवंटित न करना एक सोची-समझी योजना थी और यह स्वीकृत नीति से विचलन नहीं था, टाटा मेमोरियल केंद्र गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के रोगियों के लिए कंपनी के नाम शामिल करने के लिए एक डिजाइन परिवर्तन करने पर विचार करेगा।

ix. विदेशी मरीजों के पंजीकरण में कमजोर आंतरिक नियंत्रण-वीजा सत्यापन का अभाव

पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सिस्टम ने डुप्लिकेट वीजा नंबर या समाप्त हो चुके वीजा

(जो देश में अवैध रूप से रहने का संकेत देते हैं) के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया, जिससे विदेशी रोगियों की उचित पहचान को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। समाप्त हो चुके वीजा को चिह्नित भी नहीं किया गया, जिससे अस्पताल के लिए कानूनी और नियामक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सिस्टम ने परिचारकों के वैध वीजा की जानकारी दर्ज किए बिना ही रोगियों के पंजीकरण की अनुमति दे दी, जो रोगियों के साथ आने वाले परिचारकों के लिए अनिवार्य चिकित्सा वीजा की आवश्यकता का उल्लंघन है।

इस अवलोकन को स्वीकार करते हुए, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) कहा कि मरीजों और उनके परिचारकों के लिए वीजा संख्या और वीजा समाप्ति तिथि के लिए प्रविष्टि फ़ील्ड मार्च 2023 से सिस्टम में उपलब्ध हैं। हालांकि, डुप्लिकेट या समाप्त हो चुके वीजा को प्रतिबंधित करने के लिए सत्यापन जांच को सिस्टम में शामिल किया जाएगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

ख. रोगी प्रवेश

i. मृत रोगियों से संबंधित विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा में पांच अस्पतालों में मृत मरीजों के रिकॉर्ड के प्रबंधन में नियंत्रण संबंधी कमियां सामने आईं। एक मामले में, दान प्राप्त होने के हफ्तों बाद मरीज के नाम पर दवाएं जारी की गईं।

तालिका 18: मृत मरीजों से संबंधित विसंगतियों का विवरण

मृत्यु की तारीख	दान प्राप्त	प्रिस्क्रिप्शन जारी किया गया	दवा जारी की गई
18.8.2023	13.9.2023	13.9.2023	13.9.2023

एक समीक्षा में पाया गया कि मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में 484 मृत रोगियों से कुल ₹0.37 करोड़ की सेवाओं के लिए बिल लिया गया था, जिसमें व्यक्तिगत बिलों की

राशि ₹0.03 करोड़ से ₹0.05 करोड़ तक थी, जिसमें लिपिड प्रोफाइल परीक्षण, विभिन्न ग्रेड की सर्जरी, प्रमुख और मामूली ऑपरेशन थिएटर प्रक्रियाएं, अल्ट्रासोनोग्राफी शामिल थीं और कुछ सेवाएं मृत्यु के दो से तीन साल बाद तक दर्ज की गईं।

तालिका 19: मरीजों की मृत्यु के बाद के रिकॉर्ड

अस्पताल का नाम	मृत्यु के बाद सेवाएँ प्रदान किए गए मृत मरीजों की संख्या	कुल मेमो संख्या*	कुल मेमो राशि (₹ में)	किसी विशेष मरीज के लिए मृत्यु तिथि और मृत्यु के पश्चात जारी किए गए मेमो की तिथि के बीच अधिकतम अंतर (दिनों में)
टी.एम.एच.	341	2051	2970844	1165
ए.सी.टी.आर.ई.सी.	4	4	2545	9
एम.पी.एम.एम.सी.सी. वाराणसी	100	109	47564	391
एच.बी.सी.एच.आर.सी. वाईजाग	37	81	577993	819**
एच.बी.सी.एच.आर.सी. मुल्लानपुर	2	91	121870	335
कुल	484	2336	3720816	-

*रद्द किए गए मेमो, नकद प्रतिपूर्ति/अंतिम निपटान की सेवाओं वाले मेमो, विविध अस्पताल शुल्क, चिकित्सा देखभाल टीम शुल्क (प्रति दिन) और डुप्लिकेट बिल प्रिंटिंग (प्रति बिल) के लिए शुल्क को छोड़कर।

**सेवा राशि शून्य है।

आगे के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई, कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र इन कैंसर, नवी मुंबई और होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च केंद्र, विशाखापत्तनम के 145 मृत रोगियों के नाम विभिन्न ट्रस्टों, निधियों या संगठनों से कुल ₹0.44 करोड़ के दान दर्ज किए गए थे, जहां व्यक्तिगत रोगी के लिए जमा राशि ₹100 से ₹0.14 करोड़ तक है, यहां तक कि मृत्यु के तीन साल से अधिक समय बाद भी।

लेखापरीक्षा में चिकित्सा अभिलेखों में विसंगतियां पाई गईं, जिनमें निम्नलिखित दो अलग-अलग मामले शामिल हैं जहां रोगी की स्थिति, महत्वपूर्ण संकेत, उपचार योजना और

डॉक्टर की सलाह जैसे नैदानिक आकलन रोगियों की मृत्यु के बाद दर्ज किए गए थे। यह गलत डेटा प्रविष्टि या अपर्याप्त सिस्टम सत्यापन नियंत्रणों को इंगित करता है, जो रोगी अभिलेखों की सटीकता और विश्वसनीयता में कमजोरियों को उजागर करता है।

तालिका 20: चिकित्सा प्रविष्टियों में विसंगतियां

मरीजों की संख्या	मृत्यु की तिथि	टिप्पणियां
मरीज ए	14.12.2021	मई 2022 में मरीज का मूल्यांकन किया गया और डॉक्टर की कुछ सलाह दर्ज की गई।
मरीज बी	29.8.2021	मरीज का क्लिनिकल मूल्यांकन 2.9.2021 को बी.पी. और कुछ उपचार सलाह/योजना जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ दर्ज किया गया था।

इस प्रकार, यह प्रणाली मृत रोगियों के लिए बिलिंग, दान स्वीकार करने, नुस्खे जारी करने और नैदानिक रिकॉर्ड दर्ज करने की अनुमति देती है। इसका कारण तीन प्रमुख कमियाँ थीं: (i) मृत्यु की स्थिति को अद्यतन करने में देरी, (ii) मृत्यु के बाद की प्रविष्टियों को रोकने के लिए स्वचालित सत्यापन या अवरोधक तंत्र का अभाव, और (iii) ऐसी प्रविष्टियों को ट्रैक और अधिकृत करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल का अभाव।

हालांकि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025 में) दावा किया कि इस तरह की बिलिंग को रोकने के लिए सिस्टम चेक मौजूद हैं, फिर भी मरीजों को मृत घोषित करने में देरी होती रही, खासकर उन लोगों के मामले में जिनकी मृत्यु अस्पताल के बाहर होती है।

इस जवाब को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि ऐसे मामले भी मौजूद हैं जहां मरीज की मृत्यु की तारीख के बाद सेवाएं प्रदान की गई थीं, जबकि मरीज की मृत्यु अस्पताल के भीतर ही हुई थी।

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र ने स्वीकार किया कि कुछ मृत्युोत्तर प्रविष्टियाँ वैध कारणों से होती हैं, लेकिन उन्होंने अनुमोदनों के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा रिकॉर्ड की

कमी को भी स्वीकार किया। उन्होंने नियंत्रणों को मजबूत करने, मृत्योत्तर प्रविष्टियों को चिह्नित करने और अनधिकृत दान को रोकने पर सहमति व्यक्त की। ये निष्कर्ष बिलिंग, रोगी डेटा प्रबंधन और निगरानी में गंभीर कमियों को उजागर करते हैं, जिससे वित्तीय कुप्रबंधन और संसाधनों के दुरुपयोग का खतरा पैदा होता है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और कहा कि सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता रोकने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू किए जाएंगे।

इन निष्कर्षों से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली में स्वचालित सुरक्षा उपायों की कमी का पता चला, जिससे डेटा की अखंडता, वित्तीय जवाबदेही और रोगी चिकित्सा अभिलेखों की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है।

ii. छूट या आस्थगित भुगतान प्रक्रिया में विसंगति

रोगी प्रवेश बिलिंग और पंजीकरण एप्लिकेशन के अंतर्गत, भर्ती मरीजों के अंतिम बिलों पर छूट/भुगतान स्थगन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच, 257 छूट के मामले (₹0.10 करोड़) और 296 स्थगन भुगतान के मामले (₹1.31 करोड़) दर्ज किए गए। चिंताजनक रूप से, उचित अनुमोदन चैनल के अभाव में, 257 में से 251 छूट अनुमोदन एक ही चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिए गए, जिसमें अक्सर 100 प्रतिशत तक बिल माफ़ी की अनुमति दी गई, जबकि इसके लिए अनिवार्य प्रावधान न होने के कारण सिस्टम में पर्याप्त औचित्य दर्ज नहीं किया गया। इसी प्रकार, 288 स्थगन भुगतान मामलों की सिफारिश और स्वीकृति भी उसी प्राधिकरण द्वारा की गई, जिससे सिस्टम द्वारा लागू जांच के बिना नियंत्रण का केंद्रीकरण उजागर होता है। दो स्थगन मामलों को अनधिकृत कर्मियों द्वारा स्वीकृत किया गया और छह मामलों को न तो स्वीकृत किया गया और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई, और कोई भुगतान वसूल

नहीं किया गया।

इसके अलावा, सिस्टम विलंबित भुगतानों की वसूली को स्वचालित रूप से चिह्नित या ट्रैक करने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.38 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सका। सिस्टम में अलर्ट, अनुमोदन प्रक्रिया या वसूली निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति सिस्टम डिज़ाइन में एक गंभीर खामी को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी नागरिकों को छूट/स्थगन लाभों का विस्तार करने से अनुपालन संबंधी और भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से वित्तीय रियायतों के लिए व्यवस्थित लेखापरीक्षा लॉग या कारण-कैप्चर फ़िल्ड की अनुपस्थिति में।

इस संबंध में, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने कहा कि वह इन मामलों के लिए एक तंत्र बनाएगा और चिकित्सा अधीक्षक और लेखा टीम द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, एम.एस. कार्यालय के परामर्श से इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि आवेदन में कोई भी बदलाव किया जा सके और छूट/स्थगन के कारणों को सिस्टम में दर्ज किया जा सके।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, सिस्टम को भूमिका-आधारित प्राधिकरण लागू करना होगा, औचित्य फ़िल्ड अनिवार्य करना होगा, डिजिटल लेखापरीक्षा ट्रेल बनाए रखना होगा और विलंबित भुगतान वसूली के लिए अनुवर्ती ट्रैकिंग के साथ स्वचालित अलर्ट लागू करना होगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

2.2.14.2 ओ.पी.डी. अपॉइंटमेंट

बाह्य रोगी विभाग अस्पताल और रोगी के बीच संपर्क का पहला बिंदु होता है, जहां रोगियों को निदान या उपचार प्राप्त होता है लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

क. मृत घोषित किए जा चुके अस्पताल से छुट्टी पा चुके रोगियों के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना

इस सिस्टम के ज़रिए उन मरीज़ों के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक किए जा सकते थे जिन्हें डिस्चार्ज के समय मृत घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, एप्लिकेशन की जाँच करने पर पता चला कि टाटा मेमोरियल केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार मृत घोषित किए गए मरीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी सिस्टम चेक-इन, डॉक्टर से संपर्क, परामर्श और चेक-आउट जैसी सभी प्रक्रियाओं की अनुमति देता है। इसलिए, मेडिकल प्रक्रियाओं को शुरू करने से पहले मरीज़ की जीवित स्थिति की जाँच करने का काम उनके अपने सिस्टम में नहीं किया गया था।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 26:

सिस्टम चेक इस तरह से विकसित किए जा सकते हैं कि वे उन रोगियों की पहचान कर सकें जिन्हें पहले मृत घोषित किया जा चुका है।

ख. पूर्वव्यापी समय के साथ उसी दिन की नियुक्ति

लेखापरीक्षा के दौरान, टाटा मेमोरियल केंद्र के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एप्लिकेशन में परीक्षण डेटा से पता चला कि सिस्टम उसी दिन पहले से बुक किए गए अपॉइंटमेंट के समय से पहले अपॉइंटमेंट का समय आवंटित करने की अनुमति देता है। इससे मरीज़ों के विजिट रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है या सिस्टम का दुरुपयोग हो सकता है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 27:

वर्तमान समय बीत जाने के बाद बीते हुए समय के स्लॉट का चयन रोकने के लिए एक सत्यापन प्रणाली होनी चाहिए।

ग. परामर्श के बाद अपॉइंटमेंट रद्द करना

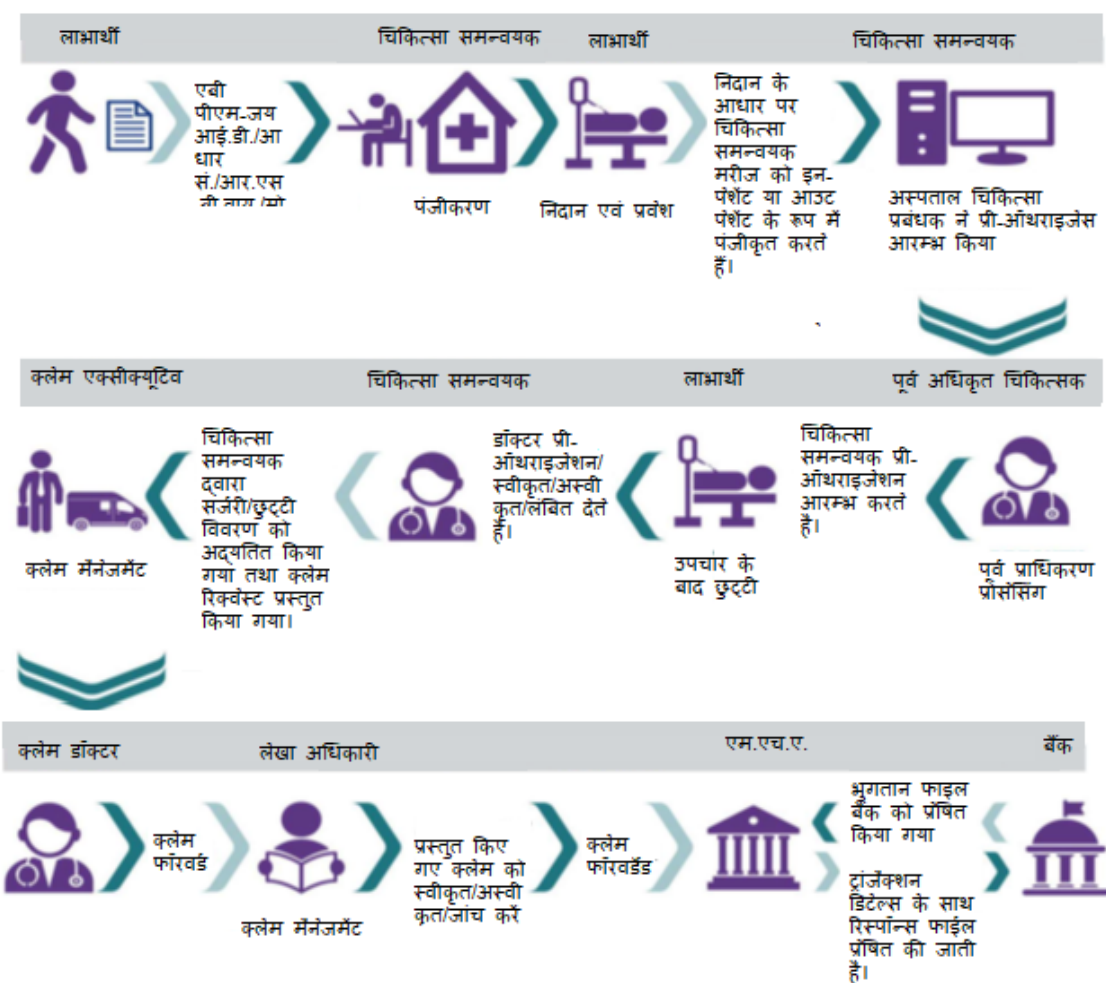
इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम डॉक्टर से परामर्श होने के बाद भी मरीज के अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड को हटाने की अनुमति देता है। इससे क्लिनिकल रिकॉर्ड का नुकसान हो सकता है या रिपोर्टिंग में विसंगतियां आ सकती हैं।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और कहा कि रोगी के दौरे का बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह के विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक सत्यापन लागू किया जाएगा।

2.2.14.3 रोगी योजना प्रबंधन

आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की अनुशंसाओं के अनुसार स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक, आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का एक घटक है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2012 में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना शुरू की, जिसे अप्रैल 2020 से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई.) में एकीकृत कर दिया गया। यह योजना सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से निर्दिष्ट बीमारियों के लिए कैशलेस, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है।



चिकित्सा समन्वयक: एम.ई.डी.सी.ओ./प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र

चित्र 5: पी.एम.जे.ए.वाई./एम.पी.जे.ए.वाई. का कार्यप्रवाह

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित डॉ. नंदामुरी तारका रामाराव वैद्य सेवा योजना, जिसे पहले डॉ. वाई.एस.आर. आरोग्य श्री योजना के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह स्वास्थ्य बीमा में एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है, जो सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से चिन्हित बीमारियों के लिए कैशलेस माध्यमिक और तृतीयक देखभाल प्रदान करता है। इस योजना में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के पूरक के रूप में मुफ्त स्क्रीनिंग, बाह्य रोगी परामर्श, स्वास्थ्य शिविर और निवारक देखभाल शामिल है।

सभी मामलों में, आरोग्यमित्र मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में उपर्युक्त योजनाओं के तहत रोगियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया से लेकर दावों को संभालने

और पैकेज राशि के निपटान और निपटान राशि के मिलान तक, जिसमें रोगियों को बी.पी. श्रेणी में परिवर्तित करना भी शामिल है, सभी प्रक्रियाओं में सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

क. श्रेणी रूपांतरण के लिए आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों ने आयुष्मान भारत एप्लिकेशन को लागू किया है, जिसके तहत मरीजों को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है और उन्हें पैकेज राशि आवंटित की जा रही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मरीजों के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने या दस्तावेज़ अपलोड करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि मरीजों ने अपनी नामांकन प्रक्रिया के लिए सहमति दी थी या उन्हें इसकी जानकारी थी। टाटा मेमोरियल केंद्र ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का नामांकन दावा प्रबंधन काउंटर पर होता है।

दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि रोगियों को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में उचित रूप से परिवर्तित किया गया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सही राशि आवंटित की गई थी या नहीं।

विभाग ने (दिसंबर 2025) बताया कि किसी विशेष सरकारी योजना के लिए रोगी की पात्रता का सत्यापन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त आरोग्यमित्र द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि टाटा मेमोरियल केंद्र आरोग्यमित्र द्वारा किए गए सत्यापन/पंजीकरण के रिकॉर्ड रखने का कार्य करेगा।

ख. मरीज श्रेणी में परिवर्तन में डेटा विसंगति

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई द्वारा प्रस्तुत जानकारी और एन.सी. में परिवर्तित सी श्रेणी

के रोगियों की संख्या के संबंध में श्रेणी⁴⁸ हस्तांतरण आवेदन में दिखाए गए डेटा की जांच करने पर, निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

तालिका 21: मरीज श्रेणी में परिवर्तन में डेटा विसंगति

वित्त वर्ष	दिनांक 03.10.2024 के उत्तर के अनुसार सी श्रेणी के एनसी में परिवर्तित किए गए मरीजों की संख्या	दिनांक 03.10.2024 के उत्तर के अनुसार सी श्रेणी के रोगियों की संख्या एनसी में परिवर्तित की गई	अंतर
2019-20	3502	287	3215
2020-21	2750	9	2741
2021-22	5356	23	5333
2022-23	6644	1676	4968
2023-24	6097	7588	(-) 1491

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने शुरू में (मार्च 2025) 16,257 श्रेणी स्थानांतरण मामलों (2019-2023) का कारण सिस्टम बग बताया था, जिससे सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई को बग की प्रकृति का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए मूल कारण विश्लेषण करना चाहिए।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने (जून 2025 में) बताया कि पहले दी गई जानकारी गलत स्रोत से थी। अब त्रुटिरहित और सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए प्रश्न को संशोधित कर दिया गया है।

यह इसके पहले के बयान (मार्च 2025) के विपरीत है जिसमें समस्या का कारण सिस्टम बग बताया गया था। पांच वर्षों में लगातार और बड़े पैमाने पर हुई विसंगतियां एक प्रणालीगत समस्या का संकेत देती हैं, न कि किसी एक बार की सोर्सिंग त्रुटि का। तथ्य यह है कि मार्च 2025 में समाप्त हुए फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान टी.एम.सी. सिस्टम में

⁴⁸ श्रेणी सी रोगियों से आंशिक रूप से शुल्क लिया जाता है, अर्थात्, जांच और परामर्श के लिए 20 प्रतिशत और शेष वास्तविक के अनुसार, जबकि श्रेणी एन.सी. रोगियों से कुछ सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाता है, कोई जांच या परामर्श शुल्क नहीं और शेष वास्तविक के अनुसार।

रोगी संबंधी डेटा की लेखापरीक्षा जांच में यह विसंगति देखी गई और इसकी रिपोर्ट की गई। टाटा मेमोरियल केंद्र ने फील्ड लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद जून 2025 में संशोधित उत्तर दिया, जिसमें सटीक और सुसंगत डेटा पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्वेरी में सुधार का उल्लेख किया गया था। हालांकि, टाटा मेमोरियल केंद्र ने संशोधित प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का कोई सबूत नहीं दिया, जिससे सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) इस अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र लेखापरीक्षा को संशोधित डेटा पुनर्प्राप्ति प्रश्न प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। चूंकि फील्ड लेखापरीक्षा पूरा हो चुका है और संशोधित प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के साक्ष्य के अभाव में इस समस्या के साथ-साथ, लेखापरीक्षा की पहुंच केवल ऑनसाइट लेखापरीक्षा सेटअप तक ही सीमित है, इसकी पुष्टि अनुवर्ती या बाद के लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

2.2.14.4 सामग्री प्रबंधन प्रणाली

टाटा मेमोरियल केंद्र ने एक सामग्री प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जिसमें इंडेंटेशन, स्टोर की खरीद के लिए मांग, खरीद, मंजूरी, आदेश, स्टोर रसीद और अंतिम उपयोगकर्ताओं को स्टोर आइटम जारी करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि, खरीद स्वीकृति नोट की स्वीकृति और खरीद आदेश जारी करने से पहले सत्यापन सिस्टम में मैप नहीं किया गया है और इसे मैन्युअल रूप से किया जाता है।

डेटाबेस और सामग्री प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित प्रक्रियाओं के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

क. स्टॉक में बची हुई एक्सपायर्ड दवाएँ: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी मेडिकल स्टोर संगठन और सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो

के लिए खरीद एवं परिचालन नियमावली के पैरा 7.3.4 के अनुसार, अधिकृत निर्गम अनुरोध/इंडेंट प्राप्त होने पर वस्तुओं के उचित निर्गम के माध्यम से उपभोक्ताओं/आवेदकों की मांग पूरी की जाती है। चूंकि अधिकांश वस्तुओं की समाप्ति तिथि होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वास्तविक निर्गम को 'पहले समाप्ति, पहले बाहर' (एफ़.ई.एफ़.ओ.) के आधार पर निपटाया जाए, जिससे उत्पाद की समाप्ति से होने वाली बर्बादी कम हो।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 145 मामलों में, दवाओं की समाप्ति तिथि बीत जाने के बाद, 1 से 1,264 दिनों के बीच, वापसी लेनदेन संसाधित किए गए। इससे फार्मास्युटिकल इन्वेंट्री और रिटर्न के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले आई.टी. एप्लिकेशन में समय पर ट्रेकिंग और अलर्ट तंत्र की कमी का संकेत मिलता है, जो उपयोगकर्ताओं को प्रतीक्षारत या बीत चुकी समाप्ति तिथियों के बारे में सूचित करेगा।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) बताया कि आई.टी. टीम ने दवाओं की समाप्ति तिथि के बाद हुए लेन-देन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। यह समस्या बिक्री केंद्रों पर बैच संख्या में समायोजन के कारण उत्पन्न हुई, जिससे वास्तविक और सिस्टम में दर्ज समाप्ति तिथियों में अंतर आ गया। केंद्र ने कहा कि वह डिस्पेंसरी टीम के साथ इस प्रक्रिया की समीक्षा करेगा और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए उपाय लागू करेगा।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 28:

एक्सपायरी के करीब दवाओं को मार्क करने के लिए असरदार कदम उठाए जा सकते हैं, जिन्हें एक तय समय में वापस किया जा सकता है।

ख. खरीद से संबंधित घटनाओं की तारीखों में असंगति: डेटा तालिका के विश्लेषण से पता चला कि वस्तु प्राप्ति तिथि, स्थापना तिथि और वितरण चालान तिथि संबंधित खरीद आदेश तिथि से पहले दर्ज की गई थीं। इससे आई.टी. एप्लिकेशन सिस्टम में तार्किक तिथि अनुक्रम के अनुपालन में संभावित चूक का संकेत मिलता है।

आगे की जांच से पता चला कि उपयोगकर्ताओं को सिस्टम-स्तरीय सत्यापन के बिना मैनुअल रूप से स्थापना तिथि दर्ज करने की अनुमति दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह खरीद आदेश और वस्तु प्राप्ति तिथियों के बाद आती है। इसके अलावा, एप्लिकेशन इस प्रक्रिया के दौरान वस्तु के "निर्माता" को संपादित करने की अनुमति देता है।

डेटा की सटीकता और प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, सिस्टम में मैनुअल प्रविष्टि से बचने के लिए डेटा इनपुट के दौरान सिस्टम-स्तरीय सत्यापन नियंत्रण आवश्यक है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 29:

सिस्टम में डेटा के मैनुअल इनपुट के बजाय सिस्टम स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन को जांच लागू करने की आवश्यकता है।

2.2.14.5 वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

क. वित्तीय रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की असमर्थता

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफ.एम.एस.) बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय सारांश सहित आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट उत्पन्न करने में असमर्थ थी।

विश्लेषण करने पर पता चला कि सिस्टम में लेन-देन दर्ज होने के बावजूद, रिपोर्ट तैयार करने की कार्यक्षमता वित्तीय डेटा को संरचित रिपोर्टों, जैसे कि निर्दिष्ट अवधि के लिए कैश बुक, में संसाधित और संकलित करने में सक्षम नहीं थी। कई दिनों की तिथि सीमा दर्ज करने के बावजूद, सिस्टम केवल एक दिन की कैश बुक तैयार करता है, जिससे चयनित अवधि के लेन-देन का समेकित दृश्य उपलब्ध नहीं हो पाता। स्वचालित रिपोर्ट तैयार करने की इस कमी के कारण रिपोर्टिंग प्रक्रिया लंबी खिंच गई और समग्र परिचालन दक्षता प्रभावित हुई।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई, स्वचालित रिपोर्ट निर्माण पर काम करने और अधिक सिस्टम जनित रिपोर्ट पेश करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ निश्चित रूप से विचार-विमर्श करेगा।

अनुशंसा 30:

सिस्टम में मौजूद कमियाँ या संभावित कॉन्फिगरेशन त्रुटियों की समीक्षा की जा सकती है। वित्तीय विवरणों को सटीक रूप से तैयार करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

ख. नए बिल पोर्टल पर मरीजों के बिल संबंधी गलत विवरण प्रदर्शित हो रहे हैं

वाराणसी स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में किए गए लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि न्यू बिल पोर्टल नामक एक इंटरफ़ेस में मरीजों के बिलिंग रिकॉर्ड प्रदर्शित करने में विसंगति थी। जब किसी मरीज केस नंबर '1' के लिए बी.पी. योजना के तहत कोई भी बिल नंबर खोला गया, तो सिस्टम मरीज केस नंबर '2' के विवरण के साथ-साथ मरीज केस नंबर '1' के मेमो विवरण वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देता था। इसके अलावा, उक्त पोर्टल में मरीज केस नंबर '2' के बिल विवरण को खोलने

पर, वही बिल नंबर पाया गया, जिससे पता चलता है कि कई मरीजों के लिए बिल नंबर की डुप्लीकेशन हुई है, और यह फिर से उसी पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है जिसका उल्लेख पहले किया गया है। इससे न्यू बिल पोर्टल में विशिष्ट मरीज केसों से संबंधित बिल विवरणों को जोड़ने में मूलभूत त्रुटि का पता चलता है।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) स्पष्ट किया कि कुछ स्थितियों में, सिस्टम ने सही मेमो जानकारी को बनाए रखते हुए रोगी के विवरणों को गलत तरीके से संयोजित या अदला-बदली कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम और संभावित डेटा विसंगतियां उत्पन्न हुईं। समीक्षा करने पर पाया गया कि यह समस्या बैकएंड लिंकिंग त्रुटि और एप्लिकेशन लॉजिक में बग के कारण थी।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 31:

संबंधित पोर्टल के मूल डिजाइन पर फिर से विचार किया जा सकता है और मरीजों के संबंध में बिल विवरण को ठीक से मैप किया जा सकता है।

ग. मेमो के आधार पर रसीदें जारी नहीं की गईं

जेनरेट किए गए मेमो तथा उनके संबंधित रसीद अभिलेखों के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे मेमो थे जिनके विरुद्ध संबंधित रसीदें जेनरेट नहीं की गई थीं। इन अप्राप्त मेमो का कुल वित्तीय मूल्य ₹34.98 करोड़ है, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 22: मेमो के बदले में जनरेट नहीं की गई रसीदों का विवरण

वर्ष	टी.एम.एच.		ए.सी.टी.आर.ई.सी.		एच.बी.सी.एच.आर.सी., बाइजाग		एम.पी.एम.एम.सी.सी.		एच.बी.सी.एच.आर.सी., मुल्लानपुर	
	मेमों संख्या	कुल राशि (₹ में)	मेमों संख्या	कुल राशि (₹ में)	मेमों संख्या	कुल राशि (₹ में)	मेमों संख्या	कुल राशि (₹ में)	मेमों संख्या	कुल राशि (₹ में)
2019-20	7083	3819835	19105	61669762	22	-14040	1	147	-	-
2020-21	18974	3032809	15825	44767747	594	1224139	22	16186	-	-
2021-22	31409	10002436	16602	49360431	507	1505747	185	213677	-	-
2022-23	48602	34833242	15735	46118337	667	1753904	11934	12704926	669	32000
2023-24	64257	47868783	3332	6772127	722	3307225	16931	20332603	1710	526735
कुल	170325	99557105	70599	208688404	2512	7776975	29073	33267540	2379	558735

बड़ी संख्या में मेमो के लिए रसीदों की अनुपलब्धता से संभावित राजस्व हानि के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि मेमो से संबंधित राशि एकत्र की गई है या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्राप्त राशियों के मिलान के लिए स्वचालित प्रणाली के अभाव में, वित्तीय विसंगतियों, गलत बयानों और संभावित राजस्व हानि का जोखिम बना रहता है।

विभाग ने (दिसंबर 2025) स्पष्ट किया कि अवलोकन में उल्लिखित मामले गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी (सरकारी योजना के लाभार्थी) से संबंधित थे। इन मामलों में रसीद की मार्किंग और आय की बुकिंग वास्तविक धनराशि प्राप्त होने और उसके मिलान के बाद ही की गई थी। इसलिए, इन्हें बिना मार्किंग वाले मेमो के रूप में दर्शाया गया था।

हालांकि, इस जवाब में इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद भी संयुक्त बैठक (मई 2025) के दौरान भी टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के सिस्टम में काफी संख्या में बिना चिह्नित मेमो दर्ज किए गए थे, जिनका पता नहीं चल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के वित्तीय प्रबंधन एप्लिकेशन सिस्टम में असंगत प्रविष्टियां हो सकती हैं।

अनुशंसा 32:

एक स्वचालित मिलान प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा और राजस्व और वित्तीय विश्वसनीयता की सुरक्षा के लिए बेहतर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित होंगे।

घ. मेमो राशि और संबंधित बिल राशि में विसंगति

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के अंतर्गत चयनित अन्य चार अस्पतालों के साथ मिलकर, निर्धारित आई.टी. एप्लिकेशन के माध्यम से सेवाओं से संबंधित लागतों का विवरण देने वाले सेवा ज्ञापन तैयार करता है, जो मौजूदा शुल्क अनुसूची पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार, दवाइयों और शल्य चिकित्सा सामग्री की कीमतों सहित फार्मसी ज्ञापन भी विशिष्ट एप्लिकेशन से तैयार किए जाते हैं। इस संबंध में, इन ज्ञापनों को बिलों में परिवर्तित करने की सुविधा के लिए सिस्टम में एक स्वचालित शेड्यूलर अंतर्निहित है।

हालांकि, मुंबई के टाटा मेमोरियल केंद्र में एफ.एम.एस. के फ्रंटएंड इंटरफेस के माध्यम से रोगी-वार मेमो और बिलों की जांच करने पर पता चला कि बिल की कुल राशि और बिल बनाने वाले मेमो के मूल्यों के योग में विसंगतियां मौजूद हैं। जांच किए गए मामलों में यह विसंगति ₹95,667 तक थी।

मेमो मूल्यों और बिल की गई राशियों के बीच देखी गई विसंगति के जवाब में, टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने स्पष्ट किया (जून 2025) कि यह विसंगति एप्लिकेशन में एक बग के कारण थी, जिसके कारण पुराने बिल पोर्टल में बिल नंबर एक्सेस करने पर फार्मसी रिटर्न मेमो सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। हालांकि, इस दावे के समर्थन में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, 34 रोगी मामलों की एक परीक्षण समीक्षा से पता चला कि उनके विरुद्ध सेवा और फार्मसी संबंधी मेमो 13 महीनों की अवधि से अप्रकाशित हैं। यह अवलोकन मेमो को समय पर इनवाँइस में परिवर्तित करने की प्रणाली की क्षमता में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करता है।

स्वचालित शेड्यूलर सही ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बिलिंग उद्देश्यों के लिए कुछ मेमो संसाधित नहीं हो पाए। इसके अलावा, अपर्याप्त निगरानी या अप्रतिबंधित मेमो पर नियमित मिलान और अनुवर्ती कार्रवाई करने में असमर्थता के कारण बिलिंग प्रक्रिया अधूरी रह गई।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) बताया कि सिस्टम-स्तरीय जांच और सत्यापन के माध्यम से शेड्यूलर में इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। हालांकि, इस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया और लेखापरीक्षा में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 33:

मेमो को बिल में परिवर्तित करने के लिए ऑटो-शेड्यूलर को इस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वसूली के लिए कोई भी मेमो बिना बिल के न रह जाए।

इ. ट्रस्ट खाता शेष से संबंधित निष्कर्ष

ट्रस्ट खाते का बंद न किया जाना

टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में पालन की जाने वाली ट्रस्ट खाता खोलने, रखरखाव, दावों के निपटान और ट्रस्ट खाते के बंद करने की मानक संचालन प्रक्रिया के खंड 3.2.15 (i) और (iv) में कहा गया है कि ट्रस्ट खाते का अंतिम निपटान किया जाएगा, (क) रोगी की मृत्यु के समय, या (ख) यदि खाता 18 महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है।

इसके अलावा, टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में ट्रस्ट खाता खोलने, रखरखाव, दावों के निपटान और ट्रस्ट खाते के बंद होने की मानक संचालन प्रक्रिया के खंड 3.2.21 में यह निर्धारित किया गया है कि ₹3,000 से कम की शेष राशि वाले मरीजों को 'गरीब रोगी कल्याण कोष' में स्थानांतरित किया जाएगा।

- i. **मरीज की मृत्यु:** टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में न्यू बिल पोर्टल में 'मृत' के रूप में दिखाए गए जीवित स्थिति वाले रोगियों के ट्रस्ट खाते की शेष राशि की परीक्षण जांच से पता चला है कि मार्च 2025 तक 12 महीने से अधिक समय तक रोगी की मृत्यु के बावजूद ₹47,765 से ₹69,263 तक की शेष राशि का निपटान अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
- ii. **18 महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय:** 10 रोगियों के संबंध में ट्रस्ट खाते की शेष राशि की परीक्षण जांच से पता चला कि उक्त खातों में शेष राशि ₹3,00,379 से ₹6,97,705 के बीच थी। हालांकि, टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई या कैंसर में उपचार अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र में उनकी अंतिम विज़िट मार्च 2025 तक 23 से 68 महीने के बीच थी। इस प्रकार, सिस्टम में व्यावसायिक नियमों की गैर-मैपिंग और सिस्टम में एम.आई.एस./अलर्ट के प्रावधान के अभाव के कारण, खाते को बंद करने के लिए निर्धारित समय सीमा 18 महीने से अधिक 5 से 50 महीने की अवधि के बाद भी ट्रस्ट खाता निष्क्रिय हुआ।
- iii. **₹3,000 से कम के ट्रस्ट बैलेंस का गैर-हस्तांतरण:** टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई में बनाए गए न्यू बिल पोर्टल के परीक्षण जांच में पाया गया कि 13 रोगियों के संबंध में ₹3,000 से कम (₹25 से ₹2,728 के बीच) के ट्रस्ट बैलेंस को 'गरीब मरीज कल्याण कोष' में स्थानांतरित नहीं किया गया था, हालांकि मार्च 2025 तक उनकी समाप्ति की तारीख 485 से 2211 दिनों तक थी।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने कहा कि नियमित निगरानी और प्रासंगिक मानक संचालन प्रक्रिया

के कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच शुरू की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिस्टम के भीतर उचित स्वचालन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण ट्रस्ट बैलेंस का निपटान नहीं हो पाया और इसे उचित फंड में स्थानांतरित नहीं किया जा सका, जो स्वयं संगठन की ट्रस्ट खाता नीति की मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 34:

समय पर एस.ओ.पी. के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

च. एक ही मरीज़ के लिए कई बार डे केयर शुल्क का भुगतान करना।

कीमोथेरेपी, रक्त और रक्त उत्पाद आधान के लिए आवश्यक डे केयर सेवाओं के लिए बिस्तर शुल्क को किसी विशेष रोगी के लिए एक विशेष दिन के दौरान एक से अधिक बार नहीं काटा जा सकता है।

हालांकि, आई.टी. सिस्टम और मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित बिलिंग की जांच करने पर यह पाया गया कि सिस्टम एक ही मरीज के लिए एक ही दिन में डेकेयर सेवाओं के लिए कई कटौतियां करने की अनुमति देता है, जो मानक बिलिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इससे सिस्टम की डुप्लिकेट या अनावश्यक शुल्कों को रोकने की क्षमता में कमी का संकेत मिलता है। डेकेयर शुल्कों के निपटान की प्रक्रिया में मेमो रद्द करने या रिफंड के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) में कहा कि वर्तमान में यह प्रणाली स्मार्टकार्ड

वाले मरीजों के लिए डेकेयर शुल्क के लिए कई बार बिलिंग की अनुमति देती है और इसलिए, उन्होंने दिन के भीतर कई बार गलत बिलिंग के मामलों की पहचान की है।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 35:

एक ही दिन में एक ही मरीज के लिए डे केयर सेवाओं के लिए कई कटौतियों को प्रतिबंधित करने के लिए आई.टी. सिस्टम में एक मजबूत सिस्टम नियंत्रण लागू किया जा सकता है।

छ. सिस्टम में अद्वितीय मेमो नंबर को न अपनाना

जब भी कोई मरीज मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र के अंतर्गत किसी अस्पताल से कोई सेवा या दवाइयाँ प्राप्त करता है, तो संबंधित आई.टी. सिस्टम स्वतः ही एक सेवा मेमो या फार्मसी मेमो तैयार कर देता है, जिसमें मरीज का विवरण, सेवा का विशिष्ट विवरण और संबंधित सेवा शुल्क जैसी विस्तृत जानकारी शामिल होती है। प्रत्येक मेमो को एक विशिष्ट संख्या दी जाती है, जो क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। मुल्लापुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र ने पुष्टि की है कि एक ही मेमो एक से अधिक मरीजों को जारी नहीं किया जा सकता।

हालांकि, लेखापरीक्षा में फ्रंट-एंड इंटरफेस और संबंधित डेटा तालिकाओं दोनों में यह पाया गया कि कुछ मामलों में एक ही मेमो नंबर अलग-अलग तारीखों पर कई मरीजों को दिया गया था। इस तरह की विसंगतियां सिस्टम के तर्क में अंतर्निहित खामियों, जैसे कि कमजोर सत्यापन नियंत्रणों, को दर्शाती हैं।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने मई 2025 में जवाब दिया कि सभी मेमो डिस्पेंसरी मेमो हैं। डिस्पेंसरी में विशिष्टता लेनदेन संख्या और लेनदेन तिथि पर आधारित होती है, न कि

मेमो संख्या पर। मेमो संख्या डिस्पेंसरी मेमो के पृष्ठ पर पहले से छपी हुई संख्या होती है, इसलिए एक ही मेमो कई रोगियों के लिए हो सकता है। यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग रोगियों को एक ही मेमो संख्या जारी करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इससे गलत बिलिंग और संभावित वित्तीय गड़बड़ियां हो सकती हैं।

टाटा मेमोरियल केंद्र ने (जून 2025) बताया कि उसने हाल ही में मेमो नंबरों को पहले से प्रिंट करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल में अब डिस्पेंसरी मेमो नंबरों में केवल लेनदेन संख्या होती है, जो सभी मेमो के लिए अलग-अलग होती है। एक ही मेमो को कई मरीजों के लिए दोबारा जारी होने से रोकने के लिए सिस्टम में उचित नियंत्रण लागू किए जाने चाहिए।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) बताया कि सिस्टम द्वारा उत्पन्न अद्वितीय संख्याओं को प्रिंट करने के लिए आवेदन प्रणाली में परिवर्तन शामिल किए गए हैं।

ज. स्मार्टकार्ड में ऋणात्मक शेष राशि

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में, स्मार्टकार्ड के माध्यम से मरीजों को सेवाएं और फार्मसी की वस्तुएं अग्रिम भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती थीं। सेवा वितरण या दवा वितरण से संबंधित मेमो तैयार करते समय स्मार्टकार्ड से राशि काट ली जाती थी। टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई में प्रचलित रोगी पुस्तिका के पैरा 11 और 12 के अनुसार, जो सामान्य, निजी और विदेशी मरीजों के पंजीकरण से संबंधित हैं, स्मार्टकार्ड में न्यूनतम जमा राशि क्रमशः ₹1,000, ₹10,000 और ₹50,000 होनी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बड़ी संख्या में मरीजों के स्मार्ट कार्डों में नकारात्मक राशि जमा हो गई थी। टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में अंतिम बार आने वाले या वर्ष 2020 से 2022 के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे पांच नकद भुगतान करने वाले मरीजों

की न्यू बिल पोर्टल एप्लिकेशन सिस्टम पर की गई जांच में उनके स्मार्ट कार्डों पर कुल ₹0.03 करोड़ की नकारात्मक राशि पाई गई।

इस प्रकार, इसने संकेत दिया कि सिस्टम में (1) सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन को प्रमाणित करने के लिए ओवरराइड/लेखापरीक्षा ट्रेल और (ii) इन-पेशेंट नकारात्मक शेष राशि की वसूली को ट्रैक करने के लिए निगरानी तंत्र की कमी है।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई ने (जून 2025) कहा कि वह इस मुद्दे का उचित समाधान करेगा और ऐसे मामलों की नियमित निगरानी और समय पर निवारण के लिए तंत्र स्थापित करेगा। उसने यह भी आश्वासन दिया कि पूर्वव्यापी मामलों की पहचान की जाएगी और सक्षम अधिकारियों के मार्गदर्शन में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा 36:

वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और अस्पताल के राजस्व चक्र प्रबंधन को बनाए रखने के लिए सिस्टम के भीतर बैलेंस सत्यापन नियंत्रण लागू किए जा सकते हैं।

2.2.15 निष्कर्ष

टाटा मेमोरियल केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अनुदान प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करता है और इसे राष्ट्रीय कैंसर केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य कैंसर के क्षेत्र में सेवा, शिक्षा और अनुसंधान करना है। टाटा मेमोरियल केंद्र ने केंद्र की समग्र गतिविधियों के प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आई.टी. प्रणाली लागू की है।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई में आई.टी. रणनीति और योजना, तथा डेटा प्रतिधारण नीति तैयार न होने के कारण आई.टी. प्रशासन में कई कमियां पाई गईं। आई.टी. संचालन समिति का गठन

भी नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र प्रक्रिया और परीक्षण वातावरण का भी सुव्यवस्थित अभाव था। इसके अलावा, औपचारिक गुणवत्ता आश्वासन/उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण ढांचा, डेटा प्रतिधारण नीति का निर्माण और आई.टी. एप्लिकेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण का अभाव था, साथ ही बाह्यश्रोत किए गए कर्मचारियों को असीमित पहुंच प्राप्त थी।

टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई के आई.टी. सिस्टम के सामान्य नियंत्रण विभाग में आई.टी. सुरक्षा नीति और उपयोगकर्ता पंजीकरण एवं पंजीकरण रद्द करने की नीति का निर्माण नहीं किया गया था। उपयोगकर्ता आई.डी. बनाने में अनियमितताएँ थीं। आवधिक सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। व्यापार निरंतरता एवं आपदा रिकवरी योजना लागू नहीं की गई थी। मास्टर डेटा प्रबंधन में असंगति थी। टाटा मेमोरियल केंद्र साइबर हमले को रोकने और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली में एप्लिकेशन नियंत्रणों में एक महत्वपूर्ण कमजोरी थी, जैसे कि एक ही रोगी के लिए डुप्लिकेट पंजीकरण संख्या उत्पन्न करना, आधार और पैन को एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में मान्य करने का अभाव, इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण गलत डेटा दर्ज करने में चूक, विदेशी रोगी के पते के विवरण भरते समय अनियंत्रित जाँच और विदेशी रोगियों के पंजीकरण में खराब नियंत्रण। रोग प्रबंधन समूह के चयन में सत्यापन नियंत्रणों का अभाव था। रोगी प्रवेश के एप्लिकेशन नियंत्रण में कमजोरियों से पता चला कि मृत रोगियों के मामले में स्वचालन नियंत्रण का अभाव था। बाह्य रोगी विभाग नियुक्ति एप्लिकेशन में नियंत्रण के मामले में, नियुक्ति निर्धारण में चूक हुई। रोगी योजना प्रबंधन में एप्लिकेशन नियंत्रण में श्रेणी रूपांतरण के प्रावधान में चूक हुई। इसके अलावा, सामग्री प्रबंधन प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के मामले में, दवाओं के स्टॉक को बनाए रखने में कमी, डेटा इनपुट में सिस्टम स्तर सत्यापन नियंत्रण की कमी, आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में असमर्थता, नए बिल पोर्टल पर गलत रोगी बिलिंग विवरण प्रदर्शित होना, मेमो

मूल्यां और संबंधित बिल राशियों में असंगति और टाटा मेमोरियल केंद्र नीति के अनुसार ट्रस्ट खाते को बंद न करना पाया गया।

टाटा मेमोरियल केंद्र का मिशन सभी को व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करना है, इसलिए आई.टी. प्रणाली में मौजूद खामियों और अपर्याप्त नियंत्रणों को दूर करने और शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है ताकि आई.टी. प्रणाली में आगे की कमियों को रोका जा सके और समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट सेवाओं को किफायती, नवीन और देश की जरूरतों के अनुरूप प्रदान करके, आई.टी. प्रणाली में सुरक्षित और पर्याप्त नियंत्रणों के साथ अपने दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।

2.3 स्थापना स्थलों के पूर्ण न होने और लिफ्ट के पुर्जों के लंबे समय तक भंडारण के कारण खराब होने से ₹1.45 करोड़ का परिहार्य व्यय

स्थापना स्थल के सात वर्षों से अधिक समय तक पूर्ण न होने के कारण, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय को लिफ्ट की स्थापना से पहले उसके पुर्जों के प्रतिस्थापन और मरम्मत पर ₹1.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

सामान्य वित्त नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग का सचिव, जो मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है, उस मंत्रालय या विभाग के निर्धारित परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तरदायी होता है, साथ ही प्रदर्शन मानकों का अनुपालन भी करता है।

मुंबई स्थित निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय ने अनुशक्तिनगर, मुंबई में विभिन्न भवनों के लिए 18 लिफ्टों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने हेतु मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चार कार्य आदेश प्रदान किए (*तालिका 1*), जिनकी कुल लागत ₹5.76 करोड़⁴⁹ है। अनुबंध के अंतर्गत जारी कार्य आदेशों के पूर्ण करने की समय-

⁴⁹ टाइप ई बिल्डिंग में अभी तक पूरा होने वाले कार्य के मूल्य सहित।

सारणी और किए गए अतिरिक्त व्यय का विवरण **अनुलग्नक 8** में दिया गया है।

नियमों और शर्तों के अनुसार, लिफ्टों से संबंधित उपरोक्त कार्य, कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पूरे किए जाने थे। 18 लिफ्टों के सभी पुर्जे नवंबर 2014 से सितंबर 2015 के बीच निर्माण-स्थल (साइट) पर आपूर्ति कर दिए गए थे। हालांकि, स्थापना स्थल (इंस्टॉलेशन साइट) पूरी न होने के कारण लिफ्टों को स्थापित (इंस्टॉल) नहीं किया जा सका और लिफ्ट के पुर्जे, जंग लगने और खराब होने से रोकने की उचित व्यवस्था किए बिना साइट पर ही पड़े रहे। यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त भवनों का निर्माण कार्य (सिविल कार्य और विद्युत कार्य सहित) शुरू से ही धीमा था और मुख्य रूप से ड्राइंग जारी करने और निदेशालय द्वारा साइट से पेड़ों को हटाने में विलंब होने के कारण इसमें असामान्य रूप से देरी हुई। इसके आगे, विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि ठेकेदार शेष कार्यों को उचित समय के अंदर पूर्ण करने की स्थिति में नहीं था। अतः अक्टूबर 2017 (टाइप III-सी बिल्डिंग, टाइप IV-डी और टाइप ई बिल्डिंग) और मई 2018 (आवास बी1 और एम1) में कार्य बंद कर दिए गए और शेष कार्य के लिए 2018-2020 के दौरान पुनः निविदा जारी की गई।

इसके बाद, जब सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका था, विभाग ने (2018 और 2020 में) लिफ्ट ठेकेदार से स्थापना के उद्देश्य हेतु अपनी टीम भेजने का अनुरोध किया। ठेकेदार ने मई 2019 और अक्टूबर 2020 में दोषपूर्ण/खराब घटकों की सूची प्रस्तुत की और क्षतिग्रस्त सामग्रियों के प्रतिस्थापन और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा लिफ्ट सामग्रियों के पुनर्निर्माण हेतु ₹1.66 करोड़ (₹1.45 करोड़+₹0.21 करोड़⁵⁰=₹1.66 करोड़) (**अनुलग्नक 8**) की अतिरिक्त राशि की मांग की। इसके विरुद्ध, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय ने चरणबद्ध कार्य पूर्ण होने के बाद ठेकेदार को ₹1.45 करोड़ का भुगतान जारी किया। इसके आगे, टाइप V-ई बिल्डिंग में दो लिफ्टों की स्थापना के लिए ₹0.21 करोड़ का बकाया भुगतान

⁵⁰ ₹0.21 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है।

लंबित था क्योंकि इन स्थलों पर सिविल कार्य अभी तक अपूर्ण थे और शेष कार्य पूर्ण होने के बाद इसे जारी किया जाना था।

निदेशालय ने बताया (नवंबर 2025) कि सिविल कार्य प्रगति पर थे, हालांकि कुछ विलंब हुए थे लेकिन वे पूरी तरह से रुके नहीं थे तथा इस प्रकार के किसी भी कार्य के आवंटन की कार्यालयीय प्रक्रियाओं में लगभग छह महीने लगते हैं और सिविल कार्यों के पूर्ण होने की आशा के साथ, निदेशालय ने परियोजना के समग्र समापन लक्ष्य तिथियों के अनुरूप लिफ्टों की स्थापना के लिए कार्य आदेश जारी किए। इसके अलावा, निदेशालय ने बताया कि साइट पर लाई गई लिफ्ट सामग्री को संबंधित साइट पर एजेंसी द्वारा सर्वोत्तम संभव सुरक्षित भंडारण व्यवस्था के तहत रखा गया था। इसलिए, घटकों का प्रतिस्थापन "अनुचित भंडारण" के कारण नहीं, बल्कि सात वर्षों की लंबी भंडारण अवधि के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों के कारण पुराने होने और खराब होने के कारण हुआ था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मई/अगस्त 2014 तक पूर्ण होने वाले सिविल कार्य, एक को छोड़कर, वास्तव में जून 2021 से मार्च 2022 के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किए गए थे। जब सिविल कार्य पूर्ण होने के करीब भी नहीं था, नवंबर 2013 से अप्रैल 2015 के महीनों के दौरान सिविल कार्य की वास्तविक स्थिति की अनदेखी करते हुए, लिफ्टों के लिए कार्य आदेश जारी किए गए। सिविल कार्य पूरा न होने के कारण, ठेकेदार निर्धारित तिथि पर लिफ्ट स्थापित नहीं कर सका और लिफ्ट के पुर्जे साइट पर ही बेकार पड़े रहे। इसके अलावा, निदेशालय के जवाब से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि लिफ्ट के पुर्जे सात वर्षों की लंबी अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों और उपयोग में न आने के कारण खराब हो गए थे।

इस प्रकार, सात वर्षों से अधिक समय तक स्थापना स्थलों का पूरा न होना, बिल्डिंग की साइट की तैयारी की वास्तविक स्थिति की जाँच किए बिना लिफ्टों की स्थापना के लिए समय से

पहले कार्य आदेश जारी करना और लिफ्ट के पुर्जों का लंबे समय तक भंडारण, इन पुर्जों के प्रतिस्थापन और मरम्मत पर ₹1.45 करोड़ के अनावश्यक व्यय का कारण बना।

अध्याय III

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 लेजर वेल्डिंग मशीन के गैर/उप-इष्टतम (सब-ऑप्टिमल) उपयोग के कारण ₹1.52 करोड़ का निष्फल व्यय

केंद्र ने एक लेजर वेल्डर पर ₹1.52 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया, जो आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी विफलताओं के कारण लंबे समय तक अप्रयुक्त रहा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (केंद्र) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड द्वारा ₹17.24 करोड़ की लागत से "इलेक्ट्रिक वाहन अनुप्रयोगों के लिए लिथियम-आयन बैटरी का विकास" परियोजना के लिए पांच वर्ष की अवधि (दिसंबर 2011 से) हेतु स्वीकृति दी गई थी, जिसे बाद में जून 2017 तक बढ़ा दिया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत पायलट संयंत्र सुविधा की स्थापना और लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रमुख उद्देश्य था।

लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में लेजर वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेजर वेल्डिंग मशीन का उपयोग लिथियम-आयन सेल के चुंबकीय आवरण को वायुरोधी रूप से सील⁵¹ करने के लिए किया जाता है। केंद्र ने इस परियोजना के अंतर्गत मार्च 2012 में ₹0.98 करोड़⁵² की लागत से एक लेजर वेल्डर सहित वर्कस्टेशन खरीदा। उपकरण में एक लेजर स्रोत और एक वर्कस्टेशन शामिल था। उपकरण मई 2012 तक प्रदान किया जाना था। चूंकि जिस कमरे में उपकरण को

⁵¹ एक वायुरोधी वस्तु वह होती है जिसमें हवा का प्रवेश या निकास नहीं हो सकता।

⁵² लेजर वेल्डर की कीमत ₹0.55 करोड़ और वर्कस्टेशन की कीमत ₹0.43 करोड़ है।

स्थापित किया जाना था वह तैयार नहीं था, इसलिए केंद्र ने प्री-डिस्पैच निरीक्षण को अगस्त 2012 तक स्थगित कर दिया और तत्पश्चात उपकरण को अक्टूबर 2012 में प्रदान किया गया। हालांकि उपकरण अक्टूबर 2012 में प्राप्त हो गया था, लेकिन जुलाई 2013 तक भी ड्राई रूम और समर्पित चिलर (5टी) उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, केंद्र ने मौजूदा कूलिंग सिस्टम (2टी) के साथ कार्यक्षमता जांच और प्रारंभिक परीक्षण किए। समर्पित चिलर सितंबर 2013 में प्राप्त हुआ, हालांकि लेजर स्रोत के लेजर वेल्डर उपकरण की बिजली आपूर्ति इकाइयों और मोशन कंट्रोलर में खराबी के कारण, केंद्र दिसंबर 2015 तक उपकरण को चालू नहीं कर सका। केंद्र ने इन पुर्जों को पुनः निर्माता को निर्यात किया (दिसंबर 2015) और अप्रैल 2016 में उन्हें वापस प्राप्त किया। केंद्र, उसके बाद भी, जंग लगे चिलर सिस्टम, चूहों द्वारा केबलों और पाइपों को नुकसान, बार-बार बिजली की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव, लेजर वेल्डर उपकरण के सॉफ्टवेयर में खराबी आदि जैसी समस्याओं के कारण उपकरण चालू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की पूरी अवधि (जून 2017) के दौरान उपकरण काम नहीं कर पाया। केंद्र सरकार ने उपकरण के प्रापण, पुनर्निर्यात और प्राप्ति पर ₹1.08⁵³ करोड़ का व्यय किया। लेजर वेल्डर मशीन की अनुपलब्धता के कारण, केंद्र ने आउटसोर्स वेल्डिंग का उपयोग करके पॉलीप्रोपाइलीन कंटेनर/स्टेनलेस स्टील कंटेनर में सेल बनाए, लेकिन इसे आवश्यक शुष्क परिस्थितियाँ बनाए रखने में असमर्थता हुई, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से क्षरण और सेल की गुणवत्ता खराब हुई।

इसके अलावा, चूंकि मूल उपकरण निर्माता ने मॉडल का उत्पादन बंद कर दिया था, इसलिए केंद्र खराब लेजर स्रोत की मरम्मत की व्यवस्था नहीं कर सका। उपकरण को बचाने के लिए, केंद्र ने तकनीकी अनुसंधान केंद्र परियोजना के तहत ₹0.44 करोड़ की लागत से एक नया लेजर स्रोत (मई 2019) खरीदा और इसे उपरोक्त लेजर वेल्डिंग उपकरण के हिस्से के रूप में प्राप्त

⁵³ इसमें उपकरण के लिए 90 प्रतिशत भुगतान, पुर्जों का पुन-निर्यात और बीमा शामिल है।

वेल्डिंग वर्कस्टेशन के साथ एकीकृत (सितंबर 2019) किया।

इससे पहले फरवरी 2019 में, केंद्र ने प्रापण को उचित ठहराते हुए कहा था कि तकनीकी अनुसंधान केंद्र एक समयबद्ध परियोजना थी जिसके लिए बैटरी पैक का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन के लिए 2000 से 3000 सेल के उत्पादन की आवश्यकता थी और इस उद्देश्य के लिए लेजर वेल्डिंग की तत्काल आवश्यकता थी। अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले, उपकरण का उपयोग कभी-कभी लगभग 600 वस्तुओं की वेल्डिंग के लिए किया गया था। इस प्रकार, यहाँ तक कि रीफर्बिशड उपकरण का भी बहुत कम उपयोग किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने (अक्टूबर 2025) जवाब दिया कि सितंबर 2019 में इसके एकीकरण के बाद से, उन्नत लेजर वेल्डिंग प्रणाली का नियमित रूप से लिथियम-आयन सेल निर्माण और अन्य कार्यों को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। केंद्र ने प्रदर्शन के लिए प्रिज्मीय सेल और बैटरी पैक विकसित किए और बेलनाकार और प्रिज्मीय सेल निर्माण और कौशल विकास के लिए तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यद्यपि मूल योजना के अनुसार एन.डी.-वाई.ए.जी.⁵⁴ लेजर स्रोत का उपयोग वायुरोधी सीलिंग के लिए नहीं किया जा सका, फिर भी यह तकनीकी ज्ञान के लिए मूल्यवान साबित हुआ और कई घटकों को अन्य लेजर प्रणालियों के रखरखाव के लिए पुनः उपयोग में लाया गया।

हालांकि जानकारी का हस्तांतरण सराहनीय है, लेकिन यह एक तथ्य है कि इसे मूल या नवीनीकृत लेजर वेल्डर के बिना किसी प्रमुख योगदान के प्राप्त किया गया है।

आगे जवाब देते हुए (नवंबर 2025) केंद्र ने बताया कि उपलब्ध दो ड्राई रूम (इलेक्ट्रोड निर्माण और लिथियम-आयन बैटरी सेल असेंबली, जिसमें लेजर वेल्डिंग भी शामिल है) मई 2022 से

⁵⁴ एन.डी.-वाई.ए.जी. (नियोडोमियम-डॉपड यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट) एक स्पंदित लेजर स्रोत है जिसे विशेष रूप से सटीक कटिंग और वेल्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

खराब होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप लिथियम-आयन सेल की असेंबली और लेजर वेल्डिंग मशीन का उपयोग में काफी कमी हो गई थी। केंद्र ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि आवश्यक प्रणालियों को प्राप्त करने और ड्राई रूम को फिर से चालू करने में देरी के कारण लेजर वेल्डिंग मशीन का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि केंद्र ने लेजर वेल्डर के प्रापण पर ₹1.08 करोड़ खर्च किए, लेकिन उपकरण की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उचित सावधानी नहीं बरती, इसके परिणामस्वरूप, लेजर वेल्डिंग मशीन लंबे समय तक अप्रयुक्त रही, जिससे इसके मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। यहाँ तक कि मरम्मत के बाद भी, आवश्यक बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण मशीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2012 में खरीदा गया मूल लेजर स्रोत (लगभग ₹0.55 करोड़ की लागत वाला) 12 वर्षों से अधिक समय से बिना उपयोग के निष्क्रिय पड़ा है।

परिणामस्वरूप, ₹1.52 करोड़ (मूल लेजर उपकरण के लिए ₹1.08 करोड़ और नए लेजर स्रोत के लिए ₹0.44 करोड़) का व्यय निष्फल रहा।

अध्याय IV

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1.1 प्रस्तावना

देश में औद्योगिक अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सितंबर 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। समय के साथ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के दायरे और विस्तार को बढ़ाया है और अब यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और नवाचार में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में केंद्रित बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 39 आउटरीच केंद्र, मुंबई में एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और तीन इकाइयाँ⁵⁵ स्थापित की इसमें लगभग 3,376 वैज्ञानिक और 3,746 तकनीकी एवं सहायक कर्मचारी हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

⁵⁵ सी.एस.आई.आर.-मानव संसाधन विकास केंद्र, गाजियाबाद; सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास इकाई पुणे; सी.एस.आई.आर.-पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, सत्संग विहार, नई दिल्ली।

विभिन्न ग्राहकों को अनुबंध अनुसंधान और विकास, परामर्श और ज्ञान-आधारित सेवाएँ प्रदान करके महत्वपूर्ण मात्रा में बाहरी नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। 1992 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने प्रयोगशाला आरक्षित निधि योजना बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें बजटीय संसाधनों के पूरक के रूप में पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए निधियों को आगे ले जाने और उनका उपयोग करने का प्रावधान था।

प्रयोगशाला आरक्षित निधि के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली प्रयोगशालाओं/संस्थानों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
- समुचित उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास और गैर-अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियों को अलग-अलग करना।
- एक प्रयोगशाला आरक्षित निधि बनाना और व्यवस्थित बजट के माध्यम से प्रयोगशाला के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए इसके उपयोग को निर्देशित करना तथा इसके बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और प्रयोगशालाओं के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करना।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने 9 दिसंबर 1999 को आयोजित अपनी 147 वीं बैठक में, मुख्यालय आरक्षित निधि की स्थापना और 'प्रयोगशाला आरक्षित निधि' के नाम को बदलकर "प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि (प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि⁵⁶)" करने के साथ मौजूदा प्रयोगशाला आरक्षित निधि योजना में संशोधन को मंजूरी दी। मुख्यालय आरक्षित निधि की स्थापना प्रयोगशाला आरक्षित निधि की तर्ज पर ही की गई थी, जिसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय द्वारा प्रतिधारित, संचालित और उपयोग किया जाना था। मुख्यालय आरक्षित निधि बनाने का उद्देश्य

⁵⁶ यद्यपि इस निधि का नाम बदलकर प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि कर दिया गया था, लेकिन सी.एस.आई.आर. परस्पर रूप से एल.आर.एफ./एच.आर.एफ./एल.एच.आर.एफ. नामों का उपयोग कर रहा था। इस रिपोर्ट में, लेखापरीक्षा ने प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के रूप में एक समान नामकरण बनाए रखा है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय के बजट में प्रदान किए गए व्यय के अतिरिक्त आकस्मिक और अनपेक्षित व्यय को पूरा करना था, जैसे कि उपकरणों की खरीद, अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए मानव संसाधन विकास।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने मार्च 1992 में प्रयोगशाला आरक्षित निधि की स्थापना के बाद से समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के माध्यम से प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन, उपयोग, लेखांकन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

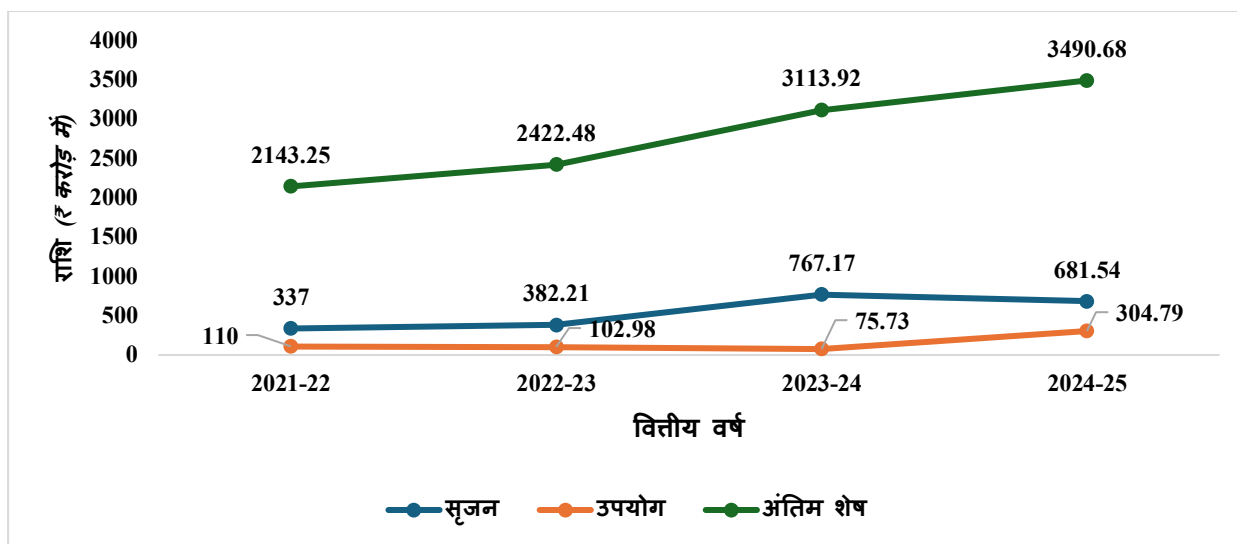
पिछले चार वर्षों के लिए प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का वर्ष-वार अंतिम शेष नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 23: सी.एस.आई.आर. में एल.एच.आर.एफ. का संचित निधि का अंतिम शेष

निम्न को समाप्त होने वाला अंतिम शेष	अंतिम शेष ⁵⁷ (₹ करोड़ में)
31 मार्च 2022	2143.25
31 मार्च 2023	2422.48
31 मार्च 2024	3113.92
31 मार्च 2025	3490.68

31 मार्च 2025 तक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पास प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि (**अनुलग्नक 9**) में ₹3,490.68 करोड़ का संचित शेष था, जो इसकी 37 इकाइयों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में फैला हुआ है।

⁵⁷ इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमशः ₹38.90 करोड़, ₹49.73 करोड़, ₹177.26 करोड़ और ₹208.87 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है।



चार्ट 1: एल.एच.आर.एफ. का सृजन उपयोग और अंतिम शेष

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, अनुसंधान और विकास से निधि का सृजन ₹337 करोड़ से बढ़कर ₹681.54 करोड़ (2021-25) हो गया है, जबकि उपयोग पहले तीन वर्षों के लिए अपेक्षाकृत स्थिर और कम रहा, जिसके बाद 2023-24 के बाद अचानक वृद्धि हुई।

4.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पहलुओं की जाँच की गई:

- क. क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बजटीय संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्राप्तियों को बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम था।
- ख. क्या प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग के लिए उचित योजना बनाई गई थी।
- ग. क्या प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के तहत प्राप्तियों को दिशानिर्देशों में उल्लिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किया गया था और क्या व्यय अनुमोदित शीर्षों के तहत किया गया था।
- घ. क्या प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना के कार्यान्वयन की उचित

निगरानी और समीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2021-2024 की अवधि के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के दायरे में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय और योजना के कार्यान्वयन में शामिल इसकी चयनित प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जाँच शामिल थी। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में मुख्य रूप से प्रश्नावली के उत्तर, इन संस्थानों में रिपोर्टों और अभिलेखों की जाँच और विश्लेषण शामिल था।

4.1.3 लेखापरीक्षा नमूनाकरण/विस्तृत विवरण

लेखापरीक्षा नमूने में 12 इकाइयाँ शामिल थीं, जो ₹2,384.90 करोड़ की प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि राशि (मार्च 2024 तक कुल प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का 72.46 प्रतिशत) को कवर करती हैं। नमूने में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अंतिम शेष (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार) के मामले में शीर्ष सात इकाइयाँ और शेष 30 इकाइयों में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई पाँच इकाइयाँ शामिल थीं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 24: 12 नमूना इकाइयों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम. संख्या	प्रयोगशाला/संस्थान	अंतिम शेष की राशी
1.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय	811.55
2.	केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद	679.68
3.	राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बेंगलुरु	349.10
4.	केंद्रीय विद्युत् रसायन अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी	118.10
5.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	117.58
6.	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	109.64
7.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा	98.69
8.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	48.76
9.	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	20.68
10.	जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान, दिल्ली	16.40
11.	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता	12.05
12.	हिमालय जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर	2.67

क्रम. संख्या	प्रयोगशाला/संस्थान	अंतिम शेष की राशी
	कुल	2384.90

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1.4 प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का नियोजन और उपयोग

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के अनुसार, सभी स्वायत्त संगठनों को आंतरिक संसाधनों के सृजन को अधिकतम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.1.4.1 प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का कम उपयोग

दिशानिर्देशों (सितंबर 2000) के अनुसार, एक वर्ष में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग पिछले वर्ष में उत्पन्न राशि के एक-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उसकी नमूना प्रयोगशालाओं द्वारा 2021-2025 की अवधि के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पन्न निधियों का वर्ष-वार उपयोग नीचे दिया गया है।

तालिका 25: नमूना इकाइयों की उत्पन्न निधियां बनाम निधियों का वर्ष-वार उपयोग

(₹ करोड़ में)

संस्थान/प्रयोगशाला	वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का सृजन	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग	प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग का प्रतिशत
सी.एस.आई.आर. - एच.क्यू.	2021-22	47.85	17.94	37.49
	2022-23	142.25	0.91	0.64
	2023-24	73.17	3.71	5.07
	2024-25	46.64	18.43	39.52
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान	2021-22	26.96	2.77	10.27
	2022-23	-6.98	2.76	100
	2023-24	9.25	0.71	7.68
	2024-25	23.5	2.66	11.32

संस्थान/प्रयोगशाला	वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का सृजन	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग	प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग का प्रतिशत
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला	2021-22	5.95	4.94	83.03
	2022-23	4.69	0.66	14.07
	2023-24	9.05	3.01	33.26
	2024-25	17.12	28.42	166
राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं	2021-22	78.95	10.38	13.15
	2022-23	59.07	17.91	30.32
	2023-24	46.04	17.97	39.03
	2024-25	71.53	33.75	47.18
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान	2021-22	215.96 ⁵⁸	17.76	8.22
	2022-23	45.69	20.06	43.9
	2023-24	45.83	13.24	28.89
	2024-25	372.82	15.18	4.07
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान	2021-22	1.21	2.64	218.18
	2022-23	1.36	0.25	18.38
	2023-24	0.83	0.07	8.43
	2024-25	3.01	9.79	325.25
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला	2021-22	21.93	2.27	10.35
	2022-23	31.68	1.83	5.78
	2023-24	12.6	3.26	25.87
	2024-25	17.67	5.72	32.37
हिमालय जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	2021-22	10.98	0.54	4.92
	2022-23	-0.83	2.19	100
	2023-24	1.26	0.09	7.14
	2024-25	0.75	6.55	873.33
केंद्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान	2021-22	105.71	2.1	1.99
	2022-23	-3.08	0.4	100
	2023-24	9.32	0.34	3.65
	2024-25	2.69	10.02	372.49

⁵⁸ प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के शुद्ध सृजन की गणना (वर्ष 2020-21) वर्ष 2020-21 के दौरान कुल सृजन ₹453.49 करोड़ था, जिसमें से मुख्यालय आरक्षित निधि को हस्तांतरित ₹237.53 करोड़ घटाने के बाद शुद्ध राशि ₹215.96 करोड़ रही।

संस्थान/प्रयोगशाला	वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का सृजन	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग	प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग का प्रतिशत
जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान	2021-22	26.09	3.26	12.5
	2022-23	-0.24	0.48	100
	2023-24	0.74	0.86	116.22
	2024-25	12.63	13.91	110.13
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	2021-22	8.35	4.36	52.22
	2022-23	13.82	3.09	22.36
	2023-24	19.97	0.726	3.64
	2024-25	13.34	10.67	79.99

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, नमूना ली गई प्रयोगशालाओं के कुल 44 मामलों में से केवल 19 बार ही यह देखा गया कि प्रयोगशालाओं ने पिछले वर्ष के प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि सृजन के एक-तिहाई (1/3) से अधिक का उपयोग किया। नमूना प्रयोगशालाओं में से केवल 'जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान' ही 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान व्यय की इस निर्धारित सीमा को पार कर सका है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (मुख्यालय और इसकी सभी प्रयोगशालाओं/इकाइयों/संस्थानों) द्वारा प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का कुल उपयोग भी बहुत कम रहा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित निधि की तुलना में, 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान यह उपयोग केवल 19.81 प्रतिशत से 39.79 प्रतिशत के बीच रहा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 26: वर्ष-वार निधियों का उपयोग बनाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उत्पन्न निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकारी अनुदान से व्यय	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि की उत्पत्ति	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग	प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग का प्रतिशत
2021-22	5174.34	453.93	110.00	24.23
2022-23	5808.59	337.00	102.98	30.56
2023-24	6107.07	382.21	75.73	19.81
2024-25	6303.45	767.17	304.79	39.79

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि सभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं/संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी वर्ष में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का उपयोग सामान्यतः पिछले वर्ष उत्पन्न राशि के कम से कम एक-तिहाई से कम न हो।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का यह उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष उत्पन्न राशि की तुलना में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के न्यूनतम एक-तिहाई उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2000 में ही जारी कर दिए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि से निधियों का उपयोग वर्षों से कम स्तर पर बना हुआ है, जिससे इस निधि की स्थापना का उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है।

अनुशंसा 37:

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने बजटीय संसाधनों की पूर्ति के लिए पिछले वर्ष में उत्पन्न प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का कम से कम 1/3 भाग सुनिश्चित करते हुए संचित निधियों का उपयोग करने का प्रयास कर सकती है।

4.1.4.2 अपर्याप्त योजना तंत्र

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग न किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूलभूत प्रणाली, जिसमें व्यवस्थित योजना और बजट निर्धारण आवश्यक है, का पालन नहीं किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

क. बजटीय अनुमान

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वर्ष 2000 की प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना दिशा-निर्देशों⁵⁹ के अनुसार, अपने वार्षिक बजट अनुमानों को अंतिम रूप देते समय प्रत्येक प्रयोगशाला को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाना आवश्यक है:

- वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि
- वर्ष के दौरान अपेक्षित सृजन
- बजट के प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित उपयोग।

बजट अनुमान चरण में प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा आवश्यकता होने पर संशोधित अनुमान चरण में प्रस्तावित उपयोग में संशोधन करना अपेक्षित था। वित्त मंत्रालय को बजटीय आवश्यकताओं का आकलन प्रस्तुत करते समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अन्य आंतरिक प्राप्तियों के साथ प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अनुमानित उपयोग को भी शामिल करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा नमूना के रूप में चयनित प्रयोगशालाओं ने बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग का इस प्रकार का वार्षिक आकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रभावी बजटीय योजना और

⁵⁹ सी.एस.आई.आर. कार्यालय ज्ञापन सं. 1(11)/लेखा./2000-2001 दिनांक 4.9.2000।

निगरानी तंत्र स्थापित नहीं कर सका।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वे बजट परिपत्र के परिशिष्ट VI-ई के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अपेक्षित सृजन का विवरण वित्त मंत्रालय को प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 से पूर्व, उस समय लागू बजट परिपत्र के अंतर्गत प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अनुमानित सृजन या उपयोग की रिपोर्टिंग के लिए कोई निर्धारित प्रारूप उपलब्ध नहीं था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने आगे (दिसंबर 2025) बताया कि बजट परिपत्र के परिशिष्ट VI-ई में वर्ष 2022-25 की अवधि के लिए प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक डेटा और प्रक्षेपित अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

हालांकि, आंकड़ों को तैयार करने के आधार/कार्यप्रणाली से संबंधित फाइलें या विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट VI-ई में वर्ष के दौरान प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के प्रस्तावित उपयोग का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का यह दावा कि वर्ष 2022-23 से पूर्व कोई निर्धारित प्रारूप उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित सृजन का विवरण वित्त मंत्रालय को प्रेषित नहीं किया गया, उसके स्वयं के वर्ष 2000 के दिशा-निर्देशों का भी खंडन करता है।

अतः प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के लिए बजट निर्धारण की व्यवस्था विकसित करने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को दो दशक लग गए, और वह व्यवस्था भी अभी तक पूर्ण नहीं है।

अनुशंसा 38:

सी.एस.आई.आर. और उसकी प्रयोगशालाएं वार्षिक बजटीय योजना में एल.एच.आर.एफ. के प्रस्तावित उपयोग को शामिल कर सकती हैं।

ख. प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग के लिए योजना

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना के उद्देश्यों में से एक यह है कि इसके उपयोग को प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की ओर निर्देशित किया जाए तथा व्यवस्थित बजट निर्धारण के माध्यम से उनके अवसंरचना उन्नयन को सुनिश्चित करते हुए उनके वित्तीय संसाधनों को पूरक बनाया जाए। प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि की स्थापना से पूर्व, बजटीय आवंटनों की अनिश्चितता और विलंब के कारण दीर्घकालिक संसाधन योजना बनाना संभव नहीं था। अतः दीर्घकालिक योजना को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना का अभिन्न अंग बनाया जाना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2024) यह पाया कि प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग की योजना के लिए कोई संरचित तंत्र अपनाया नहीं जा रहा है, जैसे कि लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करना आदि। परिणामस्वरूप, परिषद के पास समापन शेष राशि वर्ष 2021-2025 के दौरान ₹1,948.19 करोड़⁶⁰ से बढ़कर ₹3,699.55 करोड़⁶¹ हो गई, जो 62.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इस उल्लेखनीय वृद्धि का एक प्रमुख कारण अप्रयुक्त शेष राशि पर अर्जित ब्याज था।

इस पर ध्यान आकर्षित किए जाने पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने (सितंबर 2025) कहा कि वह प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के विवेकपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग के लिए नए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक पहलों को निरंतर प्रोत्साहित

⁶⁰ ₹31.94 करोड़ के अर्जित ब्याज सहित।

⁶¹ ₹208.87 करोड़ के अर्जित ब्याज सहित।

और आरंभ कर रहा है। ऐसी पहलों का एक उल्लेखनीय उदाहरण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्पेशल प्रोजेक्ट्स स्कीम 2024 है, जिसे अक्टूबर 2024 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज़न 2030 की पूर्ति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया तथा जो पूर्णतः वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि से वित्तपोषित है। इस पहल का चरण-1 (2024 से 2027) वर्तमान में संचालित है और इसका उद्देश्य विज्ञान काल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अमृत काल चुनौतियों का समाधान करने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्वदेशी प्रयासों को सुदृढ़ करना है। अगस्त 2025 तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गई: (क) अनुसंधान एवं विकास सीड फंड परियोजनाओं हेतु ₹33.48 करोड़, (ख) सुविधा सृजन परियोजना 2.0 के लिए ₹75.35 करोड़, (ग) पायलट प्लांट परियोजनाओं हेतु ₹76.83 करोड़, (घ) प्राथमिकता उपकरण निधि के अंतर्गत क्रय हेतु ₹88.08 करोड़, तथा (ङ) औचित्यपूर्ण कार्य एवं सेवाएँ से संबंधित कार्यों हेतु ₹36.36 करोड़। उक्त धनराशियाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए निर्धारित हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने आगे (दिसंबर 2025) जोड़ा कि दीर्घकालिक योजना के रूप में सी.एस.पी.एस. के अंतर्गत लगभग ₹400 करोड़ के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

यह उत्तर इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि यद्यपि प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि की स्थापना का उद्देश्य दीर्घकालिक संसाधन योजना सुनिश्चित करना था, तथापि ऐसी योजना को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अत्यंत हाल में, अर्थात् 2024-25 से, लेखापरीक्षा (6 अगस्त 2024) की शुरुआत के बाद ही अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उल्लिखित परियोजनाओं (औचित्यपूर्ण कार्य एवं सेवाएँ से संबंधित कार्यों)⁶²

⁶² वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

को छोड़कर) के लिए ₹235.77 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 31 मार्च 2025 तक केवल ₹95.64 करोड़ ही व्यय कर सका। यह इन परियोजनाओं के अंतर्गत धीमी वित्तीय प्रगति को दर्शाता है।

अनुशंसा 39:

सी.एस.आई.आर. और उसकी प्रयोगशालाओं को एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग के लिए अपनी योजना और बजट तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में अनुशंसा को स्वीकार किया तथा बताया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को समय-समय पर प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के प्रभावी उपयोग के लिए संवेदनशील बनाया जाता है। प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग तथा संबंधित विषयों के संबंध में एफ.ए., वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सितंबर 2025 में एक पत्र भी जारी किया गया।

ग. नवाचार निधि

जुलाई 2016 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने संबंधित प्रयोगशाला में संधारित प्रयोगशाला आरक्षित निधि तथा मुख्यालय में संधारित मुख्यालय आरक्षित निधि में से प्रत्येक के 50 प्रतिशत अंश को मिलाकर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नवाचार निधि के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। इस निधि का उपयोग प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्रों और प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना, स्टार्ट-अप एवं स्पिन-ऑफ का सृजन, स्टार्ट-अप को सीड पूंजी प्रदान करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएँ विकसित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आउटरीच

केंद्रों की स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन तथा अन्य संबंधित पहलों के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषद ने नवाचार निधि के उपयोग के लिए कोई ठोस योजना विकसित नहीं की। स्थापना के बाद से इस निधि का अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया तथा यह सावधि जमा में निष्क्रिय पड़ी रही। मार्च 2019 से मार्च 2024 के बीच कोष राशि ₹423 करोड़ से बढ़कर ₹627.71 करोड़ हो गई।

इस प्रकार, वर्ष 2016 से नवाचार निधि के संचालन में न आने के कारण इसकी कोष राशि सावधि जमा में निष्क्रिय पड़ी रही, जिससे इसके सृजन का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणी में उठाई गई चिंता पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा हाल के महीनों में नवाचार निधि को संचालित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों—जैसे नवाचार पार्क एवं इनक्यूबेशन केंद्र, औद्योगिक संघों या उत्पादन भागीदारों के लिए अगली पीढ़ी की अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ, अन्य मंत्रालयों या उद्योगों के साथ संयुक्त उपक्रम, अकादमिक-अनुसंधान सहयोग तथा नवाचारी (क्रेज़ी) विचारों को प्रोत्साहन में कई दौर की चर्चाएँ आयोजित की गई हैं।

4.1.5 सृजन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दिनांक 4 सितंबर 2000 के आदेश के पैरा संख्या 2 'प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का सृजन' के अनुसार, प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अंतर्गत शामिल अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियों के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं:

- रॉयल्टी एवं प्रीमिया (बौद्धिक संपदा अधिकारों के लाइसेंसिंग से),

- परामर्श शुल्क,
- प्रायोजित परियोजना शुल्क,
- ओवरहेड प्रभार,
- समाप्त परियोजनाओं/कार्यादेशों की अप्रत्यावर्तनीय शेष राशि,
- कार्यादेश (जॉब वर्क) प्रभार,
- परीक्षण एवं विश्लेषणात्मक प्रभार।
- कंप्यूटर शुल्क,
- अन्य तकनीकी सेवाएँ,
- प्रायोजित/परामर्श परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना का उपयोग,
- प्रयोगशाला आरक्षित निधियों के निवेश पर अर्जित ब्याज, तथा
- प्रायोजित/परामर्श परियोजना निधियों के निवेश पर अर्जित ब्याज।

हालांकि, उपर्युक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदेश (सितंबर 2000) के अनुसार, निम्नलिखित प्राप्तियाँ प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में शामिल नहीं की जाती हैं:

- प्रायोजित/परामर्श/अनुदान-इन-एड परियोजना निधियों के निवेश पर अर्जित वह ब्याज, जो वित्तपोषण एजेंसी को समायोज्य और/या प्रत्यावर्तनीय हो।
- रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग; तथा
- परामर्श/संविदा, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी सेवाओं से प्राप्त बौद्धिक शुल्क का वितरणीय भाग।

4.1.5.1 निवेश से प्राप्त ब्याज

यह विवरण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित

निधि (प्रयोगशाला आरक्षित निधि) के कानूनी और प्रक्रियात्मक आधार को स्पष्ट करता है। सितंबर 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह निधि पूरी तरह से संस्थान की अपनी सेवाओं से उत्पन्न राजस्व पर निर्भर है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2021-2024 के दौरान एल.एच.आर.एफ. में उत्पन्न ₹1,066.94 करोड़ में से ₹510.68 करोड़ (47.86 प्रतिशत) निवेश पर ब्याज से आया, जैसा कि अनुलग्नक 10 में विस्तृत है।

यह प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अपर्याप्त उपयोग के कारण इसके संचय को दर्शाता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि इस निधि में वृद्धि काफी हद तक संचित राशि पर अर्जित ब्याज के कारण हुई थी, न कि अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियों—जैसे कि रॉयल्टी और प्रीमियम, परामर्श शुल्क, प्रायोजित परियोजना शुल्क तथा परीक्षण एवं विश्लेषणात्मक शुल्क के कारण।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, आंकड़ों और टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे इस संबंध में आवश्यक पहल करने के लिए तैयार हैं।

अनुशंसा 40:

सी.एस.आई.आर. यह सुनिश्चित कर सकता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.) के लाइसेंस से उत्पन्न होने वाले रॉयल्टी और प्रीमियम जैसे वैकल्पिक स्रोतों से धन उत्पन्न करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

4.1.5.2 गैर-निर्धारित स्रोतों से प्राप्तियाँ

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, प्रयोगशाला आरक्षित निधि के सृजन का एक उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास तथा गैर-अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियों को उनके उपयुक्त उपयोग हेतु पृथक करना था। गैर-अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियाँ (विविध प्राप्तियाँ) प्रयोगशाला और

मुख्यालय आरक्षित निधि में जमा नहीं की जानी चाहिए तथा इन्हें व्यय के विभिन्न मदों के अंतर्गत होने वाली कमी की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 की प्राप्ति वाउचरों की परीक्षण-जांच से यह उजागर हुआ कि ₹25.35 करोड़ की विविध प्राप्तियाँ निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में जमा कर दी गई। इसका विवरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 27: प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में गलत रूप से जमा की गई प्राप्तियाँ

(₹ लाख में)

प्रयोगशाला/संस्थान	वर्ष	विवरण	राशि
नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज	2021-22	जी.एस.टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट	1496.65
	2021-22	रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग	10.74
	2022-23	रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग	4.31
	2023-24	परियोजना शुल्क/बौद्धिक शुल्क का वितरणीय भाग	433.78
		उप-योग	1945.48
सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	2021-22	रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग	10.88
	2022-23	जी.एस.टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट	370.71
	2022-23	रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग	33.72
	2023-24	रॉयल्टी एवं प्रीमिया का वितरणीय भाग	3.57
		उप-योग	418.88
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी,	2023-24	सावधि जमा रसीद की प्रेषण राशि	128.47
	2023-24	प्रशिक्षण शुल्क	32.98
		उप-योग	161.45
इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी	2023-24	प्रकाशन शुल्क	7.11
		पाठ्यक्रम/इंटर्नशिप शुल्क	1.84
		पी.एच.डी. प्रवेश शुल्क	0.20
		उप-योग	9.15
कुल योग			2534.96

इससे न केवल अनुसंधान एवं विकास तथा गैर-अनुसंधान एवं विकास प्राप्तियों को उनके उपयुक्त उपयोग हेतु पृथक करने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में राजस्व सृजन को अधिक दर्शाए जाने (ओवरस्टेटमेंट) की स्थिति भी उत्पन्न हुई।

इस पर ध्यान आकर्षित किए जाने पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने (दिसंबर 2025) कहा कि प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त जी.एस.टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना उचित नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि सावधि जमा रसीद की प्रेषण राशि, प्रशिक्षण शुल्क, प्रकाशन शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क तथा पी.एच.डी. प्रवेश शुल्क से संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त कर सुधारात्मक कार्रवाई कर दी गई है। रॉयल्टी एवं प्रीमिया के वितरणीय भाग को प्रयोगशाला आरक्षित निधि की प्राप्ति के रूप में लेने के संबंध में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा उसकी प्रयोगशालाओं में किसी भी परियोजना या कार्य के अंतर्गत कर्मचारियों के बीच धनराशि/मानदेय के वितरण/साझेदारी को 26 मार्च 2021 से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने यह भी बताया कि इस संबंध में आगे दिशा-निर्देश जारी किए जाने प्रस्तावित हैं।

अनुशंसा 41:

सी.एस.आई.आर. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-अनुसंधान और विकास प्राप्तियों को एल.एच.आर.एफ. में जमा नहीं किया जाए और उनका उचित उपयोग किया जाए ताकि बजटीय समर्थन पर निर्भरता कम की जा सके।

4.1.5.3 बंद की गई बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं में देखी गई समस्याएँ

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएँ बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं, जैसे कि प्रायोजित, परामर्श और तकनीकी सेवा परियोजनाओं को हाथ में लेकर पर्याप्त बाह्य नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।

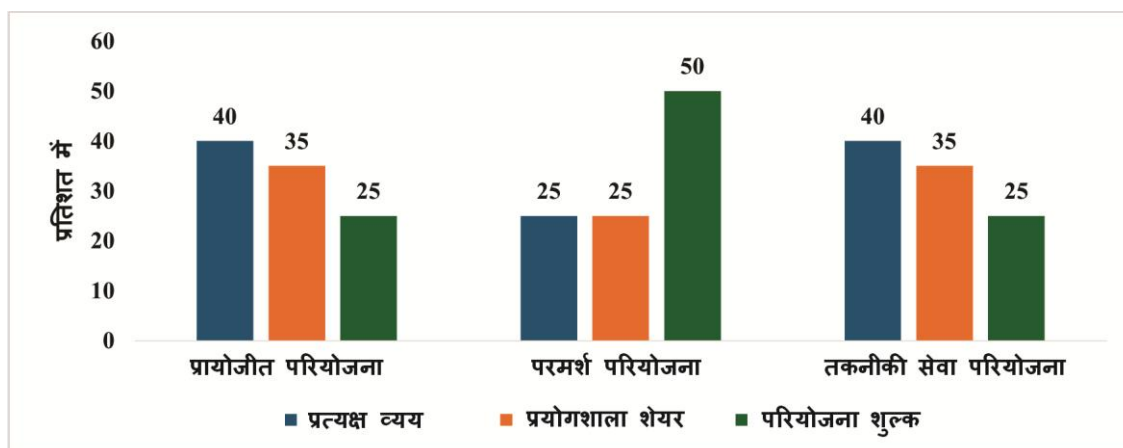
- **प्रायोजित परियोजनाएं:** ऐसी परियोजनाएं जो पूरी तरह से क्लाइंट (ग्राहक) द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जिनके विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास उद्देश्य और स्पष्ट रूप से परिभाषित

अपेक्षित परिणाम होते हैं। ये परियोजनाएं आमतौर पर बौद्धिक संपदा या ज्ञानकोष के सृजन के साथ संपन्न होती हैं। प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्रक्रिया डिजाइन और इंजीनियरिंग, प्रोसेस मॉडलिंग और सिमुलेशन, गणनात्मक विधियों का अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर का विकास आदि भी शामिल हैं।

- **परामर्श परियोजनाएं:** इसमें प्रयोगशाला के उपलब्ध ज्ञानकोष या विशेषज्ञता के आधार पर वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरिंग या अन्य पेशेवर सलाह/सहायता शामिल होती है। इसमें परामर्श के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयोगों और गणनाओं हेतु प्रयोगशाला की सुविधाओं के न्यूनतम उपयोग की परिकल्पना की जाती है।
- **तकनीकी सेवाएँ:** इनका उद्देश्य ग्राहकों को प्रयोगशाला के उपलब्ध ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के आधार पर सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार तकनीकी सेवाओं में परीक्षण और विश्लेषण (प्रमाणन और अंशांकन/कैलिब्रेशन सहित), नियमित प्रशिक्षण, सलाहकार प्रकृति की तकनीकी सहायता, निर्माण अनुसंधान एवं विकास के लिए विशेष उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव तथा सूचना प्रदान करना शामिल है।

उपरोक्त परियोजनाओं की लागत में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात्, प्रत्यक्ष व्यय प्रयोगशाला हिस्सा और परियोजना शुल्क। प्रत्यक्ष व्यय में परियोजना से संबंधित सभी अनुमानित खर्च शामिल होते हैं। प्रयोगशाला हिस्सा शुल्क सी.एस.आई.आर. द्वारा एक अवधि के दौरान ज्ञानकोष और सुविधाओं के निर्माण एवं उन्हें बनाए रखने में किए गए निवेश के लिए लिया जाता है। परियोजना शुल्क में कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय शामिल है।

तकनीकी हस्तांतरण और ज्ञानकोष के उपयोग के लिए सी.एस.आई.आर. दिशानिर्देश 2017 के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत में प्रत्यक्ष व्यय, प्रयोगशाला हिस्सा और परियोजना शुल्क घटकों का अनुपात **चार्ट 2** में दर्शाए अनुसार होना चाहिए।



चार्ट 2: परियोजना लागत के घटक

क. बंद की गई परियोजनाओं का गैर-निपटान

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दिशा-निर्देशों (2017) के अनुसार, प्रयोगशाला हिस्से को प्रत्यक्ष व्यय के गैर-वापसी योग्य शेष के साथ प्रयोगशाला हस्तगत आरक्षित निधि (प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 2021-2024 के बीच बंद की गई बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाओं के ₹415.71 करोड़ के अनसुलझे शेष का निपटान नहीं किया गया था और देय राशि को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया था। प्रयोगशाला-वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 28: बंद की गई बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाओं के अनसुलझे शेष

(₹ करोड़ में)

संस्थान/प्रयोगशालाएं	वर्ष				योग
	मार्च 2021 तक	2021-22	2022-23	2023-24	
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान	54.19	8.82	20.00	35.82	118.83
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला	2.94	0.41	0.93	1.75	6.03
राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं	16.58	2.77	6.72	24.57	50.64
भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान	निरंक	0.49	0.38	0.23	1.10
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला	3.06	2.59	8.96	8.40	23.01
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान	27.82	52.12	54.56	38.90	173.40

संस्थान/प्रयोगशालाएं	वर्ष				योग
	मार्च 2021 तक	2021-22	2022-23	2023-24	
केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान	7.17	0.87	1.74	1.69	11.47
जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान	0.19	0.02	0.03	2.76	3.00
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान	0.01	निरंक	निरंक	निरंक	0.01
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	15.56	2.41	8.31	1.94	28.22
कुल योग					415.71

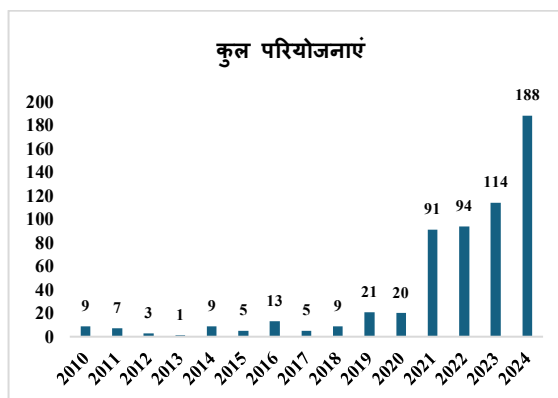
यह दर्शाता है कि संस्थानों/प्रयोगशालाओं ने संबंधित हितधारकों या वित्तपोषक एजेंसियों के साथ इन परियोजना खातों का निपटान करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा कि बंद की गई बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाओं के शेष खातों के निपटान के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस मामले को तेजी से निपटाने के लिए, सी.एस.आई.आर. के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (सितंबर 2025) और केंद्रीय योजना निदेशालय के प्रमुख (दिसंबर 2025) द्वारा सभी सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं को विस्तृत पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें उन्हें लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

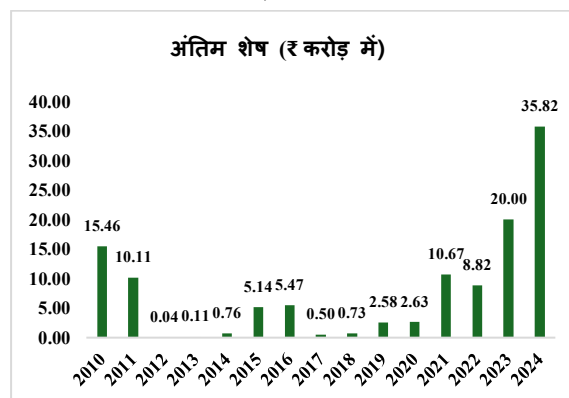
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से संबंधित बंद परियोजना के बिना खर्च किए गए शेष से जुड़ी एक केस स्टडी नीचे दी गई है:

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने मार्च 2024 तक 589 बंद परियोजनाओं में ₹118.83 करोड़ की राशि 'बिना खर्च किए गए शेष' के रूप में दिखाई थी, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

अनसुलझी बंद बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाएं



बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाओं में अनसुलझा अंतिम शेष



चार्ट 3: बंद की गई ई.सी.एफ. परियोजनाएं और उनमें अनसुलझा अंतिम शेष

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष 2010 से ही बंद परियोजनाओं में पर्याप्त राशियाँ अनसुलझी पड़ी हुई हैं।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में मद-वार बिना खर्च किए गए शेष के आगे के विश्लेषण से पता चला कि परियोजनाओं की लागत का निर्धारण अवास्तविक था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 29: केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में मद-वार बिना खर्च किया गया शेष

(₹ करोड़ में)

मद	राशि
रसायन और उपभोग्य वस्तुएं	1.78
आकस्मिक व्यय	7.17
उपकरण	3.34
बाह्य भुगतान	1.62
शुल्क	46.12
फेलोशिप खाता	0.83
विविध पूंजीगत वस्तुएं	0.26
उपरि-व्यय (ओवरहेड्स)	32.38
वेतन	14.75
सेवा कर	1.63
यात्रा भत्ता	3.01
अवर्गीकृत	5.66
मजदूरी	0.21

मद	राशि
कार्य और सेवाएँ	0.08
कुल योग	118.84

शुल्क में ₹46.12 करोड़, उपरि-व्यय में ₹32.38 करोड़, वेतन में ₹14.75 करोड़, उपकरण में ₹3.34 करोड़ और रसायन एवं उपभोग्य वस्तुओं की मदों में ₹1.78 करोड़ जैसे खर्च न किए गए शेष की उपस्थिति दर्शाती है कि परियोजनाओं की लागत का निर्धारण अवास्तविक और बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'अवर्गीकृत' मद के तहत पड़ी ₹5.66 करोड़ की राशि यह स्पष्ट करती है कि खातों का उचित मिलान नहीं किया गया था।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने अपने उत्तर (सितंबर 2025) में कहा कि 589 बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं में से 188 परियोजनाओं को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। सी.आर.आर.आई. ने ₹10.78 करोड़ के शेष के साथ 107 परियोजनाओं को पहले ही बंद कर दिया है और प्रयोगशाला आरक्षित निधि के ₹6.87 करोड़ के देय हिस्से को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शेष 81 परियोजनाओं को अक्टूबर 2025 तक बंद करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा उपरोक्त कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बाद की गई। इसके अलावा, सभी परियोजनाओं को बंद करने के संबंध में अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

ख. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत ऋणात्मक शेष

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशों⁶³ के अनुसार, बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं में ऋणात्मक शेष नहीं दिखना चाहिए, अर्थात्, किसी भी परियोजना के तहत व्यय प्राप्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाओं के पास 265

⁶³ पत्र संख्या 41(43)/2004-IA दिनांक 30 सितंबर 2014।

बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 182 परियोजनाओं में ₹35.73 करोड़ का धनात्मक शेष (*अनुलग्नक 11*) और 83 परियोजनाओं में ₹32.51 करोड़ का ऋणात्मक शेष (*अनुलग्नक 12*) था। राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाओं ने इन 83 परियोजनाओं में किए गए अतिरिक्त व्यय का समायोजन, 182 परियोजनाओं के धनात्मक शेष के साथ कर दिया। शेष ₹3.23 करोड़ की राशि को (मार्च 2023 में) प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹32.50 करोड़ का कम विवरण हुआ, क्योंकि ₹35.73 करोड़ के अंतिम शेष के मुकाबले केवल ₹3.23 करोड़ ही एल.एच.आर.एफ. में जमा किए गए।

ध्यान दिलाए जाने पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और अपनी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को ऊपर उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

अनुशंसा 42:

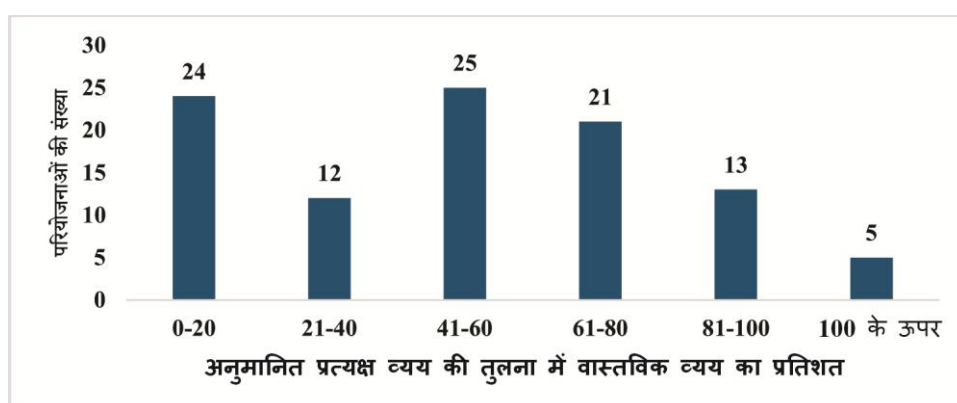
सी.एस.आई.आर. यह सुनिश्चित कर सकता है कि बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के खातों का निपटान उनकी स्वीकृत अवधि की समाप्ति पर तुरंत किया जाए और बंद परियोजनाओं की गैर-वापसी योग्य शेष राशि बिना किसी देरी के एल.एच.आर.एफ. में स्थानांतरित कर दी जाए।

ग. परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष व्यय का आकलन और प्रभारित किया जाना

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञानकोष के उपयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देश 2017 के अनुसार, बाह्य नकदी प्रवाह परियोजना की प्रत्यक्ष लागत में तैनात सी.एस.आई.आर. कर्मचारियों के मैन-डेज़ की लागत, उपभोग्य वस्तुएं, कच्चे माल की लागत, सेवाएं, उपयोगिताएं (उपकरण, कंप्यूटर का उपयोग, आकस्मिक व्यय आदि शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत की गणना करते समय इन

प्रत्यक्ष लागतों को ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार धनराशि प्राप्त की जाती है।

वर्ष 2021-2024 की अवधि के दौरान केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की बंद की गई बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं में प्रभारित प्रत्यक्ष व्यय के विरुद्ध किए गए वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।



चार्ट 4: सी.ई.सी.आर.आई. में प्रत्यक्ष व्यय का अनुमान

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय के मुकाबले, 61 परियोजनाओं पर किया गया वास्तविक व्यय वित्तपोषित एजेंसी से लिए गए अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय का 60 प्रतिशत या उससे कम था।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्रत्यक्ष व्यय के अनुमानों में ऐसी लागतें शामिल थीं जिनका आकलन काल्पनिक आधार पर किया गया था, जैसे—नियमित रूप से कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए जनशक्ति, सेवा और उपयोगिताएँ तथा उपकरण एवं कंप्यूटर का उपयोग। हालाँकि ये लागतें परियोजना के तहत प्रायोजकों से वसूल की गई थीं, लेकिन कोई वास्तविक व्यय दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन लागतों को बिना खर्च किए गए शेष के रूप में दिखाया गया और नियमित बजट में स्थानांतरित करने के बजाय प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में ले लिया गया, जबकि मूल रूप से इन लागतों का वहन उसी नियमित बजट से किया गया था।

उदाहरण के लिए, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि 'जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान' ने दिसंबर 2021 में 'सेलोजन थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक परियोजना के लिए समझौता किया था, जिसका शीर्षक 'लैटिवायरल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कंस्ट्रक्ट्स का आणविक क्लोनिंग और इन-विट्रो सत्यापन' था। इस परियोजना की समापन रिपोर्ट फरवरी 2023 में सेलोजन थेरेप्यूटिक्स को सौंपी गई थी। इस परियोजना पर अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय के मुकाबले किए गए वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 30: अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय के विरुद्ध परियोजना पर किया गया वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय

मद-वार विवरण	अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय (₹ में)	वास्तविक प्रत्यक्ष व्यय (₹ में)	बिना खर्च की गई राशि (₹ में)	बिना खर्च की गई राशि (प्रतिशत)
जनशक्ति	431760	291000	140760	32.60
रसायन/उपभोग्य वस्तुएं	1100000	1055106	44894	4.08
सेवा और उपयोगिताएँ	50000	0	50000	100
उपकरण और कंप्यूटर का उपयोग	52670	0	52670	100
बाह्य भुगतान	10000	0	10000	100
आकस्मिक व्यय	100000	0	100000	100
कुल योग	1744430	1346106	398324	22.83

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों के लिए वित्तपोषक एजेंसी से ₹0.17 करोड़ लिए गए थे। परियोजना पर किया गया कुल व्यय ₹0.14 करोड़ था। 'जनशक्ति' के तहत लागत अनुमानों में के नियमित वैज्ञानिक के 10 मैन-डेज़ के लिए ₹60,000 'सेवा और उपयोगिताओं' पर ₹50,000 तथा 'उपकरण और कंप्यूटर के उपयोग' पर ₹53,000 शामिल थे। हालांकि, यह देखा गया कि इन मदों के तहत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन मदों के तहत बिना खर्च की गई शेष राशि को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि नियमित कर्मचारियों और स्थायी बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं से जुड़ी लागतों का वहन पहले की तरह सरकारी अनुदानों से ही होता रहा।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2025) में सरकारी अनुदानों पर निर्भरता कम करने के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि परियोजना का उच्च मूल्य प्रत्यक्ष व्यय के हिस्से के रूप में काल्पनिक अनुमान के कारण है। इसलिए, बेहतर लागत वास्तविकता के लिए लागत पद्धति को तर्कसंगत बनाने हेतु, इसने एक नया लागत ढांचा तैयार किया है और 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दिशा-निर्देशों' को संशोधित किया है। संशोधित दिशा-निर्देश पहले ही व्यय विभाग (जून 2025) को सौंप दिए गए हैं और वर्तमान में उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

अनुशंसा 43:

सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रत्यक्ष लागत से संबंधित प्राप्तियों के लेखांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है।

4.1.5.4 प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि से वित्तपोषित परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने, नीति आयोग के तत्वावधान में, कोयला आधारित मेथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2020 में 'कोल-सिनगैस टू मेथनॉल' नामक एक परियोजना शुरू की थी। प्रारंभ में, परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना था, जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद, परियोजना को 30 सितंबर 2025 तक और विस्तारित किया गया, लेकिन वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही अगस्त 2024 में इसे समय से पहले बंद कर दिया गया।

परियोजना के मुख्य डिलिवरेबल्स में 50 Nm³/h सिनगैस को संभालने में सक्षम एक सिनगैस क्लीनिंग यूनिट का विकास, साथ ही 250 किग्रा/दिन की क्षमता वाली सिनगैस-से-मेथनॉल उत्पादन के लिए एक पायलट-स्केल सुविधा, और सिनगैस-से-मेथनॉल रूपांतरण की प्रक्रिया

विकसित करना शामिल था। हालाँकि, यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ; इसके बजाय, मौजूदा इन-हाउस संसाधनों का उपयोग करके 40 किग्रा/दिन की क्षमता वाला एक पायलट प्लांट स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के दायरे में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन हुआ।

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि से ₹26.30 करोड़ की राशि से वित्तपोषित इस परियोजना के तहत अगस्त 2024 तक केवल ₹0.56 करोड़ का व्यय किया गया था। देरी और कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही अगस्त 2024 में परियोजना को समय से पहले बंद कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि विक्रेताओं से बहुत अधिक कीमत के उद्धरण प्राप्त हुए थे, हालाँकि, बाद में किसी भी विक्रेता ने सी.एस.आई.आर. की बोली का जवाब नहीं दिया। इस प्रकार, कई बार पुनः निविदा करने के बाद भी निविदा आमंत्रण सूचना के जवाब में बोली दाताओं से खराब या कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसने 250 किलोग्राम/दिन क्षमता वाले मेथनॉल संयंत्र के विकास के उद्देश्यों को लागू करने में समस्याएँ पैदा कीं।

यह उत्तर स्पष्ट करता है कि अनुमान वास्तविक नहीं थे, जिसके कारण परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.1.6 अनुश्रवण

अनुश्रवण निरंतर देखरेख की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि गतिविधियाँ योजना के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं, उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। यह समस्याओं की समय पर पहचान करने में सक्षम बनाता है और सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करता है।

4.1.6.1 अनुश्रवण समिति का गठन न किया जाना

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि दिशा-निर्देश और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विभिन्न आदेश एल.एच.आर.एफ. के सृजन और उपयोग के लिए अनुश्रवण तंत्र के संबंध में मौन हैं। हालांकि, दिसंबर 2019 में, सी.एस.आई.आर. ने एल.एच.आर.एफ. के तहत सहायता के लिए पात्र अतिरिक्त गतिविधियों को निर्दिष्ट करते समय, इन गतिविधियों पर वार्षिक व्यय सीमा और उनके निर्धारित उद्देश्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में एक समिति के माध्यम से एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया था। यह समिति एल.एच.आर.एफ. से प्रतिस्पर्धी निधियों की निकासी निर्धारित करने, ऐसी निधियों से उत्पन्न परिणामों की निगरानी करने और एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से वार्षिक सीमा के विरुद्ध व्यय की समग्र ट्रैकिंग बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी।

इसके अतिरिक्त, गतिविधियों के लिए प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग का निर्धारण प्रयोगशाला स्तर पर किया जाना था और अनुपालन की रिपोर्ट अनुश्रवण पोर्टल पर दी जानी थी। प्रयोगशाला निदेशकों को निर्धारित सीमा तक निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया था, जो समेकित त्रैमासिक रिपोर्टिंग और पोर्टल पर व्यक्तिगत मामलों के अपलोड के अधीन था।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वार्षिक व्यय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया और वर्ष 2021-24 के दौरान किसी भी प्रतिस्पर्धी निधि का वितरण नहीं किया। हालांकि, लेखापरीक्षा शुरू होने के बाद, सी.एस.आई.आर. ने अक्टूबर 2024 में एक 'सी.एस.आई.आर. विशेष परियोजना योजना' शुरू की, जिसकी देखरेख विभिन्न अनुश्रवण समितियों के माध्यम से की जा रही है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सरकारी अनुदान और प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि

के उपयोग की निगरानी के लिए हर महीने सभी सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/मुख्यालयों के साथ 'मासिक उपयोगिता अनुश्रवण बैठकें' आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक सी.एस.आई.आर. प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई के एल.एच.आर.एफ. के उपयोग की नियमित निगरानी सी.एस.आई.आर. के लेखांकन सॉफ्टवेयर, यानी 'अकाउंट्स मैनेजर सॉफ्टवेयर' में उपलब्ध रिपोर्टों के माध्यम से की जा रही है। हालांकि, केंद्रीय लेखा प्रभाग-सूचना प्रौद्योगिकी से वर्तमान सॉफ्टवेयर में एल.एच.आर.एफ. के व्यय के आंकड़ों, सीमाओं, लक्ष्यों, प्रेषण आदि की प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक मॉड्यूल तलाशने/विकसित करने का अनुरोध किया गया है।

ए.एम.एस. के माध्यम से प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग की निगरानी के संबंध में डी.एस.आई.आर. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सी.एस.आई.आर. ने स्वयं (फरवरी 2026 में) कहा था कि एल.एच.आर.एफ. निधि की निगरानी के संबंध में ए.एम.एस. से कोई विशिष्ट डेटा तैयार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक अलग मॉड्यूल विकसित करने का प्रस्ताव अभी भी प्रारंभिक चरण में है और एक समर्पित पोर्टल या रिपोर्टिंग तंत्र की अनुपस्थिति प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण की कमी को दर्शाती है।

4.1.6.2 निधियों के हस्तांतरण में विसंगति

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2004) के अनुसार, वर्ष के दौरान उत्पन्न प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि का पांच प्रतिशत हिस्सा प्रयोगशालाओं द्वारा सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में बनाए रखे जाने वाले 'मुख्यालय आरक्षित कोष' में हस्तांतरित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा कम राशि (56 मामले) या बिल्कुल भी राशि हस्तांतरित न करने, और कुछ अन्य द्वारा 'मुख्यालय आरक्षित कोष' में अतिरिक्त राशि (55 मामले) हस्तांतरित करने में विसंगति थी, जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक 13 में दिया गया है। यह प्रयोगशालाओं और सी.एस.आई.आर.

मुख्यालय द्वारा रखे गए खातों के बीच मिलान की कमी की ओर इशारा करता है।

डी.एस.आई.आर. ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों के आलोक में एक व्यापक समीक्षा की गई, जिससे पता चला कि वर्ष 2021-24 की अवधि के लिए कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा मुख्यालय को प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के अपने पांच प्रतिशत हिस्से के रूप में ₹3.07 करोड़ प्रेषित किया जाना शेष था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि सी.एस.आई.आर. द्वारा अब पूर्ण देय राशि प्राप्त कर ली गई है।

अनुशंसा 44:

सी.एस.आई.आर. मुख्यालय एक समर्पित पोर्टल सहित एल.एच.आर.एफ. के उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार कर सकता है।

4.1.7. निष्कर्ष

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि से व्यय बहुत कम था क्योंकि अधिकांश समय, नमूना ली गई प्रयोगशालाओं (सी.एस.आई.आर. मुख्यालय सहित) ने पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पन्न निधि के अनिवार्य एक-तिहाई हिस्से का भी उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में संचित शेष बढ़ता रहा और 31 मार्च 2025 तक यह ₹3,490.68 करोड़ पर पहुंच गया।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के सृजन और उपयोग के लिए वार्षिक बजटीय योजना और दीर्घकालिक योजना को बहुत हाल ही में वर्ष 2024-25 से अपनाया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इनोवेशन फंड के तहत ₹627.71 करोड़ की धनराशि, जिसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना, स्टार्टअप्स और स्पिन-ऑफ बनाना आदि था, अप्रयुक्त रही। प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि की लगभग 48 प्रतिशत प्राप्तियां ब्याज से आईं। यह अपर्याप्त उपयोग के कारण प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के संचय को दर्शाता

है और यह भी कि फंड में वृद्धि, काफी हद तक, अनुसंधान और विकास प्राप्तियों के बजाय संचित निधि पर अर्जित ब्याज के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि में विविध प्राप्तियों के अनधिकृत जमा, बंद हो चुकी बाह्य नकदी प्रवाह परियोजनाओं के खातों का निपटान न होने और ईसीएफ परियोजनाओं के तहत प्रायोजक/वित्तपोषित एजेंसी से लिए गए काल्पनिक प्रत्यक्ष व्यय के मामले भी देखे गए। इसके अलावा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनिवार्य समिति, पोर्टल और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि के उपयोग पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण का अभाव रहा।

अध्याय V

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

5.1 फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय तथा प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में एक फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया, जो स्वीकृत योजना में शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रतिपूरक वनीकरण निधि से प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया गया।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 5 के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एकत्रित सभी धनराशियों का 10 प्रतिशत, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के तहत रखा गया है और उस पर अर्जित ब्याज, तथा राष्ट्रीय निधि में होने वाली सभी नई प्राप्तियाँ जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (4) में प्रावधान है और उन पर अर्जित ब्याज का उपयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण अर्थात्, (कैम्पा) के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

नवंबर 2019 में, कैम्पा के शासी निकाय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) के लिए ₹313.67 करोड़ की कुल लागत वाली एक योजना, 'पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढीकरण' को मंजूरी दी थी, जिसे 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' से वित्तपोषित किया जाना था। कैम्पा ने इस योजना को मंजूरी देते समय (जनवरी 2020), खंड 9 के

माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया था कि राशि केवल योजना के अनुसार ही खर्च की जाएगी और कैम्पा की पूर्व सहमति के बिना व्यय की अनुमोदित मदों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस योजना का एक घटक 'भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की वानिकी विस्तार रणनीति और कार्य योजना का संचालन' था, जिसे पांच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2024-25) में ₹47.88 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाना था। इस घटक में दो गतिविधियाँ शामिल थीं, अर्थात्, 'मौजूदा विस्तार गतिविधियों का सुदृढीकरण' और 'नई विस्तार पहल'। अन्य बातों के साथ-साथ, 'नई विस्तार पहल' के अंतर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के प्रत्येक संस्थान में ₹3.42 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ 'प्रौद्योगिकी विकास केंद्र' स्थापित किए जाने थे, ताकि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की तकनीक और अनुसंधान उपलब्धियों का प्रसार किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह देखा (मई 2024) कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने 'नई विस्तार पहल' घटक के कार्यान्वयन के लिए अपने अधीन एक स्वायत्त निकाय, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (वन अनुसंधान संस्थान) से एक कार्ययोजना मांगी थी, जिसे वन अनुसंधान संस्थान द्वारा दिसंबर 2019 में प्रस्तुत किया गया था। इस कार्ययोजना में, 'नई विस्तार पहल' के तहत ₹1.06 करोड़ की अनुमानित लागत से 'प्रौद्योगिकी विकास केंद्र' की स्थापना के अतिरिक्त, ₹1.54 करोड़ की अनुमानित लागत से एक 'फोटो गैलरी' का विकास भी शामिल था। चूंकि फोटो गैलरी का विकास कैम्पा के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित योजना का हिस्सा नहीं था, इसलिए कार्ययोजना में इसे शामिल किया जाना अनियमित था।

इसके बावजूद, वन अनुसंधान संस्थान ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 1 जुलाई 2020 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्य आदेश जारी कर दिया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2022 में फोटो गैलरी वन अनुसंधान संस्थान को सौंप दी और जून 2022 में ₹1.99 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रस्तुत किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के प्रत्येक संस्थान (कुल नौ⁶⁴) में 'प्रौद्योगिकी विकास केंद्र' स्थापित किए जाने थे। मार्च 2025 तक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने आठ केंद्रों⁶⁵ की स्थापना पर ₹3.42 करोड़ की अनुमोदित राशि के मुकाबले ₹5.28 करोड़ का व्यय किया, जिससे स्वीकृत राशि से ₹1.86 करोड़ अधिक खर्च किए गए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से प्राप्त उत्तर (दिसंबर 2025) अग्रेषित किया, जिसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने कहा कि वन अनुसंधान संस्थान पहले एक फोटो गैलरी का रखरखाव करता था, जिसे 2017 में वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य परिसर में स्थानांतरित किया जाना था। हालांकि, बजटीय बाधाओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के साथ फोटो गैलरी की स्थापना के बजट प्रस्ताव को केवल भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मंत्रालय के उत्तर पर इस तथ्य के आलोक में विचार किया जाना चाहिए कि जिस फोटो गैलरी को पहले धन की कमी के कारण वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य परिसर में स्थानांतरित नहीं किया जा सका था, उसे वर्ष 2019-20 में 'पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वानिकी अनुसंधान का सुदृढीकरण' योजना के तहत स्थानांतरित किया गया। अतः, फोटो गैलरी की स्थापना स्वीकृत घटकों से एक विचलन है और यह कैम्पा के अनुमोदन के खंड 9

⁶⁴ 1. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, 2. वन उत्पादकता संस्थान, रांची, 3. वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, 4. काष्ठविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु 5. उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, 6. वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद, 7. हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला, 8. वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर, 9. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।

⁶⁵ शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया था और वर्तमान में यह दो स्थानों, अर्थात् वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर और वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद में प्रगति पर है।

का उल्लंघन है, क्योंकि यह कैम्पा के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत गतिविधियों में शामिल नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का यह दावा कि फोटो गैलरी की स्थापना स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के भीतर की गई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों' की स्थापना के लिए केवल ₹3.42 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जिस पर मार्च 2025 तक पहले ही ₹5.28 करोड़ का वास्तविक व्यय किया जा चुका था।

इस प्रकार, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने न केवल कैम्पा निधि से फोटो गैलरी की स्थापना पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया, जो कि कैम्पा के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर भी ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया है।

अध्याय VI

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

6.1 भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सिस्टम के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

6.1.1 परिचय

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.ई.सी.आई./कंपनी) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम' है, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 को राष्ट्रीय सौर मिशन⁶⁶ के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में एस.ई.सी.आई. की एक प्रमुख भूमिका है।

इसके अतिरिक्त, एस.ई.सी.आई. ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों के लिए टर्नकी आधार पर सौर परियोजना विकास में भी कदम रखा है। कंपनी के पास श्रेणी-1 का पावर⁶⁷ ट्रेडिंग लाइसेंस है और वह सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से बिजली व्यापार क्षेत्र में सक्रिय है। संगठन को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया है और इसे सौर-पवन हाइब्रिड (ऊर्जा भंडारण के साथ/बिना), चौबीसों घंटे बिजली

⁶⁶ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती का समाधान करते हुए पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान भी होगा।

⁶⁷ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की दिनांक 2 जनवरी 2020 की अधिसूचना के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार लाइसेंस के आधार पर आवेदक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, श्रेणी 1 विद्युत व्यापार लाइसेंस के संबंध में आवेदन की तिथि पर आवेदक की न्यूनतम कुल संपत्ति (नेट वर्थ) ₹50 करोड़ होनी चाहिए और एक वित्तीय वर्ष में व्यापार के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा 7,000 मि.यू. (मिलियन यूनिट) से अधिक होनी चाहिए।

आपूर्ति, सुनिश्चित चरम बिजली आपूर्ति वाली नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिर एवं प्रेषणीय नवीकरणीय ऊर्जा जैसी नवीन परियोजना संरचनाओं की परिकल्पना/प्रोटोटाइपिंग/मॉडलिंग/नीतिगत वकालत के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाजार विकास को बढ़ावा देने और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का कार्य सौंपा गया है।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सिस्टम का कार्यान्वयन

अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एस.ई.सी.आई. ने प्रभावी निगरानी, दक्षता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाने के लिए एक एकीकृत आई प्रणाली लागू करने का इरादा किया। एस.ई.सी.आई. ने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की:

- विद्युत व्यापार, पूंजीगत व्यय परियोजना जीवनचक्र प्रबंधन और रूफटॉप योजनाओं के लिए सब्सिडी प्रबंधन हेतु एक एकीकृत मंच तैयार करना तथा ग्राहकों, विक्रेताओं और कर्मचारियों को मानक व्यावसायिक प्रथाओं का उपयोग करके सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक, त्वरित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना, जिससे प्रणाली के रखरखाव और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को कम किया जा सके।
- सत्य का एक प्रामाणिक एकल स्रोत प्रदान करना और उत्पत्ति के स्थान पर ही आँकड़ों को संगृहीत करने की सुविधा देना, जिससे आँकड़ों की पुनरावृत्ति समाप्त हो सके और विभिन्न रूपों में एक ही जानकारी को बार-बार दर्ज करने के प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके; इसके साथ ही विविध स्रोत प्रणालियों से आँकड़ों को एकत्रित करने और उन्हें साझा संरचनाओं व वर्गीकरणों में परिवर्तित करने के जटिल कार्य को भी समाप्त करना है।
- सटीक वित्तीय डेटा प्रबंधन और प्रभावी व्यय नियंत्रण, योजनावार और परियोजनावार व्यय की प्रभावी ट्रैकिंग, ग्राहक प्राप्ति का बेहतर प्रबंधन, निवेश और बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन के साथ विभागों में लेनदेन के स्वचालित समाधान के संदर्भ में प्रभावी वित्तीय अनुशासन

की सुविधा के लिए वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना।

- प्रबंधन को प्रबंधन सूचना प्रणाली और डैशबोर्ड प्रदान करना, उन्हें संगठन के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की दृश्यता प्रदान करना और हितधारकों को वास्तविक समय की जानकारी की सुविधा प्रदान करना, संगठन-व्यापी नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाना।

एस.ई.सी.आई. ने जुलाई 2019 में एस.ए.पी.⁶⁸-एंटर्प्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी)⁶⁹ सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन का कार्य करके प्रमुख कम्प्यूटरीकरण शुरू किया और 27 फरवरी 2020 को मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड के साथ 'एस.ई.सी.आई. में क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ई.आर.पी. का कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव सहित लाइसेंस की आपूर्ति' परियोजना के लिए एक समझौता किया। गो-लाइव प्रणाली आखिरकार 18 जनवरी 2021 को प्राप्त हो गया। अनुबंध के अनुसार, इस परियोजना की लागत इस तरह थी:

तालिका 31: परियोजना लागत का विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
ई.आर.पी. -लाइसेंस की लागत	6.07
कार्यान्वयन के दौरान क्लाउड-इंफ्रास्ट्रक्चर और होस्टिंग	2.49
ई.आर.पी.-कार्यान्वयन लागत	4.70
ई.आर.पी. - सालाना टेक्निकल सपोर्ट लागत	5.58
क्लाउड-होस्टिंग और सपोर्ट लागत	2.07
ई.आर.पी. -ऑपरेशन और मेंटेनेंस लागत (लागू होने के पांच साल बाद)	2.08
कुल	22.99

मई 2024 तक, एस.ई.सी.आई. ने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए ₹19.62 करोड़ का व्यय किया था।

कार्यक्षेत्र के सामान्य दायरे के अनुसार, मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड ने एस.ई.सी.आई. की व्यावसायिक आवश्यकताओं, ई.आर.पी. प्रदर्शन आवश्यकताओं और सेवा स्तर समझौतों को पूरा

⁶⁸ मूल उपकरण निर्माता।

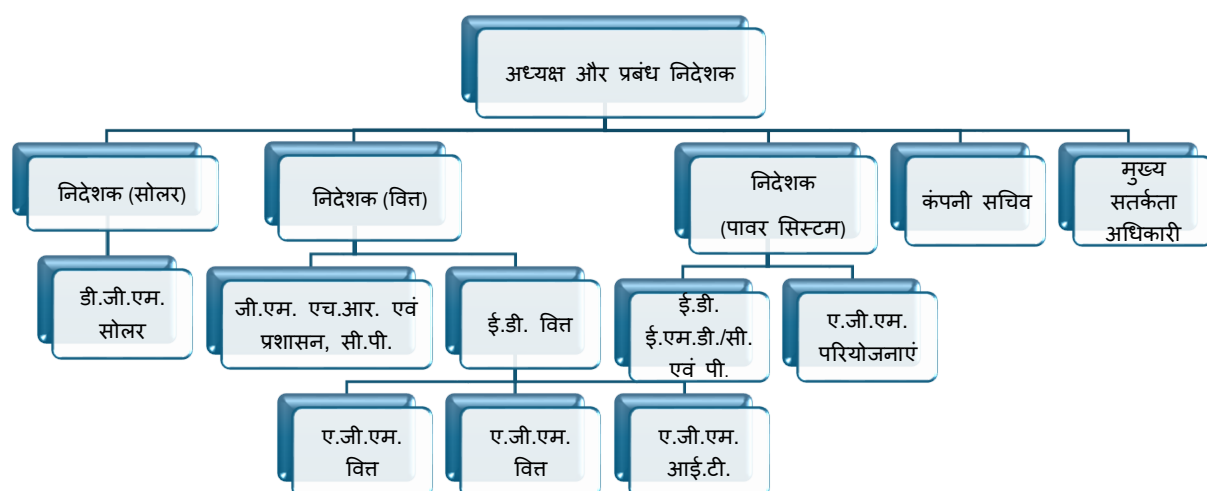
⁶⁹ ई.आर.पी. एक एकीकृत सॉफ्टवेयर समाधान है जो संगठन के प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को समाहित करता है।

करने के लिए क्लाउड पर तैनात आवश्यक आई.टी. बुनियादी ढांचे को डिजाइन और प्राप्त किया। मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड ने परियोजना को पूरा करने के लिए ओ.ई.एम. से एस.ए.पी. लाइसेंस और अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त की। वर्चुअल वातावरण में एक समर्पित सर्वर के प्रदर्शन का लाभ उठाने और सर्वर होस्टिंग की लागत-प्रभावशीलता विशेषता को बढ़ाने के लिए क्लाउड पर ई.आर.पी. अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए, सर्विस पाइथ लिमिटेड को क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया था। मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड ने फ्रंट-एंड टूल के रूप में एस.ए.पी. जी.यू.आई./वेब ब्राउज़र और बैकएंड के रूप में एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. डेटाबेस संस्करण 2.00.053.00 का उपयोग करते हुए एस.ए.पी. एस/4 एच.ए.एन.ए. 1909 उत्पाद को लागू किया। एस.ई.सी.आई. ने निम्नलिखित मॉड्यूल लागू किए:

तालिका 32: मॉड्यूल एवं उनके कार्य

मॉड्यूल	कार्य
वित्त और नियंत्रण	सामान्य खाता बही और प्रक्रिया, देय और प्राप्य खातों की प्रक्रिया, नकदी और बैंक संबंधी प्रक्रिया, परिसंपत्ति प्रसंस्करण, कर, वित्तीय संस्थान के समापन संबंधी गतिविधियाँ और रिपोर्ट आदि।
मानव पूंजी प्रबंधन	कार्मिक प्रशासन, संगठनात्मक प्रबंधन, समय प्रबंधन, ई-भर्ती, कर्मचारी स्व-सेवा और प्रबंधक स्व-सेवा, पेरोल और यात्रा प्रबंधन आदि का रखरखाव।
सामग्री प्रबंधन	सामग्री, भंडार और पुर्जों, उपभोग्य वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, सेवाओं, माल प्राप्ति और माल निर्गमन, स्टॉक हस्तांतरण आदि की सभी खरीद के लिए चालान सत्यापन की ट्रैकिंग।
बिक्री एवं वितरण	भौतिक इन्वेंट्री आदि। बिक्री और वितरण में स्वचालन।
संयंत्र रखरखाव	सामग्री मूल्यांकन, इन्वेंट्री प्रबंधन, नियोजन संयंत्र, रखरखाव संयंत्र और उत्पादन संयंत्र आदि में स्वचालन।
परियोजना प्रणालियाँ और पोर्टफोलियो तथा परियोजना प्रबंधन	परियोजना गतिविधियों में स्वचालन
उपयोगिताओं के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान (आई.एस.-यू.)	बिजली व्यापार प्रक्रिया का स्वचालन - बिलिंग और इनवॉइसिंग, शेड्यूलिंग डेटा, भुगतान प्रसंस्करण, आदि।

6.1.2 संगठनात्मक संरचना



चित्र 6: संगठनात्मक संरचना

6.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आई.टी. लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- आई.टी. प्रणाली को स्वीकृत कार्यक्षमता, समयसीमा और लागत के अनुपालन में लागू किया गया था।
- आई.टी. प्रणाली के संचालन से संबंधित सामान्य नियंत्रण कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन में लागू किए गए थे।
- कार्यकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक नियमों का सही ढंग से मानचित्रण किया गया और प्रणाली में एप्लिकेशन नियंत्रण लागू किए गए।

6.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

एस.ई.सी.आई. में लागू किए गए एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, अधिग्रहण और प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों का उपयोग करके किया गया:

- सॉफ्टवेयर के विकास के समय एस.ई.सी.आई. द्वारा निर्धारित उद्देश्य।

- एस.ई.सी.आई. और ठेकेदार के बीच हुए समझौते।
- निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की बैठकों की कार्यसूची (एजेंडा) और कार्यवृत्त (मिनट्स)।
- एस.ई.सी.आई./भारत सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक नियम, नियमावली (मैन्युअल), शक्तियों का प्रत्यायोजन और प्रक्रियाएं।
- आई.टी. नियंत्रण, विकास, कार्यान्वयन और सुरक्षा मापदंडों में सर्वोत्तम अभ्यास।

6.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्य पद्धति

एस.ई.सी.आई., नई दिल्ली में संचालित एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली का आई.टी. लेखापरीक्षा, सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(1) और लेखापरीक्षा एवं एकाउंट्स पर विनियम (संशोधन 2020) के अध्याय 3 के विनियम 16 से 18 के तहत आयोजित किया गया था। एस.ई.सी.आई. द्वारा लागू किए गए सात एस.ए.पी. मॉड्यूल पैरा 6.1.1 देखें में से, लेखापरीक्षा के लिए तीन मॉड्यूल चुने गए थे, अर्थात्: वित्त और नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन और उपयोगिताओं के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान।

लेखापरीक्षा ने अपने सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल के लिए तीन एस.ई.सी.आई. संयंत्रों⁷⁰ (प्लांट्स) का चयन किया। एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन के प्रस्ताव की तारीख से लेकर स्रोत दस्तावेजों की और 'गो-लाइव' की तारीख यानी 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 तक की अवधि के लेनदेन और प्रणाली रिपोर्ट की लेखापरीक्षा में जांच की गई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित कई प्रमुख प्रक्रियाएं, जैसे कि विचलन निपटान, डनिंग और ब्याज गणना, शेड्यूलिंग प्रक्रिया और प्रणाली-जनरेटेड वर्कफ्लो के माध्यम से निविदा (टेंडरिंग) प्रक्रिया, या तो लागू नहीं की गई थीं या उनका उपयोग

⁷⁰ 1. 10 मेगावाट, बड़ी सिड, जोधपुर, राजस्थान, 2. 10 मेगावाट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कोलार, कर्नाटक और, 3. 100 मेगावाट राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

नहीं किया जा रहा था। इसके बजाय, एस.ई.सी.आई. महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन प्रक्रियाओं के लिए ई-ऑफिस और स्प्रेडशीट (जैसे एक्सेल) जैसे मैन्युअल या समानांतर प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर है।

नीचे दी गई तालिका बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित कार्यात्मकताओं की तुलना एस.ई.सी.आई. में उनकी वास्तविक कार्यान्वयन स्थिति से करती है (जिसकी रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है):

तालिका 33: कार्यक्षमताओं के कार्यान्वयन की स्थिति।

परिकल्पित कार्यप्रणाली (व्यापार ब्लूप्रिंट योजना के अनुसार)	एस.ई.सी.आई. में एस.ए.पी.- ई.आर.पी. में स्थिति
पावर शेड्यूलिंग प्रक्रिया	कार्यान्वयन नहीं किया गया
विचलन निपटान तंत्र	कार्यान्वयन नहीं किया गया
बकाया भुगतान और ब्याज गणना (अतिरिक्त भुगतान, जमा, चालान)	कार्यान्वयन नहीं किया गया
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ.) संवितरण	उपयोग नहीं किया गया(मैन्युअल)
विक्रेता को ब्लैकलिस्ट करना	कार्यान्वयन नहीं किया गया
परिसंपत्तियों, सेवाओं, परियोजना खरीद की खरीद	आंशिक रूप से लागू

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान निम्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग किया गया:

- प्रबंधन को पत्राचार और प्रश्नावली जारी की गई और प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया।
- एस.ई.सी.टी. के अपने संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए परिसंपत्तियों की खरीद हेतु विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत विद्युत खरीद समझौते, विद्युत बिक्री समझौते, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण समझौते, खरीद आदेश और चालान, विभिन्न समिति बैठकों के कार्यवृत्त, स्रोत दस्तावेज और प्रणाली रिपोर्ट आदि दस्तावेजों की गहन जांच की गई।
- कंप्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक का उपयोग करके प्रणाली से प्राप्त मानक और अनुकूलित रिपोर्टों का डेटा विश्लेषण।

28 जून 2024 को अतिरिक्त महाप्रबंधक के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के दायरे और लेखापरीक्षा पद्धति की व्याख्या की

गई। 6 जून 2025 को एस.ई.सी.आई. के वरिष्ठ प्रबंधक (आई.टी.) और उप प्रबंधक (आई.टी./ई.आर.पी.) के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के विचार और उनके उत्तर रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किए गए हैं।

6.1.6. स्वीकृति

लेखापरीक्षा समिति, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एस.ई.सी.आई., नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक (आई.टी.), वरिष्ठ प्रबंधक (आई.टी.), उप प्रबंधक (आई.टी./ई.आर.पी.) और अन्य कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करती है।

6.1.7 शासन तंत्र

शासन तंत्र से तात्पर्य नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के उस ढांचे से है जो यह सुनिश्चित करता है कि एप्लिकेशन प्रणाली प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और संगठनात्मक उद्देश्यों तथा नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित हो। इसमें प्रणाली की अखंडता और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ इसके तालमेल को सुरक्षित रखने के लिए जोखिम प्रबंधन, निर्णय लेने और जवाबदेही की निगरानी शामिल है।

6.1.7.1 संचालन समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के सुचारु और सफल कार्यान्वयन के लिए एस.ई.सी.आई. ने मार्च 2020 में ई.आर.पी. शासन संरचना के एक भाग के रूप में, अन्य बातों के अलावा, एक संचालन समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो ई.आर.पी. के कार्यान्वयन को समग्र दिशा और नेतृत्व प्रदान करेगी और इसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक और महाप्रबंधक शामिल होंगे। एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के स्थिरीकरण तक कार्यान्वयन के छह चरण थे:

तालिका 34: एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन के चरण

फेज़	कार्यान्वयन
I	परियोजना की तैयारी/प्रारंभ
II	व्यवसायिक रूपरेखा (ब्लूप्रिंट)/विस्तार
III	प्राप्ति/निर्माण
IV	अंतिम तैयारी/ट्रांजिसन
V	गो-लाइव/उत्पादन
VI	गो-लाइव के बाद सहायता (स्थिरीकरण/मार्गदर्शन)

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, आई.टी. विभाग चरण II से V के दौरान सभी व्यावसायिक प्रक्रिया स्वामियों के साथ मासिक आधार पर संचालन समिति की बैठक आयोजित करेगा। संचालन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नलिखित थीं:

- परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन और प्रतिबद्धता करना;
- प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा उठाए गए किसी भी प्रोजेक्ट-व्यापी मुद्दों और जोखिमों का समाधान और प्रबंधन करना;
- अंतरविभागीय महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर निर्णय लेना;
- परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए परियोजना टीम को दिशा-निर्देश प्रदान करना;
- परियोजना की प्रगति को नियंत्रित करना और
- यह सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक उद्देश्यों को बनाए रखना।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- यद्यपि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की कार्यान्वयन प्रक्रिया फरवरी 2020 में शुरू हुई और यह प्रणाली 18 जनवरी 2021 को चालू हो गई, फिर भी संचालन समिति केवल आई.टी. विभाग द्वारा आयोजित दो ऑनलाइन बैठकें ही कर सकी, जो 1 जून 2020 और 2 नवंबर

2020 को आयोजित की गई थीं।

- दो बैठकों में से केवल एक की कार्यवाही का विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया। हालांकि, अभिलेखों में बैठक में उपस्थित निदेशकों, महाप्रबंधकों और व्यावसायिक प्रक्रिया स्वामियों की संख्या निर्दिष्ट नहीं थी।
- लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई बैठक की कार्यवाही में यह उल्लेख नहीं था कि जोखिम मूल्यांकन और निवारण उपायों पर चर्चा की गई थी या उन्हें दस्तावेज़ित किया गया था। कोर टीम के सदस्यों को दिए गए इनपुट (यदि कोई हो), अंतर-विभागीय एकीकरण संबंधी मुद्दों के लिए समन्वय, गो-लाइव के बाद एस.ए.पी. के उपयोग को सुनिश्चित करना आदि के बारे में कार्यवाही से जानकारी नहीं मिल सकी। ई.आर.पी. कार्यान्वयन की जटिलता को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण था कि समिति संभावित जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करे और उन्हें कम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करे।
- हालांकि परियोजना आरंभ रिपोर्ट (संस्करण 2) के खंड 8.7 के अनुसार, एस.ई.सी.आई. के परियोजना प्रबंधक को प्रमुख मुद्दों की तुरंत पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाना था और परियोजना के कार्यान्वयन की साप्ताहिक स्थिति (जिसमें समग्र परियोजना स्थिति शामिल है: अनुसूची, कार्यक्षेत्र और गुणवत्ता का विवरण, समीक्षा अवधि के कार्य और डिलिवरेबल की स्थिति; आगामी सप्ताह के लिए नियोजित कार्य; बाधाओं की ट्रैकिंग स्थिति; जोखिम ट्रैकिंग स्थिति; यदि कोई हो तो परिवर्तन लॉग) संचालन समिति को रिपोर्ट करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्राप्त और मूल्यांकित संचार के समर्थन में ऐसे दस्तावेज एस.ई.सी.आई. द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

इस प्रकार की चर्चाओं का अभाव शासन और जोखिम प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। बैठक के कार्यवृत्त में पहचाने गए जोखिमों या परियोजना संबंधी चुनौतियों के संबंध में की गई किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा इस बात का आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ रही कि संपूर्ण कार्यान्वयन

की निगरानी संचालन समिति द्वारा प्रभावी ढंग से की गई थी।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि संचालन समिति की बैठकें 1 जून 2020 और 2 नवंबर 2020 को ऑनलाइन आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2021 से एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसके तहत प्रबंधन समीक्षा के लिए त्रैमासिक आई.टी. जोखिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें ई.आर.पी. से संबंधित जोखिम भी शामिल हैं।

इस जवाब में लेखापरीक्षा की उस टिप्पणी का समाधान नहीं किया गया है जिसमें कहा गया है कि ई.आर.पी. कार्यान्वयन के चरणों (फरवरी 2020-जनवरी 2021) के दौरान नियमित निगरानी, जोखिमों पर चर्चा या अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित कोई रिकॉर्ड या कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं थे। गो-लाइव (मार्च 2021) के बाद लागू की गई जोखिम प्रबंधन नीति भी कार्यान्वयन अवधि के दौरान निगरानी में हुई इस चूक को दूर नहीं करती है।

अनुशंसा 45:

एस.ई.सी.आई. को यह सुनिश्चित करके अपने आई.टी. शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए कि संचालन समिति ई.आर.पी. कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करे।

6.1.7.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करना

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, समयसीमा, चरणबद्ध परिणाम, संसाधन आवश्यकताएँ, शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और निवारण, वित्तीय अनुमान, निगरानी तंत्र और प्रदर्शन संकेतक सहित एक व्यापक योजना शामिल होती है। यह प्रभावी परियोजना निष्पादन को सक्षम बनाती है और हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

एस.ई.सी.आई. ने जनवरी 2021 में प्रणाली इंटीग्रेटर मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड के माध्यम से एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली लागू किया। हालांकि, एस.ई.सी.आई. ने इस परियोजना के लिए कोई डी.पी.आर. (विस्तृत शोध रिपोर्ट) तैयार या बनाए नहीं रखा। डी.पी.आर. के अभाव

ने एस.ई.सी.आई. के परियोजना प्रबंधन को प्रभावित किया, जिससे व्यवहार्यता मूल्यांकन और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ तालमेल बिगड़ गया। इसके अलावा, इससे जोखिम की अपर्याप्त पहचान/निवारण योजना और सफलता के लिए कोई परिभाषित मानदंड या मापने योग्य परिणाम न होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। डी.पी.आर. की अनुपस्थिति प्रगति की निगरानी करने, लागतों को नियंत्रित करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की क्षमता को भी सीमित करती है और अनुबंध खंडों से परे प्रणाली इंटीग्रेटर की जवाबदेही को कम करती है।

दस्तावेजी साक्ष्यों की कमी के कारण, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि परियोजना की योजना और क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया गया था या नहीं, और न ही यह मूल्यांकन कर सका कि कार्यान्वयन के दौरान पहचाने गए जोखिमों का समाधान किया गया था या नहीं। यह निर्धारित करना भी कठिन था कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी या नहीं। एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के संचालन, नियंत्रण और दीर्घकालिक स्थिरता पर साक्ष्य-आधारित राय बनाने में बाधाएँ थीं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि सभी डिलिवरेबल्स को ठीक से परिभाषित और वितरित किया गया था या नहीं। इसके अलावा, डी.पी.आर. की अनुपस्थिति के कारण बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित कई प्रमुख कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन नहीं हो सका, क्योंकि व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार डिलिवरेबल्स को ट्रैक करने के लिए कोई संरचित आधार रेखा नहीं थी। इन कार्यात्मक कमियों का विश्लेषण इस रिपोर्ट के बाद के अनुच्छेदों में किया गया है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) उत्तर दिया कि पी.डब्ल्यू.सी. प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना सलाहकार के रूप में पूर्व-कार्यान्वयन और कार्यान्वयन गतिविधियों जैसे आवश्यकता विश्लेषण, बजट निर्धारण और निविदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। ई.आर.पी. परियोजना और बजट को जुलाई 2018 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और पी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निष्पादित कार्य को डी.पी.आर. की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला माना गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पी.डब्ल्यू.सी. द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ परियोजना उद्देश्यों, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी तंत्र और प्रदर्शन संकेतकों को समाहित करने वाली औपचारिक डी.पी.आर. (विस्तृत जोखिम रिपोर्ट) नहीं हैं। संरचित डी.पी.आर. के अभाव ने ई.आर.पी. कार्यान्वयन के दौरान परियोजना संचालन, जोखिम प्रबंधन और निगरानी को कमजोर कर दिया।

6.1.7.3 अपर्याप्त परिवर्तन प्रबंधन

2 जुलाई 2019 की निविदा के खंड 5.1.3.9.4 के अनुसार, चयनित बोलीदाता को परियोजना जीवनचक्र को कवर करते हुए एक विस्तृत परिवर्तन प्रबंधन रणनीति और योजना तैयार करनी थी, परिवर्तन प्रबंधकों/चैंपियनों की नियुक्ति में एस.ई.सी.आई. का सहयोग करना था, परिवर्तन प्रबंधन सामग्री (न्यूज़लेटर, पुस्तिकाएँ आदि) तैयार करनी थी, कार्यशालाएँ आयोजित करनी थीं और ई.आर.पी. कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले प्रक्रिया-स्तर और भूमिका-स्तर के परिवर्तनों की पहचान करनी थी। ये गतिविधियाँ एक संरचित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आदर्श रूप से डी.पी.आर. के साथ एकीकृत होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र से जुड़ाव, जिसमें डिजाइन, परीक्षण, प्रशिक्षण और गो-लाइव तत्परता के लिए महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं।
- प्रत्येक परिवर्तन गतिविधि के लिए विस्तृत समयसीमा और अपेक्षित परिणाम, साथ ही अंतिम कार्यान्वयन तक अपेक्षित परिणामों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग तंत्र।
- हितधारक मानचित्रण, जोखिम मूल्यांकन, संचार और प्रशिक्षण रणनीतियाँ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्न का अवलोकन किया:

- मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई परिवर्तन प्रबंधन रणनीति में केवल सैद्धांतिक पहलुओं को संबोधित किया गया था और इसमें हितधारक पहचान, जोखिम

विश्लेषण, नेतृत्व की भागीदारी और अनुकूलित प्रशिक्षण/संचार योजनाओं का अभाव था।

- ई.आर.पी. नोडल अधिकारियों को नामित करने वाले एस.ई.सी.आई. के कार्यालय आदेश (28 फरवरी 2023) में परिवर्तन-विशिष्ट भूमिकाओं, स्वामित्व या प्रदर्शन संकेतकों को परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे जवाबदेही कम हो गई।
- हालांकि एस.ई.सी.आई. ने प्रक्रिया और भूमिका परिवर्तनों की पहचान करने का दावा किया था, लेकिन लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान निविदा दस्तावेज़ में आवश्यक कोई औपचारिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था, जिससे पारदर्शिता और योजना की कठोरता कम हो गई।
- इसके अलावा, परिवर्तन प्रबंधन आउटपुट को संग्रहीत करने के लिए कोई केंद्रीकृत भंडार नहीं रखा गया था, जिससे निरंतरता और ज्ञान हस्तांतरण प्रभावित हुआ। कोई औपचारिक परिवर्तन प्रबंधन सामग्री (न्यूज़लेटर, मैनुअल, पुस्तिकाएँ) या संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार नहीं किए गए थे और आयोजित तदर्थ रिक्रेशर सत्र एक व्यवस्थित, प्रलेखित प्रशिक्षण ढांचे का विकल्प नहीं हो सकते।

एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन, स्वचालित सुलह और मजबूत एम.आई.एस. रिपोर्टिंग जैसी महत्वपूर्ण ई.आर.पी. कार्यक्षमताएँ अधूरी रहीं, जो परियोजना शासन और परिवर्तन योजना दोनों में कमियों को दर्शाती हैं।

एक सशक्त डी.पी.आर. (विस्तृत अनुसंधान रिपोर्ट), यदि सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार और निगरानी की जाए, तो उसमें परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित परिणाम, मापने योग्य मील के पत्थर, ई.आर.पी. विकास/परीक्षण चरणों से जुड़े होने चाहिए और समयसीमा के अनुसार प्रगति को ट्रैक करने के लिए तंत्र उपलब्ध होने चाहिए। इससे संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ तालमेल, गतिविधियों का उचित क्रम, अनुपलब्ध कार्यात्मकताओं की समय पर पूर्ति और उपयोगकर्ता की तत्परता सुनिश्चित होती।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) उत्तर दिया कि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. कार्यान्वयन छह संरचित

चरणों में किया गया था, जिसमें मॉड्यूल अवलोकन सत्र, प्रक्रिया-मैपिंग, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और हितधारक सहभागिता जैसी परिवर्तन प्रबंधन गतिविधियाँ शामिल थीं। इसके अलावा, फरवरी 2023 में ई.आर.पी. नोडल अधिकारियों को नामित किया गया था और उन्होंने प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के समन्वय के लिए परिवर्तन चैंपियन के रूप में कार्य किया, हालांकि परिवर्तन प्रबंधन संबंधी दस्तावेजों के लिए कोई अलग भंडार नहीं रखा गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एस.ई.सी.आई. ने निविदा खंड के तहत अपेक्षित व्यापक परिवर्तन प्रबंधन रणनीति और योजना तैयार नहीं की। परिभाषित भूमिकाओं, मापने योग्य परिणामों, जोखिम विश्लेषण और संरचित संचार सामग्री का अभाव भी इस उत्तर को स्पष्ट करता है। इससे पता चलता है कि ई.आर.पी. कार्यान्वयन के दौरान परिवर्तन प्रबंधन की योजना और क्रियान्वयन अपर्याप्त था।

अनुशंसा 46:

एस.ई.सी.आई. को मापने योग्य लक्ष्यों के साथ परिवर्तन प्रबंधन प्रदेयों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परिवर्तन प्रबंधन रणनीति और योजना तैयार करके भविष्य की परियोजनाओं के लिए अपने शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए, उन्हें ई.आर.पी. विकास/परीक्षण चरणों से जोड़ना चाहिए और समय-सीमा के सापेक्ष प्रगति को ट्रैक करने के लिए तंत्र प्रदान करना चाहिए।

6.1.7.4 विद्युत समय-निर्धारण प्रक्रिया का कार्यान्वयन न होना

एस.ई.सी.आई. के लिए व्यावसायिक ब्लूप्रिंट योजना में प्रोफाइल प्रबंधन और शेड्यूलिंग कार्यक्षमताओं सहित विद्युत शेड्यूलिंग प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। ये प्रक्रियाएं व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुपालन में सही पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और निपटान के लिए अंतराल-संबंधी ऊर्जा डेटा के प्रबंधन हेतु आवश्यक हैं। व्यावसायिक ब्लूप्रिंट योजना में प्रोफाइल

प्रबंधन, डेटा सत्यापन जांच, सी.एस.वी. अपलोड, स्वचालित रिपोर्टिंग, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर पोर्टल और डैशबोर्ड के साथ एकीकरण से संबंधित शेड्यूलिंग कार्यक्षमताओं का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. ने व्यावसायिक ब्लूप्रिंट योजना में निर्धारित शेड्यूलिंग कार्यक्षमताओं को लागू नहीं किया।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) बताया कि बिजली आपूर्ति अनुसूची संचालन 2020 में बंद कर दिया गया था और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आर.एल.डी.सी.) के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (ए.पी.आई.) भी एकीकरण के लिए उपलब्ध नहीं थे। अब, आर.एल.डी.सी. ए.पी.आई. की उपलब्धता के बाद, मेसर्स हाईबार क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर एपीआई को एकीकृत करके एस.ए.पी. ई.आर.पी. प्रणाली में चौबीसों घंटे चलने वाली (आर.टी.सी.) परियोजनाओं के लिए बिलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करेगा, जिसमें बिजली आपूर्ति अनुसूची के समान कार्यक्षमता शामिल है।

ई.आर.पी. के दायरे से शेड्यूलिंग कार्यात्मकताओं को बाहर रखने के संबंध में एस.ई.सी.आई. द्वारा कोई औपचारिक अनुमोदन या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही प्रणाली इंटीग्रेटर के विरुद्ध संविदात्मक कार्रवाई का कोई प्रमाण दिया गया। इस कार्यान्वयन न होने के कारण एकीकरण के लाभों का नुकसान हुआ है और भविष्य में कार्यान्वयन के दौरान अतिरिक्त लागत और पुनर्कार्य की संभावना है।

अनुशंसा 47:

मजबूत शासन के लिए, एस.ई.सी.आई. शेड्यूलिंग कार्यात्मकताओं को लागू न करने के वित्तीय और परिचालन प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन कर सकता है, जिसमें पुनर्कार्य, लागत वृद्धि और एकीकरण लाभों की हानि के जोखिम शामिल हैं।

6.1.7.5 व्यावसायिक ब्लूप्रिंट योजना की आवश्यकता के अनुसार विचलन निपटान तंत्र का कार्यान्वयन न होना

एस.ई.सी.आई. में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक योजना में निर्धारित ऊर्जा, वास्तविक उत्पादन, विचलन और लागू शुल्कों की गणना को स्वचालित करने के लिए विचलन निपटान तंत्र मॉड्यूल के कार्यान्वयन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इस आवश्यकता में एस.ई.सी.आई. के भीतर/अंतर-क्षेत्रीय परियोजनाओं और चौबीसों घंटे चलने वाली बिजली परियोजनाओं, दोनों को शामिल किया गया था, जिसमें डेटा एकीकरण, स्वचालित सत्यापन और शुल्क गणना के प्रावधान थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यावसायिक योजना में शामिल विचलन निपटान तंत्र (डी.एस.एम.) कार्यक्षमता एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में लागू नहीं की गई थी, जबकि यह एक दस्तावेजी आवश्यकता थी। इसके अलावा, कार्यान्वयन के दायरे से शेड्यूलिंग को बाहर करने के निर्णय को दर्शाने वाले औपचारिक अनुमोदन का कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं मिला।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में डी.एस.एम. मॉड्यूल का कार्यान्वयन न होना किसी कार्यात्मक कमी को नहीं दर्शाता है, बल्कि प्रचलित नियामक और संविदात्मक व्यवस्थाओं के अनुसार एस.ई.सी.आई. के वास्तविक परिचालन ढांचे और अनुपालन संरचना को दर्शाता है।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परियोजना के दायरे से एक दस्तावेजीकृत कार्यक्षमता को बाहर करने का निर्णय एक औपचारिक परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया गया था, जिसके लिए एक स्पष्ट तर्क, हितधारकों से परामर्श और एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दस्तावेजीकृत जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

अनुशंसा 48:

एस.ई.सी.आई. को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित सभी प्रमुख कार्यक्षमताओं, जिसमें शेड्यूलिंग, विचलन निपटान तंत्र और डनिंग गणना शामिल हैं, को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में लागू किया गया है।

6.1.7.6 आई.टी. रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना का दस्तावेजीकरण न होना

यद्यपि कम्प्यूटरीकरण से पहले एक सुविचारित 'सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति' का विकास आवश्यक है, फिर भी एस.ई.सी.आई., आई.टी. पहलुओं को शामिल करते हुए रणनीतियों, प्रस्तावों और आपूर्ति व्यवस्थाओं, उनके मूल्यांकन और उपलब्धि निगरानी आदि को दर्शाने वाली कोई दीर्घकालिक रणनीतिक आई.टी. योजना तैयार नहीं कर सका। इसके पास एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली को लागू करने की योजना दर्शाने वाली और अपने ई.आर.पी. परियोजनाओं और संचालन के लिए धन उपलब्ध कराने की दिशा निर्धारित करने वाली कोई दस्तावेजित वार्षिक कार्य योजना भी नहीं है।

एस.ई.सी.आई. अपनी आई.टी. और साइबर सुरक्षा नीति को आई.टी. रणनीतिक योजना के रूप में उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आई.टी. संसाधनों का सुरक्षित और सुसंगत तरीके से उपयोग करने के दायित्वों के प्रति जागरूक करना है। यह नीति आई.टी. अवसंरचना के उपयोग, सुरक्षा और निपटान के लिए एक ढांचा प्रदान करती है और सूचना की सुरक्षा के प्रति उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

आई.टी. रणनीतिक योजना के अभाव में, आई.टी. गतिविधियों का व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ तालमेल न बैठने का जोखिम रहता है, जिसमें एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली का कार्यान्वयन भी शामिल है। दस्तावेजित रणनीतिक योजना के अभाव में, तदर्थ निर्णय लेने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे संसाधनों का कुशल आवंटन, आई.टी. प्रस्तावों का उचित मूल्यांकन बाधित हो सकता है और संगठन को आई.टी. निवेशों के संबंध में

मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और सूचित निर्णय लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अनुचित आवंटन और परिणाम हो सकते हैं। रणनीतिक योजना में आमतौर पर जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ शामिल होती हैं।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के निरंतर संचालन और रखरखाव के लिए धन आवंटन हेतु स्पष्ट वित्तीय रोडमैप और दिशा प्रदान करने के लिए एक दस्तावेजित वार्षिक कार्य योजना भी आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. के पास कोई वार्षिक कार्य योजना नहीं है, लेकिन बजट डेटा वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है। हालांकि वार्षिक बजट एक आवश्यक वित्तीय आवंटन प्रक्रिया है, यह दस्तावेजित आई.टी. रणनीतिक योजना या वार्षिक कार्य योजना का विकल्प नहीं हो सकता।

बजट केवल यह निर्दिष्ट करता है कि कितना पैसा खर्च किया जाना है, जबकि एक रणनीतिक योजना दीर्घकालिक आई.टी. उद्देश्यों, प्राथमिकताओं, जोखिम आकलन और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को परिभाषित करती है, जिससे एस.ए.पी.-ई.आर.पी. के सफल कार्यान्वयन जैसे संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार, एक वार्षिक कार्य योजना प्रभावी निगरानी के लिए रणनीति को विशिष्ट गतिविधियों, समय-सीमाओं, जिम्मेदारियों और प्रदर्शन संकेतकों में परिवर्तित करती है। इन नियोजन दस्तावेजों के बिना, बजट आवंटन तदर्थ होने का जोखिम रहता है, प्रमुख आई.टी. जोखिमों को संबोधित करने में विफल हो सकता है और सतत ई.आर.पी. कार्यान्वयन, संसाधन अनुकूलन और उभरते तकनीकी खतरों के खिलाफ तैयारी के लिए आवश्यक संरचित ढांचा प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार, ऐसी योजना का अभाव प्रभावी वित्तीय नियोजन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि वे आई.टी. पहलों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए एक व्यापक आई.टी. रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना को

लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

अनुशंसा 49:

एस.ई.सी.आई. यह सुनिश्चित कर सकता है कि आई.टी. पहलों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए व्यापक आई.टी. रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना विकसित और कार्यान्वित की जाए, जिसमें शामिल हैं- समयबद्ध तरीके से सफल एस.ए.पी.-ई.आर.पी. कार्यान्वयन और निरंतर संचालन सुनिश्चित करना।

6.1.7.7 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. की प्रभावशीलता मापने के लिए विभिन्न संकेतकों का निर्धारण न होना

सूचना एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, एस.ई.सी.आई. को सभी आई.टी. प्रणालियों की प्रभावशीलता मापने के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारक (के.पी.आई.) और प्रमुख लक्ष्य संकेतक जैसे विभिन्न संकेतक निर्धारित करने चाहिए थे। यह परियोजना मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड द्वारा पूरी की गई और एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली 18 जनवरी 2021 को चालू हो गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2025 तक प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त मैट्रिक्स में से किसी को भी डिज़ाइन और मापा नहीं गया था। यह भी देखा गया कि कंपनी के आई.टी. प्रशासन में बोर्ड की भूमिका सीमित थी, क्योंकि प्रबंधन ने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित कोई भी डेटा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परियोजना अंततः कंपनी के लिए लाभदायक थी या नहीं। आगामी परियोजनाओं में एक संरचित प्रदर्शन मापन प्रणाली के लिए औपचारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एस.ई.सी.आई. ने (मार्च 2025) उत्तर दिया कि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन का उपयोग किया गया है।

निर्धारित प्रदर्शन मापदंडों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि

एस.ई.सी.आई. ने अपने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की सफलता का प्रभावी ढंग से आकलन किया है, कमियों की पहचान की है या व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित किया है। बोर्ड की निगरानी का अभाव आई.टी. प्रशासन को और कमजोर करता है, जिससे आई.टी. निवेशों के गलत संरेखण और परिचालन अक्षमताओं का जोखिम बढ़ जाता है।

एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर का उपयोग न करना (जिस पर पैरा 6.1.8.4 में आगे चर्चा की गई है) और विक्रेता पर अत्यधिक निर्भरता जैसी कमियों का पता लगाया जा सकता था और शुरुआती चरण में ही उनका समाधान किया जा सकता था यदि संरचित प्रदर्शन संकेतक मौजूद होते।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (के.पी.आई.) तैयार किए गए हैं और परिभाषित आवृत्ति और मापदंडों के अनुसार उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 50:

एस.ई.सी.आई. प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (के.पी.आई.) के अनुसार एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी सुनिश्चित कर सकता है और परिभाषित आवृत्ति और मापदंडों के अनुसार उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई भी कर सकता है।

6.1.7.8 एस.ए.पी. का अपर्याप्त अनुकूलन

2 जुलाई 2019 को जारी "क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ई.आर.पी. का कार्यान्वयन, एस.ई.सी.आई. में संचालन और रखरखाव सहित लाइसेंस की आपूर्ति" संबंधी एन.आई.टी. के अनुसार, प्रणाली इंटीग्रेटर को अनुमोदित व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप ई.आर.पी. प्रणाली को कॉन्फिगर और कस्टमाइज़ करना था, जिसमें मानक ई.आर.पी. कार्यक्षमताओं को अपनाना शामिल था, और अनुकूलन केवल वहीं किया जाना था जहां आवश्यक हो, ताकि स्थिर और कुशल संचालन

सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, इष्टतम प्रदर्शन और प्रणाली स्थिरता बनाए रखने के लिए ई.आर.पी. वातावरण को उचित रूप से कॉन्फ़िगर और मॉनिटर किया जाना आवश्यक है।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच में प्रणाली वातावरण के अपर्याप्त अनुकूलन और प्रबंधन की खामियां पाई गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इंडेक्स सर्वर, जो डेटा को स्टोर करने और क्वेरी को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. का मुख्य घटक है, मेमोरी का अत्यधिक उपयोग कर रहा था, जो प्रभावी आवंटन सीमा के करीब पहुंच रहा था। इससे टेबल अनलोड होने, प्रणाली धीमा होने या मेमोरी की कमी के कारण प्रणाली के प्रदर्शन में गिरावट, क्रैश या डाउनटाइम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। मेमोरी की अधिक खपत का कारण आमतौर पर खराब प्रणाली कॉन्फ़िगरेशन और अत्यधिक क्वेरी प्रोसेसिंग होता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. वातावरण को ठीक से संचालित और मॉनिटर करने के लिए एस.ई.सी.आई. के भीतर प्रशिक्षित आई.टी. पेशेवरों की कमी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया, जिससे उपयोगकर्ता अधिकारों और शासन के कमजोर कार्यान्वयन का संकेत मिलता है और एस.ई.सी.आई. अपने मुख्य प्रशासन के लिए बाहरी सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भर था। ये सभी कारक एस.ई.सी.आई. के एस.ए.पी. प्रणाली के प्रबंधन में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करते हैं, जिनमें अपर्याप्त अनुकूलन और मेमोरी प्रबंधन से लेकर उपयोगकर्ता प्राधिकरण नियंत्रणों की खामियां शामिल हैं।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उन्होंने सपोर्ट वेंडर, मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड को उच्च मेमोरी खपत के मूल कारण का विश्लेषण करने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया है।

अनुशंसा 51:

एस.ई.सी.आई. को अलर्ट तंत्र के साथ मेमोरी सीमा को परिभाषित करना चाहिए, नियमित सिस्टम स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए, स्पष्ट विक्रेता जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए और बाहरी विक्रेताओं पर निर्भरता को कम करने के लिए उचित डेटाबेस आकार और स्टाफ प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च मेमोरी उपयोग के मूल कारण का समाधान करना चाहिए।

6.1.7.9 आई.टी. संगठन

एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में, इसके लिए एक आई.टी. संगठनात्मक संरचना की स्थापना की आवश्यकता होती है जो व्यावसायिक आवश्यकताओं को दर्शाती है, प्रमुख आई.टी. कर्मियों को परिभाषित और पहचान करने के लिए और एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले एक ही व्यक्ति पर निर्भरता को कम करने के लिए, और मुख्य सूचना अधिकारी एक संगठन के भीतर आई.टी. समूह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। सर्वोत्तम अभ्यास के लिए कर्तव्यों के पृथक्करण की भी आवश्यकता होती है, अर्थात्, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विभाजन जो एक ही व्यक्ति द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से समझौता करने की संभावना को कम करेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यकारी निदेशक (वित्त और आई.टी.) पदनामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी हैं जो आई.टी. कार्यों के समग्र प्रभारी हैं। सी.ई.सी.आई. एक महत्वपूर्ण जॉब फ़ंक्शन करने वाले एकल व्यक्ति पर निर्भरता को कम करने में असमर्थ है।

ई.आर.पी. के सुचारु संचालन के लिए एस.ई.सी.आई. ने (फरवरी 2023) 11 विभागों के 11 नोडल अधिकारियों वाली एक समर्पित ई.आर.पी. टीम का गठन किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 नोडल अधिकारियों को नामित करते समय और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते समय, एस.ई.सी.आई. ने कंपनी के आई.टी. प्रणाली पर प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए कोई भूमिका परिभाषित नहीं

की।

गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना सुरक्षा और उसके शासन के कार्यान्वयन के लिए नामित कर्मियों और शासन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचे के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। शासन प्रक्रिया और सूचना सुरक्षा के शासन के लिए नियुक्त कर्मियों को सुरक्षा नीति में बताया जाना चाहिए और सूचना सुरक्षा संचालन समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिए। हालाँकि, एस.ई.सी.आई. ने नोडल अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हुए अपनी आई.टी. सुरक्षा नीति को अद्यतन नहीं किया। आई.टी. शासन के लिए समग्र ढांचे को मंजूरी देने के लिए इसकी कोई सूचना सुरक्षा संचालन समिति नहीं है और इसके बजाय मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी सीधे निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करते हैं।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) उत्तर दिया कि आई.टी. विभाग के भीतर कर्तव्यों का पृथक्करण कार्यान्वयन के अधीन है।

अनुशंसा 52:

सुशासन के लिए, एस.ई.सी.आई. एक ऐसी आई.टी. संगठनात्मक संरचना स्थापित कर सकता है जो व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हो, प्रमुख आई.टी. कर्मियों को परिभाषित और पहचान कर सकती हो और महत्वपूर्ण कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता को कम कर सकती हो।

6.1.8 सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण आई.टी. नियंत्रण संरचना की आधारशिला हैं। ये उस सामान्य वातावरण से संबंधित हैं जिसमें आई.टी. प्रणालियों का विकास, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है। सामान्य आई.टी. नियंत्रण आई.टी. गतिविधियों के लिए समग्र नियंत्रण का ढांचा स्थापित

करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि समग्र नियंत्रण उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

6.1.8.1 नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा का संचालन न करना

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों⁷¹ के अनुसार आई.टी. एप्लिकेशन का तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा साल में एक बार किया जाना चाहिए। साथ ही, सी.ई.आर.टी.-इन दिशानिर्देशों के अनुसार, महत्वपूर्ण आई.टी. अनुप्रयोगों के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा वार्षिक व्यापक सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'ओपन वर्ल्डवाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट' (ओ.डब्ल्यू.ए.एस.पी.⁷²)-'2017 की शीर्ष 10 वेब-एप्लिकेशन कमजोरियों' के अनुसार एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली का सुरक्षा लेखापरीक्षा केवल जनवरी 2021 तक ही किया गया था। अब जबकि ओ.डब्ल्यू.ए.एस.पी. -2021 की शीर्ष 10 वेब एप्लिकेशन कमजोरियों को जारी कर दिया गया है और इसका उपयोग किया जा रहा है, ज्ञात कमजोर घटकों का उपयोग करने वाली अतिरिक्त कमजोरियां, जैसे कि असुरक्षित डिज़ाइन, सर्वर-साइड रिक्वेस्ट फोरजरी, सॉफ्टवेयर और डेटा अखंडता विफलता, आदि, जो शुरू में 2017 के लिए कवर नहीं की गई थीं, जनवरी 2021 के बाद एस.ई.सी.आई. द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा न किए जाने के कारण सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अनदेखी रह गईं।

इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चला कि एस.ई.सी.आई. ने जुलाई/अगस्त 2024 के दौरान सी.ई.आर.टी.-इन सूचीबद्ध संस्था द्वारा एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के ई-बैंकिंग सुविधा के साथ होस्ट-टू-होस्ट एकीकरण के लिए ही साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा किया था।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि एस.ई.सी.आई. सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों और ई.आर.पी. प्रणाली के लिए हर दो साल में एक बार साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा करेगा।

⁷¹ दिनांक 17 सितंबर 2009 के परिपत्र संख्या 29/9/09 के अनुसार।

⁷² ओ.डब्ल्यू.ए.एस.पी. टॉप 10 वेब अनुप्रयोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिमों की सूची है। इसे ओपन वेब एप्लिकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट (ओ.डब्ल्यू.ए.एस.पी.) द्वारा बनाया गया है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है और सॉफ्टवेयर सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

अनुशंसा 53:

एस.ई.सी.आई. अपनी आई.टी. और साइबर सुरक्षा नीति में आई.टी. प्रणालियों के आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक प्रावधान शामिल कर सकता है, जो मौजूदा सी.ई.आर.टी.-इन-आधारित बाहरी लेखापरीक्षा का पूरक होगा।

6.1.8.2 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सिस्टम के परिवर्तन प्रबंधन में कमियां

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में, प्रणाली के भीतर परिवर्तनों या विकास कार्यों को प्रबंधित करने के लिए 'परिवहन अनुरोधों' का उपयोग किया जाता है। यह निगरानी और नियंत्रण करने के लिए परिवहन अनुरोध बनाए जा सकते हैं कि प्रणाली के संशोधनों—जैसे कि विन्यास, कस्टम विकास या अद्यतनों—को विभिन्न प्रणाली परिवेशों के बीच कैसे स्थानांतरित किया जाता है।

18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुद्दे देखे गए, जिनकी पुष्टि ओ.ई.एम. रिपोर्ट में भी की गई है:

1. मानक परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए, उत्पादन वातावरण में सीधे कुल 24 परिवहन अनुरोध बनाए गए।
2. उत्पादन के लिए 1,715 परिवहन अनुरोध जारी किए गए, जिनमें से 1,141 अनुरोधों (66 प्रतिशत) का संक्रमण समय एक दिन से कम था, जो व्यापक परीक्षण और सत्यापन के लिए अपर्याप्त समय दर्शाता है।
3. परिवहन के 82 अनुरोधों को महत्वपूर्ण परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए तैनाती से पहले कठोर समीक्षा, परीक्षण और सत्यापन अनिवार्य था।
4. परिवहन अनुरोधों के लिए कोई परीक्षण रिपोर्ट या सहायक दस्तावेज नहीं रखे गए थे।

परीक्षण संबंधी दस्तावेजों की कमी और एक ही दिन के भीतर परिवहन अनुरोधों की तीव्र तैनाती से महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होते हैं, जिनमें अप्रमाणित या अपूर्ण परिवर्तनों के कारण

प्रणाली में व्यवधान और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया में पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही में कमी शामिल है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि दस्तावेज़ीकरण, अनुमोदन और परीक्षण नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए औपचारिक ई.आर.पी. परिवर्तन प्रबंधन और परिवहन अनुरोध प्रबंधन मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को मंजूरी दे दी गई है।

अनुशंसा 54:

एस.ई.सी.आई., प्रणाली-आधारित नियंत्रणों और आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से अनुमोदित एस.ओ.पी. के अनुपालन के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी को सुनिश्चित कर सकता है।

6.1.8.3 अद्यतनों के कार्यान्वयन में देरी

एस.ए.पी. नोट्स, एस.ए.पी. द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो प्रणाली की खामियों को दूर करते हैं, कार्यों को बेहतर बनाते हैं और बदलते व्यावसायिक और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन नोट्स में सॉफ्टवेयर त्रुटि सुधार, सुरक्षा अपडेट, प्रदर्शन में सुधार और कानूनी परिवर्तन शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ए.पी. ने 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 के बीच प्रणाली अपडेट के लिए 82 एस.ए.पी. नोट्स जारी किए। इनमें से 71 नोट्स अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। एस.ए.पी. नोट्स की इतनी बड़ी संख्या का लंबित होना प्रणाली अपडेट में देरी और एस.ए.पी. की सिफारिशों के अनुपालन में कमी को दर्शाता है।

एस.ए.पी. नोट्स के अनसुलझे रहने से प्रणाली असुरक्षित हो सकता है, परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और अनुपालन संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसलिए, एस.ई.सी.आई. को लंबित एस.ए.पी. नोट्स के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए ताकि प्रणाली

सुरक्षित और कुशल बने रहें।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) कहा कि ओ.ई.एम. ने केवल अनिवार्य नोटों को लागू करने का सुझाव दिया और एस.ई.सी.आई. से अनिवार्य नोटों की पहचान के लिए मानदंड मांगे। इसके अतिरिक्त, 82 नोटों में से कई या तो सलाहकारी हैं या सुधारों से संबंधित हैं, जबकि महत्वपूर्ण और सुरक्षा संबंधी नोटों को लागू करने में प्राथमिकता दी गई है।

इस प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एस.ई.सी.आई. ने एस.ए.पी. नोट्स को अनिवार्य, महत्वपूर्ण या सलाहकारी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई दस्तावेजी मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है।

अनुशंसा 55:

एस.ई.सी.आई, एस.ए.पी. नोट्स के महत्व के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने और प्राथमिकता देने के लिए स्पष्ट मानदंड बना सकता है और उन्हें दस्तावेजित कर सकता है।

6.1.8.4 घटना एवं परिवर्तन प्रबंधन के लिए एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर का उपयोग न करना

एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर एक व्यापक एप्लीकेशन लाइफसाइकिल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे एस.ए.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन, रखरखाव और एकीकरण को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली सुरक्षित, कुशल और निर्बाध रूप से संचालित हों।

क. घटना का प्रबंधन

एस.ई.सी.आई. की आरंभिक रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट किया गया था कि मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड समस्या लॉगिंग और समाधान के लिए एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर का उपयोग करेगी। इस टूल से कोर आई.टी. सर्विस मैनेजमेंट (आई.टी.एस.एम) प्रक्रियाओं जैसे कि घटना, सेवा अनुरोध, समस्या और ज्ञान प्रबंधन के साथ-साथ परिवर्तन अनुरोध प्रबंधन, जिसमें एस.ए.पी. ऑब्जेक्ट्स का परिवहन, केंद्रीकृत परिवर्तन नियंत्रण, जोखिम

प्रबंधन और व्यावसायिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का वर्कफ़्लो-आधारित कार्यान्वयन शामिल है, को समर्थन मिलने की उम्मीद थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. ने घटनाओं, समस्या प्रबंधन या परिवर्तन अनुरोध प्रबंधन के लिए एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। एस.ई.सी.आई. ने (फरवरी 2025) बताया कि एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर को 2021 में लागू किया गया था, लेकिन इसका उपयोग केवल एस.ए.पी.-ई.आर.पी. से संबंधित घटनाओं को लॉग करने के लिए हेल्पडेस्क टूल के रूप में किया गया था। एस.ई.सी.आई. ने आगे कहा कि एस.ए.पी. सॉल्यूशन प्रबंधक की जटिलता और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के कारण, एक अलग उपयोगकर्ता-अनुकूल आई.टी.-सक्षम हेल्पडेस्क टूल को मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड द्वारा 2023 में विकसित और कार्यान्वित किया गया था।

एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर का उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग न करने से संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर से कस्टम टूल पर स्थानांतरण से घटना समाधान प्रक्रियाओं, समस्या प्रबंधन और परिवर्तन प्रबंधन वर्कफ़्लो की सुदृढ़ता पर प्रश्न उठते हैं, जिन्हें मूल रूप से एस.ए.पी.-एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

ख. परिवर्तन प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. के पास परिवर्तन प्रबंधन के लिए कोई केंद्रीय भंडार नहीं है, जिससे आई.टी. प्रशासन और प्रणाली संशोधनों पर नियंत्रण और भी कमजोर हो जाता है। एक संरचित और केंद्रीकृत परिवर्तन प्रबंधन प्रणाली के अभाव में, प्रणाली संशोधनों पर नज़र रखना, परिवर्तनों से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करना और महत्वपूर्ण ई.आर.पी. घटकों में किए गए बदलावों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना अपर्याप्त रहता

है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि एस.ई.सी.आई. व्यापक जीवनचक्र और परिवर्तन प्रबंधन कवरेज प्राप्त करने के लिए अगले ई.आर.पी. संवर्धन चक्र में सॉल्यूशन मैनेजर या समकक्ष आई.टी.एस.एम. कार्यक्षमता के एकीकरण का मूल्यांकन करेगा।

अनुशंसा 56:

एस.ई.सी.आई., आई.टी. सेवा प्रबंधन ढांचे के लिए एस.ए.पी. सॉल्यूशन मैनेजर को लागू और उपयोग कर सकता है और परिवर्तन प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत भंडार स्थापित कर सकता है।

6.1.8.5 यूजर एक्सेस मैनेजमेंट की कमियां

एस.ए.पी. पर किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता की भूमिका और प्रोफाइल संगठन में उस कर्मचारी की भूमिका, कार्यक्षेत्र, अधिकार और जिम्मेदारी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एस.ए.पी. तक पहुंच से कर्मचारी अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेगा। हालांकि, पहुंच उन पहलुओं तक ही सीमित होनी चाहिए जहां कर्मचारी से किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

हालांकि, एस.ई.सी.आई. ने वर्कफ्लो-आधारित एस.ए.पी. एक्सेस मैनेजमेंट प्रणाली लागू नहीं किया था। एस.ई.सी.आई. के विभागों से प्राप्त ई-मेल के आधार पर लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था कि इसका प्रबंधन मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, लेखापरीक्षा को इस बात की पुष्टि करने के लिए ई-मेल की कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने भूमिकाओं और प्राधिकरणों में भी विरोधाभास पाया, उपयोगकर्ताओं के बारे में, जिनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली पर उपयोगकर्ताओं के एक्सेस कंट्रोल की लेखापरीक्षा जांच से

निम्नलिखित बातें सामने आईं:

क. अपूर्ण मास्टर डेटा वाले उपयोगकर्ता

एस.ए.पी. प्रणाली में उपयोगकर्ता मास्टर रिकॉर्ड, जो एक्सेस स्तरों को परिभाषित करता है, पूर्ण और सही ढंग से बनाए रखा जाना चाहिए। अपूर्ण पते की जानकारी वाले उपयोगकर्ताओं की सूची (एस.ए.पी. SU0) लेनदेन कोड के माध्यम से प्राप्त की गई थी। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि कुल 83 उपयोगकर्ताओं के पते की जानकारी अपूर्ण थी, जिनमें उपयोगकर्ता समूह, विभाग आदि जैसे फ़ील्ड गायब थे, छह उपयोगकर्ताओं के ई-मेल पते के फ़ील्ड गायब थे और 13 उपयोगकर्ताओं के फ़ंक्शन फ़ील्ड गायब थे।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उपयोगकर्ताओं को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या संगठन से अलग होने तक बिना किसी प्रतिबंध के एस.ए.पी. तक पहुंच प्रदान की गई थी।

ख. सुरक्षा प्राधिकरण में किए गए परिवर्तन

किसी भी ई.आर.पी. प्रणाली में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू प्राधिकरण प्रबंधन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं को उनकी भूमिकाओं के आधार पर उचित पहुंच प्राप्त हो।

लेखापरीक्षा के दौरान, अंतर्निहित एस.ए.पी. रिपोर्ट (आर.एस.यू.एस.आर.100एन.) के निष्पादन के माध्यम से सुरक्षा प्राधिकरणों में किए गए परिवर्तनों की एक सूची प्राप्त हुई। इस डेटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली में 2,73,279 परिवर्तन दर्ज किए गए थे। इन परिवर्तनों में प्राधिकरण ऑब्जेक्ट, भूमिकाओं और प्रोफाइलों में संशोधन शामिल थे।

हालांकि, कर्मचारियों की निर्धारित भूमिकाओं के साथ इन परिवर्तनों को दर्शाने वाले समेकित दस्तावेजों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पुष्टि नहीं कर सकी कि ये परिवर्तन संगठनात्मक भूमिका आवश्यकताओं के अनुरूप थे या नहीं।

ग. उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में किए गए परिवर्तन

एस.ए.पी. में उपयोगकर्ता मास्टर रिकॉर्ड प्रत्येक उपयोगकर्ता को सौंपी गई भूमिकाओं और प्रोफाइल को परिभाषित करता है, जिससे प्रणाली के भीतर उनकी पहुंच का स्तर निर्धारित होता है। सुरक्षा नीतियों और पहुंच नियंत्रणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इन रिकॉर्ड में किसी भी परिवर्तन की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, उपयोगकर्ता सुरक्षा में किए गए सभी परिवर्तनों की सूची प्रदान नहीं की गई। एस.ई.सी.आई. ने (फरवरी 2025 में) कहा कि भूमिकाएँ उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर सौंपी गई थीं।

हालांकि, उचित दस्तावेज़ीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा इन परिवर्तनों के औचित्य को सत्यापित करने या यह आकलन करने में असमर्थ था कि क्या वे उपयोगकर्ताओं के निर्धारित कार्य कार्यों के अनुरूप थे।

घ. एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में आवधिक उपयोगकर्ता पहुंच समीक्षा का अभाव

उपयोगकर्ता पहुंच की नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण उपाय है कि कर्मचारियों के पास उनकी कार्य जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित पहुंच अधिकार हों। लेखापरीक्षा के दौरान, एस.ई.सी.आई. ने (जनवरी 2025) बताया कि एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में उपयोगकर्ता पहुंच और भूमिकाओं को बनाए रखा गया था और प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी अपने-अपने विभागों में उपयोगकर्ताओं की पहुंच की समीक्षा के लिए जिम्मेदार थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा को कोई उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रोफाइल, एक्सेस समीक्षा रिपोर्ट या आवधिक समीक्षाओं के संचालन का कोई प्रमाण प्रदान नहीं किया गया। दस्तावेजी समीक्षाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि अनधिकृत पहुंच या अत्यधिक विशेषाधिकारों के संचय को रोकने के लिए एक्सेस अधिकारों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा था या नहीं, जिससे संभावित रूप से सुरक्षा जोखिम उत्पन्न

हो सकते थे।

मंत्रालय ने अपने जवाब (दिसंबर 2025) में कहा कि मास्टर डेटा प्रबंधन और उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप दिया गया है और उचित नियंत्रण और आवश्यक दस्तावेजीकरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अब से इनका पालन किया जाएगा।

अनुशंसा 57:

एस.ई.सी.आई. को वर्कफ़्लो-आधारित एस.ए.पी. एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना चाहिए।

6.1.8.6 एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. में उपयोगकर्ता प्रणाली का निरंतर उपयोग

एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. डेटाबेस बनाते समय सबसे पहले प्रणाली उपयोगकर्ता बनाया जाता है। प्रणाली डेटाबेस का सुपरयूजर होता है। इसे अपरिवर्तनीय प्रणाली विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि अन्य डेटाबेस उपयोगकर्ता बनाने, प्रणाली टेबल तक पहुँचने आदि की क्षमता।

एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. एडमिनिस्ट्रेशन गाइड में यह पुरजोर सिफारिश की गई है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में दैनिक कार्यों के लिए प्रणाली यूजर का उपयोग न किया जाए। इसके बजाय, इसका उपयोग केवल प्रारंभिक सेटअप के लिए किया जाना चाहिए और फिर इसे निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग यूजर बनाए जाने चाहिए और प्रत्येक को न्यूनतम आवश्यक विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। प्रणाली जैसे मानक यूजर अकाउंट सभी प्रणाली में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होने के कारण हैकिंग हमलों का एक आम निशाना होते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानक उपयोगकर्ता खाता प्रणाली सक्रिय है और 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 की अवधि के दौरान, उपयोगकर्ता प्रणाली द्वारा विशिष्ट 61

गतिविधियों से संबंधित कुल 5,34,793 गतिविधियाँ की गईं। हालांकि, एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. बैंक-एंड तक पहुंच न होने के कारण लेखापरीक्षा इन गतिविधियों की प्रकृति को सत्यापित नहीं कर सका।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि एस.ई.सी.आई. ने कार्यान्वयन भागीदार को प्रणाली उपयोगकर्ता को तुरंत निष्क्रिय करने और सभी प्रशासनिक कार्यों को व्यक्तिगत भूमिका-आधारित खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

अनुशंसा 58:

एस.ई.सी.आई. उपयोगकर्ता प्रणाली को निष्क्रिय कर सकता है और भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण लागू कर सकता है।

6.1.8.7 महत्वपूर्ण एस.ए.पी. कार्यों तक अत्यधिक और अनधिकृत उपयोगकर्ता पहुँच

एस.ए.पी. तालिका रखरखाव लेनदेन⁷³ प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील तालिका डेटा प्रदर्शित करने और संशोधित करने की अनुमति देता है। यह पहुँच उपयोगकर्ता को गोपनीय व्यावसायिक और वित्तीय डेटा देखने और निकालने और महत्वपूर्ण मास्टर डेटा और कॉन्फिगरेशन तालिकाओं में परिवर्तन करने की अनुमति देती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ए.पी. प्रणाली में 105 वैध उपयोगकर्ताओं में से 75 को अत्यधिक डेवलपर-स्तरीय प्राधिकरण⁷⁴ और प्रणाली में सभी तालिकाओं को संशोधित करने या प्रदर्शित करने की पहुँच दोनों सौंपी गई थी।

एस.ए.पी. डिबगिंग कार्यक्षमता आमतौर पर डेवलपर्स और प्रणाली प्रशासकों के लिए कोड निष्पादन का विश्लेषण करने और त्रुटियों का निवारण करने के लिए आरक्षित होती है। हालाँकि, जब उपयोगकर्ताओं को डिबगिंग और प्रतिस्थापन प्राधिकरण दिए जाते हैं, तो वे एस.ए.पी. के

⁷³ एस.ई. 16, एस.ई. 16.एन., एस.ई. 17, एस.एम. 30 और एस.एम. 31।

⁷⁴ ए.सी.टी.वी.टी.=02 (परिवर्तन) और ओ.बी.जे.टी.यू.पी.-डी.ई.बी.यू.जी. के साथ एस_डिबलप प्राधिकरण।

अंतर्निहित प्राधिकरण जाँचों को दरकिनार कर सकते हैं और लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान डेटा को संशोधित कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय-महत्वपूर्ण डेटा में हेरफेर और सुरक्षा उल्लंघन हो सकते हैं। यह प्राधिकरण उपयोगकर्ताओं को एस.ए.पी. सुरक्षा जाँचों को ओवरराइड करने, प्रतिबंधित लेनदेन और संवेदनशील डेटा तक पहुँच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह मेमोरी में गतिशील डेटा संशोधन की अनुमति देता है, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन और डेटा मिथ्याकरण का जोखिम होता है।

इसके अतिरिक्त, यह एस.ए.पी. सुरक्षा लॉग को दरकिनार कर सकता है, जिससे अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेखापरीक्षा ट्रेल की अनुपस्थिति से ये जोखिम और बढ़ गए, जिससे अनधिकृत गतिविधियों का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) कहा कि मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड के नियुक्त सलाहकारों के परामर्श से भूमिका और प्राधिकरण मैट्रिक्स की समीक्षा की जा रही है।

अनुशंसा 59:

एस.ई.सी.आई. को भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण लागू करते समय अनावश्यक तालिका प्रदर्शन और संशोधन प्राधिकरणों को रद्द कर देना चाहिए। डिबगिंग विशेषाधिकारों को अनुमोदित डेवलपर्स तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और अनधिकृत पहुँच को हटा दिया जाना चाहिए।

6.1.8.8 एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. में डेटा एडमिन विशेषाधिकार का अनधिकृत अनुदान

एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. में डेटा एडमिन प्रणाली विशेषाधिकार उपयोगकर्ताओं को सभी स्कीमाओं में ऑब्जेक्ट्स को संशोधित और हटाने की अनुमति देता है। यह इसे एक बहुत ही संवेदनशील विशेषाधिकार बनाता है जिसके लिए सख्त एक्सेस नियंत्रण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा

में पाया गया कि यह विशेषाधिकार डिफॉल्ट उपयोगकर्ताओं⁷⁵ के अलावा अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को दिया गया है, जिनके पास स्वाभाविक रूप से यह विशेषाधिकार होता है और जिनसे इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

ऐसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार पर सख्त नियंत्रण की अनुपस्थिति डेटाबेस संरचनाओं में अनधिकृत परिवर्तनों, संभावित डेटा अखंडता समस्याओं और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या आकस्मिक विलोपन के बढ़ते जोखिम का कारण बन सकती है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) उत्तर दिया कि सभी गैर-डिफॉल्ट उपयोगकर्ताओं से डेटा एडमिन विशेषाधिकार वापस ले लिया गया है।

6.1.8.9 बाह्य विक्रेता को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. लाइसेंस का आवंटन

एस.ई.सी.आई. ने अपने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली कार्यान्वयन के तहत कुल ₹6.07 करोड़ की लागत से 100 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. लाइसेंस खरीदे। इसके अतिरिक्त, एस.ई.सी.आई. ने मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड को वार्षिक तकनीकी सहायता के लिए ₹5.58 करोड़ और संचालन एवं रखरखाव सेवाओं के लिए ₹2.08 करोड़ का भुगतान किया। साथ ही, निविदा में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि एस.ई.सी.आई. को मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. के उपयोग के लिए निर्धारित पांच एस.ए.पी.-ई.आर.पी. लाइसेंस मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड के कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे। हालांकि मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड को संचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए पहले ही अलग से भुगतान किया जा चुका था, फिर भी इस आवंटन के परिणामस्वरूप ₹0.24 करोड़ (₹4,85,723.8 प्रति लाइसेंसx5 लाइसेंस) का अनावश्यक व्यय हुआ।

एस.ई.सी.आई. के लाइसेंस मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड के कर्मचारियों को आवंटित करने

⁷⁵ तकनीकी और _एस.याई.एस._आर.ई.पी.ओ./

से पहले किसी वैकल्पिक पहुंच विधि (जैसे साझा पहुंच या अस्थायी क्रेडेंशियल) का मूल्यांकन नहीं किया गया था। एस.ई.सी.आई. ने (फरवरी 2025 में) कहा कि एस.ए.पी. से अनुरोध किया जाएगा कि वह तृतीय पक्ष विक्रेताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में बेंचमार्किंग और मार्गदर्शन प्राप्त करे ताकि अनुपालन और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि बाहरी सलाहकारों की पहुंच 5 से घटाकर 4 कर दी गई है और सर्वोत्तम अभ्यास मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ओ.ई.एम. से संपर्क किया गया है।

अनुशंसा 60:

एस.ई.सी.आई. अपनी एस.ए.पी.-ई.आर.पी. लाइसेंसिंग रणनीति की समीक्षा कर सकता है और विक्रेता पहुंच विकल्पों पर एस.ए.पी. से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

6.1.8.10 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के लिए बैकअप प्रबंधन में कमियां

एस.ई.सी.आई. की बैकअप नीति के अनुसार, उपयोगकर्ता-स्तर और सर्वर-स्तर के सभी डेटा का समय-समय पर बैकअप लेना अनिवार्य है। एम.ई.आई.टी.वाई. द्वारा सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा संचालित क्लाउड सर्वरों के बैकअप की समय-सारणी संबंधित विक्रेताओं से परामर्श करके या अनुबंध के अनुसार तय की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैकअप डेटा का उपयोग पुनर्स्थापन परीक्षण के लिए किया जाना चाहिए ताकि इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 के बीच किए गए 4,817 डेटा बैकअप प्रयासों में से कुल 510 असफल रहे, जो लगभग 10.60 प्रतिशत की विफलता दर दर्शाता है। असफल बैकअप की निगरानी और समाधान का प्रबंधन मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हालांकि, बैकअप विफलताओं को दूर करने के लिए उठाए गए

विशिष्ट सुधारात्मक कदमों का कोई विस्तृत दस्तावेज या प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसके अलावा, एस.ई.सी.आई. ने बैकअप और रिकवरी प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए कोई स्पष्ट कार्यक्रम या आवृत्ति प्रस्तुत नहीं की और न ही बैकअप पुनर्स्थापना की प्रभावशीलता दर्शाने वाली कोई नवीनतम परीक्षण रिपोर्ट या साक्ष्य समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। आवधिक परीक्षण और सत्यापन की कमी एस.ई.सी.आई. की बैकअप प्रबंधन पद्धतियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, क्योंकि विफलता की स्थिति में डेटा को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह स्थिति डेटा की उपलब्धता और व्यावसायिक निरंतरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि एस.ई.सी.आई. क्लाउड सेवा प्रदाता और मेसर्स हाईबैट टेक्नोक्रेट लिमिटेड के समन्वय से एक संरचित बैकअप प्रबंधन और पुनर्स्थापना सत्यापन प्रक्रिया तैयार करेगा।

अनुशंसा 61:

एस.ई.सी.आई. बैकअप विफलताओं के मूल कारणों का विश्लेषण और दस्तावेजीकरण कर सकता है और समय पर समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।

6.1.8.11 एस.ए.पी. एच.ए.एन.ए. प्रणाली प्रतिकृति संचार के लिए असुरक्षित नेटवर्क कॉन्फिगरेशन

एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. में प्रणाली प्रतिकृति संचार को समर्पित नेटवर्क इंटरफेस तक सीमित रखा जाना चाहिए और अनधिकृत पहुंच को रोकने और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए। सुरक्षित संचार को

लागू करने के लिए पैरामीटर⁷⁶ उचित रूप से कॉन्फ़िगर किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. प्रणाली रेप्लिकेशन संचार की वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट (सार्वजनिक) नेटवर्क रूट के उपयोग की अनुमति देती है। लिसन इंटरफ़ेस पैरामीटर 'ग्लोबल' पर सेट है, जो रेप्लिकेशन संचार को समर्पित होस्ट तक सीमित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली रेप्लिकेशन संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन सक्षम नहीं है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि उन्होंने मौजूदा सहायता विक्रेता, मेसर्स हाईबार टेक्नोक्रेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे एन्क्रिप्शन लागू करके और केवल अधिकृत होस्ट तक पहुंच को प्रतिबंधित करके प्रणाली प्रतिकृति संचार को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और अनुशंसित सुरक्षा मानकों के अनुसार नेटवर्क सेटिंग्स की समीक्षा और कॉन्फ़िगरेशन करें।

अनुशंसा 62:

एस.ई.सी.आई. प्रणाली प्रतिकृति संचार को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठा सकता है।

6.1.8.12 एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. रखरखाव रणनीति का अभाव और अपग्रेड में देरी

एक प्रभावी एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. रखरखाव रणनीति प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता के साथ-साथ एस.ए.पी. की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के पालन का आश्वासन प्रदान करेगी। नियमित अपग्रेड सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को दूर करते हैं, प्रदर्शन को बढ़ाते हैं और कार्यक्षमता में सुधार करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. के पास एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. रखरखाव रणनीति नीति नहीं है। अपग्रेड के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की कमी एस.ई.सी.आई. की प्रणाली

⁷⁶ सक्षम_एस.एस.आई., एस.एस.एल. और सुनें इंटरफ़ेस।

सुरक्षा, समय पर अपडेट और प्रदर्शन अनुकूलन सुनिश्चित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है।

एस.ए.पी. अर्ली वॉच रिपोर्ट में बताया गया है कि एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. डेटाबेस के मौजूदा संस्करण का सुरक्षा रखरखाव अगस्त 2025 तक समाप्त हो जाएगा। पुराने संस्करण के कारण पहले से ही प्रकाशित और अप्रकाशित महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधार अनुपस्थित हैं। इसके अलावा, एस.ए.पी. जल्द ही मौजूदा संस्करण के लिए सुरक्षा खामियों का विश्लेषण करना बंद कर सकता है, जिससे अज्ञात सुरक्षा खतरों के सामने आने का जोखिम बढ़ जाएगा।

समय पर अपग्रेड न करने से सिस्टम साइबर खतरों, डेटा लीक और अनुपालन संबंधी जोखिमों के प्रति असुरक्षित बना रहता है। एस.ए.पी. हर साल कम से कम एक बार एच.ए.एन.ए. के नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करने की सलाह देता है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि एक संरचित एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. रखरखाव और अपग्रेड नीति को परिभाषित करने के लिए ओ.ई.एम. और कार्यान्वयन भागीदार से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके अलावा, ओ.ई.एम. के परामर्श से मौजूदा एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. डेटाबेस को नवीनतम समर्थित संस्करण में अपग्रेड करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं।

अनुशंसा 63:

एस.ई.सी.आई. एक संरचित एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. रखरखाव नीति स्थापित कर सकता है और नवीनतम एस.ए.पी.-एच.ए.एन.ए. संशोधन में अपग्रेड कर सकता है।

6.1.9 व्यावसायिक नियमों की मैपिंग और अनुप्रयोग नियंत्रण

बिजनेस रूल्स मैपिंग से तात्पर्य किसी एप्लिकेशन सिस्टम के भीतर व्यावसायिक संचालन को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों की पहचान और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया से है, जबकि एप्लिकेशन कंट्रोल प्रत्येक कम्प्यूटरीकृत एप्लिकेशन के लिए विशिष्ट नियंत्रण होते हैं।

बिजनेस ब्लूप्रिंट योजना के अनुसार, परिसंपत्तियों, सेवाओं की खरीद, चालान सत्यापन और माल प्राप्ति एवं माल जारी करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सामग्री प्रबंधन (एम.एम) मॉड्यूल में लागू किया जाना है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा विभाग ने पाया कि एस.ई.सी.आई. द्वारा लागू किए गए एम.एम. मॉड्यूल में परिसंपत्तियों, सेवाओं और परियोजनाओं की खरीद का कार्य शामिल था, जिसमें सिस्टम के बाहर आयोजित निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद खरीद अनुरोध जारी करना और खरीद आदेश बनाना शामिल था। चालान सत्यापन प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा सेवा प्रविष्टि पत्रक या माल प्राप्ति नोट संख्या का उपयोग करके मैन्युअल रूप से की जाती है।

इसके अलावा, एम.एम. मॉड्यूल ने बिजली उत्पादकों (संयुक्त मीटर रीडिंग और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं दोनों के लिए) के लिए बिलिंग प्रक्रिया को संभाला। संयुक्त मीटर रीडिंग परियोजनाओं के लिए, संयुक्त मीटर रीडिंग बिल डेटा को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. सिस्टम में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा खाता डेटा डाउनलोड करके दर्ज किया जाता है। क्षेत्रीय विद्युत समिति की वेबसाइट और विंडोज आधारित उपयोगिता के माध्यम से एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में डेटा फीड करना। चयनित मॉड्यूल, अर्थात् उपयोगिताओं के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान, वित्त और नियंत्रण तथा सामग्री प्रबंधन में प्रमुख प्रक्रियाओं की कार्यान्वयन स्थिति का सारांश **तालिका 35** में दिया गया है।

तालिका 35: चयनित मॉड्यूल में मुख्य प्रक्रियाओं की कार्यान्वयन स्थिति

यूटिलिटीज मॉड्यूल के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान की कार्यान्वयन स्थिति			
क्र.सं.	उपयोगिता मॉड्यूल के लिए उद्योग विशिष्ट समाधान में प्रक्रिया	कार्यान्वयन स्थिति	अभ्युक्तियां/टिप्पणियां
1	विचलन सेटल्मेंट तंत्र	लागू नहीं किया गया	बिज़नेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित शेड्यूलिंग कार्यक्षमताएं लागू नहीं की गईं।
2	विचलन सेटल्मेंट तंत्र	लागू नहीं किया गया	एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में विचलन निपटान तंत्र की कार्यक्षमता को कॉन्फ़िगर नहीं किया गया था।
3	बकाया वसूली प्रक्रिया और ब्याज गणना (अतिरिक्त भुगतान, जमा राशि, बिलिंग)	लागू नहीं किया गया	वसूली नोटिस और ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की जाती है, क्योंकि संबंधित प्रणाली-आधारित कार्यक्षमताएं उपलब्ध नहीं हैं।
वित्त और नियंत्रण मॉड्यूल में कार्यान्वयन की स्थिति			
क्र.सं.	वित्त और नियंत्रण मॉड्यूल में प्रक्रिया	कार्यान्वयन स्थिति	अभ्युक्तियां/टिप्पणियां
1	व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) वितरण	उपयोग नहीं किया गया	वीजीएफ भुगतान की प्रक्रिया एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के बाहर की गई थी।
2	प्रबंधन रिपोर्टिंग और योजना-वार व्यय की स्वचालित ट्रैकिंग।	लागू किया गया	मानक वित्तीय रिपोर्ट एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली से तैयार की जाती हैं।
सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में स्थिति का कार्यान्वयन			
क्र.सं.	सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में प्रक्रिया	कार्यान्वयन स्थिति	अभ्युक्तियां/टिप्पणियां
1	संपत्ति व सेवाओं की खरीद, परियोजना खरीद	आंशिक	खरीद अनुरोध और खरीद आदेश एम.एम. मॉड्यूल में बनाए जाते हैं, लेकिन पूरी निविदा प्रक्रिया प्रणाली के बाहर संचालित की जाती है।
2	चालान सत्यापन	लागू किया गया	वित्त विभाग, एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न सेवा प्रविष्टि पत्रक या माल प्राप्ति नोट संख्याओं का उपयोग करके मैनुअल रूप से चालान सत्यापन करता है।
3	माल प्राप्ति/माल जारी	उपयोग नहीं किया गया	मानक एस.ए.पी. कार्यक्षमता
4	संयुक्त मीटर रीडिंग पावर डेवलपर्स के लिए बिलिंग प्रक्रिया	आंशिक लागू किया गया	संयुक्त मीटर रीडिंग बिल डेटा को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है।

सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में स्थिति का कार्यान्वयन			
क्र.सं.	सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल में प्रक्रिया	कार्यान्वयन स्थिति	अभ्युक्तियां/टिप्पणियां
5	अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के बिजली डेवलपर्स के लिए बिलिंग प्रक्रिया	कार्यान्वित (उपयोगिता के माध्यम से)	क्षेत्रीय विद्युत समिति की वेबसाइट से डेटा डाउनलोड किया जाता है और विंडोज-आधारित यूटिलिटी का उपयोग करके एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में अपलोड किया जाता है।

इनमें से कुछ मुद्दों पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है।

6.1.9.1 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में बयाना जमा, प्रदर्शन बैंक गारंटी और प्रदर्शन सुरक्षा के संबंध में आई.टी.-सक्षम सेवाओं का न्यूनतम उपयोग

एस.ई.सी.आई. ने 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 के बीच विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त बयाना जमा, प्रदर्शन बैंक गारंटी और प्रदर्शन प्रतिभूतियों से ₹9,820.13 करोड़ की धनराशि का प्रबंधन किया। इन लेन-देन को स्वचालन, पारदर्शिता और वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एस.ए.पी.-ई.आर.पी. के माध्यम से संसाधित किए जाने की उम्मीद थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन लेन-देनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली के बजाय मैनुअल रूप से किया गया था। 348 बयाना जमा में से केवल चार, 370 प्रदर्शन बैंक गारंटी में से शून्य और 62 प्रदर्शन सुरक्षा लेन-देन में से 25 ही एस.ए.पी.-ई.आर.पी. के माध्यम से संसाधित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 96 प्रतिशत लेन-देन प्रणाली के बाहर प्रबंधित किए गए।

मैनुअल प्रक्रियाओं पर यह अत्यधिक निर्भरता ई.आर.पी. के स्वचालन, पारदर्शिता और अंतर्निहित व्यावसायिक नियमों के इच्छित लाभों को विफल कर देती है, उच्च नियंत्रण जोखिम पैदा करती है, प्रणाली द्वारा उत्पन्न लेखापरीक्षा ट्रेल्स की अनुपस्थिति, अनधिकृत परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता, त्रुटि की बढ़ी हुई संभावना और प्रणाली रिपोर्टों की अनुपलब्धता के कारण लेनदेन की पूर्णता, सटीकता और प्राधिकरण के स्वतंत्र सत्यापन को रोकती है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) बताया कि कागजी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी और बयाना जमा या प्रदर्शन प्रतिभूतियों जैसे समान दस्तावेजों को एक्सेल में ट्रैक किया जाता है ताकि उनकी रिलीज़, विस्तार या उपयोग संबंधी अनुरोधों को सुगम बनाया जा सके। मंत्रालय ने आगे बताया कि एस.ए.पी. में मौजूदा कार्यक्षमता में मेकर-चेकर सुविधा और टिप्पणी फ़ील्ड की कमी है और एक नए समाधान का विकास कार्य प्रगति पर है।

अनुशंसा 64:

एस.ई.सी.आई. को मेकर-चेकर नियंत्रणों, लेखापरीक्षा ट्रेल्स और स्वचालित वर्कफ़्लो के साथ ई.एम.डी., बैंक गारंटी और प्रदर्शन प्रतिभूतियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक एस.ए.पी.-आधारित मॉड्यूल के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।

6.1.9.2 एस.ई.सी.ई.टी. की खरीद नीति के खंडों को बिजनेस ब्लूप्रिंट में शामिल न करना और साथ ही एस.ई.सी.ई.टी. के एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में मैप न करना

एस.ई.सी.आई. की खरीद नीति (29 सितंबर 2018 को लागू) के खंड ए1.3.1(जी) के अनुसार, खरीद में दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आई.टी. और आई.टी.-सक्षम सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. एल1 बोलीदाताओं को एस.ए.पी. प्रणाली के बाहर अंतिम रूप देता है और कोटेशन के लिए अनुरोध प्रक्रिया एस.ए.पी. ई.आर.पी. में शामिल नहीं है। एस.ए.पी.-ई.आर.पी. कार्यान्वयन⁷⁷ के बिजनेस ब्लूप्रिंट चरण के दौरान, खरीद नीति के अध्याय 4 से 10 तक के कई प्रमुख प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था, जिनमें एनआई.टी. और लागत अनुमानों की तैयारी, बोलीदाता योग्यता आवश्यकताएं, बोली दस्तावेज, खरीद विधियां, बोली मूल्यांकन, अनुबंध आवंटन और पूर्व-आवंटन मुद्दे जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

⁷⁷ खरीद नीति के अनुसार, इनमें विशिष्ट प्रक्रियात्मक, वित्तीय और मूल्यांकन मानदंड शामिल हैं जैसे कि टर्नओवर, कार्यशील पूंजी, कुल संपत्ति, भुगतान की शर्तें, परिनिर्धारित हर्जाना, प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के तरीके, प्रतिक्रियाशीलता परीक्षण, मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुबंध प्रदर्शन गारंटी, पात्रता/अपात्रता के नियम और शिकायत निवारण तंत्र।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में इन्हें मैप भी नहीं किया गया था, जबकि एस.ई.सी.आई. की खरीद नीति बिजनेस ब्लूप्रिंट योजना की स्वीकृति तिथि से काफी पहले लागू की गई थी।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) कहा कि खरीद नीति का एक संशोधित संस्करण मार्च 2025 में अनुमोदित किया गया था और इसे एस.ए.पी. बिजनेस ब्लूप्रिंट में शामिल किया जाएगा।

अनुशंसा 65:

एस.ई.सी.आई. को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया और सभी प्रासंगिक खरीद नीति खंडों को बिजनेस ब्लूप्रिंट में शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में मैप किए गए हैं।

6.1.9.3 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध कार्यक्षमता का उपयोग न करना

एस.ई.टी.सी. की खरीद नीति पारदर्शिता, अखंडता सुनिश्चित करने और भ्रष्ट या अनैतिक प्रथाओं में लिप्त विक्रेताओं को बाहर करने के लिए आई.टी.-सक्षम प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य बनाती है, जिसमें ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध शामिल है (खंड ए1.3.1(जी), ए1.3.3 और बी5.8.2)।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एस.ई.टी.सी. के एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में बिजनेस ब्लूप्रिंट में विक्रेता ब्लैकलिस्टिंग और डिबारमेंट के लिए एकीकृत कार्यक्षमता का अभाव था, साथ ही इसमें प्रणाली-आधारित निष्पादन, लेखापरीक्षा ट्रेल या मजबूत भूमिका-आधारित पहुंच और मेकर-चेकर नियंत्रण भी नहीं थे।

हालांकि एस.ई.सी.आई. ने (अक्टूबर 2024) कहा था कि किसी भी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, फिर भी तीन विक्रेताओं को गैर-योजना-आधारित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि उन्होंने ई.आर.पी. प्रणाली में अपने प्रतिबंध का कोई सबूत, अधिकृत अनुमोदकों का विवरण, प्रतिबंध की अवधि या बोली सुरक्षा/अनुबंध प्रदर्शन गारंटी की

ज़बती के लिए प्रणाली रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। हालांकि, एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में प्रतिबंधित विक्रेताओं के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं:

तालिका 36: एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में अवरुद्ध विक्रेताओं का विवरण

क्र. सं.	नाम	द्वारा बनाया गया	बनाने की तिथि	बदलने की तिथि	द्वारा बदला गया	से मान्य	तक मान्य
1.	शस्त्र परिधीय (आर्म्स पेरिफेरल्स)	एम.एम.ए. डी.एम.आई. एन.	14.12.2020	21.10.2021	100118	00.01.1900	31.12.9999
2.	52000327	100118	16.02.2021	26.07.2024	100118	00.01.1900	31.12.9999
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कर्नाटक)	एस.डी.ए.डी. एम.आई.एन	14.12.2020	17.08.2021	100118	00.01.1900	31.12.9999
4.	एक्स.वाई.जेड.	100178	18.09.2024	18.09.2024	100178	00.01.1900	31.12.9999

लेकिन, एस.ई.सी.आई. ने ब्लॉकिंग कार्रवाइयों पर सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए, सक्षम प्राधिकारी की पहचान नहीं की, यह स्पष्ट नहीं किया कि एम.एम.ए.डी.एम.आई.एन., एस.डी.ए.डी.एम.आई.एन., 100118 और 100178 के रूप में दर्ज उपयोगकर्ता विक्रेताओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत थे या नहीं, प्रतिबंध अवधि क्या थी, या यह पुष्टि नहीं की कि क्रमांक 4 (एक्स.वाई.जेड.) परीक्षण डेटा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में वैधता अवधि प्रदर्शित हो रही थी, लेकिन इसमें डिफॉल्ट मान (00.01.1900 से 31.12.9999 तक वैध) दर्शाए गए थे, जिससे पता चलता है कि ब्लॉकिंग/प्रतिबंध के लिए कोई वास्तविक या अधिकृत समय सीमा परिभाषित या दर्ज नहीं की गई थी। एस.ई.सी.आई. ने कहा कि प्रणाली में विक्रेता को ब्लॉक करने की सुविधा है, लेकिन अनुरोध अगले अनुमोदन प्राधिकारी को अग्रेषित नहीं किया जाता है।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) उत्तर दिया कि प्रतिबंधित किए गए तीनों बोलीदाताओं को

ई.आर.पी. प्रणाली में निष्क्रिय कर दिया गया है।

6.1.9.4 एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में वसूली और ब्याज गणना प्रक्रिया का कार्यान्वयन न होना

एस.ई.सी.आई. में एस.ए.पी.-ई.आर.पी. कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक योजना में राजस्व संग्रह में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए वसूली और ब्याज गणना प्रक्रियाओं के स्वचालन की परिकल्पना की गई थी। वसूली सुविधा का उद्देश्य बकाया भुगतानों के लिए व्यवस्थित रूप से अनुस्मारक और नोटिस जारी करना था, जबकि ब्याज गणना सुविधा को सामूहिक भुगतान, व्यक्तिगत मदों, वसूली नोटिस और बिलिंग में मानकीकृत नियमों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य मैनुअल श्रम को कम करना, बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करना और वित्तीय नीतियों के अनुपालन को मजबूत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस.ई.सी.आई. ने बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में स्वचालित वसूली और ब्याज गणना की कार्यक्षमताओं को लागू नहीं किया है। इसके बजाय, एस.ई.सी.आई. बकाया भुगतानों के लिए मैनुअल ब्याज गणना पर निर्भर है। एस.ई.सी.आई. मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भर रहना जारी रखता है, जिससे वित्त टीमों का कार्यभार बढ़ जाता है जिन्हें बकाया भुगतानों को मैनुअल रूप से ट्रैक करना होता है और ब्याज की गणना करनी होती है। यदि ये कार्यक्षमताएँ ई.आर.पी. में लागू की गई होतीं, तो एस.ई.सी.आई. को भुगतान अनुस्मारक के स्वचालित निर्माण, देय तिथियों के सुसंगत अनुप्रयोग, सटीक और पारदर्शी ब्याज गणना और विश्वसनीय लेखापरीक्षा ट्रेल्स से लाभ होता, जिससे राजस्व प्राप्ति मजबूत होती और मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भरता कम होती।

इसके अतिरिक्त, सत्यापन के लिए वसूली गणनाओं का कोई मैनुअल रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया गया और केवल एक सामान्य बकाया शेष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा

वसूली प्रक्रिया के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) उत्तर दिया कि उन्हें मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और प्रक्रिया दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है और वे मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में स्वचालन को सक्षम करने के लिए देय तिथि और ब्याज तर्क के मानकीकरण की खोज कर रहे हैं। एस.ई.सी.आई. ने यह भी कहा कि वित्तीय प्रक्रिया स्वचालन के लिए इन कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

अनुशंसा 66:

एस.ई.सी.आई., एस.ए.पी.-ई.आर.पी. में स्वचालित वसूली और ब्याज गणना कार्यात्मकताओं के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

6.1.9.5 अपूर्ण मास्टर डेटा

एस.ए.पी. मटेरियल मैनेजमेंट (एम.एम.) मॉड्यूल, एस.ए.पी. ई.आर.पी. प्रणाली का एक प्रमुख घटक है जो किसी संगठन के लिए खरीद और इन्वेंट्री प्रबंधन के सभी पहलुओं को संभालता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही सामग्री सही मात्रा में, सही समय और लागत पर उपलब्ध हो, जिससे आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन और लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं का अनुकूलन हो सके।

वेंडर मास्टर डेटा के विश्लेषण से कई गंभीर कमियां सामने आईं, जिनमें 2,402 विक्रेताओं में से 735 विक्रेताओं के पास अपडेटेड टैक्स नंबर (पैन या जी.एस.टी.) नहीं था। इसके अलावा, 2402 विक्रेताओं में से 1,192 विक्रेताओं के पते की जानकारी अधूरी थी।

इसी प्रकार, मटेरियल मास्टर डेटा की जांच से पता चला कि सभी 583 मटेरियल रिकॉर्ड के लिए मूल्यांकन प्रकार अनुपस्थित था। इसके अलावा, 583 रिकॉर्ड में से 400 रिकॉर्ड में कोई क्रय समूह निर्दिष्ट नहीं था, जिससे खरीद की निगरानी और जवाबदेही प्रभावित होती है। एसेट

मास्टर डेटा के लेखापरीक्षा से पता चला कि 2,631 रिकॉर्ड में से 875 में अधिग्रहण वर्ष दर्ज नहीं था, जिससे एसेट लाइफसाइकिल ट्रैकिंग प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, 2,631 रिकॉर्ड में से 854 में माप प्रकार का उल्लेख नहीं था, जिससे एसेट का सही वर्गीकरण मुश्किल हो गया। 2,631 रिकॉर्ड में से 2,527 में इन्वेंट्री नंबर नहीं था, जिससे ट्रेसबिलिटी और एसेट मैनेजमेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ। साथ ही, कस्टमर मास्टर डेटा में, 921 कस्टमर रिकॉर्ड में से 629 में पैन (पैन) विवरण गायब पाया गया।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025 में) जवाब दिया कि ई.आर.पी. में मास्टर डेटा को पूरा करने और अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है।

अनुशंसा 67:

रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर संख्या और परिसंपत्ति विवरण जैसे प्रमुख फ़ील्ड पूर्ण हैं, एस.ई.सी.आई. द्वारा अनिवार्य डेटा सत्यापन प्रोटोकॉल लागू किए जाने की आवश्यकता है।

6.1.9.6 व्यवहार्यता अंतर निधि संवितरण प्रक्रिया के लिए एस.ए.पी.-ई.आर.पी. का उपयोग न करना

व्यवहार्यता अंतर निधि (वी.जी.एफ.) प्रक्रिया की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 18 जनवरी 2021 से 31 मई 2024 की अवधि के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त 34 स्वीकृति पत्रों में से केवल तीन को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. के माध्यम से संसाधित किया गया था।

मंत्रालय ने (दिसंबर 2025) कहा कि वी.जी.एफ. संवितरण ई-ऑफिस में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किए जा रहे थे, लेकिन लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज़, वर्कफ़्लो रिकॉर्ड या मिलान प्रस्तुत नहीं किया गया था जो यह दर्शाता हो कि इन भुगतानों को प्रणाली के बाहर कैसे ट्रैक किया गया था।

अनुशंसा 68:

एस.ई.सी.आई. यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठा सकता है कि बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में परिकल्पित सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को एस.ए.पी.-ई.आर.पी. के माध्यम से कॉन्फ़िगर और उपयोग किया जाए और मैनुअल या समानांतर प्रसंस्करण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।

6.1.10 निष्कर्ष

बिजनेस ब्लूप्रिंट प्लान में शुरू में परिकल्पित कई महत्वपूर्ण विशेषताओं को या तो लागू नहीं किया गया या उनका केवल आंशिक रूप से उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹19.62 करोड़ के व्यय के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों में मैनुअल प्रक्रियाओं और अक्षमताओं पर निरंतर निर्भरता बनी रही।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली में शेड्यूलिंग और विचलन निपटान तंत्र, वसूली गणनाओं का अभाव और व्यवहार्यता अंतर निधि वितरण का उपयोग न होना मूल परियोजना के दायरे से एक बड़ा विचलन है। इसी प्रकार, एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली ने आवश्यक खरीद प्रक्रियाओं को मैप नहीं किया, जबकि एस.ई.सी.आई. की खरीद नीति में दक्षता और पारदर्शिता के लिए स्वचालन अनिवार्य था। अनुबंध प्रबंधन, बोली मूल्यांकन, विक्रेता ब्लैकलिस्टिंग और निविदा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रणाली में या तो आंशिक रूप से या बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया था।

एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली लागू करने के बावजूद, बयाना जमा, प्रदर्शन बैंक गारंटी और प्रदर्शन प्रतिभूतियों से संबंधित मुख्य वित्तीय लेनदेन प्रणाली से बाहर रहे, और 96 प्रतिशत लेनदेन अभी भी मैनुअल रूप से संसाधित किए गए। इससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय स्वचालन और नियंत्रण के लिए प्रणाली का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिससे ई.आर.पी. समाधान को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य ही विफल हो गया।

औपचारिक परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण की कमी ने एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली को अपनाने में और बाधा उत्पन्न की। अपर्याप्त पहुँच नियंत्रण और निगरानी के कारण सुरक्षा जोखिम भी बढ़ गए, क्योंकि प्रणाली इंटीग्रेटर को अनधिकृत उच्च-विशेषाधिकार भूमिकाएँ सौंपी गई थीं और डिफ़ॉल्ट प्रणाली खाते अभी भी उपयोग में थे। आंतरिक विशेषज्ञता विकसित किए बिना एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रशासन के लिए एस.ई.सी.आई. की मेसर्स हाईबर टेक्नोमार्ट लिमिटेड पर निर्भरता ने संगठन को विक्रेता पर निर्भरता के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

समग्र निष्कर्ष बताते हैं कि एस.ई.सी.आई. ने स्वचालन, पारदर्शिता और दक्षता के अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एस.ए.पी.-ई.आर.पी. प्रणाली का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन न होना, प्रमुख मॉड्यूल का सीमित उपयोग और मैनुअल प्रक्रियाओं पर निरंतर निर्भरता ने ई.आर.पी. प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर दिया है, जिससे परिचालन अक्षमताएं और जोखिम बढ़ गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है कि प्रणाली का पूर्ण उपयोग हो, कार्यात्मकताओं को मूल योजना के अनुसार लागू किया जाए और ई.आर.पी. उपयोग में आगे की कमियों को रोकने के लिए शासन तंत्र को मजबूत किया जाए।

6.2 ₹5.07 करोड़ का निष्फल व्यय

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल परियोजना (लघु जलविद्युत परियोजनाएं) की खराब योजना के कारण ₹5.07 करोड़ का निष्फल व्यय

अप्रैल 2010 में, अवसंरचना संबंधी कैबिनेट समिति ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 'लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल' नामक परियोजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता को कम करना था। इस परियोजना में लघु जलविद्युत परियोजनाएं, सौर फोटोवोल्टिक, सौर तापीय प्रणालियां आदि स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। परियोजनाओं/प्रणालियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (लेह और कारगिल) को सौंपी गई थी। दोनों परिषदों को संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों और उनके इंजीनियरिंग विभागों के माध्यम से इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करवाना था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अप्रैल 2010 में इस परियोजना की गतिविधियों की देखरेख और निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जून 2010 में ₹473 करोड़ की कुल लागत पर इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी, जिसमें से ₹266.80 करोड़ लघु/सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे।

इस परियोजना का उद्देश्य लेह और कारगिल जिलों में कुल 23.68 मेगावाट (लेह में 11.18 मेगावाट और कारगिल में 12.50 मेगावाट) क्षमता वाली 30 लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करना था। इनमें से, कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक, लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को लेह जिले में कुल 11.18 मेगावाट क्षमता वाली 22 लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करनी थीं। हालांकि, अप्रैल 2012 में प्रस्तावित 22 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद, समय और

लागत संबंधी बाधाओं को देखते हुए एजेंसी ने केवल 10 लघु जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹87.67 करोड़ थी। इस परियोजना को पूरा करने की प्रारंभिक लक्षित तिथि दिसंबर 2013 थी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए जून 2011 से फरवरी 2025 तक ₹63.37 करोड़ जारी किए, जबकि इसे दिसंबर 2013 तक पूरा करने के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया। 10 परियोजनाओं में से, मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 तक पांच परियोजनाओं⁷⁸ को चालू घोषित किया था और एक परियोजना⁷⁹ लगभग पूरी होने वाली थी। शेष चार परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसका विवरण **अनुलग्नक 14** में दिया गया है।

सितंबर 2017 में, 5वीं संचालन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित एक समिति ने स्थलों का दौरा किया और अक्टूबर 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 10 लघु जलविद्युत परियोजनाओं में से चार को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। ये परियोजनाएं दुर्बुक, सुंडा-धो, शायोक और वारिस III में स्थित थीं। हालांकि, मंत्रालय ने सभी लघु जलविद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी), रुड़की (अगस्त 2018) को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

आई.आई.टी. रुड़की ने नवंबर 2018 में मंत्रालय को परियोजना-वार मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आई.आई.टी. रुड़की ने तकनीकी-आर्थिक आधार पर दुर्बुक, सुंडा-धो और शायोक में तीन परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश की और बताया कि सड़क की दीर्घकालिक खराबी के कारण वह वारिस स्थित परियोजना का दौरा नहीं कर सका। मंत्रालय ने आई.आई.टी.

⁷⁸ त्सती, हेनाचे, चामशेन, चालुंगखा और तुरतुक-1।

⁷⁹ बोगदडांग।

रुड़की द्वारा इन परियोजनाओं को बंद करने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की।

काफी समय बीत जाने के बाद, मार्च 2023 में मंत्रालय ने फिर से आई.आई.टी., रुड़की द्वारा 2018 में मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पिछली रिपोर्ट को अपडेट कराने का निर्णय लिया। इस बीच, मंत्रालय ने न तो मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम उठाया और न ही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी हस्तक्षेप किया, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि नवंबर 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान इन चार परियोजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया है। आई.आई.टी., रुड़की ने जुलाई 2023 में अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इन चार परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश की गई थी। आई.आई.टी., रुड़की की सिफारिशों और किए गए व्यय की मदों का विवरण **अनुलग्नक 14** में दिया गया है।

अतः, एम.एन.आर.ई. द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ खराब योजना और दोषपूर्ण डिज़ाइनों से ग्रस्त थीं, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन में खामियाँ आईं और चारों परियोजनाओं में सिविल और विद्युत-यांत्रिक कार्यों में नाममात्र की प्रगति हुई। वारिस और दुर्बुक् परियोजनाओं का ठेका निविदा प्रक्रिया के दो वर्ष बाद ठेकेदारों को आवंटित किया गया, जबकि शायोक परियोजना में चिनाई बांध के निर्माण के प्रस्ताव ने इसे तकनीकी-आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया। 22 सितंबर 2023 को संचालन समिति ने इन चारों परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश की। मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार कर ली और ₹6.49 करोड़ के व्यय के बाद चारों परियोजनाओं को बंद कर दिया।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के जवाब में, मंत्रालय ने (दिसंबर 2024 में) बताया कि वारिस III एस.एच.पी. के ठेकेदार से बैंक गारंटी भुनाकर ₹1.42 करोड़ की राशि वसूल की गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाएं उच्च ऊंचाई और दुर्गम भूभाग में स्थित हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों को कई

समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे मौसम संबंधी समस्याएं, वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन, अलगाववादियों द्वारा अशांति, कई क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन, कोविड-19 महामारी आदि।

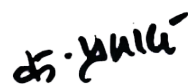
इस जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मंत्रालय को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मौसम और अन्य प्रकार की गड़बड़ियों की पहले से जानकारी थी और सर्वेक्षण एवं जांच के बाद 22 परियोजनाओं में से केवल 10 परियोजनाओं को ही कार्यान्वयन के लिए चुना गया था। इसलिए, इन चुनौतियों की जानकारी होने के बावजूद ही स्वीकृतियां दी गईं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी का प्रकोप 2020 से 2023 तक रहा, जबकि इन चार परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश संचालन समिति द्वारा गठित मंत्रालय की एक समिति ने अक्टूबर 2017 में ही कर दी थी। इन परियोजनाओं को बंद करने के प्रमुख कारण खराब योजना और दोषपूर्ण डिजाइन थे, जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा 2018 और 2023 में प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि परियोजना चयन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और उसका क्रियान्वयन लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया गया था, जबकि मंत्रालय ने केवल रिपोर्टों के आधार पर प्रगति की निगरानी की, क्योंकि वह सभी स्थलों का भौतिक निरीक्षण नहीं कर सकी। इस स्पष्टीकरण को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि संचालन समिति समग्र निरीक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार थी, जिसे परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों को शुरू से ही संभालना चाहिए था। संचालन समिति की 2010 और 2023 के बीच सात बैठकें हुईं; हालाँकि, समिति ने समय बीतने के बाद, सितंबर 2017 में परियोजना स्थलों का निरीक्षण हेतु दौरा करने का निर्णय लिया, तब तक काफी खर्च पहले ही हो चुका था।

इस प्रकार, परियोजना की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन के प्रति मंत्रालय के ढीले रवैये के परिणामस्वरूप ₹5.07 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

नई दिल्ली

दिनांक: 10 जुलाई 2026



(डॉ. कविता प्रसाद)

महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2026



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

(पैरा 1.5 देखें)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 और 15 के तहत लेखापरीक्षित केंद्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

संख्या	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2023-24 में जारी अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
1.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	211.00
2.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडांकी	42.84
3.	पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, उमियान	40.04
4.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	115.31
	उप कुल	409.19
परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
5.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी, मुंबई	125.00
6.	हरिश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज	42.15
7.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	81.36
8.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	42.77
9.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	301.09
10.	साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता	145.02
11.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई	824.29
12.	टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई	1311.81
13.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	190.89
14.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई	7.15
15.	बेसिक साइंसेज में उत्कृष्टता केंद्र, मुंबई	39.63
	उप कुल	3111.16
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
16.	अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट-मैक्स, पुणे	39.14
17.	आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला विज्ञान संस्थान, नैनीताल	49.19
18.	बोस संस्थान, कोलकाता	90.00
19.	बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ	103.51
20.	सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु	15.93
21.	भारतीय संघ कृषि विज्ञान, कोलकाता	159.12
22.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु	119.16
23.	भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई	54.64
24.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	38.27

संख्या	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2023-24 में जारी अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)
25.	नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान, मोहाली	37.31
26.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटाल्लुर्ग्य एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद	83.31
27.	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु	105.16
28.	रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु	68.51
29.	सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता	50.10
30.	वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून	44.56
31.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	20.12
32.	राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन-भारत, गांधीनगर	18.08
33.	प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए पूर्वोत्तर केंद्र, शिलांग	18.67
34.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	10.06
35.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु	12.82
36.	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली	3.00
37.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	27.13
38.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता	4.96
39.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, प्रयागराज	4.13
	उप कुल	1176.88
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
40.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	105.17
41.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे	80.00
42.	डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र, हैदराबाद	56.00
43.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव	39.50
44.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	71.80
45.	जैव-संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल	22.61
46.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	45.50
47.	अनुवाद स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	97.09
48.	राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	131.00
49.	राष्ट्रीय बायोमेडिकल जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	45.37
50.	राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	41.00
51.	इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु	66.23
52.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	36.30
53.	सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली	13.50
	उप कुल	851.07
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		

संख्या	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2023-24 में जारी अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)
54.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	230.00
55.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	105.00
56.	जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा	25.00
57.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	18.46
58.	राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र, चेन्नई।	124.75
59.	सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर।	10.06
60.	वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर।	25.51
61.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग	लागू नहीं
62.	ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर	22.27
63.	फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंस्टीट्यूट, रांची	10.33
64.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	19.72
65.	बांस और रतन के लिए वन अनुसंधान केंद्र, आइजोल	0.23
66.	आजीविका और विस्तार के लिए वन अनुसंधान, अगरतला	32.77
	उप कुल	624.10
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
67.	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई	10.14
68.	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, पंजाब	7.40
69.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	20.75
	उप कुल	38.29
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय		
70.	राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र, गोवा	280.48
71.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	205.00
72.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	266.69
73.	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद	135.95
74.	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम	21.09
	उप कुल	909.21
	सकल योग	7119.90

अनुलग्नक 2

(पैरा 1.6 देखें)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान किस अवधि से संबंधित है (मार्च 2023 तक)	23 मार्च तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2024 तक देय थे (संख्या में)	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग			
		मार्च 2014 तक	207	15.81
		2014-22	398	53.28
		2022-23	46	5.84
		उप कुल	651	74.93
2.	अंतरिक्ष विभाग			
		मार्च 2014 तक	120	3.28
		2014-22	144	6.69
		2022-23	46	2.16
		उप कुल	310	12.13
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
		मार्च 2014 तक	--	--
		2014-22	13172	4732.61
		2022-23	131	86.04
		उप कुल	13303	4818.65
4.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग			
		मार्च 2014 तक	--	--
		2014-22	20054	9270
		2022-23	446	404
		उप कुल	20500	9674.00
5.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	3787	160.91
		2014-22	723	738.97
		2022-23	223	323.58
		उप कुल	4733	1223.46
6.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	116	80.96

संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान किस अवधि से संबंधित है (मार्च 2023 तक)	23 मार्च तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2024 तक देय थे (संख्या में)	राशि (₹ करोड़ में)
		2014-22	676	748.03
		2022-23	18	53.96
		उप कुल	810	882.95
7.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
		मार्च 2014 तक	460	31.41
		2014-22	235	43.88
		2022-23	0	0
		उप कुल	695	75.29
कुल			41002	16761.41

अनुलग्नक 3

(पैरा 1.7 देखें)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

संख्या	सी.पी.एस.ई. का नाम	पूरक लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरी हो गई है
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
1.	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, शिमला	प्रबंधन पत्र के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गईं
2.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, दिल्ली	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियां जारी की गईं
3.	सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियां जारी की गईं
4.	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
5.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियां जारी की गईं
6.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
7.	केरल लिमिटेड का नवीकरणीय पावर कॉर्पोरेशन, कासरगोड	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
8.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाड़ा	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियां जारी की गईं
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
9.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दिल्ली	निरंक टिप्पणी
10.	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली	लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है
11.	भारतीय वैक्सीन कंपनी लिमिटेड, दिल्ली	निरंक टिप्पणी
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
12.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
13.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियां जारी की गईं
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
14.	अंडमान द्वीप वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	एमसीए 21 डेटाबेस से पता चलता है कि सीपीएसई को बंद कर दिया गया है, लेकिन संबंधित मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी बाकी है।
अंतरिक्ष विभाग		
15.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र

संख्या	सी.पी.एस.ई. का नाम	पूरक लेखापरीक्षा वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरी हो गई है
16.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
परमाणु ऊर्जा विभाग		
17.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भवानी), कल्पाक्कम	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
18.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
19.	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
20.	भारतीय दुर्लभ पृथ्वी (भारत) लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, मुंबई	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
21.	भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड - भारतीय तेल परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
22.	भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
23.	आई.आर.ई.एल.-आई.डी.सी.ओ.एल. लिमिटेड, (कॉर्पोरेट कार्यालय)	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र
24.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (यू.सी.आई.एल. कॉर्पोरेट कार्यालय)	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
25.	ए.आई.सी.-आई.पी.आर. प्लास्माटेक इनोवेशन फाउंडेशन	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं
26.	ए.आई.सी.-आर.आर. कैट पी.आई.-हब फाउंडेशन	प्रबंधन पत्र के साथ शून्य टिप्पणियाँ जारी की गईं

अनुलग्नक 4
(पैरा 1.8 देखें)

2023-24 के दौरान हानियों और अप्राप्य देय राशि/बट्टे खाते में डाली गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	घाटे और अप्राप्य देय राशि को बट्टे खाते में डालना									
	तंत्र की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी, आदि।		अन्य कारण		वसूली की छूट		अनुग्रह राशि भुगतान	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	10	8.11	-	-	-	-
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	निरंक									
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	निरंक									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	निरंक									
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	-	-	-	-	2	1.91	-	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	1	0.55	-	-	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	निरंक									
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	निरंक									
कुल	-	-	-	-	13	10.57	-	-	-	-

अनुलग्नक 5

(पैरा 1.9 देखें)

बकाया निरीक्षण रिपोर्ट और पैरा का विभाग/मंत्रालयवार ब्रेक-अप

सं. ख्या	मंत्रालय/विभाग	31 मार्च 2024 तक लंबित आई.आर./पैराग्राफ की संख्या										सकल योग	
		पर्यावरण		निरीक्षण		कोलकाता		मुंबई		बैंगलोर			
		आई.आर.	पैरा	आई.आर.	पैरा	आई.आर.	पैरा	आई.आर.	पैरा	आई.आर.	पैरा	आई.आर.	पैरा
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	75	363	80	563	28	222	183	1148
2.	अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	4	15	0	0	140	932	144	947
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	0	0	22	112	56	265	11	73	68	413	157	863
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	18	90	107	421	8	70	62	543	195	1124
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	26	153	21	86	1	8	13	78	61	325
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	0	0	18	144	23	75	18	118	40	261	99	598
7.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	177	1325	0	0	140	557	9	46	58	410	384	2343
8.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	58	418	0	0	0	0	1	3	9	89	68	510
कुल		235	1748	84	499	426	1782	128	881	418	2948	1291	7858

अनुलग्नक 6

(पैरा 1.11 देखें)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जनवरी 2026 तक प्रतीक्षित पहले कार्रवाई की गई टिप्पणियों
(ए.टी.एन.) की संक्षेपित स्थिति

संख्या	रिपोर्ट का वर्ष और संख्या	क्र. सं.	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति दिनांक	ए.टी.एन. जमा करने में देरी
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
1.	2020 का 6	14.2	भत्ते के अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय	23.9.2020	64 महीने 9 दिन
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
2.	2025 का 8	पूर्ण रिपोर्ट	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की गतिविधियां	12.8.2025	5 महीने 20 दिन
वाणिज्यिक इकाइयाँ					
परमाणु ऊर्जा विभाग					
3.	2021 का 2	4.5	कर्मचारियों को अस्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान।	24.3.2021	58 महीने 8 दिन
4.	2023 का 24	8.2	भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड में अनुबंध और सामग्री प्रबंधन	9.2.2024	23 महीने 23 दिन

अनुलग्नक 7

(पैरा 1.11 (क) देखें)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित कार्रवाई की स्थिति का सारांश जिसमें जनवरी 2026 तक लेखापरीक्षा ने टिप्पणियां/अवलोकन दिए हैं

संख्या	रिपोर्ट का वर्ष एवं संख्या	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर जांच टिप्पणियां जारी करने की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. जमा करने में देरी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
1.	2022 का 4	संपूर्ण रिपोर्ट	तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर निष्पादन रिपोर्ट।	25.7.2025	6 महीने 7 दिन
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग					
2.	2021 का 2	11.1	आई.टी. एप्लीकेशन सिस्टम 'वन सी.एस.आई.आर.' की कार्यक्षमता	12.11.2025	2 महीने 20 दिन
3.	2022 का 21	4.1	प्रोत्साहन और भत्तों का अनियमित अनुदान	17.11.2023	26 महीने 15 दिन
4.	2023 का 24	4.1	अपर्याप्त अनुबंध प्रबंधन के कारण ₹0.94 करोड़ का व्यय हुआ	19.6.2025	7 महीने 13 दिन
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
5.	2023 का 24	3.1	यात्रा भत्ते पर ₹0.68 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान	10.1.2025	12 महीने 22 दिन
परमाणु ऊर्जा विभाग					
6.	2023 का 24	8.1	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का कार्य	30.9.2025	4 महीने 2 दिन

अनुलग्नक 8

(पैरा 2.3 देखें)

लिफ्टों के कार्य आदेशों का विवरण और उन पर किया गया अतिरिक्त व्यय

सिविल कार्य					लिफ्ट से संबंधित कार्य					(₹ लाख में)
क्रम संख्या	जिस भवन में लिफ्टें लगानी हैं उसका नाम	कार्य आदेश जारी करने की तिथि	सिविल कार्य पूरा होने की तिथि	सिविल कार्य पूरा होने की तिथि	कार्य आदेश जारी करने की तिथि	लिफ्ट के काम को पूरा करने की निर्धारित तिथि	लिफ्ट के घटकों की आपूर्ति की तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य आदेश का मूल्य	अतिरिक्त व्यय
1	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (बी1) में स्नातक आवास	25.4.2012	8.5.2014	28.2.2022	23.1.2014	5.10.2014	21.11.2014	29.12.2021	63.5	16.21
2	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एम1) में विवाहित छात्रों के लिए आवास भवन	25.4.2012	8.5.2014	15.3.2022	28.1.2015	10.10.2015	19.9.2015	28.2.2022	68.5	18.36
3	टाइप III -सी बिल्डिंग	8.8.2012	21.8.2014	30.6.2021	13.11.2013	26.7.2014	26.11.2014	31.12.2020	88.00	25
4	टाइप IV - डी बिल्डिंग	8.8.2012	21.8.2014	31.3.2022	16.4.2015	29.12.2015	26.9.2015	31.3.2022 और		85.69

सिविल कार्य				लिफ्ट से संबंधित कार्य							
								31.5.2022			
5	टाइप ई बिल्डिंग	8.8.2012	21.8.2014	पूरा नहीं हुआ	16.4.2015	29.12.2015	26.9.2015	पूरा नहीं हुआ	356.00	21.10 (अभी तक भुगतान नहीं किया गया है)	
				कुल						576.00	166.36

अनुलग्नक 9
(पैरा 4.1.1 देखें)
एल.एच.आर.एफ. की उत्पत्ति, उपयोग और समापन शेष राशि

(₹ करोड़ में)

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22			2022-23			2023-2024			2024-2025		
		जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*
1.	सी.एस.आई.आर. मुख्यालय ⁸⁰	142.25	17.94	696.47	73.17	0.91	768.73	46.64	3.71	811.66	49.62	18.44	1,190.70
2.	केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	45.69	17.76	294.34	45.83	20.06	320.12	372.82	13.26	679.68	206.18	15.18	513.43
3.	राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएँ, बेंगलुरु	59.07	10.38	267.41	46.04	17.91	295.54	71.53	17.97	349.10	96.90	33.75	366.62
4.	केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी	-	2.10	106.83	9.32	0.40	115.75	2.69	0.34	118.10	6.38	10.01	30.58
5.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	31.68	2.27	92.40	12.60	1.83	103.17	17.67	3.26	117.58	17.21	5.72	101.37
6.	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	-	2.77	80.35	9.25	2.76	86.85	23.50	0.71	109.64	14.24	2.66	83.70

⁸⁰ मानव संसाधन विकास केंद्र, गाजियाबाद (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक केंद्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) में ₹0.11 करोड़ के समापन शेष सहित।

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22			2022-23			2023-2024			2024-2025		
		जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*
7.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा	13.82	4.36	69.18	19.97	3.09	86.06	13.34	0.72	98.69	14.50	10.67	73.85
8.	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	9.82	3.84	36.47	36.86	4.26	69.07	18.88	6.61	81.34	19.53	5.30	78.79
9.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	6.20	0.42	28.45	11.42	2.47	37.40	22.42	0.59	59.22	35.54	8.63	100.67
10.	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	4.82	0.39	28.72	20.80	2.19	47.33	11.11	0.71	57.73	7.12	3.16	66.74
11.	संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, चेन्नई	0.18	2.60	22.63	3.71	2.32	24.02	30.81	0.11	54.71	59.75	2.78	123.67
12.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	4.69	4.94	26.26	9.05	0.66	34.65	17.12	3.01	48.76	11.19	28.42	36.32
13.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली	8.82	3.33	35.73	14.73	9.27	41.18	9.02	2.88	47.32	16.59	11.65	53.98
14.	केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	-	0.42	41.27	8.87	4.07	46.06	1.30	0.62	46.75	2.65	1.44	59.39

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22				2022-23				2023-2024				2024-2025			
		जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू
15.	खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	-	3.20	35.79	8.16	6.44	37.51	9.43	2.19	11.37	3.91	44.75	11.37	3.91	64.67		
16.	केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	-	2.18	29.30	2.39	4.11	27.58	15.79	3.20	20.94	7.90	40.18	20.94	7.90	68.51		
17.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	1.47	1.06	27.75	5.58	1.07	32.26	5.84	0.23	22.32	6.46	37.86	22.32	6.46	66.53		
18.	सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़	1.83	1.09	23.58	1.88	0.75	24.72	4.72	1.76	4.91	7.30	27.69	4.91	7.30	40.93		
19.	कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद	5.96	3.72	6.19	10.06	0.44	15.81	9.33	0.14	0.70	10.49	25.00	0.70	10.49	21.77		
20.	केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	3.91	1.01	19.24	2.95	0.57	21.63	3.48	0.23	4.86	9.29	24.88	4.86	9.29	28.87		
21.	केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर	1.25	1.08	21.09	1.90	1.30	21.69	3.08	1.18	7.37	13.02	23.59	7.37	13.02	29.43		
22.	केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान,	1.51	5.97	16.88	3.21	0.19	19.89	3.38	0.25	3.75	2.92	23.02	3.75	2.92	30.09		

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22				2022-23				2023-2024				2024-2025			
		जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*
	दुर्गापुर																
23.	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर	4.99	1.39	16.40	3.91	0.98	19.33	3.74	1.13	5.47	10.00	21.94	5.47	10.00	25.73		
24.	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	0.92	0.61	11.95	1.86	0.92	12.90	9.39	1.61	5.36	6.49	20.68	5.36	6.49	32.22		
25.	केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2.33	0.09	11.96	4.29	0.14	16.11	4.34	0.06	3.74	6.68	20.39	3.74	6.68	23.28		
26.	जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान, दिल्ली	-	3.26	4.37	0.74	0.48	4.63	12.63	0.86	0.28	13.91	16.40	0.28	13.91	15.91		
27.	उत्तर-पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट	2.90	0.40	14.69	1.56	4.09	12.17	3.38	0.04	1.93	8.43	15.51	1.93	8.43	14.79		
28.	केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़	3.78	2.04	10.62	3.19	1.56	12.25	1.96	0.96	4.38	2.28	13.25	4.38	2.28	15.52		
29.	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता	1.36	2.64	8.53	0.83	0.25	9.11	3.01	0.07	0.19	9.79	12.05	0.19	9.79	16.54		
30.	केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स	2.65	2.35	11.03	1.84	0.65	12.22	1.36	2.53	4.01	1.48	11.06	4.01	1.48	14.72		

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22			2022-23			2023-2024			2024-2025		
		जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	सी.बी.*	जी*	यू	सी.बी.*
	इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी												
31.	केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधे संस्थान, लखनऊ	-	0.29	5.62	2.68	0.51	7.80	2.37	0.22	9.95	2.74	3.97	16.87
32.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	-	2.08	6.99	1.15	0.15	7.99	1.76	0.00	9.74	9.63	2.11	18.89
33.	राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	2.82	0.27	9.01	2.40	3.22	8.18	3.62	4.15	7.65	6.52	8.10	19.40
34.	भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश	-	0.32	8.90	-	0.24	4.57	2.38	0.16	6.79	1.12	1.50	14.12
35.	उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, भोपाल	-	0.41	4.76	0.70	0.39	5.08	0.71	0.01	5.78	0.79	1.05	9.39
36.	फोर्थ पैराडाइम इंस्टीट्यूट, बेंगलोर	1.47	0.35	2.96	0.85	0.01	3.80	0.13	0.09	3.84	0.12	2.04	4.76
37.	हिमालय जैव	-	0.54	2.94	1.26	2.19	2.01	0.75	0.09	2.67	0.96	6.55	4.15

संख्या	प्रयोगशाला संस्थान	2021-22			2022-23			2023-2024			2024-2025		
		जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*	जी*	यू*	सी.बी.*
	संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर												
38.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।	-	0.13	6.20	1.27	0.14	7.34	1.73	0.09	8.98	0.68	1.30	13.77
	कुल	337.00	110.00	2143.25	382.21	102.98	2422.48	767.17	75.73	3113.92	681.54	304.79	3490.68⁸¹

जी*-वर्ष के दौरान उत्पत्ति, यू-वर्ष के दौरान उपयोग, सी.बी.*-समापन शेष

⁸¹. ₹38.90 करोड़, ₹49.73 करोड़, ₹177.26 करोड़ और ₹208.87 करोड़ की अर्जित ब्याज को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-34 और 2024-25 के लिए।

अनुलग्नक 10
(पैरा 4.1.5.1 देखें)

2021-2024 की अवधि के लिए कुल निधि सृजन और निवेश से ब्याज

प्रयोगशाला/संस्थान	वर्ष	कुल उत्पत्ति (₹ करोड़ में)	निवेश से ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज से उत्पन्न एल.एच.आर.एफ. का प्रतिशत
सी.एस.आई.आर. मुख्यालय	2021-22	142.25	39.25	27.59
	2022-23	73.17	20.83	28.47
	2023-24	46.64	42.00	90.05
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान	2021-22	-	8.78	100.00 ⁸²
	2022-23	9.25	9.25	100.00
	2023-24	23.50	15.98	68.00
राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला	2021-22	59.07	9.79	16.57
	2022-23	46.04	21.89	47.55
	2023-24	71.53	30.71	42.93
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला	2021-22	4.69	2.02	44.07
	2022-23	9.05	3.85	42.54
	2023-24	17.12	4.64	27.10
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	2021-22	13.82	5.99	43.34
	2022-23	19.97	4.10	20.53
	2023-24	13.34	6.30	47.22
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान	2021-22	1.36	0.19	13.97
	2022-23	0.83	0.84	101.20
	2023-24	3.01	0.40	13.29
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला	2021-22	31.68	7.26	22.93
	2022-23	12.60	6.34	50.32
	2023-24	17.67	9.62	54.44
हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	2021-22	-	0.00	0.00
	2022-23	1.26	0.00	0.00
	2023-24	0.75	0.00	0.00
केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान	2021-22	-	0.94	100.00
	2022-23	9.32	0.80	8.58
	2023-24	2.69	1.02	37.92
केंद्रीय खनन एवं ईंधन	2021-22	45.69	47.60	104.18

⁸² मुख्यालय को निधि हस्तांतरण को छोड़कर।

प्रयोगशाला/संस्थान	वर्ष	कुल उत्पत्ति (₹ करोड़ में)	निवेश से ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज से उत्पन्न एल.एच.आर.एफ. का प्रतिशत
अनुसंधान संस्थान	2022-23	45.83	62.99	137.44
	2023-24	372.82	147.30	39.51
कुल		1066.94	510.68	47.86

अनुलग्नक 11

(पैरा 4.1.5.3 ख देखें)

परियोजनाओं में सकारात्मक शेष राशि

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
1	एस.एस.पी.0141	90651044.81
2	एस.एस.पी.0855	13921926.26
3	एस.एस.पी.0151	11033217.81
4	एस.एस.पी.2065	9558076
5	एस.एस.पी.2698	8128457
6	एस.एस.पी.0636	8073783.08
7	एस.एस.पी.1945	7928811
8	एस.एस.पी.2682	7521639.42
9	एस.एस.पी.2682	7518695
10	एस.एस.पी.2666	7214278.7
11	एस.एस.पी.3642	6916557.15
12	एस.एस.पी.2712	5785154
13	एस.एस.पी.2047	5413779
14	एस.एस.पी.0852	5101068.85
15	एस.एस.पी.2058	5038401.38
16	एस.एस.पी.0253	4125118.65
17	एस.एस.पी.3641	4061855.5
18	एस.एस.पी.1724	3934452
19	एस.एस.पी.0142	3915223.29
20	एस.एस.पी.2049	3805612
21	एस.एस.पी.3724	3698399
22	एस.एस.पी.3650	3574041.9
23	एस.एस.पी.1631	3287403
24	एस.एस.पी.2735	2878001
25	एस.एस.पी.3295	2832712.5
26	एस.एस.पी.0642	2795558
27	एस.एस.पी.2051	2782923
28	एस.एस.पी.0665	2649501
29	एस.एस.पी.3735	2589455
30	एस.एस.पी.2689	2526207
31	एस.एस.पी.2056	2525176
32	एस.एस.पी.0650	2371701.01
33	एस.एस.पी.2655	2336673.5
34	एस.एस.पी.2506	2289000

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
35	एस.एस.पी.2042	2279363.6
36	एस.एस.पी.0640	2243655.39
37	एस.एस.पी.1281	2192006
38	एस.एस.पी.2721	2126537
39	एस.एस.पी.2672	2042401
40	एस.एस.पी.2688	1995002
41	एस.एस.पी.0858	1964100.43
42	एस.एस.पी.0682	1909282
43	एस.एस.पी.3802	1904788.83
44	एस.एस.पी.3318	1903572
45	एस.एस.पी.2043	1882131
46	एस.एस.पी.1829	1854628.79
47	एस.एस.पी.5607	1848084
48	एस.एस.पी.3803	1767791.32
49	एस.एस.पी.0660	1671579.26
50	एस.एस.पी.3646	1668611
51	एस.एस.पी.2677	1665139
52	एस.एस.पी.0669	1622274
53	एस.एस.पी.1289	1612500
54	एस.एस.पी.3680	1579039
55	एस.एस.पी.0643	1440780.56
56	एस.एस.पी.1286	1439097
57	एस.एस.पी.2729	1407823
58	एस.एस.पी.2068	1351077
59	एस.एस.पी.2692	1335097
60	एस.एस.पी.0661	1312582
61	एस.एस.पी.3684	1300000
62	एस.एस.पी.0641	1282643.6
63	एस.एस.पी.0639	1273774.45
64	एस.एस.पी.2620	1268828
65	एस.एस.पी.1709	1208359.46
66	एस.एस.पी.2654	1203330.5
67	एस.एस.पी.0155	1196458
68	एस.एस.पी.1287	1192766

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
69	एस.एस.पी.0865	1183484
70	एस.एस.पी.2663	1113497
71	एस.एस.पी.2675	1090474
72	एस.एस.पी.0664	1080937
73	एस.एस.पी.9660	958390
74	एस.एस.पी.3821	932674
75	एस.एस.पी.3719	907542.9
76	एस.एस.पी.0646	900841.75
77	एस.एस.पी.2732	897990
78	एस.एस.पी.5804	892500
79	एस.एस.पी.2661	869825
80	एस.एस.पी.3290	851403.23
81	एस.एस.पी.3317	847315.8
82	एस.एस.पी.1714	833355.04
83	एस.एस.पी.1285	830322
84	एस.एस.पी.2718	789013
85	एस.एस.पी.5608	779456.12
86	एस.एस.पी.2681	777400
87	5615	769899
88	एस.एस.पी.0647	755543
89	एस.एस.पी.3814	738073.8
90	एस.एस.पी.3816	727931.78
91	एस.एस.पी.2077	707000
92	एस.एस.पी.5612	683195
93	एस.एस.पी.3804	646649.24
94	एस.एस.पी.1618	640703
95	एस.एस.पी.3722	632022
96	एस.एस.पी.3810	628804.2
97	एस.एस.पी.3737	604092
98	एस.एस.पी.0673	601837
99	एस.एस.पी.3663	564475
100	एस.एस.पी.2048	560617.85
101	एस.एस.पी.3725	555083.5
102	एस.एस.पी.2719	542507
103	एस.एस.पी.1610	539257.5
104	एस.एस.पी.1405	503286
105	एस.एस.पी.5901	493031.5
106	एस.एस.पी.0856	485855

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
107	एस.एस.पी.0837	478187
108	एस.एस.पी.0652	477696
109	एस.एस.पी.1293	472973.43
110	एस.एस.पी.2707	463183
111	एस.एस.पी.3818	440110
112	एस.एस.पी.2738	427184
113	एस.एस.पी.3738	427163
114	एस.एस.पी.2741	414675
115	एस.एस.पी.1290	409717.45
116	एस.एस.पी.2665	401903
117	एस.एस.पी.1634	401210
118	एस.एस.पी.2725	390000
119	एस.एस.पी.2685	377432
120	एस.एस.पी.2731	371823
121	एस.एस.पी.3289	369898
122	एस.एस.पी.3688	369764
123	एस.एस.पी.2696	368730
124	एस.एस.पी.3645	317838
125	एस.एस.पी.2743	298875
126	एस.एस.पी.1824	291965
127	1291	289775.39
128	एस.एस.पी.3807	280782.55
129	एस.एस.पी.2683	267400
130	एस.एस.पी.3661	262874.4
131	एस.एस.पी.3294	253733.2
132	एस.एस.पी.1727	237142
133	एस.एस.पी.1299	230923.78
134	एस.एस.पी.1628	228760
135	एस.एस.पी.3674	227476
136	एस.एस.पी.2054	218987
137	एस.एस.पी.2739	217177
138	एस.एस.पी.0666	198707
139	एस.एस.पी.0859	193767
140	एस.एस.पी.2071	191318
141	एस.एस.पी.5606	188727.9
142	एस.एस.पी.1408	185460
143	एस.एस.पी.1621	166731.06
144	एस.एस.पी.0256	164325.08

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
145	एस.एस.पी.2037	163804
146	एस.एस.पी.0258	152400
147	एस.एस.पी.3297	140731.45
148	एस.एस.पी.3668	119565
149	एस.एस.पी.1622	118507.75
150	एस.एस.पी.2740	117270
151	एस.एस.पी.1715	116033
152	एस.एस.पी.3685	115305
153	एस.एस.पी.2687	112750
154	एस.एस.पी.1294	109655
155	एस.एस.पी.2684	108948
156	एस.एस.पी.1723	57674.25
157	एस.एस.पी.3902	52586
158	एस.एस.पी.1708	46074
159	एस.एस.पी.3808	42520.03
160	एस.एस.पी.2073	35000
161	एस.एस.पी.3826	33741
162	एस.एस.पी.1711	31954.7
163	एस.एस.पी.5610	28177
164	एस.एस.पी.1716	17585

सं ख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
165	एस.एस.पी.2046	6826.3
166	एस.एस.पी.0658	2971
167	एस.एस.पी.0255	1.63
168	एस.एस.पी.5613	1.5
169	एस.एस.पी.3811	1.17
170	एस.एस.पी.0863	1.14
171	एस.एस.पी.5803	1.06
172	एस.एस.पी.0656	1
173	एस.एस.पी.0657	1
174	एस.एस.पी.0866	1
175	एस.एस.पी.1630	1
176	एस.एस.पी.2717	1
177	एस.एस.पी.3809	0.97
178	एस.एस.पी.0653	0.8
179	एस.एस.पी.3651	0.62
180	एस.एस.पी.2060	0.29
181	एस.एस.पी.3652	0.2
182	एस.एस.पी.3405	0.1
कुल		357349776.41

अनुलग्नक 12

(पैरा 4.1.5.3 ख देखें)

परियोजनाओं में नकारात्मक शेष राशि

संख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)	संख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
1	एस.एस.पी.1607	-0.10	36	एस.एस.पी.0651	-602490.00
2	एस.एस.पी.2059	-0.58	37	एस.एस.पी.0254	-770118.50
3	एस.एस.पी.2664	-69.60	38	एस.एस.पी.2679	-782776.00
4	एस.एस.पी.1718	-643.50	39	एस.एस.पी.1284	-829802.00
5	एस.एस.पी.2694	-1169.00	40	एस.एस.पी.3801	-892456.85
6	एस.एस.पी.0842	-1539.00	41	एस.एस.पी.0648	-917261.00
7	एस.एस.पी.3657	-6692.00	42	एस.एस.पी.0119	-932773.00
8	एस.एस.पी.3659	-8037.42	43	एस.एस.पी.3287	-989422.50
9	एस.एस.पी.2372	-9647.00	44	एस.एस.पी.0644	-1011634.50
10	एस.एस.पी.2633	-15000.00	45	एस.एस.पी.2063	-1076275.00
11	एस.एस.पी.0655	-33560.00	46	एस.एस.पी.2062	-1111178.00
12	एस.एस.पी.1402	-48167.40	47	एस.एस.पी.3647	-1246786.34
13	एस.एस.पी.1295	-57233.00	48	एस.एस.पी.3655	-1285540.72
14	एस.एस.पी.1624	-74026.00	49	एस.एस.पी.3721	-1311756.50
15	एस.एस.पी.2052	-78544.91	50	एस.एस.पी.2733	-1320068.00
16	एस.एस.पी.0250	-79586.00	51	एस.एस.पी.2045	-1602941.00
17	एस.एस.पी.1726	-79867.00	52	एस.एस.पी.2021	-1618218.00
18	एस.एस.पी.2680	-93989.00	53	एस.एस.पी.1620	-1678766.00
19	एस.एस.पी.3644	-120197.00	54	एस.एस.पी.3726	-1711406.56
20	एस.एस.पी.3648	-139270.90	55	एस.एस.पी.2053	-1911014.00
21	एस.एस.पी.1721	-152658.00	56	एस.एस.पी.1825	-1915306.00
22	एस.एस.पी.1627	-168321.00	57	एस.एस.पी.5701	-2005847.00
23	एस.एस.पी.0649	-185219.34	58	एस.एस.पी.3723	-2032057.75
24	एस.एस.पी.2727	-198826.00	59	एस.एस.पी.3649	-2099712.45
25	एस.एस.पी.1826	-220723.00	60	एस.एस.पी.1706	-2357022.87
26	एस.एस.पी.3653	-223937.00	61	एस.एस.पी.3638	-2358426.40
27	एस.एस.पी.1297	-232034.00	62	एस.एस.पी.3901	-2388126.91
28	एस.एस.पी.1710	-241346.83	63	एस.एस.पी.3603	-2453208.73
29	एस.एस.पी.1617	-243747.50	64	एस.एस.पी.1827	-2469244.00
30	एस.एस.पी.1830	-252090.40	65	एस.एस.पी.3285	-2526518.20
31	एस.एस.पी.1292	-253449.49	66	एस.एस.पी.0149	-2534779.15
32	एस.एस.पी.0862	-351529.04	67	एस.एस.पी.0257	-2561481.00
33	एस.एस.पी.1823	-520916.02	68	एस.एस.पी.1251	-3092058.00
34	एस.एस.पी.3293	-528842.80	69	एस.एस.पी.1278	-3200979.72
35	एस.एस.पी.0645	-545041.52	70	एस.एस.पी.0663	-3351685.00

संख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
71	एस.एस.पी.1707	-3386466.25
72	एस.एस.पी.0851	-4260656.72
73	एस.एस.पी.3316	-5715929.04
74	एस.एस.पी.1623	-8003555.00
75	एस.एस.पी.1221	-8099120.16
76	एस.एस.पी.0847	-9461790.00
77	एस.एस.पी.5801	-14602696.01

संख्या	परियोजना सं.	राशि (₹ में)
78	एस.एस.पी.0840	-15086785.45
79	एस.एस.पी.3315	-15488011.34
80	एस.एस.पी.3654	-15600608.72
81	एस.एस.पी.3453	-30536918.22
82	एस.एस.पी.0047	-36612648.00
83	एस.एस.पी.2014	-92121223.13
कुल		-325091467.04

अनुलग्नक 13

(पैरा 4.1.6.2 देखें)

प्रयोगशालाओं से सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में धन का हस्तांतरण

2021-22					
संकेत	प्रतिष्ठान का नाम	उत्पादन (र लाख में)	उत्पादन का 5 प्रतिशत (र लाख में)	सी.एस.आई.आर. मुख्यालय को (र लाख में)	आधिकार्य/कमी (र लाख में)
1	आई.आई.पी.	146.92	7.35	137.34	129.99
2	सी.आर.आर.आई.	-697.75	-34.89	76.08	110.97
3	आई.एम.एम.टी.	-310.82	-15.54	53.42	68.96
4	एस.ई.आर.सी.	18.01	0.9	62.8	61.9
5	आई.एच.बी.टी.	-82.91	-4.15	54.89	59.04
6	आई.एम.टी.ई.सी.एच.	183.03	9.15	58.62	49.47
7	सी.एल.आर.आई.	-59.62	-2.98	39.27	42.25
8	सी.बी.आर.आई.	-225.39	-11.27	17.24	28.51
9	सी.ई.सी.आर.आई.	-307.61	-15.38	11.05	26.43
10	सी.एस.एम.सी.आर.आई.	125.43	6.27	32.66	26.39
11	आई.आई.आई.एम.	-359.36	-17.97	3.19	21.16
12	एन.पी.एल.	882.07	44.1	63.25	19.15
13	आई.जी.आई.बी.	-23.99	-1.2	16.05	17.25
14	आई.आई.टी.आर.	92.25	4.61	21.46	16.85
15	सी.आई.एम.ए.पी.	-165.28	-8.26	7.16	15.42
16	एन.बी.आर.आई.	-213.79	-10.69	0	10.69
17	सी.एम.ई.आर.आई.	150.73	7.54	17.54	10
18	सी.जी.सी.आर.आई.	390.7	19.54	27.29	7.76
19	ए.एम.पी.आर.आई.	-93.57	-4.68	2.79	7.47
20	एन.जी.आर.आई.	481.71	24.09	30.67	6.58

2021-22					
संकेत	प्रतिष्ठान का नाम	उत्पादन (र लाख में)	उत्पादन का 5 प्रतिशत (र लाख में)	सी.एस.आई.आर. मुख्यालय को (र लाख में)	आधिकार्य/कमी (र लाख में)
21	एन.सी.एल.	469.2	23.46	29.75	6.29
22	एन.ई.ई.आर.आई.	981.69	49.08	54.63	5.55
23	सी.ई.आई.आर.आई.	265.25	13.26	14.14	0.88
24	एच.आर.डी.सी.	0	0	0	0
25	एन.आई.एस.सी.पी.आर.	-380.35	-19.02	0	0
26	एन.आई.ई.एस.टी.	282.38	14.12	12.95	-1.17
27	सी.डी.आर.आई.	233.22	11.66	10.17	-1.49
28	आई.आई.सी.बी.	136.16	6.81	4.79	-2.02
29	एन.ई.ई.एस.टी.	290.2	14.51	11.15	-3.36
30	4 पी.आई.	147.2	7.36	0.49	-6.87
31	सी.एफ.टी.आर.आई.	498.59	24.93	16.14	-8.79
32	आई.आई.सी.टी.	620.47	31.02	19.32	-11.7
33	सी.एस.आई.ओ.	378.03	18.9	6.37	-12.53
34	सी.सी.एम.बी.	595.82	29.79	12.67	-17.12
35	एन.आई.ओ.	1382.2	69.11	47.75	-21.36
36	एन.एम.एल.	3168.44	158.42	109.64	-48.78
37	एन.ए.एल.	5907.08	295.35	233.57	-61.78
38	सी.आई.एम.एफ.आर.	4568.56	228.43	0	-228.43
कुल		19474.9	974.48	1316.3	

2022-23						
संकेत	नाम	उत्पादन (₹ लाख में)	उत्पादन का 5 प्रतिशत (₹ लाख में)	मुद्रास्फीयता (₹ लाख में)	आर्थिक/व्यक्तिगत (₹ लाख में)	
1	एन.एम.एल.	1260.27	63.01	156.21	93.2	
2	एन.ए.एल.	4604.29	230.21	260.35	30.14	
3	आई.आई.आई.एम.	408.9	-20.45	7.05	27.5	
4	आई.जी.आई.बी.	73.93	3.7	9.53	5.83	
5	सी.एफ.टी.आर.आई.	390.88	19.54	24.93	5.39	
6	सी.जी.सी.आर.आई.	295.14	14.76	19.11	4.35	
7	4 पी.आई.	85.08	4.25	7.36	3.11	
8	एन.आई.आई.एस.टी.	239.58	11.98	14.12	2.14	
9	आई.आई.पी.	557.57	27.88	29.39	1.51	
10	एन.आई.आई.एस.टी.	156.49	7.82	8.93	1.11	
11	एच.आर.डी.सी.	0	0	0	0	
12	आई.एम.टी.ई.सी.एच.	188.37	9.42	9.15	-0.27	
13	सी.आई.एम.एफ.आर.	4583.33	229.17	228.43	-0.74	
14	आई.आई.सी.बी.	83.16	4.16	3.37	-0.79	
15	ए.एम.पी.आर.आई.	70.44	3.52	2.68	-0.84	
16	सी.एस.आई.ओ.	318.8	15.94	14.61	-1.33	
17	सी.डी.आर.आई.	429.15	21.46	19.12	-2.34	
18	एन.आई.एस.सी.पी.आर.	127.41	6.3705	3.89	-2.48	
19	सी.एस.एम.सी.आर.आई.	189.98	9.5	6.27	-3.23	
20	आई.आई.टी.आर.	186.23	9.31	4.61	-4.7	

2022-23						
संकेत	नाम	उत्पादन (₹ लाख में)	उत्पादन का 5 प्रतिशत (₹ लाख में)	मुद्रास्फीयता (₹ लाख में)	आर्थिक/व्यक्तिगत (₹ लाख में)	
21	एन.बी.आर.आई.	115.29	5.76	0	-5.76	
22	आई.एच.बी.टी.	125.69	6.28	0	-6.28	
23	सी.ई.आई.आर.आई.	184.44	9.22	1.5	-7.72	
24	सी.एम.आई.आर.आई.	320.73	16.04	6.92	-9.12	
25	आई.एम.एम.टी.	816.26	40.81	30.29	-10.52	
26	सी.बी.आर.आई.	239.13	11.96	0	-11.96	
27	सी.आई.एम.ए.पी.	268.37	13.42	0	-13.42	
28	एस.ई.आर.सी.	370.53	18.53	0.9	-17.63	
29	एन.सी.एल.	904.68	45.23	23.46	-21.77	
30	आई.आई.सी.टी.	1141.75	57.09	31.02	-26.07	
31	एन.आई.ओ.	1997.34	99.87	71.49	-28.38	
32	एन.पी.एल.	1472.68	73.63	44.1	-29.53	
33	सी.ई.सी.आर.आई.	931.86	46.59	14.53	-32.06	
34	सी.एल.आर.आई.	886.65	44.33	8.94	-35.39	
35	सी.सी.एम.बी.	1006.45	50.32	12.01	-38.31	
36	सी.आर.आर.आई.	925.35	46.27	0	-46.27	
37	एन.जी.आर.आई.	2079.97	104	17.53	-86.47	
38	एन.आई.आई.आर.आई.	3685.93	184.3	49.08	-135.22	
कुल		30904.3	1545.21	1140.88		

2023-24						
संख्या	नाम	उत्पादन (₹ लाख में)	उत्पादन 5 (₹ लाख में)	उत्पादन 5 प्रतिशत (₹ लाख में)	मुद्रास्फी (₹ लाख में)	आधिकार/कमी (₹ लाख में)
1	सी.आई.एम.एफ.आर.	37282.02	1864.1	2404.03	539.93	
2	एन.एम.एल.	1767.14	88.36	220.47	132.11	
3	एन.आई.ओ.	1334.39	66.72	178.76	112.04	
4	एन.ई.ई.आर.आई.	1887.72	94.39	191.28	96.89	
5	सी.एल.आर.आई.	130.46	6.52	76.35	69.83	
6	एन.जी.आर.आई.	1111.01	55.55	110.55	55	
7	सी.एस.आई.ओ.	196.37	9.82	46.78	36.96	
8	सी.जी.सी.आर.आई.	348.02	17.4	50.58	33.18	
9	एन.पी.एल.	902.04	45.1	66.07	20.97	
10	सी.सी.एम.बी.	932.94	46.65	66.68	20.03	
11	सी.आई.एम.ए.पी.	237.46	11.87	27.64	15.77	
12	सी.डी.आर.आई.	434.24	21.71	35.58	13.87	
13	एन.ई.आई.एस.टी.	338.21	16.91	30.49	13.58	
14	सी.ई.ई.आर.आई.	136.17	6.81	19.8	12.99	
15	एन.बी.आर.आई.	175.52	8.78	21.65	12.87	
16	सी.एम.ई.आर.आई.	337.83	16.89	26.26	9.37	
17	4 पी.आई.	13.12	0.66	9.82	9.16	
18	एन.आई.एस.सी.पी.आर.	173.43	8.6715	15.59	6.92	
19	आई.एम.टी.ई.सी.एच.	472.25	23.61	29.88	6.27	
20	ए.एम.पी.आर.आई.	71.43	3.57	6.38	2.81	

2023-24						
संख्या	नाम	उत्पादन (₹ लाख में)	उत्पादन 5 (₹ लाख में)	उत्पादन 5 प्रतिशत (₹ लाख में)	मुद्रास्फी (₹ लाख में)	आधिकार/कमी (₹ लाख में)
21	सी.एफ.टी.आर.आई.	374.47	18.72	19.54	0.82	
22	एच.आर.डी.सी.	0	0	0	0	
23	आई.आई.आई.एम.	237.81	11.89	10.92	-0.97	
24	आई.आई.पी.	584.26	29.21	26.73	-2.48	
25	आई.एच.बी.टी.	74.81	3.74	0	-3.74	
26	सी.एस.एम.सी.आर.आई.	308.07	15.4	9.5	-5.9	
27	एन.आई.आई.एस.टी.	362.11	18.11	11.97	-6.14	
28	आई.आई.सी.बी.	300.83	15.04	8.37	-6.67	
29	आई.एम.एम.टी.	942.68	47.13	31.52	-15.61	
30	एन.सी.एल.	1711.53	85.58	52.13	-33.45	
31	सी.ई.सी.आर.आई.	268.51	13.43	47.44	-34.01	
32	आई.आई.टी.आर.	939.2	46.96	9.31	-37.65	
33	सी.बी.आर.आई.	1579.44	78.97	27.56	-51.41	
34	आई.जी.आई.बी.	1263.13	63.16	3.69	-59.47	
35	सी.आर.आर.आई.	2349.54	117.48	46.27	-71.21	
36	आई.आई.सी.टी.	2241.63	112.08	38.73	-73.35	
37	एस.ई.आर.सी.	3080.63	154.03	28.12	-125.91	
38	एन.ए.एल.	7152.5	357.63	230.21	-127.42	
कुल		72052.92	3602.64	4236.65		

अनुलग्नक 14

(पैरा 6.2 देखें)

रद्द की गई परियोजनाओं का विवरण

सं ख्या	एस.एच.पी. परियोजना का नाम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा सिफारिश	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	खर्च की गई मद
1	वारिस-III एस.एच.पी.	सिविल कार्य में बहुत कम प्रगति और विलंब और पास के गांवों आदि में 33 केवी स्थानीय ग्रिड पावर निकासी लाइन की अनुपस्थिति के कारण, वारिस परियोजना खराब योजना और निष्पादन का प्रतिबिंब है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।	2.74	• सिविल कार्य जिसमें पावर हाउस, डिसिल्टिंग और फोरबे, पावर चैनल, टेल रेस आदि शामिल हैं। • संबंधित सिविल कार्यों सहित पेनस्टॉक • विद्युत यांत्रिक कार्य • साइट कार्यालय व्यय
2	शायोक एस.एच.पी.	शायोक परियोजना खराब योजना, डिजाइन और निष्पादन का प्रतिबिंब है और इसे इसके वर्तमान आकार में त्याग दिया जाना चाहिए।	2.49	• सिविल कार्य जिसमें पावर हाउस, डिसिल्टिंग और फोरबे, पावर चैनल, टेल रेस आदि शामिल हैं। • संबंधित सिविल कार्यों सहित पेनस्टॉक • विद्युत यांत्रिक कार्य
3	दुरबुक एस.एच.पी.	बाढ़ और कार्यों के पुनर्वास के कारण, परियोजना के पुनः निविदा सहित कई अन्य कारकों के कारण परियोजना कार्यों के निष्पादन में देरी हुई और परियोजना को बंद करने की सिफारिश की गई है।	0.64	• सिविल कार्य जिसमें पावर हाउस, डिसिल्टिंग और फोरबे, पावर चैनल, टेल रेस आदि शामिल हैं। • पेनस्टॉक, संबंधित सिविल कार्यों सहित • विद्युत यांत्रिक कार्य
4	सुम्दा ढो एस.एच.पी.	बाढ़ के कारण पुनः डिजाइन करने की ज़रूरत, कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपिंग एजेंसी (लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के बीच लागत से जुड़े मुद्दों पर विवाद वगैरह की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई और इसे बंद करने की सिफारिश की गई है।	0.62	• सिविल कार्य जिसमें पावर हाउस, डिसिल्टिंग और फोरबे, पावर चैनल, टेल रेस आदि शामिल हैं। • पेनस्टॉक, संबंधित सिविल कार्यों सहित • विद्युत यांत्रिक कार्य
कुल			6.49	

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/hi/page-17-of-26>

